ANUT

all Contains





[जिसमें नवीन संविधान की
रूपरेखा, देशी राज्यों के
एकीकरण का इतिहास,
स्वतंत्रता-प्राप्ति की कहानी,
तथा पूर्ववर्ती भारतीय
संविधानों का
संचिप्त विवरण
समाविष्ट
है।]

~~@D~~

लेखक:

श्री मदन मोहन गुप्त,

बी. ए., एल-एल. ची.

प्रकाशक

मक्तवा जामिश्रा लिमिटेड

डाकघर जामित्रानगर, दिल्ली

कापी राइटें मक्तवा जामित्रा लिं० जामित्रा नगर देहली

> प्रथम संस्करण २००० त्राक्तूबर १९५० मूल्य सजिल्द तीन रुपये

> > सुद्रक जैटयद् प्रेस देहती।

विषय सूची

प्रथम भाग

भारत का सांविधानिक इतिहास

	प्रथम अध्याय	पृष्ठ
निरं	कुशता इ। राज्यकाल	१ से रन
3	श्रंत्र जी के पहले	
2	श्र ग्रेजी व्यापार संस्था का राज्य	*
३	संसद् का श्रं कुश	3
8	सन् १७≍१ का श्रधिनियम	*
¥	पिट का अधिनियम—अधिक नियंत्रया	¥
, 8,	सन् १८३३ का संविधान और एकीकरण की प्रवृत्ति	Ę
9	सन् १८१७ की क्रांति के कारण श्रीर परिसाम	79
5	ब्यापारी राज्य का श्रन्त	5
8	विकेन्द्रीयकरण की श्रोर: १८६१ का संविधास	
90	भारत में जागृति तथा उसका प्रभाव	30.
33	साम्प्रदायिकता का समावेश : मिंटो मोरले सुधार	30
35	प्रथम विश्वयुद्ध तथा रवराज्य की मांग	92
93	मोंटफोर्ड की सुधार योजना	9.2
38	स्वराज्य श्रान्दोलन तथा नया संविधान	30
	द्वितीय श्रध्याय	
सन्	१६ ^९ ६ के संविधान का कार्यकाल	२३ से ४३
9	परिषदों में स्वराज्य की मांग	, o ,

,				
3	मुड्डीमैन समिति			२४
ર	भारत में फूट			२६
8	साइमन समिति			२६
¥	सर्वदुखीय सम्मेलन तथा नेहरू समिति			२८
, ξ	साइमन की रिपोर्ट			२६
9	गोलमेज सम्मेलनों की तैयारी			३०
5	पूर्ण स्वराज्य की मांग			३२
8	पहला गोलमेज सम्मेलन			३३
30	मैकडोनल्ड की घोषणा			३४
33	गांधी-इरविन संधि			3 8
3	द्वितीय गोलमेज सम्मेलन			80
13	साम्प्रदायिक पंचाट		,	83
18	तीसरा गोलमेज सम्मेलन तथा १६३४ का संविधान			83
	तीसरा ऋध्याय			
सन्	तीसरा ऋघ्याय १६३४ का संविधान	88	से	ĘĦ
सन्		88	से	हम ४४
	१६३४ का संविधान	४४	से	•
9	१६३४ का संविधान श्राधारभृत सिद्धांत	88	से	88
3	१६३४ का संविधान श्राधारभृत सिद्धांत संघ के श्र [ं] ग	88	से	88
0 N W	१६३४ का संविधान श्राधारभृत सिद्धांत संघ के श्रांग संघीय योजना की श्रसफलता के कारण	88	से	88 88
0 R W 30	१६३४ का संविधान श्राधारभृत सिद्धांत संघ के श्रांग संघीय योजना की श्रसफलता के कारण ब्रिटेन का नियंत्रण	88	से	88 88 88
9 2 2 2 2	१६३४ का संविधान श्राधारभृत सिद्धांत संघ के श्रंग संघीय योजना की श्रसफलता के कारण ब्रिटेन का नियंत्रण ब्रिटेन में उच्चायुक्त	88	से	88 88 88 88 88 88
0 R W W W W	१६३४ का संविधान श्राधारभृत सिद्धांत संघ के श्रंग संघीय योजना की श्रसफलता के कारण ब्रिटेन का नियंत्रण ब्रिटेन में उच्चायुक्त गवर्नर जनरल : परिवर्तन काल में	88	से	28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 2
0 N N W N N 9	१६३४ का संविधान श्राधारभृत सिद्धांत संघ के श्रंग संघीय योजना की श्रसफलता के कारण ब्रिटेन का नियंत्रण ब्रिटेन में उच्चायुक्त गवर्नर जनरल: परिवर्तन काल में व्यवस्थापक मंडल: परिवर्तन काल में	88	से	*****
J 6 m x c m n o	१६३४ का संविधान श्राधारभृत सिद्धांत संघ के श्रंग संघीय योजना की श्रसफलता के कारण ब्रिटेन का नियंत्रण ब्रिटेन में उच्चायुक्त गवर्नर जनरल: परिवर्तन काल में व्यवस्थापक मंडल: परिवर्तन काल में	88	से	** * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
m II 6 m K & M N w	१६३४ का संविधान श्राधारभृत सिद्धांत संघ के श्रंग संघीय योजना की श्रसफलता के कारण ब्रिटेन का नियंत्रण ब्रिटेन में उच्चायुक्त गवर्नर जनरल: परिवर्तन काल में व्यवस्थापक मंडल: परिवर्तन काल में गवर्नर जनरल: संव योजना में मन्त्रि परिषद्: संघीय	88	से	*****

विषय-सूची

१२	संघीय राज्य-परिषद्	¥Ę
१३	संघीय व्यवस्थापिका-सभा	२७
38	सद्नों का कार्य	४६
94	विषय वितरण	६०
18	धन-प्राप्ति के साधन	६१
90	संघीर नगथालम	ą ş
15	केन्द्र के श्रमिकर्ना (एजेंट) प्रान्त	६२
3.5	भांतीय स्मान	६३
२०	सदस्यों की यांग्यता मादि	Ę
29	पृथक किये हुए महेरा	Ęu
	प्रान्तों में स्वशास्त्र कः कार्थकाल	ĘĘ

चतुर्थ अध्याय

130	सांवि	धानिक वार्ता	६६ से १०२
	9	श्रवैधानिक शासन तथा श्रसह योग	88
	7	क्रिप्स योजना	90
	ૅર	केवल प्रयासः राष्ट्रीय सरकार का प्रश्न	199
5	8	नये निर्वाचन	9
	Ł	ब्रिटेन में श्रम सरकार की स्थापना तथा भारत को	
		स्वतन्त्रता का वचन	७२
	ξ	मन्त्री प्रतिनिधि-मंडल का प्रथम सुमाव	७३
	*	शिमला सम्मेलन	७५
	5	मन्त्री प्रतिनिधि-मंडल की नवमसूत्री योजना	७६
	8	भारत की प्रतिक्रिया	9=
	ğ 0	लीग श्रौर राष्ट्रसभा के सुम्ताव	. =9
	3 3	मन्त्री प्रतिनिधि-मंडल की श्रन्तिम वर्गीकरण योजन	I ===

\$ 5	योजना की त्रुटियां			8.8
93	संविधान सभा तथा श्रंतिस सरकार			85
88	सिक्खों तथा मुसलमानों की प्रतिक्रिया			£ =
34	श्रन्तरिम सरकार के निर्माण विषयक वार्ता			3.3
98	राष्ट्रीय सरकार की स्थापना			300
30	लीग वालों के उपद्रव			300
35	संविधान सभा का उद्घाटन			303
,	पांचवा अध्याय			
भा	रत विभाजन श्रौर स्वराज्य	१०३३	से	१२४
9	श्रवधि नियत			१०३
२	लीग भी मंत्रिमंदल में			३०६
ર	पुनः लीगी द्रपृद्धव तथा प्रान्तीय विभाजनों की मांग			१०६
8	राष्ट्रसमा द्वारा पाकिस्तान स्वीकार			350
*	ब्रिटिश संस्कार की भारत विभाजन घोषणा			900
E	प्राकिस्तान सम्बन्धी श्रांकड़े			335
9	भारतीय स्वतंत्रता श्रघिनियम			998
Ξ.	स्वतंत्रता अधिनियम के परिणाम			353
3	संविधान निर्माण			१२३
	छठा ऋध्याय			
देशी	राज्यों की समस्या का समाधान	१२६ :	से	१४०
9	संघ में प्रवेश			१२६
₹.	कारमीर			१३०
3	हैदराबाद			930
8	जूनागढ			930

विषय-सूची

¥	राज्यों का श्रन्त	939
Ę	प्रान्तों में विजीनकरण	933
9	राज्य-संघों का निर्माण	358
=	नये केन्द्र-प्रशासित प्रान्तों का निर्माण	१३६

द्वितीय भाग

स्वतंत्र भारत का संविधान

प्रथम अध्याय

संविधान के सिद्धान्त		१४३ से	१४७.
	प्रस्तावना		385
9	मुख्य रचना		385
· २	भारत का राज्य-चेत्र		188
ર	नागरिकता		38=
8	मूलाधिकार		388
*	राज्य की नीति के सिद्धान्त		***
•	द्वितीय श्रध्याय		
संघी	य शासन-व्यवस्था	१४८ से	. ४०४
9	भारत का राष्ट्रपति		34=
2	राष्ट्रपति पर महाभियोग		363
3	चमा श्रादि की राष्ट्रपति की शक्ति		988
8	राष्ट्रपति का संरच्य		382
¥	राष्ट्रपति की विधायिनी शक्तियाँ		163

Ę	भारत का उपराष्ट्रपति	- १६३
Ġ	संघकी कार्यपालिका शक्ति	368
5	मंत्रि-परिषद	944
3	सरकारी कार्य का संचालन	954
30	भारत का महान्यायवादी	' ६ ६
33	संसद की रचना	155
35	सदस्यों की अर्दता श्रादि	Mee
33	संसद श्रोर कार्यपालिका	193
38	संसद के पदाधिकारी	101
94	संसद में कार्यप्रणाली	३७२
3 £	धाय व्ययक	१७३

नुतीय अध्याय

राज्यों की शासन व्यवस्था	१७४ से १=३
-९ सम्मान्य	202
र राज्यों की श्रे यां	798
३ राज्यपाल या राजप्रमुख	908
४ राज्यपादा की विधायिनी शक्तियाँ	3 9 9
४ मंत्रि-परिषद	90=
६ महाधिवक्ता	३७८
अ. संरकारी कार्य का संचालन	3 0 =
८ विधान-मंडल की रचना	305
६ सदस्यों की श्रहेता	150
१० विधान-मंडल श्रीर कार्यपालिका	3=3
११ विधान-मंडल के पदाधिकारी	1 =2
१२ विधान-मंडल में कार्यप्रणाली	

विषय-सूची

१३ विधेयकों पर राज्यपाल या राजप्रमुख की अनुमा	ति १८२
१४ राज्यों का श्राय व्ययक	१८३
चतुर्थ श्रध्याय	
संघ और राज्यों के संबंध	१८४ से १८७
१ विषय-वितर्ग	3=8
२ प्रशासन-संबंध	3=4
२ आपात उपबन्ध	३⊏६
४ राज्यों में सांविधानिक विफलता	३ म् ६
पांचवां ऋध्याय	
न्यायपालिका	१८८ से १६३
३ सामान्य	3 ==
२ संघ की न्यायपालिका	3=8
३ राज्यों के उच्च न्यायालय	383
४ श्रधीन न्यायालय	282
छुठा ऋध्याय	* J (A
विशेष प्राधिकारी	१६४ से १६६
९ सामान्य	388
२ भारत का नियंत्रक महातेखा-परीचक	438
३ निर्वाचन श्रायोग	384
४ लोक-सेवा श्रायोग	988
सातवां श्रध्याय	
विशेष चेत्र तथा जातियां	१६७ से २००
९ चंदमान दीप समह	038

380

२ अनुसूचित तथा आदिम जातियां

३ श्रलपसंख्यको के लिये संरक्त्या	338
श्राठवां श्रध्याय	
राजमावा	२०१ से २०४
१ संघ की राजभाषा	40%
२ प्रादेशिक भाषाएँ	* Rox
३ हिन्दी भाषा का विकास	***
नौनां अध्याय	
संविधान का संशोधन	२०४
परिशिष्ट	२०६ से २१४
१ संव-सूची	२०६
२ राज्य-सूची ३ समधर्ती सची	530
३ समक्ती सूची मानचित्र	२१२
१ भारत का राजनैतिक मानचित्र	3 % &
३ भारत का भाषावर मानचित्र	202



प्राक्कथन

श्रव तक हिंदी मुज्यतः धर्म, दर्शन, श्रुद्ध साहित्य श्रादि विषयों का ही माध्यम रही है; विज्ञान, राजनीति, कान्न, संविधान श्रादि श्राधुनिक विषयों में उसका प्रयोग एक सहस्त वर्षों के परचात श्रव ही आरंम हुश्रा है। इसी कारण हिन्दी में इन श्राधुनिक कलाश्रों के साहित्य तथा पारिभाषिक शब्दाविल तक का सर्वथा श्रमाव है। श्रव हिंदी के राजभापा स्वीकृत होने के साथ साथ कई विश्वविद्यालयों ने उसे शिक्षा का माध्यम स्वीकार कर लिया है, पर इस कार्य में मुख्य कि नाई पाठ्यक्रम के योग्य हिंदी पुस्तकों का श्रमाव है। संविधान के विषय पर तो हिंदी में एक भी श्रव्छी पुस्तक है ही नहीं यद्यपि भारतीय संविधान तथा सांविधानिक इतिहास प्रायः राजनीतिशास्त्र श्रीर कान्तन के विद्यार्थियों के लिये पाठ्यक्रम का श्रावश्यक श्रंग होता है। इसके श्रितिरिक्त जन साधारण को भी इस विषय में रुचि बढ़ रही है। इन सब श्रावश्यकताश्रों का ध्यान रख कर ही हमने यह पुस्तक किस्सी है।

हमने इस पुस्तक में इस समय तक की सारी उपलब्ध सामग्री दे कर इसे लाभगद बनाने का पूरा प्रयस्न किया है । हाल ही के लोक प्रतिनिधित्व श्रधिनियम, १६४० (Peoples Representation Act, 1950) में से श्रावश्यक तालिकाएं तथा जनगणना श्रायुक्त (Census Commissioner) के नवीनतम जनसंख्या के श्रांकड़े भी इस पुस्तक में समाविष्ट कर दिये गये हैं। हाल ही में भारत सरकार के राज्य मंत्रालय द्वारा प्रकाशित देशी राज्यों संबंधी श्वेतपन्न (White Paper on Indian States) में से भी सुसंगत बातें ले ली गई हैं। भारत का नवीनतम मानचित्र भी दे दिया गया है जिसमें संविधान की प्रथम श्रनुसूची में उच्लिखित तीनों भागों के राज्यों को भिन्न भिन्न प्रकार से दिखाया गया है।

हमने इस पुस्तक के लिखने में श्रंग्रेजी की एतद्विषयक पुस्तकों से श्रवाधरूपेण सहायता ली है जिसके लिये हम उनके कृतज्ञ हैं। इसके श्रतिरिक्त भारत सरकार तथा संविधान सभा द्वारा प्रकाशित साहित्य का भी हमने स्वतंत्र प्रयोग किया है। प्रसिद्ध सांविधानिक महत्व के सरकारी लेख्यों का अत्तरशः अनुवाद दिया गया है जिससे अर्थभेद के कारण अस न हो सके।

इस पुस्तक में प्रयुक्त भाषा के विषय में स्पष्टीकरण के लिये कुछ शब्द कह देना अपेत्रित है। अब भारतीय संविधान के सरकारी अनुवाद के प्रकाशित हो जाने से भाषा में एक नई धारा श्रागई है। ११४६ तक प्रांतों में जो सभाएं थीं उन्हें धारा सभा या व्यवस्थापिका सभा ही कहते थे. किन्त १६५० से उन्हें विधान-सभा कहा जाने लगा है । इसी प्रकार पहले 'फेडरेशन' को संघ कहते थे श्रीर श्रव 'भारत संघ' का श्रर्थ 'इंडियन यूनियन' है। किन्तु नवीन संविधान की भाषा का पूर्ण प्रयोग पाठकों के लिये कठिनाई उत्पन्न करने वाला होगा, यह सोच कर इमने उस भाषा का कम प्रयोग करके, प्राय: पचिलत भाषा का ही प्रयोग किया है। किन्तु श्रंतिम भाग (नवीन संविधान) में नवीन भाषा का म्राधिकायिक प्रयोग किया गया है। भाषा के लिये यह संक्रमण काल है अतः ऐसी असंगतियां होंगी ही, पर हमने पाठकों की सुविधा का ध्यान रख कर ही ऐसा किया है। हमने सामान्यतः मध्य भारत, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश तथा बिहार श्रादि हिन्दी-भाषी प्रांतों में प्रयुक्त होने वाले शब्दों का ही प्रयोग किया है। श्री सुखसंपत राय भंडारी, महापंडित राहुल सांकृत्यायन तथा त्राचार्य रघुवीर त्रादि के सुविख्यात कोषों से भी अनुवाद में सहायता ली गई है जिसके लिये हम उनके श्राभारी हैं।

हमें श्राशा है कि यह पुस्तक राजनीतिशास्त्र के छात्रों तथा जन-साधारण के लिये समानरूपेण लाभप्रद सिद्ध होगी श्रीर हिन्दी जगत तथा शिचा संस्थाएं इसे श्रपना कर लेखक का साहस बढ़ायेंगी।

नई दिल्ली, कृष्ण जन्माष्टमी, २००७ वि०, तदनुसार ४ सितम्बर १६५०

मदन मोहन गुप्त

प्रथम ऋध्याय

निरंकुशता का राज्यकाल

१. अंग्रेजों से पहले

भारत के प्राचीन इतिहास पर दृष्टिपात करने से प्रतीत होता है कि
भारत में समय समय पर विविध प्रकार की शासन प्रणालियां थीं। अधिकतः
राजतंत्र का ही प्राधान्य था तथा यूरोप के समान भारत में छोटे छोटे
राज्य होते थे जिनमें वंशगत नरेश निरंकुश राज्य करते थे। किन्तु वे प्रजा
की इच्छा तथा हितों का ध्यान रखते थे, न्यायानुसार प्रशासन चलाते थे,
श्रीर यदि कोई नरेश अत्याचार करता था तो उसे सदा अपना राज्य खो
देने का भय बना रहता था, क्योंकि अन्य नरेश ऐसे राज्यों को हड़पने के
लिये सदा उद्यत रहते थे जहां असंतुष्ट प्रजा उनका स्वागत करने के लिये
तैयार रहे।

किन्तु राजतन्त्रों के श्रितिरिक्त प्राचीन भारत में गणराज्य भी थे जहाँ वंशगत राजा राज्य नहीं करते थे। किन्तु वे गणराज्य भी छोटे छोटे ही थे तथा कोई श्रिधिक शक्तिशाली नहीं बन सका। चाणक्य ने श्रपने 'कौटिल्य श्रर्थशास्त्र' में कुछ समकालीन गणराज्यों का वर्णन किया के जिनमें कठ, श्रिरिष्ट्र, सौभूति, श्रुद्रक, मालव श्रादि प्रमुख थे। शायद वे गणराज्य रोम के 'नगर राज्यों' के समान ही होंगे।

सुस्लिम राज्य की स्थापना से उत्तरी भारत की शासन-प्रणाली में कुछ परिवर्तन अवश्य हुए, किन्तु मूलतः वे नये शासक भी जनता के हितों के प्रति नितान्त उदासीन नहीं रहे। उन्होंने प्राचीन ग्राम्य-पंचायतों तथा

प्रादेशिक प्रशासन को अञ्चला ही छोड़ दिया और स्थानीय प्रजा का सहयोग प्राप्त करने का प्रयन्न किया।

मुस्लिम शक्ति के चीण होने के साथ साथ भारत के पृथक पृथक भाग हो गये थे। उत्तर में अफगानिस्तान, काश्मीर एवं पंजाब में सिखों का बोल-बाला था तथा महाराजा रणजीतसिंह जी की लोकप्रिय परन्तु निरंदुश सरकार अपना कार्य भारतीय शासन-प्रणाली के अनुसार चला रही थी, जिसमें जनता की आवाज को र्र्णतः कर्णगोचर किया जाता था। प्राणदंड की प्रथा उटा दी गई थी, जबकि उस समय इंगलिस्तान में छोटे छोटे अपराधों पर कृर दंड मिलते थे।

उधर मरहठा साम्राज्य में जनतन्त्र प्रणाली का सर्वोत्तम भारतीय नमूना दृष्टिगोचर होता था। शिवाजी ने मंत्रिमण्डल प्रथा स्रारम्भ की तथा राष्ट्रीय परिषद् के समान प्रायः एक सभा होती थी जो राज्य-शासन में भाग लेती थी।

उधर दिल्ला में मेसूर के हैदरश्रली का शासन भी लोकप्रिय था किन्तु शासन प्रणाली राजतन्त्र पर ही श्राधारित थी। उसके पुत्र टीपू सुल्तान ने सर्व प्रथम भारत में राष्ट्रीय भावना के श्राधार पर विदेशियों को निकालने के लिये एकता श्रान्दोलन चलाया था।

उधर अंग्रेजों व फ्रांसीसी लोगों का प्रमुख भारत में बढ़ रहा था श्रीर महान परिवर्तन हो रहे थे। फ्रांस तो जल्दी ही दौड़ में पिछड़ गया परन्तु श्रंग्रेज श्रपना प्रमुख जमाने में सफल हो गये। धीरे धीरे उन्होंने मरहठों, सिखों एवं मुसलमानों को भी हरा दिया तथा सारे भारत में उनका कोई प्रतिद्वंही नहीं रहा।

२. श्रंग्रेजी व्यापार संस्था का राज्य

भारत की शासन प्रणाली में श्रेंग्रेजों के श्राने से क्रांतिकारी परिवर्तन हुए श्रोर भारतीय शासन प्रणाली का सर्वथा नाश हो गया। नया युग श्रा गया तथा इंगलिस्तान के कूर कान्नों के श्रनुसार शासन होने लगा।

श्रंभेजी राज्य ज्यापार की भावना से स्थापित हुआ था श्रतः प्रारम्भ में एक श्रंभेजी कम्पनी जिसको ईस्ट इंडिया कम्पनी कहत थे, राज्य करती थी। कम्पनी के संचालकों (डाइरेक्टरों) का उद्देश्य श्राधिक होने के कारण

तथा भारत के शासकीय नियमों से अनभिज्ञता के कारण, वे यहां मनमानी करते थे। स्वयं अंग्रेजों पर तो कोई राजनियम लागू था नहीं, पर भारतीयों पर अंग्रेजों के क्र् नियम लगाये जाते थे। अंग्रेजी कान्न के अनुसार ही महाराजा नन्दकुमार को नकली पत्र-लेखन (forgery) पर प्राणदंड दिया गया था।

जैसा ऊपर वर्णन किया जा चुका है भारत में श्रंग्रेजी व्यापारिक संस्था ही पहले स्थापित हुई थी। वह सन् १६०० से श्रपना व्यापार श्रंग्रेजी वादशाह के श्राज्ञापत्र (Charter) के श्रनुसार करती रही। पर जब कम्पनी को वास्तव में प्रदेश मिल गया तब उसे ब्रिटिश बादशाह ने श्राज्ञापत्र द्वारा राज-सत्ता, न्याय-सत्ता तथा वैधानिक सत्ता प्रदान करदी श्रोर श्रपनी मुद्रा चलाने की श्रनुमित भी दे दी। बहुत समय तक तो वे केवल युद्ध में ही लगे रहे श्रोर कोई न्याय-व्यवस्था स्थापित न कर सके पर बाद में उन्होंने गगगाने नियम बना कर धन बटोरना श्रारम्भ कर दिया। बहुत समय तक कम्पनी का प्रवन्ध तीनों श्रधीनस्थ प्रांतों—बम्बई, बंगाल, एवं मद्रास में भिन्न भिन्न परिषदों द्वारा होता था जिनमें १२ से १६ तक श्रंग्रेज सदस्य होते थे। परिपदों के प्रधान लंदन स्थित कम्पनी के संचालक मंडल के प्रति संयुक्त रूप से उत्तरदायी थे।

३. संसद का अंकुश

ज्यों ज्यों कम्पनीकी शक्ति बढ़ती गई, त्यों त्यों इंगलिस्तान की सरकार का ध्यान कम्पनी की त्रोर श्रधिक श्राक्षित हुआ श्रोर वह श्रपना प्रभुत्व बढ़ाने की चेष्टा करने लगी जिससे कि भारत में अंग्रेजी संसद की सर्वोच्च सत्ता स्थापित हो सके। १७७३ ई० में एक महत्वपूर्ण नियमितकरण श्रधिनियम (Act)बनाया गया जिससे कम्पनी के श्राधीन सारे राज्य के लिये एक शासन-प्रणाली का श्रायोजन किया गया। इसके श्रनुसार बंगाल भारत के शासनसूत्र का केन्द्र बना दिया गया। वहां एक गवर्नर जनरल रहता था जो चार परामर्श-दाताओं की सहायता से बंगाल का सीधा शासन करता था और मद्रास तथा बम्बई के गवर्नरों (राज्यपालों) एवं परिषदों पर नियन्त्रण रखताथा। श्रधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल को नियम-उपनियम बनाने का एवं उन्हें लागू करने का श्रधिकार दिया गया। क्योंकि गवर्नर जनरल एवं प्रांतीय राज्यपालों की परिषदों में केवल श्रंग्रेज ही होते थे, श्रतः सारी राज्य-व्यवस्था विदेशियों के हाथ में ही थी और भारतीय न उनकी भाषा से भिज्ञ थे श्रीर न उन्हें राज्य काज में कोई रुचि ही थी।

सबसे महत्वपूर्ण कार्य इस नियमितकरण श्रिधिनियम द्वारा यह हुश्रा कि न्याय के लिए एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई, जिसकी शक्ति श्रंप्रेजी प्रणाली के श्रनुसार, शामन-सत्ता से परे थी श्रोर वह शक्ति ब्रिटिश बादशाह से प्राप्त हुई थी। यह सर्वोच्च न्यायालय, नियमितकरण श्रिधिनियम के श्रन्तर्गत बादशाह के एक श्राज्ञापत्र द्वारा १७७४ में कलकत्ते में स्थापित हुश्रा। इसमें एक मुख्य न्यायाधिपति तथा तीन श्रन्य न्यायाधिश थे जिन्हें बादशाह नियुक्त करता था। इनके निर्णय के विरुद्ध ब्रिटेन की संसद में श्रपील करने की भी व्यवस्था की गई थी।

यह बात समभने योग्य है कि विधि-राज्य (Rule of Law) के सिद्धान्त के अनुसार न्यायालय की शक्ति सर्वोच्च मानी जाती है श्रीर उसे शासन-सत्ता के अनियमित कार्य को रोकने का अधिकार होता है। सिद्धान्ततः यह नियम ग्रच्छा है क्योंकि शासन-सत्ता को ग्रत्याचार करने से रोकने का कोई मार्ग अवश्य चाहिए, परन्तु विदेशी राज्य, विशेषतः व्यापारिक राज्य, तो दमन पर ही निर्भर रह सकता है। सर्वोच्च न्यायालय सीधा बादशाह के श्राधीन था एवं वह कम्पनी की उपेचा कर ब्रिटिश प्रणाली से न्याय करता था। वह भारत के शासकीय नियमों से भी अनिभन्न था। कई बार इसने कम्पनी के स्थापित न्यायालयों की अवहेलना की एवं उनके न्यायाधीशों के विरुद्ध चलाए गये श्रभियोगों पर ध्यान दिया। इसी सर्वोच्च न्थायालय ने नन्दकुमार को छोटे से अपराध पर अंग्रेजी नियमानुसार मृत्यदण्ड दिया था जब कि भारत में केवल महान अपराधों के लिये ही ऐसा द्रा नियत था । इसके श्रतिरिक्त उसने राज्य-सत्ता में भी हस्तचे प करना श्रारम्भ किया जो कम्पनी को बहुत ग्रखरा। गवर्नर जनरल को यह ग्रसहा होगया क्योंकि वह एकाधिपति (तानाशाह) के समान राज्य करना चाहता था। यहां तक कि वह अपने मन्त्रियों के परामर्श के विरुद्ध भी चलना चाहता था। नियमित-करण श्रधिनियम द्वारा उसे ऐसा करने की अनुमति भी थी। उधर प्रादेशिक राज्यपालों श्रौर परिषदों से भी इसका भगड़ा रहने लगा।

इस प्रकार यह नियमितकरण श्रिधिनियम कुछ भी नियमित न कर सका। गवर्नर जनरल की एकतन्त्रीय मनोवृत्ति इसके मार्ग में बाधा थी। दूसरी बात इस श्रिधिनियम द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की तो स्थापना कर दी गई पर ठीक तरह से न्याय-प्रणाली की व्यवस्था नहीं की गई। श्रतः कहीं श्रंभे जी कानुनों का प्रयोग होता था, तो कहीं भारतीय कानुनों का।

४. सन् १७८१ का अधिनियम

परिणामतः १७८१ ई० में ही एक संशोधक अधिनियम बनाया गया। इससे निम्न परिवर्तन हुए:—

- (१) सर्वोच्च न्यायालय का श्रधिकार-चेत्र सीमित करके गवर्नर जनरल व उसकी परिषद को उससे मुक्त कर दिया गया। यह विधि-राज्य के सिद्धान्त के विरुद्ध था श्रीर वास्तव में इसके पश्चात भारत में कभी भी पूर्णतया विधि-राज्य स्थापित नहीं किया गया।
- (२) सर्वोच्च न्यायालय को अंग्रेजी कानून भारत में लागू न करने का आदेश दिया गया तथा घोषणा की गई कि भारत में हिन्दू व मुसलमानों को उनके धर्मशास्त्रों द्वारा ही उत्तराधिकार, विवाह आदि के विषय में शासित किया जाएगा। इसके अनुसार विवाह, दत्तक प्रथा तथा तलाक आदि के विषय में अब भी मिताचर, अथवा शरियत आदि का प्रयोग होता रहा है।
- (३) प्रान्तीय न्यायालयों के लिए कानृन बनाने का कार्य सपरिपद गवर्नर जनरल के नियन्त्रण में त्रागया जिससे वह न्याय के लिए भिन्न भिन्न कानृन बना सके।

उपर्युक्त अधिनियम से मानो भारत में पहला शासन-विधान (संविधान) स्थापित हुआ था। किन्तु इसमें सारी शक्ति एक विदेशी व्यक्ति में एकत्रित कर दी गई।

५. पिट का अधिनियम--अधिक नियन्त्रण

इस संशोधन के उपरान्त भी ब्रिटिश सरकार की दृष्टि से एक कमी ही रही कि भारत का वास्तिविक राज्य-शासन कम्पनी के संचालकगण के अधीन ही था और वे ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी न थे। ग्रतः १०६७ में प्रधान मन्त्री पिट ने एक महत्वपूर्ण भारतीय अधिनियम बनाया जिसके अनुसार संसद के क्षः कमिश्नरों का एक नियन्त्रक-मण्डल बना दिया गया जो भारत का शासन-प्रबन्ध करने का अधिकारी हो गया। परन्तु कम्पनी के संचालक मण्डल को गवर्नर आदि नियुक्त करने का अधिकार फिर भी रहा। इस प्रकार एक द्विमुखी नियन्त्रण (Dual Govt.) स्थापित हुआ जो दोपपूर्ण होता ही है। तत्पश्चात शनैःशनैः कम्पनी के राज्य का विस्तार होने के

साथ साथ बिटिश संसद ने अपना नियन्त्रण और भी कड़ा करना आरम्भ किया। १८१३ में संसद ने एक नया अधिनियम बना कर मद्रास, बम्बई और बंगाल की परिषदों की शक्ति को बढ़ा दिया तथा उनको कर लगाने एवं संसद के नियन्त्रण में युद्ध आदि करने की शक्ति दे दी। इस प्रकार संसद ने भारत में अपनी प्रभुशक्ति का परिचय दिया।

६. सन् १८३३ का संविधान व एकी करण की प्रवृत्ति

१८३३ में पुनः एक नया अधिनियम बनाया गया जिसमें

- (१) कम्पनी को अपनी अर्जित भूमि पर बादशाह की ओर से न्यासधारी (Trustee) घोषित कर दिया गया।
- (२) बंगाल के गवर्नर का नाम भारत का गवर्नर जनरल रख दिया गया तथ उसे सारे भारत के लिये कान्न बनाने का अधिकार दे दिया गया। उस समय तक पंजाब के अतिरिक्त सारे भारत पर या तो अंग्रे जों की प्रभुसत्ता स्थापित हो चुकी थी या राजा महाराजा उनसे मेंग्री संधि कर चुके थे। परन्तु वे मित्र राजा महाराजा अपने राज्य में अंग्रे जों को हस्तच प नहीं करने देते थे और न वहां गवर्नर जनरल के कान्न ही चलते थे। वे अंग्रेजी राज्य के अन्त तक आन्तरिक मामलों में स्वतन्त्र रहे और अपने कान्न भिन्न रखते थे। अतः इस पुस्तक में समस्त भारत का अर्थ केवल थोड़े से अंग्रेजी भारत से ही रहेगा। पर मदास व बम्बई के गवर्नरों की शक्ति कम होजाने से भारत का एक करण आरम्भ हो गया।
- (३) यह नियम बना दिया गया कि कम्पनी के आधीन किसी नौकरी पद या स्थान पर नियुक्ति के लिए कोई अपने धर्म, जन्मस्थान, वर्ण या वंश के कारण अयोग्य नहीं समक्ता जायगा।

यह नियम बड़ा सुन्दर होने पर भी इसका उद्देश्य भारतीयों को उच्च पद देने का नहीं था। २० वीं शताब्दी में तो इस नियम के विरुद्ध धर्मानुसार नियुक्तियां आरम्भ कर दी गई थीं। श्रव स्वतन्त्र भारत के संविधान में भी १८३३ के श्रिधिनियम के समान ही एक धारा रखी गई है जो निम्न लिखित हैं:—

"श्रनुच्छेद १६. (१) राज्याधीन नौकरियों या पदों पर नियुक्त के संबन्ध में सब नागरिकों के लिये श्रवसर की समता होगी ।"

(२) केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्मस्थान, निवास अथवा इनमें से किसी के आधार पर किसी नागरिक के लिये राज्याधीन किसी नौकरी या पद के विषय में न अपात्रता होगी और न विभेद किया जायेगा।

पंजाब में सिक्खों की पराजय के कारण सन् १८४० तक सारे भारत पर श्रंग्रेजों का प्रमुख हो गया। श्रतः १८४३ में ब्रिटिश संसद ने फिर एक नया श्रधिनियम बना कर भारत का सारा शासनाधिकार नियन्त्रक मण्डल को पूर्णतः सौंप दिया। ब्रिटिश भारत के एकीकरण के लिए १२ सदस्यों की भारतीय व्यवस्थापिका परिषद बनाई गई जिस में गवर्नर जनरल, उसके मन्त्री, परामर्शदाता तथा मुख्य सेनापित भी सम्मिलित थे। बंगाल के लिए एक पृथक गवर्नर नियुक्त किया गया। १८४४ ई० में एक श्रन्य श्रधिनियम बनाकर सपरिषद् गवर्नर जनरल का श्राधिपत्य सारे भारत में स्थापित कर दिया गया।

७. सन् १८५७ की क्रांति के कारण श्रीर परिणाम

जैसा ऊपर वर्णन किया जा चुका है कि भारत पर अंग्रेजों का श्राधि-पत्य जमने के उपरान्त भी वास्तव में श्राधे भारत पर राजाश्रों तथा नवाबों का ही राज्य रहा जो श्रंग्रेजों से मैत्रीपूर्ण संधियां कर चुके थे। वे युद्ध में श्रंग्रेजी सरकार की सहायता के लिए वाध्य थे, श्रपनी सेना बढ़ा नहीं सकते थे तथा किसी श्रन्य शिक्त से सम्बन्ध स्थापित नहीं कर सकते थे। संचेप में सेना तथा वैदेशिक सम्बन्धों के श्रतिरिक्त वे श्रान्तरिक मामलों में स्वतन्त्र थे तथा श्रपनी परम्परानुसार श्रपने राज्य का शासन करते थे। उनके पुत्र उनके उत्तराधिकारी होते थे। श्रंग्रेजों ने योजना बनाई कि शनैः शनैः इन देशी राज्यों का भी श्रन्त कर दिया जाए। इसी उद्देश्य से एक लुप्तकरण सिद्धान्त (Doctrine of Lapse) बनाया गया जिस के श्रनुसार उन राज्यों को ब्रिटिश भारत में लीन कर दिया जाता था जिनके राजा पुत्रहीन मर जाते थे। हिन्दु राजाश्रों में गोद लेने की प्रथा होने से कठिनाई होती देख इस प्रथा को श्रनियमित घोषित कर दिया गया। परिणामतः कुछ राज्य छीन लिये गये।

इस नीति से देशी नरेशों में श्रसंतोप पैदा हुश्रा, विशेषतः कांसी की रानी विद्रोही हो उठी। उधर विदेशियों के दमन से जनता भी विद्रोही हो गई। १८४७ में क्रांति का ज्वालामुखी फट गया। पर कुछ देशी राजाश्रों ने श्रंप्रेजों के साथ श्रपनी मैत्री निभाई, विशेषतः हैदरावाद ने, जिसके फलस्वरूप श्रंप्रेज क्रांति को दमन करने में सफल हुए।

८. व्यापारी राज्य का अंत

ब्रिटिश संसद ने भारत के "सुशासन के लिये" १८१८ में एक नया अधि-नियम निर्मित किया जिससे व्यापारिक कम्पनी का पूर्णान्त करके राज्य प्रणाली में निम्न परिवर्तन किये गये:

- (१) बिटिश भारत का राज्य सम्राज्ञो तथा उसके उत्तराधिकारियों को मिल गया।
- (२) देशी नरेशों (राजाओं तथा नवाबों) को सम्राज्ञी ने घोषणा द्वारा विश्वास दिलाया कि उनके साथ कम्पनी ने जो सिन्धयां की थीं वे श्रव सम्राज्ञी से की गई मानी जायेंगी तथा उनका पूर्णतः पालन किया जायेगा। उनके राज्य को किसी बहाने छीना न जायेगा तथा उनको गोद लेने का श्रिष्ठकार होगा। (बाद में इन संधियों का महत्व कम होता गया तथा देशी नरेश केवल नाम-मात्र के लिये ही रह गये। वे वास्तव में श्रंश्रेजों के हाथ की कठपुतली बन गये श्रीर उनके श्रान्तरिक मामलों में प्रभुसत्ता का हस्तच प बढ़ता गया।)
- (३) राज्य संभालने पर सम्राज्ञी नेयह भी घोषणा की कि भारतीयों के धर्म में कोई हस्तज्ञे प न किया जायेगा एवं किसी भी पद पर नियुक्ति के विषय में न्याय से काम लिया जायेगा। (वास्तव में उच्च पदों पर भारतीयों को स्थान न देने के विषय में इस घोषणा के परचात भी बहुत समय तक कोई परिवर्तन नहीं हुआ।)
- (४) सम्राज्ञी के श्राधीन होने पर भारत का शासन प्रबन्ध ब्रिटिश संसद के एक मंत्री (जिसे भारत मंत्री कहा जाता है) द्वारा किया जाने लगा जो संसद के प्रति उत्तरदायी था तथा ब्रिटिश मंत्रिमंडल का सदस्य था। नियन्त्रक मंडल एवं कम्पनी के संचालक मंडल की सारी शक्तियां उसे प्राप्त हो गर्थी। भारत मंत्री की सहायता के लिये एक परिषद् बना दी गई जो उसको लंदन में ही सम्मित देती थी। भारत मंत्री भारत की श्राय पर नियन्त्रण करता पर वह अपनी परिषद की सलाह से ही व्यय कर सकता था। सरकार की श्रोर से या सरकार के विरुद्ध दावे सपरिषद् भारत मंत्री के नाम से चलते थे।
- (१) गवर्नर जनरल, गवर्नर, परिषद् के सदस्यों की नियुक्ति का भी श्रिषकार सम्राज्ञी को ही मिल गया।

९ विकेन्द्रीकरण की श्रोर : १८६१ का संविधान

श्रव तक के संविधानों का उद्देश्य केन्द्रीयकरण ही था । परन्तु श्रनुभव से पता लगा कि सारे भारत के लिये एक ही स्थान में मर्याश में सुन्यवस्थित रूप से शासन होने में कठिनाइयां हैं, श्रतः विकेन्द्रीकरण की श्रोर लौटने के श्राशय से १८६१ में एक भारतीय परिषद् श्रिधनियम बनाया गया जिसके श्रनुसार बंगाल, मदास तथा बम्बई के लिये एथक एथक न्यवस्थापिका परिषद् (Legislative Councils) बना दी गई।

इस संविधान से गवर्नर जनरल की व्यवस्थापिका-परिषद में कार्य-कारिणी परिषद (Executive Council) के सदस्यों के श्रानिरिक्त ६ से १२ तक श्रन्य सदस्यों को रखा गया जिनमें से श्राधे सदस्य गैर सरकारी होने थे। यह पहला समय था कि शासकीय श्रिधकारियों के श्रातिरिक्त सम्मति देने के लिये गैर सरकारी लोगों को परिषद में रखा गया। वे सय सदस्य श्रंग्रेज ही होते थे तथा गवर्नर जनरल द्वारा नियुक्त होते थे श्रीर दो वर्ष तक रहने थे। पर भारतीय जनता का शासन से किसी प्रकार का सम्बन्ध स्थापित करने का प्रयत्न नहीं किया गया।

गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में ६ सद्स्य होते थे जिनमें कान्नों पर सम्मित देने के लिए एक वकील भी होता था । सपिरपद गवर्नर जनरल की व्यवस्थापिका शक्ति को भी बढ़ा दिया गया श्रोर उसे ६ मास के लिये श्रिधिनियमों के समान प्रभाव वाले श्रध्यादेश (Ordinance) भी बनाने की चमता दी गई। स्थानीय या प्रादेशिक व्यवस्थापिका परिपदों की शक्ति सीमित थी तथा वे श्रपने प्रदेश के लिए गवर्नर जनरल की श्रमुमित से ही कान्न बना सकती थीं। केन्द्रीय शासन से सम्बद्ध विषयों पर कान्न बनाने का उन्हें श्रिधिकार नहीं था। वास्तव में श्रभी तक केन्द्र की ही सर्वोच्य सत्ता थी श्रीर प्रांत श्रपनी शक्ति केन्द्र से ही लेते थे।

इसी वर्ष न्याय के विषय में भी विकेन्द्रीयकरण की श्रोर एक पग उठाया गया तथा एक ही सर्वोच्च न्यायालय के स्थान पर तीनों प्रदेशों—यम्बई कलकत्ते एवं मदास में तीन उच्च न्यायालय बनाने के लिये भारतीय उच्च न्यायालय श्राधिनियम निर्मित हुश्रा। ब्रिटिश सरकार के श्राज्ञापत्रों द्वारा इन न्यायालयों की स्थापना हुई तथा उनमें प्रत्येक में बादशाह हारा एक मुख्य न्यायाखिपति तथा श्रम्य न्यायाधीश नियुक्त किये गये। पुरानी सदर-दिवानी.

फौजी श्रदालतें एवं सर्वोच्च न्यायालय बंद कर दिये गये तथा उन सबके श्रधि-कार उच्च न्यायालयों को प्राप्त हो गये।

१०. भारत में जागृति तथा उसका प्रभाव

१८४७ की क्रान्ति के दमन के पश्चात् भारतीयों में देशप्रेम की भावना शनेः शनेः पुनः उभरने लगी। खंग्रेजी शिचा प्राप्त युवक उच्च पदों के लिये तथा निर्धन जनता विदेशी व्यापार नीति के विरुद्ध आवाज़ उठाना चाहती थी। स्रतः १८८४ में भारतीय राष्ट्रसभा (कांग्रेस) की स्थापना हुई। इसका प्रभाव दिन प्रतिदिन बढ़ता देख ब्रिटिश सरकार ने शासन-प्रगाली में शनैः शनैः सुधार करने की नीति अपनाई।

प्रथम सुधार: १८६२ का संविधान: पहला सुधार १८६२ में नये भारतीय परिषद् अधिनियम द्वारा किया गया। गवर्नर जनरल की परिषद् के सदस्यों में चार और सदस्य जोड़ दिये गये। वे सदस्य चारों प्रान्तों की परिषदों के अशासकीय सदस्यों के द्वारा निर्वाचित होते थे। परिषदों के सदस्यों को प्रश्न पृष्ठने के अधिकार दिये गये तथा सरकार की आर्थिक नीति पर भी आलोचना करने की छूट दी गई। प्रान्तीय परिषदों वो बढ़ा कर उनमें विशेष हितों के प्रतिनिधि भी ले लिये गये। इनमें जमींदारों, स्थानीय समितियों, विश्वविद्यालयों एवं व्यापार समितियों के नाम उल्लेखनीय हैं। इन सब सुधारों के उपरान्त भी परिषदों में शासकीय सदस्यों का ही बहुमत रहा तथा जनता को कोई सीधा प्रतिनिधित्व नहीं मिला।

११. साम्प्रदायिकता का समावेश: मिन्टो-मोरले सुधार

भारत में राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रभुत्व को बढ़ता देख कर चतुर श्रंग्रेज शासकों ने भारत में कुछ राजभक्त मुसलमानों को प्रोत्साहन देना श्रारम्भ कर दिया जिस से कि यहां एक धार्मिक समस्या उठ खड़ी हो। सर्वेप्रथम १६०६ में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई जिसने मुसलमानों की श्रोर से पृथक प्रति-निधित्व की मांग की श्रोर श्रंग्रेजों ने उसे सहर्ष स्वीकार करके पृथक साम्प्र-दायिक निर्वाचक मंडलों द्वारा मुस्लिम प्रतिनिधियों के निर्वाचन के सिद्धान्त को मान्यता देवी।

उधर कांग्रेस की ओर से १८१२ के ऋधिनियम के विरुद्ध प्रचार बढ़ता ही जा रहा था । बंगुभंग की योजना से ऋग्नि श्रौर भी भड़क उठी । ब्रिटेन

ने भारतीयों को संतुष्ट करने के लिये १६०६ में भारतीय परिषदों का नया अधिनियम बनाया जो मिन्टो-मोरले सुधारों (Reforms) के नाम से प्रसिद्ध है। इसमें जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों को परिषदों में स्थान देने का सिद्धान्त लागू कर जनतन्त्रवाद का ढिंडोरा पीटने का यत्न किया गया परन्तु भारतीय राजनीति में एक महान विष वृच्च का बीज भी बो दिया गया। वह बीज था साम्प्रदायिकता का; अर्थात् निर्वाचन में हिन्दु, मुसलमान आदि के लिये अपने अपने सम्प्रदायों के आधार पर पृथक पृथक चुनाव की व्यवस्था की गई। शनैः शनैः आगामी संविधानों में इस साम्प्रदायिक अन्तर को बढ़ाया गया; जिससे जनतन्त्र की और प्रगति के साथ साथ हम नाश की ओर भी बढ़ते गये। मिन्टो-मोरले सुधार के विशेष अंगों का दिग्दर्शन नीचे किया जायेगा:

- १. गवर्नर जनरल की व्यवस्थापिका परिषद् में कार्यकारिणी के स्रतिरिक्त स्त्रन्य सदस्यों की संख्या १६ से बढ़ा कर साठ कर दी गई। केवल २८ सदस्य शासकीय थे, १ सदस्य विशिष्ठ जातियों के प्रतिनिधि थे एवं २७ सदस्य चुने हुए थे जो मुसलमानों, जर्मीदारों, व्यापार मण्डलों, एवं प्रान्तीय परिषदों के प्रतिनिधि थे।
- २. प्रान्तीय एवं केन्द्रीय व्यवस्थापिका परिषदों की कार्यशक्ति सीमित थी। यद्यपि सदस्यों को प्रस्ताव रखने, वाद्विवाद करने तथा मत देने का अधिकार था किन्तु सदा सरकार का बहुमत रहने से भारतीयों की चलती नहीं थी। श्रतः जनता श्रसंतुष्ट रही।
- परिषदों के निर्णयों से किसी प्रकार गवर्नर या नवर्नर जनरल वाध्य नहीं थे, श्रतः परिषदें केवल वादिववाद के श्रितिरिक्त कुछ नहीं कर सकती थीं।
- ४. निर्वाचन सीधे जनता के द्वारा न होने के कारण सदस्य गण किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं थे।

फिर शीघ्र ही १६११ में उच्च न्यायालयों की संख्या बढ़ाने का, अधिनियम बना श्रीर कार्यशक्ति सम्राट को दी गई। प्रत्येक उच्च न्यायालय के न्यायाधिंशों की श्रिधिकतम संख्या २० रखी गई।

श्रव तक कई शासन सम्बन्धी नियम एवं श्रधिनियम बन चुके थे। श्रतः १६१५ में एक ही पूर्ण भारतीय संविधान निर्मित किया गया जिसमें

पहले के सारे संविधानों का संग्रह कर दिया गया था। इससे भारतीय तिनक भी संतुष्ट नहीं हुए, श्रिपतु कांग्रेस की लोकप्रियता बढ़ती गई।

१२. प्रथम विश्व युद्ध तथा स्वराज्य की मांग

१६१४ से प्रथम महायुद्ध श्रारम्भ होने पर भारत ने सर्व प्रकार जनधन से साम्राज्य की सहायता की श्रीर भारतीयों ने इस के पुरस्कार रूप में स्वराज्य की मांग की। १६१६ के लखनऊ श्रधिवेशन में राष्ट्रसभा कांग्रेस ने एक स्वराज्य सम्बन्धी प्रस्ताव पास किया जिस में निम्न लिखित मांगें कीं गई:

- सम्राट को चाहिये कि यह घोषणा कर दे कि ब्रिटिश नोति का लच्च भारत को जल्द स्वराज्य देने का है।
- २. कांग्रेस ग्रोर मुस्लिम लीग की कमेटियों द्वारा बनाई हुई सुधार योजना के श्रनुसार ब्रिटिश सरकार भारत को स्वराज्य की पहली मात्रा देवे।
- भारत को अधीनस्थ देश की श्रेणी से उठाकर साम्राज्य के अन्य स्वशासित भागों के समान बना दिया जावे।

ब्रिटिश सरकार ने यह देख कर कि भारतीयों की स्वतंत्रता की भावना को दबाया नहीं जा सकता, निम्न नीति अपनाई:

- भारत को नाम मात्र की सत्ता धीरे धीरे देते जाना त्र्रोर भविष्य के लिये उदारता से त्राश्वासन देना।
- हिन्दू मुस्लिम मतभेदों को बढ़ाना तथा इसके लिये राजभक्त मुसलमानों को प्रत्येक प्रोत्साहन देना।

१३. मौंटफोर्ड की सुधार योजना

बिटिश सरकार की इसी मुस्लिमपत्ती साम्प्रदायिक नीति से प्रोत्सा-हित हो मुस्लिम लीग ने भी अपने सम्प्रदाय के लिये विशेषाधिकारों की मांग करनी आरम्भ कर दी, तथा इसके प्रतिक्रियास्वरूप हिन्दू महासभा की स्थापना हुई। कांग्रेस के आन्दोलन के फलस्वरूप २० अगस्त १६१७ को भारत मंत्री श्री मौनटेग ने बिटेन की लोकसभा में निम्नलिखित प्रसिद्ध घोषणा की।

"ब्रिटिश सरकार की नीति, जिससे भारत सरकार पूर्णतः सहमत है, भारत में, ब्रिटिश साम्राज्य का ग्रिभिन्न भाग रहते हुये ही, प्रगति से

उत्तरदायी शसन स्थापित करने के उद्देश्य से, स्वशासित संस्थाओं के शनेः शनैः विकास करने की एवं भारतीयों का राज्य-प्रवन्ध की प्रत्येक शाखा में सम्बन्ध बढ़ाने की है। उन्होंने निश्चय किया है कि इस दिशा में यथासम्भव वास्तविक कार्यवाही करनी चाहिये और कि यह अत्यन्त आवश्यक है कि यह कार्यवाही निश्चित करने के एवं भारत तथा ब्रिटेन में जो अधिकारी हैं उनके बीच स्वतन्त्र तथा निजी रूप से विचारों का आदान प्रदान हो। ब्रिटिश सरकार ने तद्नुसार यह निर्णय किया है कि मैं (भारत मन्त्री) वाइसराय के निमन्त्रण को स्वीकार कर के भारत जाऊ तथा इन बातों पर वायसराय तथा भारतीय सरकार से विचारविमर्श करूं, स्थानीय सरकारों के दृष्टिकोणों पर वाइसराय से मिलकर विचार करूं और उस के साथ मिलकर प्रतिनिधि संस्थाओं एवं दूसरों के प्रस्तावों को प्राप्त करूं।

'मैं यह बात भी कह दूं कि इस नीति में प्रगति क्रमानुसारही हो सकती है। ब्रिटिश तथा भारत सरकार ही, जिन पर भारत के लोगों की भलाई तथा उन्नति का उत्तरदायित्व है, प्रत्येक प्रगतिशील कदम के लिये उपयुक्त समय तथा माप का निर्णय करेंगी, श्रीर वे इस कार्य में इस बात से प्रभावित होंगी कि जिन को सेवा (नौकरियों) के नये श्रवसर मिलेंगे उनके सहयोग तथा उत्तरदायित्व की भावना में कितना विश्वास किया जा सकता है।

"संसद में उचित समय पर जो प्रस्ताव रखे जायेंगे उन पर सार्वजनिक वाद विवाद के लिये पर्याप्त ख्रवसर दिया जायेगा।"

इस घोषणा की शक्ति तथा मृत्य बड़ाने के लिये प्रत्येक परिस्थिति प्रस्तुत थी इसको भाषा मिश्रित मंत्रिमंडल ने निश्चित की थी श्रतः यह किसी दल विशेष की नहीं, सारे ब्रिटन की श्रोर से घोषणा थी। राज्य के किसी दल ने इसको चुनौती नहीं दी थी।

उपर्युक्त घोषणा से निम्न महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकलते हैं :

- भारत को ब्रिटिश साम्राज्य का ही भाग रहना होगा।
- २. उत्तरदायी शासन भारत में स्थापित होगा परन्तु शनैः शनैः प्रगति द्वारा ही यह हो सकेगा । इसका अर्थ है कि पहले स्थानीय समितियां, फिर प्रान्तीय शासन एवं अन्त में ही केन्द्रीय सत्ता भारतीयों को मिलेगी ।
- कितनी उन्नति कब होगी यह अंग्रेज ही निश्चित करेंगे।

श्वीक रियों में भारतीयों को बड़े बड़े पद शनैः शनैः मिलेंगे
 श्रीर वे उस में जितनी योग्यता से कार्य करेंगे उस पर भावी उन्नित निर्भर होगी।

राष्ट्रसभा कांग्रेस ने इस घोषणा का स्वागत करते हुये यह मांग की कि स्वशासन स्थापित करने के किये श्रविध निश्चित हो।

इसके परचात् भारत मंत्री श्री मौनटेग भारत श्राये तथा उन्होंने यहां के वायसराय चैम्सफोर्ड के सहयोग से जुलाई १६१८ में श्रपनी रिपोर्ट प्रकाशित की। इस में चार बातें थीं:

- स्थानीय (नगर या जिला त्रादि) समितियों में जनता का पूर्ण नियन्त्रण हो।
- २. प्रान्तीय शासन में कुछ जनता का नियन्त्रण एवं कुछ उत्तर-दायित्व हो।
- ३ केन्द्रीय सरकार ब्रिटिश संसद के नियन्त्रण में ही रहेगी पर जनता का परिषदों में अधिक हाथ होगा जिससे कि वह सरकार की नीति पर प्रभाव डाल सके।
- ४. उपर्युक्त तीनों बातों को कार्यान्वित करने के लिए भारत मन्त्री तथा ब्रिटिश संसद का भारत के राज्य शासन पर नियन्त्रण ढीला कर दिया जायेगा।

मीन्टेग-चैम्सफोर्ड की पूर्ण रिपोर्ट के कुछ अंश नीचे दिये जाते हैं:

१, हमारी २० अगस्त १६१७ की घोषणा से प्रगट है कि कदम धीरे धीरे बढ़ाये जायेंगे तथा प्रत्येक पग पर प्रगति को आंका जायेगा। इन आवश्यकताओं के अनुसार एक वास्तिविक कदम एक दम उठाना है। यिद्र यह तर्क ठीक है तो जनता के जुने तिनिधियों को कुछ उत्तरदायित्व प्रारम्भ से ही देना चाहिये। स्पष्ट है कि तीन ही स्तर है जिन के अनुसार सत्ता सौंपी जा सकती है, स्थानीय समितियों में, प्रान्तों में और भारतीय शासन में। क्योंकि एक ही ब्यक्ति दो की आज्ञा पर नहीं चल सकता, अतः प्रतिनिधियों पर जितना जनता का नियन्त्रण होगा उतना ही उच्च अधिकारियों का नियंत्रण कम करना होगा। परिस्थितियां ऐसी हैं कि एक ही समय में तीनों स्तरों पर एक ही गति से परिवर्तन नहीं हो सकता। भारत सरकार का मुख्य कार्य भारत की रक्षा होगा, प्रान्तों का आधारभूत कर्त्तब्य शान्ति रखना होगा। जनता का

नियन्त्रण नीचे स्तरों पर अधिक होगा और उपर जाते जाते कम होता जायेगा। दूसरी तरह बात यूं कही जा सकती है, शासन के कर्तव्य आवश्य-कतानुसार इस प्रकार बांटे जा सकते हैं कि एक तो राज्य के अस्तिन्व की रच्चा का प्रधान कार्य है और दूसरे कार्य प्रजा के सुख तथा भलाई के लिये हैं। अपनी भलाई के कामों का जनता को अनुभव है और वह उसे समभती है, इस कारण इस कार्य को वह भली भांति सम्हाल सकती है। यह काम जनता के पूर्ण नियन्त्रण में दे देना हमारा उद्देश्य होना चाहिए। अतः हमारा पहला सिद्धांत यह बनता है कि:—

"यथासम्भव स्थानीय समितियों में पूर्णतः लोक नियन्त्रण होना चाहिए श्रौर उन्हें वाह्य नियन्त्रण से श्रधिकतम स्वतन्त्रता होनी चाहिए।"

(पाठकों को यह ध्यान देना चाहिये कि उपर्युक्त सुधार वास्तव में संविधान से सम्बन्धित नहीं है श्रौर देश के सामान्य कान्न से ही लागू किया जा सकता है।)

२. जब हम प्रांतीय शासन पर आते हैं तो प्रश्न दृसरा है। हमारा उद्देश उत्तरदायी सरकार है। पर अभी जनता को चुनाव के विषय में शिचा है ही नहीं और राज्य सम्बन्धी अनुभव भी इतना नहीं है कि शासन को व्यवस्थापिका सभा के प्रति उत्तरदायी बनाया जा सके। उत्तरदायित्व को शनैः शनैः बढ़ा कर ही राजनैतिक शिचा दी जा सकती है। हम इस कारण कुछ कार्यों के लिये उत्तरदायित्व देकर अन्य चेत्रों में पूर्ववत नियन्त्रण रखने की सिपारिश करते हैं और हमारा दृसरा सिद्धान्त यह बनता है:

"प्रान्त ऐसे चेत्र हैं जिन में प्रगित से उत्तरदायी सरकार के स्थापित करने के लिये शीघ्र कदम उठाने चाहियें। कुछ उत्तरदायित्व तो तत्काल ही दे देना चाहिये, और पिरिस्थितियों के अनुसार शीघ्रातिशीघ्र पूर्ण स्वराज्य देना हमारा उद्देश्य है। इसका अर्थ है कि प्रान्तों को भारत सरकार से कानून-निर्माण, प्रशासन तथा आर्थिक विषयों में इतना स्वतन्त्र कर दिया जाये कि भारत सरकार को स्वयं अपने उत्तरदायित्व को पूरा करने में कोई कठिनाई न हो।"

(इसका परिणाम यह हुआ था कि प्रान्तों में कुछ सरकारी विभागों पर भारतीय मंत्रियों को नियुक्त कर दिया गया और वे व्यवस्थापिका सभा के प्रति उत्तरदायी माने जाते थे। बाकी विभाग गवर्नर के श्रधीन थे, श्रर्थात् द्वैध शासन पद्धति थी।)

३. हम श्रमी लोकतन्त्र के श्रनुभवों के परिणामों को देखने से पहले भारत सरकार में कोई परिवर्तन करना उचित नहीं सममते । किन्तु फिर भी यह वांद्रनीय है कि भारतीय व्यवस्थापिका परिषद् को भारतीय विचारधारा की सच्ची प्रतिनिधि बनाया जाये तथा उस विचारधारा को सरकार पर प्रभाव डालने का श्रिधक श्रवसर दिया जाये । श्रतः हम संसद को यह सम्मति नहीं दे सकते कि प्रान्तों एवं भारत सरकार में एक सी श्रीर साथ साथ उन्नति की जाये, श्रतः हम निम्न सिद्धान्त पर पहुंचते हैं:

"प्रान्तों में परिवर्तन के अनुभवों को देखने से पहले भारत सरकार ब्रिटिश संसद के प्रति ही उत्तरदायी रहे और इस उत्तरदायित्व के अतिरिक्त महत्वपूर्ण मामलों में इसकी सत्ता निर्विवाद रहे। पर इसी काल में भारतीय व्यवस्थापिका सभा को बढ़ा कर अधिक प्रतिनिधित्वपूर्ण बनाया जाये तथा इसे सरकार को प्रभावित करने के अधिक अवसर दिये जायें।"

(इन सब का अर्थ यह हुआ कि प्रान्तों में द्वैध शासन तथा केन्द्र में पूर्णतः अंग्रेजी राज्य हो। एक विशेष बात यह है कि विकेन्द्रीयकरण के सिक्षान्त को श्रव पूर्णतः मान लिया गया। कार्य रूप में इन प्रस्तावों के फल-स्वरूप भी भारत की जनता को शासम-सत्ता नहीं मिली क्योंकि निर्वाचन संकुचित मताधिकार पर श्राधारित होने के कारण प्रान्तीय सभाश्रों में जनता के प्रतिनिधि नहीं गये। यदि गये, तो भी सरकार का ही बहुमत रहा क्योंकि विशेष प्रतिनिधियों को गवर्नर नियुक्त करता था। केवल शाब्दिक श्रालोचना-मात्र का श्रधिकार जनता को मिला)।

४. भारत मन्त्री तथा संसद्का नियन्त्रण ढीला करने का सुमाव : क्योंकि लोक नियन्त्रण के साथ साथ भारत मंत्री का नियन्त्रण नहीं चल सकता और कार्यकारिणी पर दोनों विरोधी वृत्तियों की श्रोर से परस्पर विपरीत दबाव पड़ने की सम्भावना थी, श्रतः चौथा सिद्धान्त यह बनाया गया कि:—

"जैसे उपर्युक्त परिवर्तन कार्यान्वित हों उसी अनुपात में भारत मंत्री तथा संसद का भारत सरकार तथा प्रान्तीय सरकारों पर से नियन्त्रण ढीला किया जाना चाहिये।"

तीन समितियां : इसके उपरान्त तीन समितियां नियुक्त हुईं :

- १. एक सिमिति का यह कार्यथा कि वह केन्द्र तथा प्रान्तों में राजकीय विषयों का बंटवारा करे तथा यह बताये कि प्रान्तों को क्या क्या विषय हस्तान्तरित किये जाने चाहिये और उन पर मंत्रियों के नियन्त्रण के विषय में क्या क्या सीमा होनी चाहिये।
- २. दूसरी समिति को मताधिकारों के विषय में निर्णय करने को कहा गया, विशेषतः उन जातियों ग्रादि के लिये जो ग्रहपसंख्या में थीं।
- ३. तीसरी समिति लगडन में श्वित भारत कार्यालय श्रर्थात् भारत मंत्री के कार्यालय के विषय में थी।

१४. स्वराज्य आन्दोलन तथा नया संविधान

उपर्यु क्त रिपोर्ट से भारतीय संतुष्ट नहीं हुए श्रिपतु वे समम्भने लगे कि युद्ध समाप्त होने पर श्रव ब्रिटेन श्रपने संकल्प को पूरा नहीं करना चाहता श्रीर मान्टेग-चैम्सफोर्ड की रिपोर्ट केवल मुलावा ही है। उधर रोलेट श्रिधिनयम तथा उस के श्रन्तर्गत किये गये श्रत्याचारों से ऊब कर महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारत ने सरकार से श्रिहिंसात्मक श्रसहयोग श्रारंभ कर दिया जिसे दमन करनेके लिये सेना-राज्य की घोषणा कर दी गई। श्रमृतसर के जलियान वाले बाग के हत्याकांड ने मानों भारत की श्रात्मा को ही उथल पुथल कर दिया। श्रव भारत श्रधिराज्य (Dominion) की श्रेणी से कम में नहीं रहना चाहता था।

भारत के विरोध करने पर भी मौनटेग-चैम्सफोर्ड योजना को प्रस्ताव रूप देकर अन्त में १६१६ का भारतीय संविधान बना दिया गया । इन सुधारों को राष्ट्र सभा कांग्रेस ने "अपर्याप्त, असंतोषजनक, निराशापूर्ण तथा अस्वीकार्य" कह कर दुकरा दिया और निर्वाचन लड़ने की बजाय असहयोग सत्याग्रह आरम्भ कर दिया।

नये संविधान की विशेष बातें निम्न लिखित थीं :-

- भूमिका में २० त्रगस्त १६१७ की घोषणा की पुनरावृत्ति की गई।
- २. नए प्रान्त—कुछ नये प्रान्त बनाये गये। पहले तो मदास, बंगाल तथा बम्बई प्रांत ही थे, श्रब युक्त प्रांत, पंजाब, बिहार तथा उड़ीसा,

मध्य प्रांत और श्रासाम भी जोड़ कर म गवर्नरी प्रांत बन गये। पर इन को पहले के तीन प्रांतों से कुछ नीचा स्थान मिला। उधर दिल्ली, कुर्ग, श्रंडेमान, श्रजमेर श्रादि ६ चीफ कमिश्नर के प्रांत भी बन गये। कुछ समय बाद सीमा- प्रांत तथा बर्मा भी गवर्नरी प्रांत बन गये।

३. प्रांतीय शासन—प्रांतों तथा केन्द्र के तेत्रों को पृथक पृथक कर दिया गया अर्थात विकेन्द्रीयकरण आरम्भ हो गया। प्रान्तीय शासन में द्वैध शासन पद्धति का समावेश हुआ जिस के अनुसार कुछ विभाग भारतीय उत्तरदायी मंत्रियों को 'हस्तान्तिरत' कर दिये गये तथा अन्य विभाग 'रिचत' रहे।

निम्न सूची से यह विषय-विभाजन स्पष्ट होगा :---

केन्द्रीय विषय

श्रांतीय विषय

	हस्तान्तरित	रचित
सेना सम्बन्धी विषय	स्थानीय स्वराज्य	पुलिस तथा जेल
विदेशी नीति	शिचा	दुभिंच
श्रायात निर्यात	स्वास्थ्य तथा सफाई	कृषि कर
रेलवे	मकान निर्माण	पैन्शन
डाक तार	कृषि	पत्रों पर नियंत्रण
ग्राय-कर	उद्योगों का विकास	कलों का निरीच्रण
मुद्रा	मद्य कर	
ब्यापार	सहकारी संस्थायें	
दंड संहिता	मीन व्यवसाय	
व्यवहार संहिता		

उपयुंक्त प्रांतीय मंत्री वास्तव में शक्तिहीन थे श्रीर हस्तांतरित विषयों में भी गवर्नर को पूर्ण सत्ता प्राप्त थी । वह लोकप्रिय मिन्त्रियों को हटा सकता था या उनकी सम्मिति के विरुद्ध काम कर सकता था। वे मंत्री व्यवस्थापिका सभा द्वारा निर्वाचित न हो कर गवर्नर द्वारा नियुक्त होते थे श्रतः उत्तरदायित्व वास्तव में था ही नहीं।

इसके त्रितिरक्त गवर्नर किसी प्रस्तावित विधान (Legislation) को त्रावश्यक प्रमाणित कर के सभा से मनवा सकता था तथा कई प्रस्तावों को रोक सकता था। रचित विषयों पर तो गवर्नर का ऋधिकार था ही, उसे कुछ ग्रंश तक हरतान्तरित विषयों पर भी नियन्त्रण करने का ऋधिकार था। प्रान्तीय ज्यवस्थापिका सभा का कोई प्रस्ताव गनर्वर उत्तरल द्वारा भी रोका जा सकता था।

उधर मिन्त्रयों को उन राज्य कर्मचारियों के द्वारा कार्य चलाना पड़ता था जो सीधे भारत मंत्री के नियन्त्रण में थे, त्रातः मंत्रियों की गवर्नर भी चिन्ता नहीं करता था श्रीर नीचे के कर्मचारी भी उन की इच्छानुसार नहीं चलते थे। मंत्रिमंडल के लिये संयुक्त विचारविमर्श या उत्तरदायित्य का सिद्धान्त न मानने से भी कठिनाई हुई। मंत्रियों को धन पर श्रिधिकार नहीं था, वे अपने विभागों के व्यय के लिये गवर्नर पर श्राश्रित थे। उधर प्रान्तों को श्राय के साधन कम मिले थे तथा केन्द्र को ही श्रिधक श्राय मिलती थी।

उपर्युक्त कारणों से प्रान्तों का श्रांशिक स्वराज्य भी केवल नाममात्र का ही था वास्तविक नहीं।

४, प्रान्तीय व्यवस्थापिका परिषदें:—प्रान्तों की व्यवस्थापिका परिषदों के सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई। किसी परिषद में २० से अधिक शासकीय सदस्य नहीं हो सकते थे श्रीर निर्वाचित सदस्य ७० प्रतिशत से कम नहीं हो सकते थे।

हन परिषदों का जीवन तीन वर्ष का थापर गवर्नर परिषद् को बीच में भंग भी कर सकता था तथा एक वर्ष श्रिधिक भी जीवित रख सकता था।

चुनाव सीधी जनता करती थी पर चुनाव पृथक सांप्रदायिक निर्वाचक-गर्गों द्वारा होता था श्रोर श्रल्पसंख्यकों को उनकी जनसंख्या के श्रनुपात से बहुत श्रधिक स्थान दिये गये थे जो कि निम्नांकित सूची से प्रगट होगाः

भारत-नये संविधान तक

	मद्रात	व + व है व + व है	बंगाल	युक्त प्रान्त	पंजाब	बिहार व उड़ीसा	मध्य प्रांत	श्रासाम	बर्मा
श्रमुस्लिम	६४	8६	४६	ξ ο	२०	४८	४०	२०	0
मुस्लिम	33	२७	३६	35	३२	3=	Ø	97	0
भारतीय ईसाई	¥	٥	0	0	0	0	0	0	0
यूरोपियन	3	. २	¥	3	o	3	0	0	3
श्रांग्ल भारतीय	3	. 0	Ŗ	0	0	۰.	٥	o	3
जमींदार	६	રૂ ં	¥	६	8	¥	इ	0	0
विश्व विद्यालय	9	3	२	3	9	3	3	0	3
चाय ग्रादि के) बगान के }- श्रधिकारी	3	•	o	0	0	ð	0	¥	٥
व्यापार उद्योग	¥	৩	१४	३	₹	٥	२	3	ş
सिक्ख	0	0	0	0	98	0	, 0	0	٥
खनिज ग्रधिकारी	0	0	0	. 0	0	२	3	0	٥
ब्यापक नगरवासी	0	0	0	o ·	0	•	0	3	3.8
भारतीय नगरवासी	0	•	•	•	0	٥	ō		2
करेन प्राम्य	0	0	•	. 0	•	•	. 0	•	¥
व्यापक ग्राम्य	0	•	•	0	0	. 0	0		88
योग (निर्वाचित का मनोनोत सदस्य (कार्यकारिणी परि-) 85	ΕĘ	ร์ร	४ १०	0 9	৭ ৩६	২৪	3.8	৩ ৪
षद् सहित)	२६	२१	२६	. २३	₹:	२ २७	98	38	२४
महायोग	320	333	380	१२३	83	१०३	७०	१ ३	g o B

⁽४) केन्द्रीय सरकार:—केन्द्रीय सरकार श्रनुत्तरदायी ही रही तथा उसका प्रान्तों पर नियंत्रण एवं देख रेख का श्रद्धिकार बना रहा। केन्द्रीय व्यवस्थापक मंडल के दो भाग कर दिये गये, एक राज्यपरिषद् जो धनिकों की प्रतिनिधि थी और दूसरी व्यवस्थापिका सभा जो सीमित रूप से जनता की

प्रतिनिधि थी। यह मंडल केवल प्रालोचना कर सकता था। वायसराय दोनों सभाओं के निर्णय के विरुद्ध कार्य करने की समता रखता था। पर वायसराय की कार्यकारिणी परिषद् में एक के स्थान पर तीन भारतीय ले लिये गये। केन्द्रीय व्यवस्थापक मंडल में भी साम्प्रदायिक निर्वाचन तथा श्रास्प्रसंकों के लिये पासंग था जैसा कि निम्न तालिकाओं से प्रकट होगा:

केन्द्रीय व्यवस्थापिका सभा में प्रतिनिधित्व (१०४ निर्वाचित तथा ४१ गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत)

							-
	श्रसांप्र- दायिक	श्रमुस्लिम	मुस्लिम	यूरोपियन	सिनख	श्रन्य	415.
मद्रास	0	30	३	3	0	२	3 8
बम्बई (सिंघ सहित)。	ঙ	8	2	٥	3	१६
बंगाल	0	ξ	ξ	ર	•	२	30
युक्त प्रान्त	0	5	६	3	•	8	9 €
पंजाब	ó	2	, ξ	0	. २	9	12
बिहार तथा उड़ीसा	0	5	ર	0	٥	9	12
मध्य प्रांत	0	æ	3	٥	٥	3	¥
त्रासाम	٥	२	3	9	٥	۰	8
वर्मा	Ŋ	0,	٥	3	0	•	8
दिल्ली	9	•	. •	۰	6	٠	9
श्रजमेर मेरवाड़ा	9		٥.	0	3 	•	3
	¥	% ৩	३०	3	₹	33	308

दूसरे सदन राज्यपरिषद् में ६० सदस्य थे जिनमें से २७ तो गवर्नर जनरल के द्वारा मनोनीत थे (२० शासकीय, एक बरार का प्रतिनिधि तथा ६ ग्रशास-कीय) बाकी ३३ प्रतिनिधि निम्न तालिका के श्रनुसार निर्वाचित होते थे:—

भारत—नये संविधान तक राज्य-परिषद् के निर्वाचित सदस्य

प्रान्तका नाम	श्रमुस्लिम	मुस्लिम	यूरोपियन	सिनख	सामान्य	ना, .ख
मद्रास प्रदेश	8	9	•	0	0	·
बंबई प्रदेश	ą	ą	9	a	0	ξ
बंगाल प्रदेश	ર	2	3	•	0	ξ
युक्त प्रान्त	ર	२	٥	. 0	9	¥
पंजाब	9	२	•	3	•	8
विहार तथा उड़ीसा	२	3	•	0	٠	3
मध्य शान्त	0	٥	٥	•	3	3
श्रासाम	•	3	o	0	•	9
बर्मा	0	o	3	٥	3	२
	98	3 3	ર	3	२	३३

- ६ सम्राट को शक्ति असीमित रही। वह बड़े बड़े पदों पर नियुक्तियां करताथा, केन्द्रीय या प्रान्तीय व्यवस्थापक मण्डलों के किसी कान्त्न को रहकर सकताथा, तथा उच्च न्यायालयों के विषय में पर्याप्त नियन्त्रण रखताथा।
- ७ लन्दन स्थित भारत मंत्री के वेतन का भार ब्रिटिश निधि पर डाल दिया गया। भारत के शासन पर भारत मन्त्री का पूर्ण नियन्त्रण जारी रहा। गवर्नर जनरल तथा उनके द्वारा गवर्नर भारत मन्त्री के त्राधीन थे।
- म् लन्दन में भारत की श्रोर से एक दूत रखने का उपबंध (Provision) रखा गया जिससे भारत के व्यापारिक तथा कुछ श्रन्य कार्य भारत मन्त्री की न करने पहें।
- १, यह भी उपबन्ध रखा गया कि दस वर्ष उपरान्त अर्थात् १६२६ में एक संविधान समिति नियुक्त की जायेगी जो इन वर्षी के अनुभव पर यह बतायेगी कि प्रान्तों या केन्द्र में उत्तरदायित्व की बहाया, घटाया या संशोधित किया जाये।
 - ५०, देशी नरेशों को नरेन्द्र-मण्डल बनाने की अनुमति देवी गई।

द्वितीय ऋध्याय

सन् १६१६ के मंविधान का कार्यकाल

१, परिषदों में स्वराज्य की मांग

जैसा कि ऊपर वर्णन किया जा चुका है राष्ट्रसभा ने मीन्टफोर्ड सुधारों को असंतोषजनक, निराशात्मक तथा अस्वीकार्य ठहरा कर असहयोग आरम्भ कर दिया और निर्वाचनों में भाग नहीं लिया अतः चुनाव के छेत्र में नरम दल का बोलबाला रहा तथा उसे प्रान्तों एवं केन्द्रीय सभाओं में बहुत से स्थान मिल गये। वे भी १६१६ के संविधान से संतुष्ट न थे अतः उन्होंने परिषदों के अन्दर से स्वराज्य की मांग आरम्भ की । २३ सितम्बर १६२१ को श्री जावृनाथ मोजुमदार ने प्रस्ताव रखा कि प्रान्तों में स्वशासन तथा केन्द्र में उतरदायित्व मिलना चाहिये। श्री जमनादास द्वारकादास ने एक संशोधन द्वारा सुकाव पेश किया कि सपरिषद गवर्नर जनरल से निवेदन किया जाता है कि वह शासकीय तथा अशासकीय सदस्यों की एक समिति नियुक्त करे, जिस में कि भारतीय व्यवस्थापक मंडल के सदस्य भी सम्मिलित हों, श्रीर जो गवर्नरी प्रान्तों में प्रान्तीय स्वशासन स्थापित करने तथा केन्द्रीय शासन में उतरदायित्व का प्रवेश करने के उत्तमोत्तम उपाय सोचे तथा अपनी सम्मित दें। श्रेषेत्र गृह-तदस्य सर विलियम विनसेन्ट ने इस प्रस्ताव का विरोध किया तथा निम्न प्रस्ताव स्वीकृत करवाया:

"यह सभा सपरिषद् गवर्नर जनरल से निवेदन करती है कि वे इस सभा का यह मत भारत मंत्री को बतायें कि उत्तरदायी शासन के मार्ग पर

भारत ने जो प्रगति की है उस से यह त्र्यावश्यक हो गया है कि १६१६ से पहले ही संविधान का पुनर्विलोकनतथा पुनरीच्या हो ।"

(यह याद रखने योग्य है कि १६१६ के संविधान में १० वर्ष पश्चात पुनर्विचार करने का उपबंध था)।

भारत मंत्री ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार करते हुए कहा कि उसी संविधान के अन्तर्गत उन्नित की जा सकती है, अभी निर्वाचकों की योग्यता का पूर्ण परिचय नहीं मिल पाया है। इस में समय एवं अनुभव चाहिये और अभी शासन-तन्त्र की पूरी तरह परीचा नहीं हो सकी है।

इसी प्रकार बाद में कई सुधारों की मांग के प्रस्ताव रखे गये तथा सरकार के विरोध के उपरांत भी स्वीकृत होगये। उधर कांग्रेस का श्रसहयोग वेग से चलता रहा।

इस संविधान के अन्तर्गत द्वितीय निर्वाचन १६२३ में होने थे । राष्ट्र सभा कांग्रेस में इस समय दो दल (नरम तथा गरम) बन गये। गरम दल तो असहयोग ही चाहता था पर नरम दल ने श्री चितरंजन दास तथा श्री मोती लाल नेहरू के नेतृत्व में स्वराज्य दल बना लिया और चुनाव लड़ने की ठानी। उन्होंने निर्वाचन सम्बन्धी नीति की घोषणा करते हुए अपना परिषदों में प्रवेश करने का निम्न उद्देश्य बताया:

- हम सरकार को, परिषदों द्वारा, राष्ट्रीय त्रान्दोलन के विरुद्ध कोई कार्य न करने देंगे।
- २. सरकार को चुनौती दी जायेगी कि यदि राष्ट्रीय मांगें स्वीकार न की गईं तो हम निरन्तर ख्रीर एक सी वाधक नीति का प्रयोग करेंगे ख्रीर परिषदों द्वारा शासन कार्य असम्भव बना देंगे !

इस घोषणाके आधार पर उन्होंने जुनाव लड़े तथा अपूर्वसफलता पाई। प्रांतों तथा केन्द्र में उन्होंने आन्तरिक असहयोग सा आरम्भ कर दिया। बंगाल व मध्य प्रान्त में बहुमत प्राप्त करके भी मन्त्रिपद स्वीकार नहीं किये। श्री मोती लाल नेहरू ने शासकों के तीव विरोध के उपरान्त भी एक प्रस्ताव न्यवस्थापिका सभा में स्वीकार करवा दिया जिसमें ब्रिटिश सरकार द्वारा संविधान के निरीचण की मांग करने के स्थान पर "भारतीयों द्वारा विचार विमर्ष के परचात पूर्णतः उत्तरदायी सरकार की स्थापना" की मांग की गई थी। उसका अंश नोचे लिखा जाता है:—

"यह सभा सपरिषद गवर्नर जनरक से सिफारिश करती है कि वे भारत में पूर्ण उत्तरदायी शासन स्थापित करने के उद्देश्य से भारतीय संविधान का पुनरीक्षण कराने के लिए कार्यवाही करें श्रौर इस के लिये:—

- (क) श्रल्पसंख्यकों के हितों तथा श्रिधिकारों का श्रावश्यक ध्यान रखते हुये भारत के निमित्त एक संविधान की योजना की सिफारिश फरने के लिये एक प्रतिनिधि गोलमेज परिषद बुलायें, श्रीर
- (ख) केन्द्रीय व्यवस्थापक मण्डल को भंग करने के पश्चात एक नवीन निर्वाचित भारतीय व्यवस्थापक मण्डल को स्वीकृति के लिये कथित योजना रखें श्रौर उसी को एक श्रिधिनियम का रूप देने के लिये ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत करें।"

शासकों की टाक मटोल के विपरीत यह प्रस्ताव स्वीकृत हो गया। पर सरकार ने यह मांग अस्वीकार कर दी। तब स्वराज्य दल ने भी आय-ज्यय के अनुमान-पत्र को सभा में अस्वीकृत करवा दिया। गवर्नर जनरल ने उसे अपने विशेषाधिकारों से प्रमाणित किया। अन्य कई शासकीय प्रस्ताव गिर गये जिन्हें गवर्नर जनरल ने पुनर्जीवित किया। ऐसी ही अवस्था प्रांतों में थी।

२. ग्रुड्डीमेन समिति

फिर सरकार ने एक समिति नियुक्त की जिस के श्रध्यत्त सर एक्षेक्जे-एडर मुड्डोमेन थे। उस में ३ श्रन्य श्रंग्रेज तथा ६ भारतीय थे जिनके नाम निम्नांकित हैं:—

- १. मियां सर मोहम्मद शफी
- २. बर्दवान के महाराजाधिराज
- ३. सर तेज बहादुर सप्रू
- ४. श्री पी० एस० शिवास्वामी त्रायर
- ४. मि० जिन्ना
- ६. डा० रघुनाथ परांजपे

तीनों अंग्रेज़ों तथा उनके साथ महाराजा और शफी साहब ने तो सुधारों के विषय में विरोधी नीति की सिफारिश की पर बाकी चार भारतीयों ने कहा कि "द्वैध शासन असफल सिद्ध हुआ है श्रतः स्वराज्य की स्थापना के उद्देश्य से संविधान में परिवर्तन करना आवश्यक है।" सरकार का यह मत

श्चरस्वीकार्य बताया गया कि "वर्तमान संविधान के श्चन्तर्गत ही वास्तविक उन्नति सम्भव है"। जब ब्यवस्थापिका सभा में यह रिपोर्ट रखी गई तो श्री मोतीलाल नेहरू ने श्रपना पहले वाला गोलमेज परिषद सम्बन्धी सुकाव पुनः पेश किया तथा स्वीकृत कराया।

३. भारत में फूट

इसके पश्चात स्वराज्य दल में फूट पड़ गई ख्रीर सर्वश्री जयकर, केलकर, मुंजे आदि ने अपने त्यागपत्र देकर एक प्रतियोगी-सहयोगी दल का निर्माण कर लिया जो सरकार के साथ सहयोग करके जनता को लाभ पहुँचाना चाहता था । उन्होंने मंत्रिपद श्रादि स्वीकार कर लिये। श्चन्त में उनका स्वराज्य दल से कुछ निपटारा सा हुआ। परन्तु उधर, कांग्रेस की मुस्लिम लीग के सामने सुकने की नीति को देख कर, महमना मदनमोहन जी मालवीय ने लाला लाजपतराय की सहायता से एक 'स्वतन्त्र दल' बना लिया जो सारे सम्प्रदायों के साथ समान व्यवहार चाहता था। उधर मुस्लिम लीग साम्प्रदायिक विष फैला रही थी श्रीर महान हिन्दू विरोधी दंगे भी करा रही थी। इस प्रकार साम्प्रदायिक अन्तर बढ़ते ही गये जो कि अंग्रेजों का उद्देश्य था और जिस उद्देश्य से साम्प्रदायिक निर्वाचन तथा मुसलमानों को विशेष पासंग (वजन) दिया गया था। १६२६ के निर्वाचन पर इस का इतना प्रभाव पड़ा कि निम्न लिखित दलों ने चुनाव लड़े, स्वराज्य, प्रतियोगी-सहयोगी, स्वतन्त्र, उदार, हिंदू महासभा, मुस्लिम लीग, खिलाफत तथा दिल्ण में अब्राह्मण आदि । परिणामतः स्वराज्य दल को "मद्रास के अतिरिक्त कहीं भी पूर्ण बहमत प्राप्त नहीं हुआ।

४. साइमन आयोग

श्रंततोगत्वा २६ नवम्बर १६२७ को अर्थात संविधान में लिखित तिथि से २ वर्ष पहले ही एक आयोग साइमन नामक अंग्रेज की अध्यक्ता में नियुक्त हुआ जिसमें समस्त सदस्य भी अंग्रेज ही थे। आयोग का उद्देश्य निम्न लिखित था:—

"कि ब्रिटिश भारत की शासन-प्रणाली के कार्यरूप की, शिचा वृद्धि की, प्रतिनिध संस्थाओं के विकास की एवं तत्सम्बन्धी विषयों की जांच करे तथा रिपोर्ट दे कि क्या उत्तरदायी शासन का सिद्धान्त लागू करना वांछनीय है, यदि है तो किस मात्रा में और शासन में तात्कालिक उत्तरदायित्व को बढाया

या घटाया जाये अथवा कोई और परिवर्तन किया जाये । इसके साथ साथ आयोग यह भी सम्मति दे कि प्रान्तों में द्वितीय परिषद स्थापित करना भी बांब्रनीय है या नहीं।"

पूर्णतः श्वेतवर्ण समिति से विश्वास उत्पन्न न होकर असंतोष की लहर दोड़ गई। भारत की स्वभाग्य-निर्णय कि मांग का इससे अधिक निरादर क्या हो सकता था कि हमारे भाग्य-निर्णय में हमारा तिनक भी सहयोग न मांगा जाये। निदान सारे दलों के २६ राजनैतिक नेताओं ने निम्न घोषणा की :

"इस मामले पर खूब गम्भीरता से विचार करने के पश्चात् हम इस परिपक्च परिणाम पर पहुँचे हैं कि भारतीयों को आयोग में न रखना सिद्धान्ततः श्रुटिमय है। भारतीयों के इस योजना में भाग न लेने का सिद्धान्त ऐसा है कि भारत अपने स्वाभिमान के साथ इसको मान नहीं सकता। इस समय निर्मित आयोग को हम सहयोग नहीं दे सकते, जब तक कि ऐसी समिति नहीं बनती जिस में कि भारतीय एवं ब्रिटिश राजनीतिज्ञ समानता से बैठने के लिये आमन्त्रित हों।"

इस विषय में राष्ट्र सभा में जो प्रस्ताव स्वीकृत हुआ उसका संचेप इस प्रकार है:

"च्रंकि स्वभाग्य-निर्णय के सिद्धान्त के विरुद्ध यह समिति नियुक्त की गई हैं श्रतः राष्ट्रसभा कांग्रेस यह निश्चय करती है कि स्वाभिमानी भारत के लिये यही एक मार्ग है कि श्रायोग का वहिष्कार किया जाये, विशेषतः

- श्रायोग के भारत में त्राने के दिन देश भर में विरोध प्रदर्शन एवं हडताल हो।
- २. श्रायोग के समन्त राजनैतिक नेता तथा परिषदों एवं व्यवस्था-पिका सभाश्रों के श्रशासकीय सदस्य विचार प्रकट न करें श्रौर न उनसे भेंट हो करें श्रौर उनके साथ सहभोग श्रादि में भी सम्मिलित न हों।
- ३. परिषदों तथा व्यवस्थापिका सभा के श्रशासकीय सदस्य उपसमितियों में भी सम्मिलित न हों श्रीर साइमन श्रायोग के व्यय के लिये मत न दें।
- ४. जब तक यह श्रायोग भारत में रहे तब तक परिषदों श्रादि का भी बहिष्कार किया जाये, जब तक कि राष्ट्रीय हित में वहां उपस्थित होना श्रावश्यक न सममा जाये।"

इसके ग्रतिरिक्त राष्ट्र सभा ने भारतीय जनता के लच्य 'पूर्ण' राष्ट्रीय स्वतन्त्रता' को हौहराया ।

३ फरवरी १६२५ को जब यह सिमिति भारत पहुंची तो देश में ह्यापक हड़ताल रही। जहां भी वे गये काले मंडों से उनका स्वागत किया गया तथा 'साइमन लौट जावो' के नारे लगाये गये। मानो देश भर में गड़बड़ मच गई।

६ फरवरी १६२८ को साइमन ने वायसराय को निम्न कार्य-प्रणाली का संकेत किया:

"जैसे ब्रिटिश संसद ने हम ७ व्यक्तियों को चुना है, भारतीय व्यवस्था-पक मराइल भी उसी प्रकार श्रपने प्रतिनिधि चुने, तथा वे हम लोगों के साथ, मेरे सभापितत्व में समवेत होकर, लोगों के विचारों को सुनें । यह 'संयुक्त स्वतन्त्र सम्मेलन' होगा । यही उचित, न्याययुक्त एवं भारत तथा ब्रिटेन के यथार्थ हित में है। शासकीय वर्ग के श्रतिरिक्त जनता, संस्थाश्रों एवं व्यक्तियों की भी बात सुनी जाये। प्रांतों के विषय में सोचते समय प्रांतीय परिषदों के प्रतिनिधि तथा केन्द्रीय विषयों के समय केन्द्रीय व्यवस्थापक मण्डल के प्रति-निधि हों तो ठीक है। हमें तो श्रपना कार्य पूरा करना ही है चाहे कुछ भी हो, पर कार्यारम्भ से पहले हमने सद्भावना से भारतीयों के लिये सम्मान तथा बराबरी के साथ सहयोग करने का द्वार खोल दिया है।"

राष्ट्रसभा के निदेश पर व्यवस्थापिका सभा ने 'संयुक्त स्वतंत्र सम्मेलन' के लिये श्रपने प्रतिनिधि चुनने से इंकार कर दिया।

५. सर्वद्लीय सम्मेलन तथा नेहरू समिति

उधर राष्ट्रसभा ने फरवरी-मार्च १६२८ में दिल्ली में एक सर्वदल सम्मेलन किया जिसने 'पूर्ण उत्तरदायी शासन' की मांग की। १६ मई की दूसरी बैठक में सम्मेलन ने, मानो साइमन की प्रतिरपर्धा में, श्री मोतीलाल नेहरू की श्रध्यचता में एक समिति भारतीय संविधान के सिद्धान्तों का मसविदा बनाने के लिये नियुक्त करदी जिसे १ जुलाई १६२८ तक श्रपनी सिफारिशें देने का श्रादेश दिया गया । नेहरू समिति की सिफारिशों में श्रधिराज्य (Dominion) स्वराज्य को भारतीय संविधान का श्राधार बनाया गया तथा उसे सर्वदल सम्मेलन ने उसके परिश्रम पर बधाई दी।

राष्ट्रसभा ने श्रपनी बैठक में, जो दिसम्बर १६२ में कलकत्ते में हुई थी, सरकार को नेहरू समिति की सिफारिशें स्वीकार करने के लिये एक वर्ष का समय दिया तथा चुनौती दी ''कि यदि नेहरू समिति की शासन पद्धित को ३१ दिसम्बर १६२६ तक ब्रिटिश संसद स्वीकार न करेगी श्रथवा इस तिथि के पूर्व ही श्रस्तिकार कर देगी तो राष्ट्रसभा श्रसहयोग श्रान्दोलन का संगठन श्रारम्भ कर देगी श्रोर देश को इस बात के लिये तैयार करेगी कि सरकार को न तो कर दिया जाये श्रोर न किसी प्रकार की सहायता दी जाये।" श्रागे चल कर श्राप पढेंगे कि ३१ दिसम्बर १६२६ को राष्ट्रसभा ने नेहरू रिपोर्ट रद्द करके पूर्ण स्वराज्य श्रथात् ब्रिटिश साम्राज्य से सम्बन्ध विच्छेद की मांग की। मानो श्रधिराज्य पद की मांग का युग भी चला गया।

६. साइमन की रिपोर्ट

१६२६ के अप्रेल में साइमन आयोग ब्रिटेन को लौट गया। पर मई में ही वहां अनुदार दल का शासनान्त हो गया तथा अमिक दल का मंत्रिमंडल स्थापित हो गया। इसके फलस्वरूप कुछ नीति में परिवर्तन हो गया तथा साइमन की सिफारिशें जो निम्नलिखित सिद्धान्तों पर आधारित थीं जून १६३० तक प्रकाशित नहीं की गईं:

- भारत का अन्तिम संविधान संघीय श्राधार पर हो (अर्थात् पूर्णं विकेन्द्रीकरण कर के तथा प्रान्तों को स्वराज्य देकर शेष विषय केन्द्र रखे) ।
- २. द्वेध शासन का अन्त तथा मंत्रिमंडल की स्थापना, जिसमें एक या अधिक श्रनिर्वाचित मंत्री हों।
 - ३. कार्यकारिसी को स्वतन्त्रता हो अर्थात् उत्तरदायित्व न हो।
- ४. ब्यवस्थापक मंडलों के सदस्यों की संख्या बढ़ाई जाये तथा मता-धिकार को श्रिटिक विस्तृत किया जाये ।
 - ४. साम्प्रदायिक निर्वाचन स्थिर रहें।
- मुसलमानों को उनकी संख्या के अनुपात से अधिक स्थान तथा
 पासङ्ग दिया जाये।
 - गवर्नरों के श्रंकुश समान विशेष श्रधिकार बने रहें, जैसे पहले थे।
- प. केन्द्रीय संघीय राज्यपरिषद् तथा ज्यवस्थापिका सभा का निर्वाचन प्रान्तीय सभात्रों द्वारा किया जाये।
 - ६. बर्मा को भारत से पृथक कर दिया जाये ।

७. गोलमेज सम्मेलनों की तैयारी

जैसा ऊपर कहा जा चुका है श्रमिक दल की सरकार ने साइमन की रिपोर्ट को एक वर्ष तक प्रकाशित नहीं किया क्योंिक वह बहुत श्रमुचित थी। प्रत्युत इसी बीच में वायसराय लार्ड इरविन जून १६२६ में विलायत चले गये जिससे कि 'साइमन की वैधानिक जांच के परिणाम स्वरूप जो सुधार योजना संसद के सम्मुख रखी जाये उससे पहले ऐसा उपाय करें जिससे कि संविधान सम्बन्धी स्थिति स्पष्ट हो जाये श्रीर भारत के लोकमत के प्रतिनिधि दलों का श्रिषक सहयोग प्राप्त हो सके।'

वायसराय इरविन ने भारत लोट कर २१ श्रक्टूबर को एक घोषणा की कि "ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य भारत में श्रधिराज्य स्थापित करना है तथा इस सम्बन्ध में विचार करने के लिये ब्रिटेन में एक गोलमेज सम्मेलन किया जायेगा।" पर यह सब श्रनिश्चित सी भाषा में था श्रोर कोई इस बात का संकेत नहीं था कि श्रधिराज्य कब तक स्थापित होगा। कांग्रेस ने इसकी स्थापना के लिये श्रन्तिम तिथि ३१ दिसम्बर १६२६ रखी हुई थी। इरविन की घोषणा का संनिष्त श्राशय निम्नलिखित था:

'सर साइमन ने प्रधान मंत्री से पत्रव्यवहार में कहा है कि शासन सुधारों के साथ ब्रिटिश भारत एवं देशी राज्यों के भावी सम्बन्धों के प्रश्न पर विचार करना भी त्रावश्यक है अतः हमारी योजना को संसद के सामने रखने से पूर्व यह अपेचित है कि ब्रिटिश सरकार ब्रिटिश भारत और देशी राज्यों दोनों के प्रतिनिधियों से मिलकर उन प्रस्तावों पर अधिकतम समभौते का प्रयत्न करे जिन्हें कि संसद में रखना उसका कर्तव्य होगा।

मुक्ते इसका ज्ञान है कि सम्राट की सरकार इन विचारों से पूर्णतः सहमत है।

ब्रिटिश नीति का लच्य, जैसा कि अगस्त १६१७ की घोषणा में उल्लिखत है, यह है कि भारत में, ब्रिटिश साम्राज्य का अभिन्न भाग रहते हुए, प्रगति से उत्तरदायी शासन स्थापित करने के उद्देश्य से स्वशासित संस्थाओं का शनैः शनैः विकास किया जाये। यह सम्राट की इच्छा है कि १६१६ में संसद द्वारा निर्मित योजनानुसार, भारत अधिराज्यों में अपना उचित स्थान प्राप्त कर सके। सम्राट के मंत्रियों ने भी कई बार सार्वजनिक घोषणायें की हैं कि ब्रिटिश सरकार की यह आकांचा है कि यथासमय भारत को साम्राज्य में

दृसरे अधिराज्यों के साथ अपना बराबर का स्थान प्राप्त करना चाहिये। किन्तु १६१६ का अधिनियम बनाने में ब्रिटिश सरकार के इरादों के विषय में ब्रिटिन एवं भारत दोनों देशों में जो सन्देह प्रकट किये गये हैं उनको ध्यान में रख कर मुफे ब्रिटिश सरकार द्वारा यह स्पष्ट कहने का अधिकार दिया गया है कि उनके विचारानुसार १६१७ की घोषणा में यह निहित है कि भारत की संविधान सम्बन्धी प्रगति का स्वाभाविक परिणाम अधिराज्य श्रेणी की प्राप्ति है।"

भारतीय नेतास्त्रों ने घोषणा का स्वागत करते हुये स्रपना सहयोग देने का स्राश्वासन दिया पर कुछ संदेह भी प्रकट किये। दिल्ली में सब दलों के भारतीय नेतास्रों की एक बैठक ने गोलमेज सम्मेलन में सम्मिलित होने के लिये निम्न शर्तें रखीं:—

- "'१. सम्मेलन में यह न सोचा जाये कि श्रधिराज्य कब स्थापित होगा वरन् श्रधिराज्य की रूपरेखा निश्चित की जाये।
 - २. सम्मेलन शीवातिशीव बुलाया जाये।
 - राजनैतिक बन्दी मुक्त कर दिये जायें।
 - ४. राष्ट्र सभा को सब से ऋधिक प्रतिनिधित्व मिले।
- ४. इसके अतिरिक्त नये संविधान के बनने से पूर्व ही देश के शासन में नई विचारधारा का प्रादुर्भाव किया जाये, कार्यकारिया और व्यवस्थापक मंडल के बीच ऐसा सम्बन्ध स्थापित किया जाये जो प्रस्तावित सम्मेलन के उद्देश्यों के अनुकृल हो तथा वैधानिक कार्यप्रणाली का अधिक अनुसरण किया जाये। यह आवश्यक है कि कि जनता को अनुभव होने लगे कि वास्तव में आज से नवीन युग का श्रीगर्णेश हो गया है और नया संविधान इस तथ्य की अभिन्यक्ति मात्र होगा।"

सरकार इन शर्तों को पूरा न कर सकी, अपित संसद में भारत को अधिकार सोंपने के अस्ताव पर विरोधात्मक भाषण हुए और अधिकारियों ने संसद में आश्वासन दिया कि ''पिरिस्थित में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, और १६१० की घोषणा के अनुसार ही कार्य होगा।" भारत मंत्री श्री वेजबुड बेन ने यहां तक कह डाला कि 'भारत को १० वर्ष से अधिराज्य पद तो मिला ही हुआ है।' इससे भारतीयों की आंखें खुल गईं और गोलमेज सम्मेलन का बहिष्कार करने का निर्णय हुआ।

पूर्ण स्वराज्य की मांग

२३ दिसम्बर १६२६ को लार्ड इरिवन से महात्मा गांघी तथा श्री मोतीलाल नेहरू की बातचीत हुई, पर इरिवन ने कोई संतोपजनक श्राश्वासन नहीं दिया कि शीघ्र ही श्रिधराज्य पद दिया जायेगा । इसके परिणाम स्वरूप एक वर्ष की श्रवधि समाप्त होने पर ३१ दिसम्बर १६२६ की मध्य रात्रि के समय लाहोर में श्री जवाहर लाल नेहरू के सभापति व में राष्ट्रसभा ने प्रस्ताव स्वीकार किया कि "वायसराय की घेषणा के परचात जो हुश्रा है उस पर तथा महात्मा गांधी, श्री मोती लाल नेहरू तथा श्रन्य नेताश्रों के बीच बातचीत के परिणाम पर विचार करने के परचात राष्ट्रसभा का यह मत है कि वर्तमान परिस्थितियों में राष्ट्रसभा के गोलमेज सम्मेलन में प्रतिनिधित्व करने से कोई भी लाभ नहीं होगा। श्रतः गत वर्ष कलकत्ते में स्वीकृत प्रस्ताव के श्रनुसार राष्ट्रसभा यह घोषणा करती है कि राष्ट्रसभा के संविधान में स्वराज्य शब्द का श्रर्थ 'पूर्ण स्वतन्त्रता' होगा श्रीर यह भी घोषणा करती है कि नेहरू समिति की सारी योजना श्रव रह हो गई है।"

२१ जनवरी १६३० को लार्ड इरिवन ने व्यवस्थापिका सभा में एक भाषण दिया जिस में उन्होंने स्पष्ट किया कि 'गोलमेज सम्मेलन में वास्तव में वह चीज न होगी जो कि भारतवासी सोच रहे हैं; उसका निर्णय बहुमत से न किया जायेगा। वह तो संसद को भारतीय सुधारों के विषय में केवल मार्ग प्रदर्शन का कार्य करेगा।' इससे मानो जले पर नमक लग गया।

राष्ट्रसभा के ऋदिशानुसार २६ जनवरी १६३० को देश भर में स्वाधीनता दिवस मनाया गया, जलूस निकाले गये, सभाएं की गईं तथा राष्ट्रसभा का राष्ट्रीय ध्वज फहरा कर निम्न प्रतिज्ञा की गईं:

'हम विश्वास करते हैं कि आहम विकास का पूर्ण अवसर प्राप्त करने के लिये दूसरे देशों के लोगों की तरह भारतीयों को पूर्ण स्वाधीनता पाने का, अपनी कमाई के उपभोग करने का तथा जीविका के उपयुक्त उपकरण पाने का अविच्छेच अधिकार है। हम यह भी विश्वास करते हैं कि यदि कोई सरकार इस उद्देश्य में वाधक हो तो उस को ध्वंस करने का अधिकार हमें है।' इत्यादि अन्तिम पैरा में करबंदी तथा सत्याप्रह की प्रतिज्ञा थी। इस प्रकार की प्रतिज्ञा प्रतिवर्ष भारत में २६ जनवरी को दौहराई जाने लगी।

फरवरी १६३० तक राष्ट्रसभा के आदेश पर १७२ सदस्यों ने ज्यवत्था-पिका सभा तथा राज्यपरिषदों से त्यागपत्र दे दिये । सत्याग्रह आरम्भ हो गया। वायसराय ने अधिराज्यपद तक के विषय में कोई आश्वासन देने से इंकार कर दिया । इसके विपरीत राष्ट्रसभा ने मांग की कि गोलमेज सम्मेलन एक त्वतन्त्र भारत का संविधान बनाये, अर्थात् राष्ट्रसभा अधिराज्य पद की मांग से भी कहीं आगे बढ़ गई।

पहला गोलमेज सम्मेलन

लंदन में १२ नवम्बर १६३० को सम्मेलन का प्रथम श्रिधिवेशन धूम-धाम से श्रारम्भ हुश्रा। कुल ८६ प्रतिनिधि सम्मिलित हुए जिनमें राष्ट्रसभा का कोई प्रतिनिधि न होने से उसका राजनैतिक महत्व कम हो गया। जो प्रतिनिधि उपस्थित थे उन में ब्रिटिश भारत के ५७ प्रतिनिधि थे, देशी राज्यों के १६ तथा ब्रिटिश सरकार के १३, जिन में ८ सरकारी दल के, ४ श्रानुदार दल के तथा १ उदार दल का था। भारत के प्रतिनिधि किसी प्रकार निर्वाचित नहीं थे वरन वे वायसराय द्वारा 'श्रामंत्रित' थे।

सब से पहले अधिराज्य-स्वराज्य के विषय पर ख्ब भाषण हुए। राष्ट्रसभा की अनुपिश्यित के कारण पूर्ण स्वतन्त्रता का विषय उठा ही नहीं। इसके पश्चान् यह प्रश्न उठा कि भारत में एक केन्द्रीय शामन रहे या संवीय शामन प्रणाली लाग् की जाये। देशी नरेशों ने अखिल भारतीय संघ में सिमालित होने की इच्छा प्रगट की। पिटयाला, बीकानर, अलवर और भोपाल के नरेशों ने विशेषकर इस प्रणाली की सराहना की। श्री श्रीनिवास शास्त्री, जो पहले कुछ मंकोच कर रहे थे, बाद में संघीय प्रणाली के पच में हो गये। बिटिश प्रधान मंत्री श्री रामसे में। डोनल्ड ने कहा कि 'नरेशों की घोषणा से पिरिस्थित में कान्तिकारी परिवर्तन हो गया है। उन्होंने वास्तिवक संयुक्त संघीय भारत के निर्माण के लिये मार्ग खोल दिया है। भारत के भावा संविधान की इमारत बनाने के लिये हम ने तथा आप सब ने बहुत सहायता की है।" इस के पश्चान प्रधान मंत्री ने निम्न ज्यवहारिक प्रश्न सुक्ताये:

- "१. संघ में मिलने वाली भिन्न भिन्न इकाइयां किस प्रकार की होंगी?
- २. केन्द्रीय शासन किस प्रकार का होगा और इकाइयों पर कैसे नियन्त्रण करेगा ?
 - ३. केन्द्र का प्रान्तों से क्या सम्बन्ध होगा ?

- थ. केन्द्र का देशी राज्यों से क्या सम्बन्ध होगा ?
- श्र. विशेष हितों का तथा श्रल्पसंख्यकों का सहयोग प्राप्त करने के लिये क्या उपबंध रखे जायेंगे?
- ६. इकाइयों ग्रोर केन्द्र के क्या विषय होंगे तथा क्या कार्य एवं कर्तब्य होंगे ?"

फिर उन्होंने कहा कि "इन प्रश्नों का व्यवहारिक उत्तर देना ही श्राप की श्रोर मेरी समस्या है जिससे कि संसद द्वारा स्वीकृत संविधान में यह बातें निहित की जा सकें।" उन्होंने दो बातें श्रावश्यक बताईं एक तो "संविधान ऐसा हो जिस पर कार्य किया जा सके, केवल श्रादर्शमय ही नहीं हो, दृसरी बात, उसका विकास होता रहे।"

इस के पश्चात् निम्न प्रश्नों पर विचार करने के लिये ६ उपसमितियों की स्थापना की गई:

- प्रथम उपसमिति को संघीय रूप रेखा बनाने के लिये निम्न प्रश्नों पर विचार करने का कार्य मिला:
 - (फ) संघ की भिन्न भिन्न इकाइयां।
- (ख) संघीय व्यवस्थापक मंडल किस प्रकार का हो तथा उसमें कितने सदन हों ?
 - (ग) संघीय व्यवस्थापक मंडल की शक्ति तथा कार्य।
- (ध) संघीय व्यवस्थापक मंडल में कितने सदस्य हों व कितने सदस्य किस प्रान्त से लिये जायें ?
- (ङ) बिटिश भारत तथा देशी राज्यों के प्रतिनिधि किस प्रकार सुने जायें ?
- (च) संवीय कार्यकारिणी का संविधान, शक्ति, प्रकार, तथा कार्य क्या हों ?
- २. दूसरी समिति को प्रान्तीय व्यवस्थापक मंडल तथा कार्य कारिगी सत्ता का संविधान, कार्य चेत्र, शक्ति श्रादि निर्धारित करने का कार्य मिला।
- ३. तीसरी उपसमिति को ऋल्पसंख्यकों के विषय में मुक्ताव पंश करने के लिये कहा गया।

- अ. चौथी उपसमिति को मताधिकार के सिद्धान्तों पर अपनी सम्मित देने की आज्ञा हुई।
 - ५. एक उपसमिति रक्ता के विषय पर नियुक्त हुई।
- सरकारी नौकरों के विषय में विचार करने के लिये भी एक उपसमिति बैठाई गई।
- ७. एक उपसमिति बर्मा के विषय में नियुक्त की गई जिससे कि बर्मा को भारत से पृथक किया जा सके।
- प्त. एक उपसमिति सीमाधान्त का विशेष संविधान बनाने के लिये नियुक्त हुई ।
 - एक उपसमिति सिंध को पृथक प्रान्त बनाने के विषय में थी।

१०. मैंबडोनल्ड की घोषणा

उपसमितियों की रिपोर्टें त्राने पर सम्गेलन ने उनकी सराहना की, विशेषत: श्रव्यमंख्यकों को दिये गये विशेषाधिकारों की जो कि मिस्टर जिन्ना ने स्वीकार करवाये थे। वास्तव में सम्गेलन में सारे राजभक्त ही थे श्रतः श्रंग्रेजी शासन की इच्छानुसार सारा काम हुआ। सम्गेलन के श्रन्त में भारत में चल रहे श्रमहयोग सत्याग्रह को बंद करने के लिये वायसराय ने महात्मा गांधी ये श्रमुरोध किया जिससे कि गोलभेज सम्गेलन के द्वारा भारत के लिये श्रच्छा संविधान बन सके। उधर प्रधान मंत्री मैक्डोनल्ड ने १६ जनवरी १६३१ को सम्राट की सरकार की नीति की निम्न घोपणा की:

- "१. स्वतन्त्रता पर प्रतिबन्धः बादशाह की सरकार का यह मत है कि भारत के शासन का उत्तरदायित्व केन्द्रीय तथा प्रांतीय व्यवस्थापक मंडलों पर डाला जाये किन्तु ऐसे ब्रावश्यक उपबंध रखे जायें जो परिवर्तन काल में कुछ विशेष कर्तव्यों के पालन करने के लिये तथा श्रव्यसंख्यकों के श्रधिकारों श्रीर राजनैतिक स्वतन्त्रता की रक्ता के लिये श्रिपेक्त हों।
- २. स्वतन्त्रता की सीढी: इस परिवर्तनकाल की त्रावश्यकतात्रों के कारण जो वैधानिक संरच्या रखे जायेंगे उन में सम्राट की सरकार यह श्रच्छी तरह ब्यवस्था करेगी कि रचित श्रिधकारों का इस प्रकार निर्माण तथा प्रयोग हो कि नये संविधान द्वारा भारत को श्रपने शासन में पूर्ण उत्तरदायित्व भाषत करने में कोई बाधा न पड़े।

- 3. समभौते का प्रयत्न: बादशाह की सरकार को इस बात का ज्ञान है कि ऐसे संविधान की सफलता के लिये जो बातें आवश्यक हैं वे पृरी नहीं हुई हैं किन्तु इतना कार्य कर के वे ऐसे स्थान पर पहुंच गये हैं जहां कि यह आशा होने लगी है कि इस घोपणा के परचात् आगे की बातचीत सफल हो सकती है।
- 8. संघीय शेजना: बादशाह की सरकार ने यह बात देखी हैं कि सम्मेलन की कार्यवाही सब दलों हारा स्वीकृत इस आधार पर चली हैं कि केन्द्रीय सरकार अखिल भारत का एक संघ हो जिसके व्यवस्थापक मंडल में दो सदन हों और बिटिश भारत तथा देशी राज्य सम्मिलत हों। नई संघीय सरकार का ठीक रूप और ढांचा तो देशी नरेशों तथा बिटिश भारत के प्रतिनिधियों से बातचीत करके ही निश्चित होगा। इसको दिये जाने वाले विषयों की सूची पर और बाद्विवाद की आवश्यकता होगी, क्योंकि संघीय सरकार को देशी राज्यों से सम्बन्धित ऐसे ही मामलों में अधिकार होंगे जो कि देशी नरेश संघ में मिलते समय उसे अपित करेंगे। देशी राज्यों का संघ से सम्बन्ध इस मूल सिझान्त पर आधारित होगा कि जो विषय वे संघ को अपित नहीं करेंगे उनके बारे में इन राज्यों के, वायसराय हारा, सम्नाट से ही सम्बन्ध होंगे।
- ५. उत्तरदायित्व : संघीय सिद्धान्त पर व्यवस्थापक मंडल के निर्माण होने पर सम्राट की सरकार व्यवस्थापक मंडल के प्रति कार्यकारिणों के उत्तरदायित्व के सिद्धान्त को मान लेने के लिये तैयार होगी ।
- ६. रित्तात विषय : वर्तमान परिस्थितियों में सुरचा तथा विदेशी सम्बन्ध के विषय गवर्नर जनरल द्वारा रित्तत होंगे और इनके प्रयन्ध के लिये उसे शिक्त प्रदान करने की व्यवस्था की जायेगी। इसके अतिरिक्त लाचार होने पर गवर्नर जनरल को संकटके समय राज्य से शान्ति रखनेकी चमता होनी चाहिये,और इसी प्रकार उसे अल्पसंख्यकों के वैधानिक अधिकारों के पालन के लिये उत्तरदायी होना चाहिये, अतः उसे इन प्रयोजनों के लिये आवश्यक शिक्त देनी होगी।
- ७. वित्तः नये संविधान में रिर्जव बैंक, ऋए ,विनिमय नीति श्रादिके लिये उपबंध रखना होगा जिससे कि भारत की श्रार्थिक श्रवस्था स्थिर रहे श्रीर भारत मंत्री के नाम से लिये गये ऋगों की पूर्ति हो सके । इन उपबंधों के

श्राधीन रहते हुए भारतीय सरकार को पूर्ण श्रार्थिक उत्तरदायित्व होगा जिसमें वह किसी प्रकार श्राय के साधन बना सके या श्ररिक्त विषयों के ब्यय पर नियन्त्रण कर सके।

- म. द्विध शासनः इसका अर्थ यह है कि केन्द्र में द्वेध शासन रहेगा। रचित शक्तियों का होना आवश्यक है, किन्तु ऐसी परिस्थितियों को उत्पन्न होने से रोकने का प्रयत्न करना चाहिये जिन में उनका प्रयोग आवश्यक हो जाये; उदाहरणार्थ मंत्रियों को गवर्नर जनरत के भरोसे अपने उत्तरदायित्व में ढील नहीं करनी चाहिये।
- प्रोतीय स्वराज्य : गवर्नरों के प्रान्त पूर्ण उत्तरदायित्व के श्राधार पर निर्मित होंगे ।
- १०. विशेषाधिकार: गवर्नरों के लिये अल्पतम विशेषाधिकार रिचत होंगे जो कि अपवाद स्वडप परिस्थितियों में शान्ति स्थिर रखने के लिये या संविधान द्वारा उपबंधित मार्वजनिक नौकरियों और अल्पसंख्यकों की रचा के लिये आवश्यक हैं।
- ११. विस्तृत मताधिकार: अन्त में सम्राट की सरकार का विचार है कि प्रान्तों में उत्तरदायी सरकारों की स्थापना से यह त्रावश्यक हो जाता है कि प्रान्तीय व्यवस्थापक मंडलों को भी बढ़ाया जाये और वे अधिक विस्तृत मताधिकार पर त्राधारित हों।
- १२. राष्ट्रसभा से श्रापील : यदि इसी बीच में वे लोग जो कि असहयोग में लगे हुये हैं वायसराय के अनुरोध का उत्तर दें तो उनकी सेवाओं को स्वीकार करने के लिये कदम उठाया जायेगा।"

उपर्युक्त घोषणा ब्रिटेन की स्वाभाविक कृटनीति से परिपृर्ण है। इस का विश्लेषण क्रमशः नीचे किया जाता है:

- १. वास्तव में प्रथम पैरा में उल्लिखित उपबंध भारत की स्वतन्त्रता के लिये घातक थे। ग्रल्पसंख्यकों के रचण के बहाने मुसलमानों को विशेषा-धिकार देकर विद्वेश फेला दिया गया तथा जनतन्त्र का प्रश्न ही समाध्त कर दिया गया।
- २. हसरे पैरा का यह अर्थ है कि पूर्ण उत्तरदायिग्व तक पहुंचने के लिये यह संविधान एक सीड़ी मात्र होगा, स्वयम इस संविधान से स्वशासन प्राप्त नहीं होगा ।

- इ. तीसरे पेरे में यह संकेत था कि राष्ट्रसभा से फिर समस्तीते का प्रयक्त किया जायेगा, किन्तु पूर्ण स्वराज्य की मांग करने वाली संस्था ऐसे अधकचरे संविधान से कैसे संतुष्ट हो सकती थी। इस विषय में राष्ट्रसभा का प्रस्ताव आगे दिया जायेगा।
- ४. चौथे पैरे में देशी राज्यों तथा शेप भारत में फूट डालने का प्रयस्त है क्योंकि यदि राज्य अपनी इच्छानुसार ही विषय अपित करने के लिये स्वतन्त्र हों तो वे कदाचित कुछ भी अपित नहीं करना चाहेंगे । इस प्रकार कई स्वतन्त्र राज्य बन सकेंगे जो कि अंग्रेजों के संकतानुसार कार्य करेंगे। याद रहे यहां राज्यों के नेशों के अतिरिक्त वहां की प्रजा की सत्ता या इच्छा की कोई चर्चा भी नहीं की गई। अंग्रेजी राज्य के अन्त तक इसी कारण संघ स्थापित ही न हो सका।
- ४. पंचम पैरा संतोषजनक है किन्तु श्रगले दो पैरों से इसका महत्व भी कम हो जाता है। बास्तव में केन्द्र में ११४६ तक उत्तरदायिश्व नहीं मिला।
- ६. ब्रुटे पैरे में दो मुख्य विषय रिचत बना कर इस बार केन्द्र में द्वैध पछति स्थापित करने का विचार प्रकट किया गया है, जब कि यह पछति प्रान्तों में सफल नहीं हो पाई थी। गवर्नर जनरल के विशेषाधिकारों से मंत्रिमंडल का उत्तरदायित्व नष्ट सा हो जाता हैं।
- . ७. सप्तम पैरे हारा श्रार्थिक शक्ति बहुत मात्रा में गवर्नर जनरल को मिल गई तथा मंत्रिमंडल से वह बहुत सा रुपया उनकी इच्छा के विक्छ लेकर हस्तान्तरित विषयों के लिये कुछ न छोड़ने की समता रखता था।
- प्त. श्रष्टम पैरे से केवल संसार को भ्रम में डालने का प्रयन्न किया गया था कि भारतीय श्रयोग्य न हों इसी भय से हमने विशेषाधिकार रुवे हैं।
- ह. नवम तथा एकादश पैरे संतोषजनक थे क्योंकि प्रान्तों में द्वैंध पड़ित का अन्त कर दिया गया परन्तु दस्वें पेरे में गवर्नरों को दिये गये विशेषाधिकार सदा व्यवहार में बाधा स्वरूप रहे जैमा कि आगे के इतिहास से पता चलेगा। वास्तव में १६३४ में केवल ह से १९ तक के पैरों के मिछांत ही कार्यान्वित हुए। केन्द्रीय सरकार तो अंग्रेजी राज्य के अन्त तक १६९६ के संविधानानुसार ही कार्य करती रही।

भारत की प्रतिक्रियाः राष्ट्रसभा की कार्यकारियां के अधिकांश सदस्य तो काराग्रह में थे किन्तु जो स्वतन्त्र थे उन्होंने २१ जनवरी १६३१ को निम्न प्रस्ताव स्वीकार किया:

"भारतीय राष्ट्रसभा की कार्यकारिणी समिति तथाकथित गोलमेज सम्मेलन को कोई मान्यता देने के लिये तैयार नहीं है जो बिटिश संसद के कुछ सदस्यों, भारतीय नरेशों तथा उन व्यक्तिगत भारतीयों के बीच हुआ था जो कि सरकार ने अपने समर्थकों में से चुनेथे और जिन्हें भारतीयों के किसी दल ने अपना प्रतिनिधि नहीं चुना था। समिति का यह मत है कि बिटिश सरकार ने भारतीय प्रतिनिधियों से सम्मित लेने का, जब कि बास्तव में वह महात्मा गांधी तथा पंडित जबाहर लाल नेहरू जैसे राष्ट्र के नेताओं को जेल में डाल कर भारत की आवाज को दबाती रही है, जो आडम्बर किया है, उससे वह स्वयम निन्दनीय बन गई है।

'समिति ने बिटिश मंत्रिमंडल की योर से प्रधान मंत्री रामजे मेक्डो-नेलड द्वारा १६ जनवरी १६३१ को की गई घोषणा पर ध्यानपूर्वक विचार किया है तथा समिति की यह राय है कि वह घोषणा इतनी अग्पष्ट तथा व्यापक है कि राष्ट्रसभा की नीति में कोई परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है।

"लाहोर राष्ट्रसभा में स्वीकृत 'पूर्ण स्वतन्त्रता' के प्रस्ताव पर अटल रहते हुये यह समिति महात्मा गांधी त्रादि नेताओं द्वारा ११ अगस्त १६३० के दिन यर्बदा जेल से वायसराय को लिखित पत्र में प्रकट किये गये विचारों का समर्थन करती है तथा प्रधान मंत्री की घोषणा को उस पत्र का यथा-योग्य उत्तर नहीं समभती। समिति का विचार है कि ऐसे उत्तर की अनुप-स्थित में और जब कि सहस्रों नर-नारी, जिन में कार्यकारिणी समिति के मोलिक सदस्य भी सम्मिलित हैं, काराग्रह में हैं, हमारी नीति की ब्यापक घोषणा करना सहायक सिद्ध नहीं हो सकता।"

११. गांधी-इरविन संधि

इस प्रस्ताव को प्रकाशित नहीं किया गया किन्तु सरकार को इसका पता लगते ही वायसगय ने २४ जनवरी १६३१ को निस्त ग्राशय की घोपणा की:

"१६ जनवरी को प्रधान मंत्री द्वारा दिये गये वक्तव्य पर विचार करने के लिये अवसर देने के उद्देश्य से मेंने यह उचित समका है कि भारतीय राष्ट्रसमा की कार्यकारिणी के सदस्य परस्पर विचार विमर्श करने की पूर्ण स्वतन्त्रता पार्थे।

"मेरी सरकार उन को मुक्त करने पर कोई शर्त न लगायेगी क्योंकि हम अनुभव करते हैं कि शान्तिपूर्ण स्थिति उत्पन्न करने की आशा इसी से हो सकती है कि बातचीत निर्बाध स्वच्छन्दना के साथ हो।"

काराब्रह से मुक्त हो कर गांधी जी ने अन्य सदस्यों से बातचीत की तथा अन्त में वायसराय से मिलने की इच्छा प्रकट करते हुए एक पत्र भेजा। १७ फरवरी से गांधी-इरविन वार्ता आरम्भ हो कर १ मार्च को एक संघि हुई जिसमें अधिकतर सत्याब्रह के विषय में निर्णय किये गये थे पर कुछ बातें संविधान के विषय में भी थीं, जिनका आशय निम्न लिखित है:

"संविधान के विषय में प्रश्नों पर आगे चल कर विचार होगा, किन्तु उसके सम्बन्ध में मुख्य बातों के तय होने के लिये ये आधार होंगे :

- १. शासन का रूप संघीय होगा।
- २. केन्द्र में उत्तरदायित्व रहेगा।
- विदेशी नीति, रचा त्रादि भारत के हित की दृष्टि सं रखे जायेंगे।
- सम्प्रेलन में राष्ट्रसभा के प्रतिनिधि लिये जायेंगे।"

१२. द्वितीय गोलमेज सम्मेलन

द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में, जो ७ दिसम्बर १६३१ को श्रारम्भ हुश्रा, राष्ट्रसभा की श्रोर से एकमात्र प्रतिनिधि महात्मा गांधी गये। ब्रिटिश सरकार ने मिस्टर जिन्ना तथा श्रन्य छोटे दलों के प्रतिनिधियों को प्रांत्माहित कर साम्प्रदायिक तथा श्रन्य प्रश्नों पर खूब चौंचें लड़वाईं। श्रकेले गांधी जी से कुछ करते न बना। पग पग पर विशेषाधिकारों की मांग होने लगी श्रोर ब्रिटिश सरकार एकता के लिये श्रनुरोधात्मक भाषण देने लगी। मुसलमानों के श्रतिरिक्त दलित जातियों को हिन्दुश्रों से पृथक करने का प्रयत्न किया गया जिस पर गांधी जी ने श्रपने प्राणों को बाजी पर लगा देने की धमकी दी। श्रन्त में १ दिसम्बर को प्रधान मन्त्री मैक्डोनल्ड ने १६ जनवरी १६३१ को घोषण को हेर-केर के साथ दोहराया श्रीर उस पर चलने का श्रपना

विचार प्रकट किया तथा भारतीयों के पारम्परिक मतभेदों पर खेद प्रकट किया एवं घोपणा की कि उन में समभीता होने के बिना श्रागे बढ़ना कठिन है। गांधी जी को भारत श्राते ही फिर बंदी बना लिया गया श्रोर श्रस्थायी गांधी-इरविन समभीता समाप्त होकर संघर्ष पुनः श्रारम्भ होगया।

१३. साम्प्रदायिक पंचाट

श्रगस्त १६३२ में प्रधान मन्त्री मैक्डोनल्ड ने श्रपने 'साम्प्रदायिक पंचाट' (Commundual Award) की घोषणा की जिसके श्रनुसार मुसलमानों को ३३ई प्रतिशत स्थान देने का निर्णय किया गया तथा हरिजनों को हिन्दुश्रों से पृथक निर्वाचनवर्ग बनाने का भी निरचय हुश्रा। यह हिन्दुश्रों के लिये नाशकारी था क्योंकि श्रावादी के श्राधार पर उन को जितने स्थान मिलने चाहिये उतने नहीं मिलते थे, इसके श्रतिरक्त उन में पृष्ट डालने का प्रयत्न किया जा रहा था। गांधी जी ने हरिजन निर्णय के विरुद्ध श्रपने संकल्प के श्रनुसार २० सितंबर से श्रामरण उपवास श्रारंभ कर दिया। इसके परिणाम स्वरूप एना-संधि हुई श्रीर हरिजनों को पृथक निर्वाचनवर्ग बनाने का निर्णय बदल दिया गया, यद्यपि उन्हें श्रीधक प्रतिनिधित्व दे दिया गया। मुसलमानों के विषय में राष्ट्रसभा चुप रही, इससे उत्पीड़ित हिन्दुश्रों को श्रसंतोष हुश्रा श्रीर महामना मालवीय जी तथा श्रीयुत श्रेणे राष्ट्रसभा से पृथक होगये।

१४. तीसरा गोलमेज सम्मेलन तथा १६३५ का संविधान

तीसरा गोलमेज सम्मेलन १७ नवम्बर से २४ दिसम्बर तक हुआ। राष्ट्रसमा ने उसमें भाग नहीं लिया तथा केवल सरकार के समर्थक ही उस में गये। श्रेमेजों ने संघीय स्थापना के प्रश्न को स्थिगित करके केवल कुछ शर्तों के साथ प्रान्तीय स्वशासन देने का निर्णय किया था, इस पर श्रमिक दल के कुछ श्रमेजों ने भी श्रमहयोग किया।

तीसरे सम्मेलन के बाद भारत मन्त्री सर सेमुछल होर ने फिर ब्रिटिश नीति दोहराई जिसमें निम्न बार्से थीं :

- १. भारत एक संघ ही बनेगा।
- देशी राज्यों के साथ की गई संधियों का सम्मान किया जायेगा।
 कुल राज्यों की श्राधी जनसंख्या वाले राज्य जब सहमत हो जायेंगे तथी

संघ स्थापित होगा। (वास्तव में वे सहमत हुए ही नहीं और भारतीय संघ की स्थापना अंग्रेजी राज्य में हो ही नहीं सकी।)

- संघ तथा प्रान्तों के चेत्र सप्टतः पृथक कर दिये जायेंगे ऋथीन दोनो एक दूसरे के विषयों में हस्तचेप न करेंगे।
 - ४. मुसलमानों को ३३ दु प्रतिशत स्थान मिलेंगे।
 - सिंघ तथा उड़ीसा पृथक प्रान्त बनाये जायेंगे।
- ६. गवर्नरों तथा गवर्नर जनरल को विशेषाधिकार होंगे, पर इस लिये नहीं कि वे मिन्त्रियों के दिन प्रतिदिन के कार्य में वाधा डालें, पर केवल नियन्त्रण के लिये।
- ७. रक्ता के प्रश्न पर, जो कि रक्षित विषय होगा, निम्न व्यवस्था होगी:—
- (क) रचा के निमित्त धन की आवश्यकता होगी उसे मन्त्री रोक न सकेंगे।
- (ख) भारतीय सेना को भारत के बाहर भेजने के प्रश्न पर श्रंथ्रेजों का नियन्त्रण होगा पर संघीय सरकार को भी कुछू निर्णय करने का श्रिश्वकार दिया जा सकता है।
- (ग) भारतीय सेना के भारतीयकरण का प्रश्न संविधान द्वारा निश्चित नहीं हो सकता।

इसके अतिरिक्त अन्य पुरानी बातों को भी उन्होंने दौहराया । फिर मार्च ११३३ में ब्रिटिश सरकार ने भारतीय संवैधानिक सुधार' नामक पुस्तिका प्रकाशित की जो 'श्वेत-पत्र' के नाम से प्रसिद्ध है। इस पर विचार करनेके लिये संसद की दोनों सभाओं के १६, १६ प्रतिनिधियों की एक 'संयुक्त संसदीय सिमिति' बनाई गई जिस ने भारत के कुछ प्रतिनिधियों के साथ परामर्श करने के परचात अपनी सिफारशें दीं। इन में गवर्नरों तथा संसद के विशेषाधिकार और भी बढ़ा दिये गये। अंततोगत्वा जिम्बे कार्यक्रम के पश्चात ११३१ का भारतीय संविधान बना। इस संविधान द्वारा संसद का भारतीय शासन पर पूर्ण नियन्त्रण रहा और अधिराज्यपद तो बहुत दूर की वस्तु जान पढ़ने जिगी। प्रान्तीय स्वराज्य तथा द्वेध प्रणाली सहित संघीय शासन इसकी विशेष-तायें थीं। बर्मा तथा अदन को भारत से प्रथक कर दिया गया।

राष्ट्रसभा ने इसे 'पूर्यारूपेण श्रस्वीकार' करते हुये कहा कि "यह संविधान किसी प्रकार राष्ट्र की इच्छा का प्रतीक नहीं है श्रीर भारत की पराधानता एवं शोषण को स्थायी बनाने के लिये ही बनाया गया है।" श्रन्य संस्थाश्रों ने भी इसकी निन्दा की। श्रगले श्रध्याय में हम इस संविधान का विश्लेषण करेंगे तथा वैधानिक दृष्टि से यह १६१६ के संविधान की तुलना में कितना भिन्न था यह बतायेंगे।

१६३४ का संविधान १ अप्रेल १६३७ से लागु किया गया।

तीसरा ऋध्याय

सन् १६३५ का संविधान

१, अधारभृत विद्वान्त

पहले संविधानों से १६६४ का संविधान कई श्रंशों में सुधार हूं। था। इस की प्रांतीय स्वराज्य सम्बन्धी योजना १६६७ में लागू कर दी गई थी पर संघ स्थापन सम्बन्धी उपवंध कभी कार्यान्वित नहीं हुए।

भारत की शासन-प्रणाली में १६६१ के मंत्रियान में यह मूल परिवर्तन हुआ कि भारत में एकात्मक शासन-प्रणाली के स्थान पर संघीय प्रणाली का समावेश हुआ। १६१६ के संविधान के अन्तर्गत प्रान्तों में हुँध प्रणाली होने के उपरान्त मी ३३ वीं धारा के अन्तर्गत दंख-भाल, निदंश तथा नियन्त्रण का कार्य केन्द्रीय सरकार को दिया गया था। उसी मंत्रियान की ४१ वीं धारा के अनुमार प्रान्तीय सरकारों को यह आदेश था कि वे सपरिपद गवर्नरजनरल की आजाओं का पालन करें। प्रान्त के शासन सम्बन्ध वे सरकारें मपरिपद गवर्नर जनरल की देख-भाल, निदेश तथा नियन्त्रण में थी। यहती कार्यकारिणी के सम्बन्ध में था पर व्यवस्थापक कार्यक्ति में भी १६१६ के संविधान की ६१ वीं धारा के अनुसार केन्द्रीय व्यवस्थापकमंडल की ब्रिटिश भारत के प्रत्येक स्थान, प्रत्येक व्यक्ति तथा प्रत्येक न्यायालय के लिये कान्त बनाने का अधिकार था। किन्तु कुल विशेष विषयों पर प्रान्तों को कुल अधिकार दिये गये थे जिन पर केन्द्रीय सरकार तथा व्यवस्थापक मंडल साधारखतः हस्तकेष नहीं करते थे।

१६३५ के संविधान में दूसरी धारा के अनुसार सारे अधिकार, शक्ति तथा कार्यचेत्र जो कि १६१६ के संविधान के अन्तर्गत भारत सरकार सं

सन् १६३४ का संविधान

मंबिन्धत थे उस से वापिस लेकर पहले सम्राट में केन्द्रित कर दिय गये श्रीर तरपश्चात सम्राटने उन्हें केन्द्रीय श्रीर प्रान्तीय सरकारों में वितरित कर दिया। इस प्रकार प्रान्तों की सन्ता का खोत भारतीय सरकार नहीं रही श्रतः दोनों का कार्यचेत्र सहयोगियों का सा बन गया। केन्द्र तथा प्रान्तों के बीच, या दो प्रांतों के बीच पारस्परिक संघर्ष होने पर न्यायालयों को ही संविधानके श्रनुसार इसका निर्णय करना होता तथा श्रन्त में १६३१ के संविधान द्वारा स्थापित संघीय न्यायालय का निर्णय लागू होता। १६१६ के संविधान के श्रन्तर्गत तो प्रान्त केन्द्रीय सरकार के नियन्त्रण से वाध्य थे श्रीर कार्यचेत्र विषयक कोई भी विवाद होने पर केन्द्रीय सरकार ही श्रन्तिम निर्णय करने की चमता रखती थी।

किन्तु १६३१ कं संविधान में यह उपबंध था कि संकट में केन्द्रीय सरकार ग्रोर केन्द्रीय व्यवस्थापकमंडल को प्रान्तों पर सर्वोच्चसत्ता होगी श्रर्थात उस समय संवीय ढांचा स्थगित हो जाता। द्वितीय महायुद्ध में इसी उपबंध के श्रन्तर्गत प्रान्तीय स्वराज्य की इतिश्री कर दी गई थी। इस संविधान में यह भी उपबंध था कि जब प्रान्तीय स्वराज्य श्रसफल होने के कारण प्रान्त का शासन गवर्नर स्वयम् संभाल लं तव वह गवर्नर जनरल के द्वारा केन्द्र के सीधे नियन्त्रण में हो जायेगा यह परिस्थित तवडःपन्न हुई थी जब कि राष्ट्र-सभा ने बहुमत में होते हुए भी प्रान्तों में मंत्रिमंडल बनाने से इंकार कर दिया था।

एक बात स्पष्ट समम लेनी चाहिये कि भारतीय सरकार की जो मंबीय रूपरेखा संविधान में उपविधान थी वह कभी कार्यान्वित नहीं हुई तथा वास्तव में केन्द्र की सरकार, श्रंभेजी राज्यके अन्त तक, १६१६ के संविधान के अन्तर्गत ही कार्य करती रही और मपरिषद् गवर्नर जनरल ही केन्द्र का शासन चलाता रहा । केवल भानतीय स्वराज्य से केन्द्र की उन विषयों में सत्ता मिट गई जो कि प्रांतों को मिल गये थे। प्रांतों तथा केन्द्र के सम्बन्धों में कुछ अन्तर आने के अतिरिक्त केन्द्राय सरकार में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। १६३५ के संविधान के द्वितीय अध्याय के अनुसार ही यह परिवर्तन संभव था और वह अध्याय अन्य अध्यायों के साथ लागू नहीं हुआ। वह सम्राट की घोषणा से लागू होना था पर देशी राज्यों के संघ में आने से आनाकानी करने के कारण तथा देश में इस अध्याय का विरोध होने के कारण एवं युद्ध के कारण सम्राट ने यह बोषणा कभी नहीं की। १६३५ के संविधान के

१३ वें अध्याय के 'परिवर्तन काल के लिशे उपबंधो' के अनुसार केन्द्रीय सरकार १६१६ के समान चलतो रही। इस की शक्ति सर्वोच्च रही पर केवल केन्द्रीय विषयों तक ही सीमित रही जिन की कि सूची संविधान की ३१३ वीं धारा के अनुसार परिशिष्ट रूप में दी गई थी। 'परिवर्तन काल' १ अप्रेल १६३७ से आरम्भ हुआ था और अन्त तक चलता ही रहा।

श्रव हम १६३१ के संविधान का विस्तृत विवरण लिखेंगे क्योंकि स्वतन्त्र भारत का संविवान भी इसी संविधान का विकास है श्रौर दोनों में कई बातें मिलती जुलती हैं।

२. संघ के अंग

भारतीय संघ की जो योजना बनाई गई थी उसमें निम्न इकाइयां सम्मिलित होने का प्रस्ताव था:

प्रथम श्रेणी गवर्नेरी प्रान्त: यह संख्या में ११ थे, उन्हें विशेष विषयों में स्वशासन का ऋधिकार था। वहां जनता की सरकारें गवर्नरों के विशेषाधिकारों: के अन्तर्गत अंशतः स्वतन्त्र रूप से काम करती थीं। इनके नाम यह हैं:

		जन संख्या (लाखों में)
۹.	उत्तर-पश्चिमी सीमांप्रांत	३०
	पंजाब	२८४
₹.	सिंघ	४१
8.	बम्बई	२१०
Ł.	मदास	980
ξ.	उड़ीसा	60
9 .	बंगाल	६ ०३
۲.	बिहार	३६०
.3	मध्य प्रांत	300
80.	थुक्त प्रांत	**0
99.	त्र्यासाम	909

लगभग २१ करोड़ ३३ लाख

सन् ११३४ का संविधान

द्वितीयश्रेणी: चीफ-किमश्नर के प्रांत:—यह संख्या में ६ थे। ये छोटे छोटे राज्य थे श्रीर इन में कोई स्वशासन नहीं था। इनका प्रश्नन्ध केन्द्रीय सरकार करती इ थी। नके नाम यह :—

- १, दिल्ली
- २. ग्रजमेर-मेरवाडा
- ३. कुर्ग
- ४. पंथ-पिप्लोदा
- ४. श्रंदेमान हीपसमृह
- ६. ब्रिटिश बलूचिस्तान

तृतीय श्रेगी: देशी राज्य:—वे आन्तरिक मामलों में स्वतन्त्र थे। अंग्रेजों से संधियों के आधार पर वे विदेशी नीति और सेना आदि पर सम्राट का नियन्त्रण मानते थे। १६३७ तक सम्राट की ओर से सप-रिषद् गवर्नर जनरल उनकी ओर से इन विषयों का प्रबन्ध करता था। १६३४ के संविधान के अनुसार इनका सम्बन्ध "सम्राट-प्रतिनिधि" से कर दिया गया था जो पद गवर्नर जनरल के पद पर आसीन व्यक्ति को ही मिलता रहा। संबीय योजना के अनुसार इन राज्यों की संधीय सरकार से और नई संधियां होना आवश्यक था जिन के द्वारा वे संघ में सम्मिलित हो सकें। वे कुछ विषयों के अतिरिक्त शेष संधीय विषयों में से जो विषय चाहें संधि द्वारा संघ को अपिंत कर सकते थे। अर्थात भिन्न-भिन्न विषय संघ को दे सकते थे।

देशी राज्य संख्या में तो ४६२ थे पर उनकी कुल जनसंख्या भारत की जनसंख्या की चौथाई थी। वहां नरेशों का निरंकुश शासन था। श्रीर संविधानों या जनतन्त्र का नाम भी न था। संधियों के श्रनुसार इन राज्यों की तीन श्रेणियां 'श्र' 'ब' श्रीर 'ज' थीं । कुछ तो राज्य इतने छोटे थे कि उन्हें कइयों को मिला कर जनसंख्या के श्राधार पर केन्द्रीय व्यवस्थापिका सभा में एक प्रतिनिधि भेजने का श्रिधकार मिला था। बड़े बड़े राज्य निम्नलिखित थे :--

नाम	लाखों में जन-संख्या	स्वतंत्र भारत में उनकाकिस राज्य में विजय हुन्रा।
१. देद राबा द २. मैसूर	१६३-३ ७३-२	
 श्रावनकोर जनमू श्रोर काशमीर 	€0∙ ⊌	श्रांवनकोर-कोचीन
४. जन्मू आर कार मार ४. ग्वाजियर	४० <i>-२</i> ४०-०	मध्य भारत
६. जयपुर ७. बङ्गेदा	३० . ४	राजस्थान वस्बई
≍. जोधपुर ६. पटियाला	२ <i>४.४</i> १६.३	राजस्थान पटियाला तथा पुर्वी
	3 & • ₹	पंजाब राज्य-मंध राजस्थान
१० उदयपुर ११ रोवा	१≒∙२	विंध्य प्रदेश
१२. इन्दौर १३∙ कोचीन	9 ₹ ∙ 9 9 8 ∙ ₹	मध्य भारत त्रांवनकोर-कोचीन
१४: बहावजपुर	33.8	पाकिस्तान
१४ बीकानेर १६ कोल्हापुर	3 2 · 8 3 0 · 8	राजस्थान बम्बई
१७ मयूरभंज	3.3	उड़ीसा राजस्थान
१८- श्रलवर १६- भोपाल	म∙२ ७•म	केन्द्र शासित राज्य
२० कोटा	9.9	राजस्थान

जोड़ ६ करोड़ १६ लाख

बाकी राज्य बहुत छोटे थे, पर अङ्चन वे भी डाल सकते थे। उनकी कुल जनसंख्या ३ करोड़ के लगभग थी। संघ स्थापन के लिये यह श्रावरयक शर्त थी कि आधी जनसंख्या वाजे राज्य अर्थात् साढ़े चार करोड़ जन संख्या के राज्य संघ में सम्मिलित हों। वास्तव में यह शर्त प्री न होने के कारण संघ स्थापित ही नहीं हो सका था।

सन् ११३४ का सँविधान

३. संघीय योजना की असफलता के कारण

१६३४ के संविधान में श्रिस्तावित संघ में कई दोष थे जिनके कारण उसका विरोध हुन्ना । साधारणतः संसार के श्रन्य संघ, जिन में श्रमरीकी संघ मुख्य है, इस प्रकार बने हैं कि कुछ बराबर सत्ता वाले स्वतन्त्र या स्वशासित राज्य अपनी इच्छा से अपनी कुछ सत्ता, जो सारे राज्यों के लिये एक सी होती है. एक संधि या संधियों द्वारा संघ को ऋर्पित कर देते हैं। किन्त भारत में ऐसी स्थिति थी कि देशी राज्य तो स्वतन्त्र थे जो कि भिनन भिन्न मात्रा तक अपनी सत्ता छोड्ने को तैयार थे, बराबर मात्रा में नहीं, श्रीर प्रान्त बेचारे किसी प्रकार देशी राज्यों से कोई संधि करने के लिये स्वतन्त्र न थे, प्रत्युत उनसे सम्राट मनचाही सत्ता छीन कर संघ को दे सकता था। दूसरी बात स्वतन्त्र देशी राज्यों, स्वशासन वाले ११ प्रान्तों श्रीर संघ के श्राधीन छः प्रान्तों में बराबरी कैसी, श्रतः यह संघ एक भानमती का कुनवा ही बनता । संघ के नियम भिन्न भिन्न मात्रा में भिन्न-भिन्न इकाईयों में चलते तथा भिन्न भिन्न प्रकार से शासन होता । तीसरी बात जनतन्त्र द्वारा शासित प्रान्तों का एकतन्त्र प्रणाली वाले प्ररातन राज्यों से निर्वाह होना किटन था । दोनों के शासकों में मनोवृति का ही अन्तर होता। राज्यों के नरेश प्रान्तों के जनतन्त्र का विरोध करते तथा प्रान्त राज्यों के एकाधिपत्य का ।

पाठकों को आगे चल कर विदित होगा कि यही कठिनाइयां एक पग पर भारत के स्वतन्त्र होने के समय पड़ी थीं। पर भारत के रियासती विभाग के मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बड़ी योग्यता से साम, दाम, दंड, भेद की नीति काम में लेकर सारे नरेशों को भारत में सम्मिलित कर लिया तथा बाद में छोटे छोटे राज्यों को या तो प्रान्तों में विलीन कर दिया या कई राज्यों के संघ बना दिये। बड़े बड़े राज्य संघों के नाम यह हैं, मध्य भारत, विंध्य, राजस्थान, सौराष्ट्र, पूर्वी-पंजाब राज्यसंघ।

इसके अतिरिक्त देशी राज्यों या राज्य संघों में जनतन्त्र प्रणाली लागू करवा कर निरंकुशता का अन्त कर दिया गया। राज्यों की समस्या का इसके अतिरिक्त कोई हल नहीं हो सकता था पर अंग्रेजी राज्य में यह मार्ग अपनाना कठिन था अतः संघ शासन योजना ११३७ में सफल न हो सकी। अभी उस के पूरा होने में १० वर्ष की कमी थी।

४. ब्रिटेन का नियन्त्रण

थ. संसद् की सत्ता: पहले के अन्य संविधानों के समान १९३४ का

संविधान ब्रिटिश संसद द्वारा निर्मित था अर्थात संसद ही सारी शक्ति का स्रोत थी एवं उसका अंकुश भारत मन्त्री के द्वारा भारत पर रहता था। संसद द्वारा निर्मित संविधान के अनुसार गवर्नर और गवर्नर जनरल भारत का शासन करते थे पर उनकी शक्तियां भी सीमित थी। उनको भारत मंत्री संसद से पूछ कर कुछ 'अनुदेश पत्र' देता था जो कि संविधान का भाग नहीं थे और उनको संविधान नहीं कहा जा सकता था। किन्तु उन में इस बात के निदेश थे कि संविधान का कार्य कैसे चलाया जाए और गवर्नर जनरल तथा गवर्नरों को किस भावना से शासन करना चाहिए। यदि उन 'अनुदेश पत्रों' को न माना जाता तो भारत मन्त्री चाहे अप्रसन्न हो जाये परन्तु भारतीय जनता कुछ न कह सकती थी। संविधान में समाविष्ट होने पर भी अनुदेश पत्रों का वैध मूल्य न था।

इस के अतिरिक्त संसद की अनुमित से राज-आज्ञायें भी लागू की जा सकतीं थीं जो संविधान में परिवर्तन कर सकती थीं। अर्थात् भारत के संविधान को समयानुकूल बनाने की शक्ति भी संसद में थी और भारतीयों को कोई स्वराज्य नहीं मिला था। संसद के किसी अधिनियम के विरुद्ध जो कि भारत पर लागू हो कोई अधिनियम बनाने का संघीय और प्रांतीय व्यवस्था-पक मंडलों को वर्जन था क्योंकि संसद सर्वोच्च सत्ताधारी थी तथा भारतीय संस्थायें उसकी 'सृष्टि' थीं।

व. सम्राट की सत्ता: सम्राट की शक्ति, संसद द्वारा नियन्त्रित होने के श्रतिरिक्त असीमित थी। भारत का शासन उसी के नाम से होता था। देशी राज्यों पर भी वह श्रपने प्रतिनिधि के द्वारा राज्य करता था। जैसा कि पहले कहा जा चुका है सम्राट ने ही प्रांतों तथा केन्द्र को शक्तियां वितरित की थीं। सम्राट के कुछ मौलिक श्रधिकार होते हैं जो उसकी श्रोर से प्रयुक्त होते थे जैसे कि चमा दान, उपाधि दान, सर्वभूमि पर श्रधिकार, निरुत्तराधिकारी की मृत्यु पर उसकी सम्पत्ति पर श्रधिकार, श्रादि। इसके श्रतिरिक्त उसे संविधान द्वारा कई श्रधिकार मिले हुए थे यथा गवर्नर जनरल, गवर्नरों, सम्राट-प्रतिनिधि, प्रधान सेनापति, उच्च न्यायाधीशों श्रादि की नियुक्ति करने की चमता, भारत के प्रांतीय या केदीय व्यवस्थापक मगडलों द्वारा निर्मित श्रथवा गवर्नर या गवर्नर जनरल द्वारा स्वीकृत किसी श्रधिनियम को एक वर्ष में रह करने का श्रधिकार तथा देशी राज्यों के विषय में पूर्ण श्रधिकार, संबीय योजना को लाग करने का श्रधिकार (जो उसने क्रभी काम में नहीं लिया).

सन् ११३४ का संविधान

सैनिक श्रफसरों को नियुक्त करने का श्रधिकार, उच्च न्यायालय स्थापित करने का श्रधिकार श्रादि, श्रर्थात् शासन की रूपरेखा बनाना तथा उस का नियन्त्रण दोनों सम्राट के द्वारा संसद के हाथ में था।

ज, भारत मंत्री के ऋधिकार : सम्राट तो वेधानिक सम्राट होने के कारण उसका नाम तथा हस्ताचर ही चलते थे। वास्तिविक भारत-सम्राट तो भारत-मन्त्री था जो संसद का प्रतिनिधि था और ब्रिटिश मन्त्रिमण्डल का सदस्य होता था। वह गवर्नर जनरल आदि को आज्ञायें भेज कर द हजार मील से भारत पर नियन्त्रण रखता था। उसके मसे १२ परामर्शदाता होते थे जिनमें से आधे भारत में दस वर्ष सरकारी कार्य का अनुभव रखने वाले अफसर होते थे। संव स्थापित होने पर उनकी संख्या द से ३ कर देने का उपबंध था जो लागू नहीं हुआ। १६३७ से भारत मन्त्री और उस के बड़े भारी कार्यालय का आर्थिक भार संसद ने अपने ऊपर ले लिया था।

भारत मन्त्री को गवर्न र जनरल श्रीर उसके द्वारा गवर्न रों पर नियंत्रण तथा श्रंकुश रखने के श्रधिकार थे। वह सम्राट का भारत के विषय में परामर्श- दाता था। वह गवर्न र जनरल श्रादि को श्रनुदेश पत्र तथा राज-श्राज्ञायें भेजता था। गवर्नर जनरल उस को भारतीय शासन के रत्ती रत्ती समाचार देता था। भारत मन्त्री ही भारत में बड़े बड़े श्रफसरों की नियुक्तियां श्रादि करता था श्रीर यहां के प्रांतीय मंत्रियों को इस विषय में कोई श्रधिकार न था। भारत के श्रफसर कठपुतलीमात्र थे जिनकी डोरियां भारत मन्त्रों के हाथ में थीं।

५. ब्रिटेन में उच्चायुक्त

भारत को स्वतन्त्रता देने के आडम्बर के साथ साथ ११३४ के संविधान में यह भी आदेश था कि गवर्नर जनरल भारत की ओर से एक उच्च आयुक्त ब्रिटेन में नियुक्त करेगा। वास्तव में यह राजदूत के पद के समान आडम्बर रचा गया था पर वास्तव में वह ज्यापार दूत का कार्य करता रहा और भारतीय ज्यापार विभाग के ही नियन्ए में रहा। एक प्रकार से भारत मन्त्री के शीश पर जो निरर्थक कार्य का भार था वह उच्च आयुक्त को सौंप दिया गया।

६. गवर्नर जनरल: परिवर्तन काल में

केन्द्रीय शासन सूत्र का सूत्रधार गवर्नर जनरल होता था। १६३७ के पहले वह सारे भारत पर राज्य करता था। १६३४ के संविधान के अनुसार उसका कार्यचेत्र ब्रिटिश भारत तक ही सीमित कर दिया गया क्यों कि देशी नरेशों पर राज्य करने का कार्य सम्राट-प्रतिनिधि का हो गया। वास्तव में एक ही ज्यक्ति गवर्नर जनरल और सम्राट-प्रतिनिधि दोनों पदों पर श्रासीन कर दिया जाता था। जनसाधारण की बोली में उसे वायसराय कहते थे। संविधान में वाइसराय शब्द कहीं प्रयुक्त नहीं हुआ। परिवर्तन काल होने के कारण १६१६ के संविधान के अनुसार सारा कार्य सपरिषद् गवर्नर जनरल करता था श्रीर वही केन्द्रीय सरकार था। उस की परिषद् के सदस्यों को सम्राट मियुक्त करता था। साधारणतः गवर्नर जनरल अपनी परिषद् के बहुमत के निर्णय से वाध्य था पर विशेषावस्था में जब कि भारत की शान्ति, सरचा आदि पर उसके विचार के अनुसार विशेष प्रभाव पड़ता हो तो वह बहुमत के विरुद्ध जा सकता था।

इस के अतिरिक्त वह धारा ७२ के अनुसार ६ मास के लिये विशेष अधिनियम भी बना सकता था अर्थात परिमित समय के लिये वह ब्यवस्था-पक-मन्डल का कार्य कर सकता था। युद्ध काल में उसे सारे युद्ध काल और तत्परचात एक वर्ष तक के लिये नये अधिनियम बनाने का अधिकार मिल गया उधर व्यवस्थापक मंडल द्वारा स्वीकृत कोई भी प्रस्ताव गवर्नर-जनरल की स्वीकृति के बिना अधिनियम नहीं बन सकता था और उसे स्वीकृति न देने का एवं सम्राट की स्वीकृति के लिये प्रस्ताव को रोकने का भी अधिकार था। सम्राट तो गवर्नर जरनल की स्वीकृति के बाद भी अधिनियम को रद कर सकता था। गवर्नर जरनल व्यवस्थापक मंडल का सदस्य न होते हुये भी उसमें भाषण देने का अधिकारी था।

बिदेश विभाग तथा राज्य विभाग गवर्नर जनरल के अपने विभाग होते थे तथा परिषद् के किसी सदस्य के आधीन नहीं थे। इसके अतिरिक्त वह कबाइली प्रदेशों, अल्पसंख्यकों की रक्ता, ईसाई धर्म सम्बन्धी नीति, सुरक्ता, धन आदि के विषयों में विशेष शक्ति से कुछ भी कर सकता था।

केन्द्रीय कार्यपालिका के रूप में गवर्नर जनरलकी एक कार्यकारिणी परिषद् थी जिसके सदस्य सम्राट द्वारा नियक्त होते थे। धीरे धीरे इस परिषद् में ६ से

सन् १६३४ का सैविधान

बढ़ा कर १४ सदस्य कर दिये गये थे। प्रायः प्रधान सेनापित भी इसका सदस्य होता था। प्रत्येक सदस्य को एक एक सरकारी विभाग मिला हुन्ना था। जिस पर वे गवर्नर जनरल तथा परिषद् के त्रादेशानुसार नियन्त्रण करते थे। परिषद् के सदस्य व्यवस्थापक मंडल के सदस्य होते थे, उसमें बैठते, मत देते, तर्क करते, प्रश्नों का उत्तर देते त्रीर त्रपने विभाग की नीति का समर्थन करते थे किन्तु वे व्यवस्थापक मंडल के प्रति उत्तरदायी नहीं होते थे।

७. व्यवस्थापक मंडल : परिवर्तन काल में

यह १६१६ के संविधान के अनुसार ही १६३७ में चुना गया था पर गवर्नर जनरल ने अपने विशेषाधिकार से उसकी आयु १६४४ तक बढ़ाई थी। इसकी शक्ति भी १६१६ के संविधानानुसार ही सीमित रही क्योंकि सदा परिवर्तन काल ही चलता रहा। १६३४ के संविधान में तीन सूचियां थीं : जिनमें दो तो क्रमशः केन्द्रीय और प्रान्तीय व्यवस्थापक मंडलों के कार्यचेत्रों की थीं तथा तीसरी सूची के विषयों पर दोनों अधिनियम बना सकते थे। यदि व्यवस्थापक मंडल किसी शासकीय प्रस्ताव को नहीं मानता था तो गवर्नर जनरल उसे प्रमाणित कर देता था और वह प्रस्ताव अधिनियम बन जाता था।

गवर्नर जनरल : संघ योजना में

जैसा उपर लिखा जा चुका है १६३४ की संवीय योजना कार्यान्वित नहीं हो सकी थी और परिवर्तन काल में ही अंग्रेजी शासन समाप्त हो गया। किन्तु हम उस योजना का विवरण इस कारण देना चाहते हैं कि स्वतन्त्र भारत के संविधान का आधार यही योजना है। इस के अनुसार केन्द्रीय शासन में महान परिवर्तन होने थे। गवर्नर जरनल की कार्यकारिणी परिषद् के स्थान पर एक मन्त्रिपरिषद् बननी थी। मन्त्री कुछ विषयों में उसे 'मन्त्रणा तथा सहायता' देने के लिये थे। गवर्नर जनरल सम्राट की ओर से भारत का राज्य प्रबन्ध करता। सुरचा, विदेशी सम्बन्ध, ईसाई धर्म, कबाइली प्रदेशों का प्रशासन आदि विषय गर्नर जरनल के रचित विषय थे जिन में परामर्श देने के लिये वह तीन परामर्शदाता तक नियुक्त कर सकता था। अर्थात केन्द्र में हैंध पद्धित आरम्भ होनी थी। रचित विषयों के अतिरिक्त बाकी हस्तान्तरित विषय थे जिन में वह मन्त्रियों के परामर्श पर चलता परन्त

जहां उसके विशेष उत्तरदायित्वों का प्रश्न त्राता वह उसकी मन्त्रेणां की उपेसा कर सकता था। वे विशेष उत्तरदायित्व निम्न थे :

- १. भारत की शान्ति व्यवस्था के लिये कोई गम्भीर भय न हो।
- २. संघीय सरकार के आर्थिक संतुलन और सम्मान की रचा हो ।
- ३. ग्रल्पसंख्यों के विरुद्ध कोई विभेद न हो ।
- थ. भारत में खंद्रोजी ख़ौर बर्मी माल खाने के विरुद्ध प्रतिबन्ध न लगें।
- ४. देशी राज्यों के अधिकारों तथा उनके नरेशों के सम्मान की रहा।
- ६. ऋपने विशेषाधिकारों की रत्ता, ऋादि ।

गवर्नर जनरल को अपने उपर्युक्त उत्तरदायित्व पूरे करने के लिये निस्त विशेष शक्तियां भी थीं:

- वह धन पर अंकुश रखता था अर्थात अपने उत्तरदायित्वों को पूरा करने के लिये जितने धन की आवश्यकता हो उतना वह ब्यव स्थापक मंडल के विरोध करने पर भी ले सकता था।
- त्रपने विशेष उत्तरदायित्व के सम्बन्ध में व्यवस्थापक सभा या परिषद् की कार्य-प्रणाली के विषयों के नियम बना सकता था, त्रर्थात उस पर वाद विवाद को रोक सकता था या नियन्त्रित कर सकता था।
- ३. वह संघीय व्यवस्थापक मंडल को किसी प्रस्ताव श्रथवा संशोधन पर विचार या वाद विवाद करने से वर्जित कर सकता था।
- अ. वह ब्यवस्थापक मंडल द्वारा अस्वीकृत प्रस्तावों को प्रमाणित कर के अधिनियम का रूप दे सकता था।
- ४. वह छै मास के लिये विशेष अधिनियम बना सकता था।

६, मंत्रि परिषद् : संघीय

मंत्रिपरिषद् में १० से अधिक मंत्री नहीं हो सकते थे जो उसे अपने गवर्नर जनरल के व्यक्तिगत कार्यचेत्र के विषयों के अतिरिक्त बाकी विषयों में सम्मति और सहायता देते थे। मंत्री व्यवस्थापक मंडल की किसी एक सभा के सदस्य होते थे और उन्हें ६ मास तक सदस्य न बनने की अवस्था में पद से हटना पड़ता था [धारा १० (२) —१६३४]।

सन् १६३४ का संविधान

गवर्नर जनरल स्वयं श्रपनी इच्छा से मन्त्रियों को चुनता श्रौर उनकी बैठक बुलाता, उन से राजभक्ति की शपथ दिलवाता तथा जब तक उसकी इच्छा होती उन्हें पदासीन रखता: [धारा १ (१) तथा १० (१)]।

त्रनुदेश पत्र के त्रनुसार वह मन्त्रियों को ऐसे व्यक्ति से परामर्श कर के चुनता जो कि उसके विचार में व्यवस्थापक-मंडल में स्थायी बहुमत रखने में समर्थ हो तथा उन व्यक्तियों को मन्त्री नियुक्त करता जिनमें यथासम्भव देशी राज्यों त्रीर ऋल्पसंख्यकों के प्रतिनिधि भी हों श्रीर जो कि संयुक्त रूप से व्यवस्थापक मंडल का विश्वास प्राप्त करने की स्थिति में हों:

वैसे तो मन्त्री गवर्नर जनरल की इच्छानुसार ही पदासीन रह सकते थे पर साधारणतः वे तब तक श्रपने पद पर रहते जब तक कि उन्हें व्यवस्था-पक मंडल का विश्वास प्राप्त हो श्रार्थात् वे उत्तरदायी मन्त्री होते।

उनके वेतन त्रादि भी व्यवस्थापक मंडल स्वीकार करता परन्तु एक मन्त्री के पदकाल में उसका वेतन घटाया बढ़ाया नहीं जा सकता था [धारा १० (३)]।

१०, अन्य पदाधिकारी

- सम्राट एक प्रधान सेनापित भी नियुक्त करता था [धारा ४ श्रीर २३२]।
- २. गवर्नर जरनल चाहता तो मन्त्रियों से परामर्श कर के एक श्रार्थिक परामर्शदाता नियुक्त कर सकता था [धारा १४]।
- ३. गवर्नर जरनल रचित विषयों में परामर्श देने के लिये तीन परामर्श दाता भी रख सकता था पर उनके परामर्श को मानना उसके लिये श्रावश्यक न था [धारा ११ (२)]।
- ४. गवर्नर जनरल श्रपनी इच्छा श्रनुसार एक महा श्रधिवक्ता (Advocate General) रख सकता था [धारा १६]।

११. संघीय व्यवस्थापक मंडल की रूपरेखो

संवीय योजना से इस में महान परिवर्तन होना था। एक तो दोनों

सभाश्रों को बढ़ा दिया जाता, दूसरे उनमें जनता के प्रतिनिधि बढ़ जाते, तीसरे देशो राज्यों के प्रतिनिधि भी रखने का श्रायोजन था, चौथी बात संबीय ज्यवस्थापिका सभा के चुनाव सीधे जनता द्वारा न होकर प्रान्तीय धारा सभाश्रों द्वारा होने का उपबंध रखा गया था।

धारा १८ (१) के अनुसार संघीय व्यवस्थापक मंडल में निम्न अंग होते:

- १. सम्राट (जिसका प्रतीक गवर्नर जरनल था) ;
- २. राज्य-परिषद्;
- ३. संघीय व्यवस्थापिका-सभाः

१२. संघीय राज्य-परिषद्

राज्य-परिषद् में ब्रिटिश भारत के १४६ प्रतिनिधि लेने थे जिन में ६ गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत थे तथा शेष साम्प्रदायिक निर्वाचन वर्गों के आधार पर चुने जाने थे; तथा इस में श्रिहिन्दुश्रों को पासंग दिया गया था। इनका वितरण इस प्रकार होना था:

प्रान्त	कुल स्थान	जनरत (हिंदु)	हरिजन	सिख	मुसलिम	स्त्रियां	
मद्रास	२०	38	9	:	8	9	
बम्बई	98	90	9	:	8	9	
गाल	२०	5	3	:	30	8	
युक्त प्रान्त	२०	33	3	:	•	. 3	
पंजाब	१६	3	o	8	5	9	
बिहार	9 €	30	3	:	8	9	
मध्य प्रांत	5	ξ	3	:	9	:	
श्रासाम .	Ł	३	0	:	२		
सीमा प्रान्त	¥	3	0	:	8		
उड़ीसा	Ł	8	٥	:	9	:	
सिंघ	২	२	•	:	3	:	
बि॰ बलुचिस्तान	3	0	0	:	9	:	
दिल्ली	3	9	o	:	:	:	
श्रजमेर मेरवाड़ा	3	9	0	:	:	:	
कुर्ग	1	9	0	:	G. B. Calland Maddid and Carl January and Carl	•	
जोड़	180	७५	ε	8	38	Ę	

सन् १६३४ का संविधान

इसके श्रितिरक्त दो भारतीय ईसाई, ७ यूरोपियन, १ श्रोंग्ल-भारतीय तथा ६ मनोनीत सदस्य होते थे। इस प्रकार राज्य-परिषद में १४६ सदस्य होते थे। इस के श्रितिरक्त राज्य-परिषद में देशी राज्यों के प्रितिधि भी होते थे जो कि सारे राज्यों के संघ में सम्मिलित होने पर १०४ होते, श्रान्यथा कम होते।

राज्य-परिषद् एक स्थायी सदन था पर उस के एक-तिहाई सदस्य प्रति तीसरे वर्ष बदलते थे। ध्यान रहे १६१६ की राज्य-परिषद् में केवल ६० सदस्य थे पर ग्रब २६० तक हो सकते थे।

परिषद् श्रपने सभापित तथा उपसभापित को स्वयम चुनती जो कि परिषद् के सदस्य न रहने पर या त्याग पत्र देने पर या परिपद् के प्रस्ताव द्वारा श्रपने पद से हट जाते। उन के वेतन व्यवस्थापक मण्डल द्वारा निर्धारित होने थे (धारा २२)।

१३. संघीय व्यवस्थापिका-सभा

इस में संघीय योजना के अनुसार प्रांतों के २४० सदस्य तथा देशी राज्यों के १२४ तक सदस्य हो सकते थे। इसका जीवन-काल पांच वर्ष रखा गया था और १६१६ के संविधान के समान गवर्नर जनरत को इसका जीवन काल बढ़ाने का अधिकार नहीं दिया गया था किन्तु वह इस सभा को अविध से पूर्व समाप्त कर सकता था। संघीय व्यवस्थापिका सभा को भी अपने अध्यक्त और उपाध्यक्त जुनने का अधिकार था और उनके वेतन निर्धारित करने तथा उन्हें पदच्युत करने का भी अधिकार था। संघीय व्यवस्थापिका सभा के सदस्यों का निर्वाचन अप्रत्यक्त रूप से होना था अर्थात् सीधे जनता द्वारा न चुने जाकर वे जनता द्वारा निर्वाचित प्रांतीय धारा-सभाओं द्वारा चुने जाते .(स्वतन्त्र भारत के संविधान में सीधे निर्वाचन का उपबंध है तथा संघीय व्यवस्थापिका-सभा का नाम लोक-सभा रखा गया है)।

संघीय व्यवस्थापिका-सभा में निम्न प्रकार स्थानों का वितरण किया गया था। (इस बार इसमें गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत या शासकीय सदस्य न थे।):

्र प्रान्त	कुल स्थान	कुल हिन्दू		सिख	मुस्लिम	भारतीय ईसाई	यूरोपियन	आंग्ल-भारतीय	ब्यापारी	जमींदार	मजदूर	स्त्रियां
मद्रास	₹ ७	38	૪	:	5	२	9	9	?	9	3	२
बम्बई	३०	१३	2	:	, દ્	3	3	3	3	3	?	२
वंगाल	३७	30	ર	:	30	3	3	3	ર	3	२	3
युक्त प्रांत	३७	3 8	ર	:	92	٩	9	3	:	3	3	3
पंजाब	3 o	ξ	9	Ę	38	9	3	;	:	9	:	3
बिहार	३०	१६	२	:	3	3	3	:	:	3	9	3
मध्य प्रान्त	38	3	2	:	ર	:	:	:	:	3	3	9
श्रासाम	30	8	9	:	ર	3	¥	:	:	:	3	:
सीमा प्रांत•	¥	3	:	:	8	:	:	:	:	:	:	:
उड़ीसा 🔭	¥	8	9	:	3	:	:	:	:	:	:	:
सिंध	¥	3	:	:	3	:	3	:	:	:	:	:
ब्रि० बलूचिस्तान	9	:	:	:	3	:	:	:		:	:	:
दिल्ली	२	3	:	:	9	:	:	:	:	:	:	:
श्रजमेर मेरवाड़ा	3	9	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
कुर्ग	9	9	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
भ्रप्रान्तीय	૪	:	:	:	:	:	:	:	ર	:	3	:
जोइ	२४०	१०४	38	ξ	5 2	5	5	૪	33	હ	90	8

सूचनाः—हरिजनों के स्थान हिन्दुत्रों के कुल स्थानों में सम्मिलित हैं तथा श्रतिरिक्त नहीं हैं।

(पाठकों को यह विचार उत्पन्न होगा कि सभा के स्थान प्रान्तों या सम्प्रदायों की जनसंख्या के आधार पर वितरित नहीं किये गये थे अपितु अंग्रेज़ों ने अपनी सुविधा के अनुसार बांटे थे। स्वतन्त्र भारत के संविधान में इस अन्याय को दूर कर के, प्रत्येक राज्य को लोक-सभा में जनसंख्या के आधार पर ही स्थान दिए गये हैं। स्वतन्त्र संविधान में लोक-सभा का निर्वाचन प्रत्यन्त, समिसलित

सन् ११३४ का संविधान

तथा वयस्क मताधिकार के सिद्धांतों पर होगा। ये सिद्धांत १६३४ के संविधान में नहीं थे। स्वतन्त्र संविधान में पासंग (वजन) भी नहीं होगा तथा हरिजनों के त्रितिस्त किसी जाति के लिए स्थान रचण नहीं होगा।)

कोई भी व्यक्ति दोनों सदनों का सदस्य नहीं हो सकता था। यदि वह ६० दिन तक सभा की आज्ञा के बिना उसकी सारी बैठकों से अनुपस्थित होता तो वह सभा उसका स्थान रिक्त घोषित कर सकती थी।

१४. सदनों (Houses) का कार्य

च्यवस्थापक मंडल द्वारा किस प्रकार व्यवस्थापन कार्य होना था इसकी एक सांकी भी यहां दिखाना आवश्यक है। चुनाव समाप्त होने पर गवर्नर जनरल सदनों की बैठकें बुलाता था जो कि एक वर्ष में कम से कम एक वार अवश्य होनी चाहिए। जनतन्त्रवाद के अनुसार वर्ष में एक बार शासन के लिए धनराशि स्वीकृत कराने के लिए सदनों को बुलाना आवश्यक होता है; क्योंकि जनता के प्रतिनिधियों की स्वीकृति के बिना जनता से धन नहीं लिया जा सकता और धन के बिना शासन नहीं चल सकता। किन्तु १६३१ के संविधान में गवर्नर जनरल को स्वयम् धन स्वीकृत करने की शक्ति भी थी। अपने स्थान पर बैठने से पहले प्रत्येक सदस्य सम्राट के प्रति भिक्त की शपथ लेता था (स्वतन्त्र संविधान में अब संविधान के प्रति शपथ ली जाती है)। किर सभापति आदि चुने जाते थे। यदि कुल सदस्यों की संख्या के छुठे भाग सदस्य उपस्थित न हों तो बैठक स्थिगत कर दी जाती थी।

सदनों में प्रश्न पूछने, साधारण प्रस्ताव रखने तथा काम रोको प्रस्तावों के पेश करने के श्रतिरिक्त मुख्य कार्य श्रधिनियम बनाना होता है जो कि विशेषक (Bill) के रूप में किसी मन्त्री या सदन के सदस्य द्वारा प्रस्तुत होता था। धन संग्रह, धन व्यय या उधार सम्बन्धी विशेषक गवर्नर जनरल की सहमित से सर्वप्रथम व्यवस्थापिका सभा में ही प्रस्तुत होता था। शेष विधेषक दोनों में से किसी सदन में पेश हो सकते थे। एक सदन में स्वीकृत होने के बाद प्रत्येक प्रस्ताव दूसरे सदन में जाता था श्रीर वहाँ भी स्वीकृत होने पर वह गवर्नर जनरल के समन्त पेश होता था। वह सम्राट के नाम

सन् १६३४ का संविधान

कि कौन सा विषय किस सूची के अन्तर्गत आता है। वास्तव में संघीय प्रणाली का यही मूल सिद्धांत है। समवर्ती सूची के विषयों पर केन्द्र तथा प्रांत दोनों अधिनियम बना सकते थे किन्तु प्रांतीय कानून उस हद तक प्रभावशून्य होता था जिस हद तक कि यह केन्द्रीय कानून के विषरीत हो।

केन्द्रीय सूची में मुख्यतः रचा (सेना त्रादि), वैदेशिक सम्बन्ध, याता-यात, मुद्रा त्रादि विषय सन्निहित थे। पुलिस, शिचा त्रादि व्यवस्थायें प्रांतों के श्राधीन थीं।

१६. धन-प्राप्ति के साधन

संविधान में केन्द्रीय तथा प्रांतीय सरकारों के बीच धन प्राप्ति के साधनों का भी वितरण था। इस विषय में केवल दो ही सूचियां थीं। केन्द्रीय सूची में आयात-निर्यात कर, तम्बाक कर, नमक कर, कृषि-आय के अतिरिक्त अन्य आय पर कर, पूंजी तथा उत्तराधिकार पर कर, बीमा, चैंक, हुंडी आदि पर फीस, आदि विषय थे। प्रान्तीय सूची में कृषि-कर, बिकी कर, मादक तथा श्रंगार की वस्तुओं पर कर, मनोरंजन कर आदि विषय थे।

इन सूचियों के अनुसार धन प्राप्त करने पर भी कई प्रांत घाटे में रहते थे। उन्हें केन्द्र की ओर से उनके प्रदेश से प्राप्त आय-कर तथा पटसम-कर का भाग दे दिया जाता था। इस के अतिरिक्त बंगाल तथा सीमा प्रांत को आर्थिक सहायता भी देनी पड़ती थी क्योंकि वह दोनों निर्धन प्रांत थे। कभी कभी अन्य छोटे प्रांतों को भी कुछ सहायता दे दी जाती थी। इसके अतिरिक्त प्रांत केन्द्र की ओर से जो कार्य करते थे उसके लिये भी उन्हें धन दिया जाता था। १६४४-४६ में प्रांतों को ४६ करोड़ रुपये दिये गये थे जिन में से ९७ई करोड़ केवल बंगाल को मिले थे।

१७. संघीय न्यायालय

जैसा कि उपर वर्णन किया जा चुक। है केन्द्र तथा प्रांतों के व्यवस्था-पक विषयों तथा धन प्राप्ति के विषयों के सम्बन्ध में संविधान में उपबन्ध थे। ऐसी अवस्था में यह प्रश्न उठ सकता था कि यदि केन्द्र अथवा प्रान्त एक दूसरे के विषय को हुइपने की अनिधकार चेष्टा करें तथ क्या हो। कई

ऐसे भी कर लगाए जा सकते थे जिन का किसी सूची में स्पष्टतः निर्देश न था, श्रीर केन्द्र तथा प्रान्तों में यह विवाद उठ सकता था कि यह कर किस सूची के अन्तर्गत आता था। ऐसे विवादों को सुलकाने के उद्देश्य से ही सुख्यतः संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। अतः इस का सुख्य कार्य यही था कि यदि संविधान की व्याख्या के सम्बन्ध में केन्द्र का प्रांतों अथवा राज्यों से, राज्यों का प्रान्तों से, प्रान्तों के ही बीच, श्रथवा राज्यों के ही बीच कोई-विवाद हो तो संघीय न्यायालय उनक! न्याय करे तथा संविधान का ठीक अर्थ बताये। यह संघीय न्यायालय का 'प्राथमिक चेत्र' था।

किसी भी वैधानिक विषय पर गवर्नर जनरल संघीय न्यायालय की सम्मति भी मांग सकता था श्रीर सम्मति देने का न्यायालय की श्रधिकार था। यह उसका 'परामर्श सम्बन्धी कार्य-चेत्र' था।

कई बार ऐसा भी हो सकता था कि जनता में से ही कोई व्यक्ति किसी प्रान्तीय या केन्द्रीय अधिनियम का इस आधार पर विरोध करे कि वह कानून निर्भाता के कार्य चेत्र की सूची से बाहर होने के कारण अनियमित है, तो वह व्यक्ति किसी छोटे न्यायालय में अपना वाद पेश कर सकता था। ऐसे वाद की अन्तिम अपील संवीय न्यायालय को आती। यह इस न्यायालय का 'अपील सम्बन्धी कार्यनेत्र' था।

संघीय न्यायालय के पास कोई ऐसी शक्ति नहीं थी कि वह श्रपने निर्णयों को पूरा करवा सके श्रतः ११३४ के संविधान में यह उपबंध था कि श.सन का प्रत्येक श्रंग तथा प्रत्येक न्यायालय उस के निर्णय को पूरा करने में सहायता करेगा।

(सूचनाः संघीय न्यायालय के विषय में कुछ हेर फेर के साथ यही नियम स्वतन्त्र संविधान में भी हैं।)

१८. केन्द्र के अभिकर्ता (Agent) प्रान्त

संघीय सरकार अपने विषयों पर कार्य करने के लिये प्रत्येक इकाई में अपने कार्यकर्ता रखती थी पर जहाँ ऐसे कार्यकर्ता नहीं होते वहाँ वह प्रान्तीय सरकारों को इस विषय में आज्ञा भी भेज सकती थी। इस प्रकार प्रान्तीय सरकारें एक प्रकार से संघ की एजन्ट थीं जो कि संघीय विषयों में संघ की

सन १६३४ का संविधान

त्राज्ञात्रों या त्रिधिनियमों को कार्यान्वित करने का कार्य पूरा करने के लिये वाध्य थीं। ऐसे न्यायालय, जो कि ज्ञान्तीय सरकार के त्रिधिकार चेत्र में थे, संघीय त्रिधिनियमों का ऐसे ही पालन करते थे जैसे कि वे प्रान्तीय श्रिधिनियमों का करते थे।

१६. प्रान्तीय शासन

१६६४ के संविधान ने प्रान्तों का मानो अपना अस्तित्व स्थिर कर दिया था। अब वे केन्द्रीय सरकार के सर्वथा आधीन नहीं रहे थे अपित उनका अपना कार्यचेत्र बन गया था जो कि प्रान्तीय सूची के विषयों तक सीमित था। इसके अतिरिक्त प्रान्तों में कुछ अंश तक स्वराज्य मिल गया था। इसी संविधान के अन्तर्गत प्रथम बार जनता की सरकारें बनी थीं और उन्होंने मार्ग में रोड़े होते हुए भी प्रगति की और कुछ पग बहाये थे।

क. गवर्नरः जैसे कि केन्द्र में गवर्नरजरनल विशेषाधिकारों से युक्त मुख्य कार्यपालक था तथा मिन्त्रपरिषद् केवल उसको सहायता तथा परामर्श देने के लिये थी उसी प्रकार प्रान्तों में गवर्नार की श्रवस्था थी। वह भी प्रान्त का मुख्य कार्यपालक होता था श्रोर मिन्त्रपरिषद् उसको सहायता तथा परामर्श देने के हेतु थी। उसको सम्राट नियुक्त करता था श्रोर उसके निम्न विशेषाधिकार तथा विशेष उत्तरदायिख थे:

- १- वह कई विषयों में स्विविवेक से कार्य कर सकता था तथा यह भी निर्णय स्वयं ही करता था कि कौन से विषय उसके स्विविवेक के विषयों की सूची में सिन्निहित थे।
- २. मन्त्रि परिषद् भी बैठकों का सभापतित्व करना ।
- जब तक व्यवस्थापक मंडल मिन्त्रयों के वेतन नियत न करे तब तक उन्हें नियत करना।
- ४. मन्त्रियों को चुनना, उनकी बैठकें बुलाना, उनको पद्च्युत करना।
- भानत की शांति की रक्ता।
- ६. अल्पसंख्यकों के उचित अधिकारों की रचा।
- ७. देशी राज्यों तथा नरेशों की मर्यादा की रचा।

- द. महा-अधिवक्ता की नियुक्ति आदि ।
- व्यवस्थापक मंडल के सदनों की बैठकें बुलाना या उनका विघटन करना।
- १०. व्यवस्थापक मंडल में वक्तृता देना।
- ११. व्यवस्थापक मगडल की संयुक्त बैठक बुलाना।
- १२. ब्यवस्थापक मंडल द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव पर अपनी स्वीकृति देना या न देना या उसे गवर्नर जनरल की अनुमित के लिये रखना।
- १३. श्रावश्यक व्यय को खोकार करना तथा यह निर्णय करना कि कौन सा व्यय श्रावश्यक है जो कि व्यवस्थापक मंडल द्वारा खीकृत होना श्रपेचित नहीं था।
- १४. किसी प्रस्ताव को व्यवस्थापक मंडल में वाद-विवाद से रोकना।
- १४. अपने अध्यादेश या अधिनियम बनाना।
- १६. आवश्यकता पड़ने पर गवर्नर प्रान्त में संविधान का भी अन्त कर के स्वयम् सर्वेसर्वा बन सकता था। यह शक्ति प्रांतों में उस समय काम में ली गई थी जब कि कांग्रेस ने बहुमत होने पर भी मन्त्रिमण्डल तोड़ दिए और संविधान को चलाने का कोई उपाय न रहा। संविधान का अन्त होने पर गवर्नर पूर्णतः गवर्नर जनरल के आधीन हो जाते थे (धारा ६३)।
- १७. गवर्नर जनरल के एजन्ट का कार्य करना।
- १८. पृथक किए हुए प्रदेशों श्रादि के विषय में सारे श्रधिकार।
- १६. पुलिस के विषय में कई विशेषाधिकार।

गवर्नर के उपर्युक्त अधिकारों के होते हुए वेचारे मन्त्रिमण्डल की क्या शक्ति शेष रहती थी यह पाठक सोच सकते हैं।

ख. प्रांतीय मन्त्रि-परिषदें : प्रान्तीय मन्त्रिमंडल चुनने के लिए वही उपबंध थे जो कि केन्द्र के विषय में लिखे जा चुके हैं। यहां भी मन्त्री संयुक्त रूप से व्यवस्थापक मंडल के प्रथम सदन (व्यवस्थापिका सभा) के प्रति उर रदायी थे।

सन् १६३४ का संविधान

ज. प्रांतीय व्यवस्थापक मण्डल: प्रान्तीय व्यवस्थापक मण्डल में भी गवर्नर के श्रितिरिक्त जो कि सम्राट का प्रतिनिधित्व करता था एक या दो सदन होते थे। जिन प्रान्तों में दो सदन श्रर्थात व्यवस्थापिका-परिषद् तथा व्यवस्थापिका-सभा थे उनके नाम यह थे: बंगाल, मद्रास, बम्बई, युक्त प्रांत, बिहार तथा ग्रासाम। बाकी पांच प्रांतों में केवल एक ही सभा थी तथा परिषद् नहीं थी। दोनों सदनों के चुनाव सीधे जनता द्वारा होते थे पर प्रत्येक वयस्क को मत देने का श्रधिकार न था। केवल सादे तीन करोड़ व्यक्ति मतदाता थे जो कि धनी होते थे। निर्वाचन साम्प्रदायिक निर्वाचन-गणों तथा पासंग श्रादि के सिद्धांत पर होता था। प्रथम सदन पांच वर्ष के लिए चुना जाता था पर गवर्नर उसके जीवन को जल्दी भी समाप्त कर सकता था। परिषद् के एक तिहाई सदस्य प्रति तीसरे वर्ष बदलते थे। दोनों सदन श्रपने सभापति तथा उपसभापति को स्वयं चुनते थे। वे मन्त्रियों सभापति, उपसभापति, सदस्यों श्रादि के वेतन भी नियत करते थे। शेप नियम केन्द्र के समान थे। दोनों सदनों के सदस्यों के स्थान निम्न प्रकार भरे जाते थे:

प्रान्तीय व्यवस्थापिका परिषदें

प्रान्त	कुल स्थान	हिंदू	मुस्लिम		भारतीय इसाई		गवर्नर हारा
मद्रास	१४ से १६	34	<u> </u>	3	a	:	म से१०
बम्बई	२६ से ३०	२०	¥	9	:	:	
बंगाल	६३ से ६४	90	9 9	3	:	२७	६ से =
युक्त प्रान्त	४८ से ६०	३४	90	9	:	:	६ से =
विहार	२६ से ३०	3	8	9	:	35	३ से ४
श्रासाम	२१ से २२	30	Ę	२	:	:	३ से ४

<u>प्र</u> न्त	मदास	बम्बई	बंगाल	युक्त प्रांत	पंजाब	बिहार	मध्य प्रांत	श्रासाम		GIT NO	स्थाना भाव उड़ीसा
कुल स्थान	29.k	49 6 *	だなの	N N N	30%	いたい	3 2 2	u o	べ。	en o	n >
हिंदू के ब	এ ১৯	8 2 2	'n	200	oc ru	it m	พู ทู	& 6	m	& ≪	م اا
हरी स्थान	w o	ى بىر	au O	<i>N</i> 0	n	عد بح	N 0	6	••	,on	••
पिछुड़ी जातियां (कबाइली)	۰۰	۵		••	••	6	ص	po		ベ	••
) सिख		••	••	••	20 ~0	••			æu	••	••
सु स्लिम	ų Š	AU M	336	An ex	ű	eu oc	જ	AU OC	AU AN	e¢.	טא, עא,
ईस भार- तीय (и	μu	æ	N	U	40		40		40	**
ईसाई भार- यूरो- तीय पियन	AU	ρU	4.0 4.0	N	M.	N	m0	٠.	••	••	N
श्रांग्ल भारतीय	טג	N	æU	*0	40	₩	ص	••		••	••
वारी	m	6	m	,eu	مـ	œ	Æ	\$	••	ص	N
ज मीं -	in.	N	*	,cn	٨	œ	w	**	Æ	N	N
- विश्व विद्या वय	ا م	٠.	N	40	۰.0	40	40	••	••	••	••
~ %표	en	6	n	w	AU	w	N	œ	••	40	40
रित्रया हिंदू	m	ж.	,e	œ	40	N	χU	م	••	AU.	٠
थूँ या स्थाप या स्थाप	w	, صد	w	Æ	AU	٠.	••	••	••	••	۰

सन् १६३१ का संविधान

प्रान्तों में भी अधिनियम बनाने की वही प्रणाली थी जो कि केन्द्र कें इयवस्थापक मंडल के विषय में बताई जा चुकी है।

२०, सदस्यों की योग्यता आदि

वान्तीय सदनों के सदस्य बनने के लिये व्यक्ति में निम्न बातें होनी चाहियें:

- रे. यदि सभा का सदन बनना चाहे तो वह २४ वर्ष से कम न होना चाहिये।
- २. यदि परिषद् का सदस्य बनना चाहे तो वह २० वर्ष का होना चाहिये।
- ३. धन सम्बन्धी विशेष नियमों के अनुसार भी अह होना चाहिये।
- ४. किसी सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिये पर मंत्री हो सकता है।
- ४. पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिये।
- ६. चुनाव के सम्बन्ध में किसी श्रपराध में दंडित न हुआ हो श्रोर चुनाव के सम्बन्ध में कभी नियमानुसार श्रपने चुनाव व्यय का हिसाब देने में न चुका हो।
- ७. दो वर्ष से अधिक दंड न भोगा हो या उस बात को १ वर्ष हो चुके हों।

सदनों के सदस्यों के विशेषाधिकार:

- वे सदन में कही गई किसी चीज के लिये किसी न्यायालय द्वारा दंडनीय न होंगे।
- वे सदन के अधिवेशन के एक सप्ताह पहले से लेकर एक सप्ताह बाद तक किसी दिवानी मुकदमें के कारण काराग्रह में नहीं भेजे जा सकते।

२१. पृथक किये हुए प्रदेश

यह वे प्रदेश थे जिन में अधिकतर आदिमवासी बसते थे। उन निवा-सियों को आधुनिक संस्कृति के प्रभाव में लाने से एक तो उनकी आत्मीयता का हास होता है; दूसरे वे आधुनिक लोगों के शोषण का शिकार बनते हैं,

श्रतः उनको विशेषतः सांविधानिक प्रशासन से बाहर रखा गया था जिससे कि वे सीधे गवर्नरों तथा गवर्नर जनरल द्वारा शासित हों। श्रावश्यकता इस बात की थी कि उनको धीरे धीरे श्राष्ट्रनिक संस्कृति सिखाई जाती जिस से कि वे सदा वैज्ञानिकों तथा इतिहासकारों के लिये पुरातन संग्रहालय न बने रहें। (स्वतन्त्र भारत में भी इन श्रादिमवासियों के शासन के लिये विशेष उपवंध रखे गये हैं।)

२२. प्रान्तों में स्वराज्य का कार्यकाल

१६६४ के नये संविधान को भारतीयों ने पसन्द नहीं किया तथा पहली अप्रेल १६३७ को, जिस दिन से यह लागू हुआ, देश ब्यापी हड़ताल तथा विरोध प्रदर्शन हुए।

इस संविधान के श्रन्तर्गत प्रान्तीय व्यवस्थापक मंडलों के चुनावों में राष्ट्रसभा ने ११ में से ६ प्रान्तों में बहुमरा प्राप्त कर लिये तथा शेष ५ में भी पर्याप्त स्थान जीत लिये। जब राष्ट्रसभा को ६ प्रान्तों में मन्त्रिमंडल बनाने का निमन्त्रण मिला तो उसने यह शर्त रखी कि जब तक गवर्नर यह आश्वा-सन नहीं देंगे कि वे अपने विशेषाधिकारों का प्रयोग नहीं करेंगे तब तक राष्ट्-सभा मन्त्रिमंडल नहीं बनायेगी । इस पर गवर्नरों ने पहले तो अल्पमत वाले दलों के मन्त्रिमंडल बना लिये किन्तु वे तभी तक चल सकते थे जब तक कि सभात्रों के ऋधिवेशन नहीं बुलाये जावें, अतः अन्त में अप्रत्यत्त रूप से आरवा-सन दे दिये गये। राष्ट्रसभा के मन्त्रिमंडल बनने पर उन्होंने कई सुधार किये तथा अपने देल के राजनैतिक बन्दियों को छोड दिया । गवर्नरों ने प्रायः अपने श्रारवासन पूरे किये किन्तु रोड़ा प्रायः सरकारी अफसरों की श्रोर से अड़ता था । मन्त्रिगण उनके प्रहयोग के बिना अपना कार्य ठीक तरह चला नहीं सकते थे। अफसर सीधे भारत मन्त्री के थे तथा अपनी उन्नति, नियुक्ति, वेतन आदि के लिये उसी के श्राधीन थे। केवल कार्यचेत्र में वे गवर्नर या अंशतः मन्त्रियों के श्राधीन थे। इस अनुपम परिस्थिति में उन पर मन्त्रियों का पूर्तः अंक्रश नहीं था।

चतुर्थं अध्याय

सांविधानिक वार्ता

१. अवैधानिक शासन तथा असहयोग

१६६६ में विश्वयुद्ध आरम्भ होने पर गवर्नर जनरल ने प्रान्तीय मन्त्रि-मंगडलों या केन्द्रीय व्यवस्थापक मंगडल से बिना पूछे ही भारत की श्रीर से जर्म नी त्रादि के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। इस पर राष्ट्रसभा ने ग्रंपने मन्त्रि-मण्डलों से जो त्राठ प्रान्तों में स्थापित थे, त्यागपत्र दिल्वा दिये तथा गवर्नरों ने संविधान की धारा ६३ के अनुसार उन प्रान्तों में सांविधानिक शासन का अन्त कर के सारी कार्यशक्ति अपने हाथ में ले ली। उधर केन्द्र में संघीय योजना पूर्ण न होने के कारण १६१६ के संविधान के अनुसार ही कार्य चल रहा था। त्रतः भारत भर में सांविधानिक शासन समाप्त हो गया। ब्रिटिश संसद ने भी संविधान में कुछ परिवर्तन करके गवर्नर जनरल की अधिनियम बनाने की शक्ति को बढ़ा दिया। उधर मुस्लिम लीग ने १६४० से पाकिस्तान की मांग त्रारम्भ कर दी जिसका त्राराय यह था कि जिन भागों में मुस्लिम बहुमत था उनको श्रात्मनिर्णय के सिद्धान्त पर भारत से पृथक करके एक नवीन देश पाकिस्तान नाम से बना दिया जाये। यह मांग साम्प्रदायिक निर्वाचनों श्रादि का तर्कसंगत परिणाम था श्रीर श्रंग्रेजों का इसे समर्थन प्राप्त था। इस मांग ने त्रागे की भारतीय राजनीति पर बड़ा प्रभाव डाला।

२. क्रिप्स योजना

१६४२ के श्रारमें में भारत की परिस्थिति बडी विषम थी। उधर जापान हमारे द्वारे पर था. इंधर सरकार और जनता में श्रसहयोग था। राष्ट्र सभा ब्रिटेन का इस शर्त पर साथ देने को उद्यत थी कि वह भारत को पूर्ण स्वतन्त्रता दे दे या युद्धोपरान्त देने की घोषणा करें तथा अवैधानिक शासन को समाप्त करे। ब्रिंटिश मन्त्रिमएडल ने अपना एक प्रतिनिधि सर रंटेफोर्ड किप्त भारत भेजा जिसने राजनीतिक दुलों के समन्न कुछ प्रस्ताव रखे। इनके श्रनुसार युद्ध के पश्चात भारत में साम्प्रदायिक निर्वाचन के श्राधार पर ही एक संविधान सभा चुनी जानी थी जो भारत संघ का संविधान बनाती। इसमें प्रत्येक प्रान्त ग्रौर देशी राज्य को यह स्वतन्त्रता थी कि वह उस भारत-संघ में मिले या ने मिले। इसका आशय भारत के ४६२ देशी राज्यों तथा कर्छ मिस्लिम प्रान्तों को भारत से पृथक होने का अधिकार देना था जिससे कि देश की एकता तथा शक्ति छिन्न भिन्न हो जाये। यह एक धूर्त चाल थी श्रीर घातक प्रस्ताव थे . सलमानों को इससे पाकिस्तान ही नहीं पर उससे भी श्रधिक मिलता क्योंक े न्याय से केवल सिंध तथा सीमा प्रान्त में ही बहमत में थे। उधर बंगाल और रंजाब में ऐसी अवस्था थी कि पूर्वी बंगाल तथा पश्चिमी पंजाब में हिन्दू बहुमत था पर पूर्ण प्रान्तों को साथ लेने पर पंजाब तथा बंगाल दोनों ान्त थोड़े थोड़े बहुमतों श्रीर साम्प्रदायिक निर्वाचनों के कारण पाकिस्तान में जा सकते थे। मुस्लिम लीग भी यही चाहती थी पर इससे राष्ट्र के हित के साथ घोर अन्याय होता तथा देश का नाश ही जाता ।

देशी राज्यों के विषय में सदा यही समस्या रही थी कि उनकी जनता भारत में मिलना चाहती थी और जनतन्त्रवाद के लिये श्रान्दोलन कर रही थी किन्तु निरंकुश नरेश १६३४ की संघीय योजना में सम्मिलित नहीं होते थे श्रीर श्रं प्रेजों के संकेत पर चलते थे। प्रस्तावित संविधान सभा में प्रान्तों के निर्वाचित प्रतिनिधि श्रात, पर देशी राज्यों की जनता के प्रतिनिधियों के स्थान पर नरेशों के मनोनीत प्रतिनिधि श्राते जो कि प्रगति में रोडा श्रटकाते तथा संघ योजना को श्रसफल बनाते। इन कारणों से श्रीर कई श्रन्य किमयों के कारण किप्स योजना भारत को श्रस्वीकार्य थी। किप्स श्रपनी योजना को लेकर लीट गया पर भारत में विद्रोह की भावना भड़क उठी। प श्रगस्त १६४२ की

राष्ट्रसभा के सारे नेता पकड़ लिये गये और आगामी मासों में भारत भर में विद्रोह तथा दमन का चक्र चला।

क्रिप्स लीला से एक ही लाभ हुआ कि ब्रिटेन ने आगामी संविधान भारतीयों की निर्वाचित संविधान सभा द्वारा बनवाने का सिद्धान्त मान लिया, किन्तु वह अधिराज्यपद से अधिक कुछ भी देने के लिये तैयार न था। उधर राष्ट्रसभा पूर्ण स्वतन्त्रता मांग रही थी।

३. वेवल प्रयास : राष्ट्रीय सरकार का प्रश्न

युद्ध के अन्त में १४ जून १६४४ को राष्ट्रसभा के नेता छोड़ दिये गये श्रीर वायसराय लार्ड देवल ने शिमला में एक सम्मेलन किया जिसमें राष्ट्रसभा तथा मुस्लिम लीग के नेताओं को श्रामन्त्रित किया। उस सम्मेलन में केन्द्र में एक राष्ट्रीय सरकार बनाने के प्रश्न पर विचार किया गया जिसलें लीग तथा राष्ट्र सभा के बराबर प्रतिनिधि एवं कुछ ग्रन्य जातियों के प्रतिनिधि लेने का प्रस्ताव था। यह बहुत श्रनुचित तो था ही क्योंकि मुस्लिम जनसंख्या में १।४ हैं, श्रतः उन्हें ३।४ अमुस्लिमों के बराबर प्रतिनिधित्व देना अन्याय था। इसके श्रतिरिक्त राष्ट्रसभायह दावा करती थी कि वह हिन्दू, मुसलमान, सिख, पारसी. ईसाई सबकी प्रतिनिधि है अतः वह अपने प्रतिनिधियों में सबको रखना चाहती थी। यद्यपि राष्ट्रसभा साम्प्रदायिक दल नहीं थी फिर भी राष्ट्रसभा उपय क अनुचित शर्त भी मान ही गई, किन्तु लीग इस से भी संतुष्ठ नहीं हुई। वह वास्तव में अपने आप को मुसलमानों की एकमात्र प्रतिनिधि और राष्ट्रसभा को हिन्दू संस्था सिद्ध करना चाहती थी, अतः उस ने यह शर्त रख दी कि राष्ट्रसभा अपने प्रतिनिधियों में कोई मुसलमान न रखे। राष्ट्रसभा ने अपने प्रतिनिधियों में एक राष्ट्रीय मुस्लिम की रखना चाहा पर लीगने उसे न माना श्रीर इस पर सारी वार्ता भंग हो गई। साम्प्रदायिक विशेषाधिकारों की नीति श्रव पराकाष्ठा तक पहुंच गई थी।

४. नये निर्वाचन

श्रव यह देखने के लिये कि राष्ट्रसभा तथा लीग में से कौन किस की प्रतिनिधि है, प्रान्तीय सभाश्रों के निर्वाचनों की श्राज्ञा दी गई। यद्यपि यह निर्वाचन दस वर्ष पश्चात हुए थे पर परिणाम वही रहा । क्यों कि

साम्प्रदायिक मताधिकार था त्रतः लीग को पाकिस्तान के नाम पर त्रिधिकांश मुस्लिम स्थान मिल गये। उधर राष्ट्रसभा को कुछ मुस्लिम स्थान तथा लगभग सारे हिन्दु स्थान मिल गये।

प्र ब्रिटेन में श्रम सरकार की स्थापना तथा भारत को स्वतन्त्रता का वचन

ह्थर भारत में चुनाव हुए पर उस से श्रिधक महत्वपूर्ण चुनाव ब्रिटेन में हुए जिनके फलस्वरूप वहां रूढिवादी दल के स्थान पर श्रमदल की सरकार बन गई। इस सरकार की नीति भारत के प्रति उदार थी श्रीर श्रन्तराष्ट्रीय पिरिध्यितयों ने भी उसे वाध्य कर दिया कि वह श्रब साम्राज्य का मोह त्याग दे। सर्वप्रथम श्रम सरकार ने संसद का एक शिष्ट मण्डल भारत की पिरिध्यितयों का श्रध्ययन करने के लिये भेजा श्रीर उसके यह रिपोर्ट देने पर कि भारत में स्वातन्त्र्य के भाव पूर्णतः जागृत हो चुके हैं प्रधान मन्त्री एटली ने लार्ड पैथिक लारंस, सर स्टेकोर्ड क्रिप्स तथा सर एलक्जेंडर के एक प्रतिनिधि मण्डल को भारतीय दलों से वार्ता करने के लिये भारत भेजने की घोषणा की। उन्हें पर्याक्ष श्रिधकार प्राप्त थे। प्रधान मन्त्री ने १४ मार्च १६४४ की ऐतिहासिक घोषणा में कहा था कि:

"मेरे सहयोगी भारत को यथासम्भव शीघातिशीघ पूर्णतः स्वतन्त्रता प्राप्त करने के कार्य में सहायता करने के निमित्त अपना अधिकाधिक प्रयत्न करने की इच्छा से भारत जा रहे हैं। वर्तमान शासन के स्थान पर किस प्रकार का शासन बने, यह तो भारत को ही निर्णय करना है, किन्तु उसके यह निर्णय करने के लिये व्यवस्था स्थापित करने में सहायता देना ही हमारी आकांता है।

"मुक्ते आशा है कि भारतवासी ब्रिटिश राष्ट्र मण्डल में ही रहने का निर्णय करेंगे। मुक्ते विश्वास है कि उन्हें इसमें बहुत लाभ दिखेगा।... किन्तु यदि भारत इस प्रकार का निश्चय करे थी वह अपनी खतन्त्र इच्छा से ही करेगा। ब्रिटिश राष्ट्र मण्डल तथा साम्राज्य वाह्य दवाब की श्रंखलाओं से जुड़ा हुआ नहीं हैं। यदि वह स्वतन्त्र रहने का भी निर्णय करे तो इमारे विचार में उसे ऐसा करने का अधिकार है। इमारा यह कार्य होगा कि

साविधानिक वाती

हम उस परिवर्तन को यथासम्भव साध्य तथा संघर्षरहित बनाने में सहायता हैं।"

६. मंत्री प्रतिनिधि मंडल का प्रथम सुकाव

उपर्यु क्त शब्दों में सचाई थी। भारत में श्राकर प्रतिनिधि मगडल ने पहले तो सारे राजनैतिक दलों तथा व्यक्तियों के विचार सुने। फिर यह निश्चय किया कि शिमला में एक सम्मेलन किया जाये जिस में यह सब सिद्धान्त विचारार्थ रखने का संकेत थाः

"ब्रिटिश भारत का भावी सांविधानिक ढांचा इस प्रकार का हो :

क. संघीय सरकार निम्न विषयों को संभाले : सुरत्ता, विदेशी नीति तथा संचार (Communication)।

ख प्रान्तों के दो वर्ग हों, एक तो मुख्यतः मुश्लिम प्रान्तों का श्रीर दूसरा मुख्यतः हिन्दू प्रान्तों का, जो ऐसे श्रन्य विषयों को संभालें जो कि उस वर्ग के प्रान्त सम्मलित रूप से रखना चाहें। बाकी बिषय प्रान्तीय सरकारें संभालें तथा उनको शेष सार्वभीम श्रधिकार प्राप्त हों।

ग यह विचार है कि देशी राज्य इस ढाँचे में उनसे तय होने वाली शर्तों पर उचित स्थान पायेंगे।"

२८ श्रप्रेल १६४६ को राष्ट्र सभा के तत्कालीन प्रधान मौलाना श्राजाद ने लार्ड पैथिक लौरेंस को यह उत्तर दिया:

"में आपके २७ अप्रेल के पत्र के लिये धन्यवाद देता हूँ। मैंने राष्ट्रसभा की कार्यकारिणी के अपने सहयोगों से आप के प्रस्तावों के विषय में विचार विमर्श किया है और उन्होंने मुभे आपको यह सूचित करने के लिये कहा है कि वे भारत के भविष्य के विषय में मुस्लिम लीग या किसी अन्य संस्था से, किसी भी बात पर, पूर्णतः विचार करने के लिये सदा तैयार हैं। किन्तु मैं यह कहना आवश्यक समभता हूँ कि जिन मूल सिद्धान्तों की आपने चर्चा की है उन पर कुछ स्पष्टीकरण तथा ज्याख्या की आवश्यकता है जिससे कि समभने में कोई ब्रिट न हो।

"जैसा त्राप को विदित है हमने स्वशासित इकाइयों के एक संघ की योजना स्वीकार की है। यह त्रावश्यक है कि ऐसा संघ कुछ त्रावश्यक विषयों को संभाले जिनमें सुरचा त्रोर तत्संबन्धी विषय त्रधिक महत्वपूर्ण हैं। यह संघ जीवित होना चाहिये तथा इसके पास कार्यपालिका त्रीर व्यवस्थापिका की व्यवस्था होनी चाहिये। इन विषयों के लिये धन चाहिये एवं उसे त्रपने त्रधिकार से यह धन संग्रह करने की भी शक्ति होनी चाहिये। इन शक्तियों त्रीर कार्यों के बिना यह निर्वल तथा त्रसंगुक्त होगा जिससे सुरचा त्रीर प्रगति को हानि होगी। त्रतः विदेश विभाग, सुरचा तथा संचार के त्रविरिक्त यह भी विषय होने चाहिये: धन, मुद्रा, त्रायात-निर्यात तथा ऐसे विषय जो ध्यान से सोचने पर इन से घनिष्ट रूप में सम्बन्धित पाये जायें।

''श्राप का मुख्यतः हिन्दू तथा मुख्यतः मुस्लिम प्रान्तों का उल्लेख स्पष्ट नहीं है। मुख्यतः मुस्लिम प्रान्त तो केवल सीमाप्रान्त, सिन्ध तथा बल्चिस्तान ही हैं। बगाल श्रीर पंजाब में मुसलमानों का केवल बहुमत है। हम संघ के श्रन्तर्गत प्रांतों के वर्ग बनाना बुरा समक्तते हैं विशेषतः धार्मिक या साम्प्रदायिक श्राधार पर। यह भी दिखता है कि श्रापने किसी वर्ग विशेष में सिम्मिलित होने या न होने के विषय में कोई स्वतन्त्रता नहीं दी है। यह जरा भी श्रावश्यक नहीं है कि कोई प्रान्त किसी वर्ग विशेष में मिलना चाहे। किसी श्रवस्था में यह सर्वथा गलत होगा कि किसी प्रान्त को श्रपनी इच्छा के विरुद्ध चलने के लिये बाध्य किया जाये। यद्यपि हम इस बात से सहमत हैं कि प्रांतों को शेष विषयों में पूर्ण सत्ता मिलनी चाहिये, हमने यह भी कहा है कि प्रान्तों को हस बात के लिये स्वतन्त्र रखा जाये कि वे श्रपनी इच्छा से संघ को श्रिषक विषय श्रपित कर सकें। संघ के श्रन्दर कोई उपसंघ बनने से संघीय केन्द्र की शक्ति कम होगी और यह वेसे भी गलत होगा। श्रतः हम इस प्रकार के विकास को नहीं चाहते।

"भारतीय राज्यों के विषय में हम यह स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि हम यह त्रावश्यक समझते हैं कि वे उपयुक्त सामान्य विषयों के सम्बन्ध में संघ के भाग होने चाहियें। वे किस प्रकार संघ में श्रायेंगे इस पर बाद में पूरी तरह सोचा जा सकता है।

"श्रापने कुछ मूल सिद्धांतों के विषय में लिखा है पर श्राधारभूत मरन की, जो हमारे सामने है—श्रर्थात् पूर्ण स्वतन्त्रता श्रीर इसके परिसाम

स्वरूप भारत से श्रंग्रेजी सेना का निकालना—उसकी कहीं चर्चा नहीं है। इसी श्राधार पर हम भारत के भविष्य या किसी श्रन्तरिम प्रबन्ध पर विचार कर सकते हैं।"

तत्परचात इस पत्र में राष्ट्रसभा ने श्रपने चार प्रतिनिधि मौलाना श्राजाद, पं॰ नेहरू, सरदार पटेल तथा खान श्रव्हुल गफ्फार खां के नाम लिखे थे । उपर्युक्त पत्र से यह प्रकट है कि राष्ट्रसभा निर्वल संब केन्द्र नहीं चाहती थी ।

मुस्लिम लीग ने श्रपने चार मुसलमान प्रतिनिधियों के नाम लिखते हुये श्रपना एक प्रस्ताव भेजा जिसमें यह मांगे की गई थीं कि:

"बंगाल, श्रासाम, पंजाब, सीमा प्रांत, सिंध तथा बलूचिस्तान को मिलाकर एक सार्वभौम-सत्ता-प्राप्त स्वतन्त्र पाकिस्तान बनाया जाये तथा हिन्दुस्तान एवं पाकिस्तान के संविधान बनाने के लिये वहां के निवासियों की दो मिन्न भिन्न संविधान सभायें बनें।

यह मांगे पूर्णतः अनुचित थीं क्यों कि आसाम, आधा पंजाब एवं आधा बंगाल हिन्दू बाहुत्य प्रदेश थे तथा सीमाप्रांत और पंजाब के व्यवस्थापक मंडलों में भी लीग का बहुमत नहीं था । सीमाप्रांत में तो राष्ट्रसभा का मंत्रिमण्डल था और पंजाब में एकता दल (Unionist Party) का शासन था ।

७. शिमला सम्मेलन

र मई १६४६ को शिमला सम्मेलन में अंग्रेजों ने यह बात मान ली कि वार्ता का त्राधार पूर्ण स्वतन्त्रता होगा और ब्रिटेन तथा भारत के सम्बन्ध संविधान सभा निश्चित करेगी। इस कारण राष्ट्रसभा के श्रध्यच्च ने ६ मई के पत्र में लिखा:

"संविधान सभा स्वतन्त्र भारतीय राष्ट्रकी इच्छा की प्रतिनिधि होगी तथा उसे पूरी करेगी। वह किसी पूर्व प्रबन्ध से नहीं बंधेगी।

किंतु संविधान बनने में पर्याप्त समय लगता, उस समय तक अंग्रेजी अबेधानिक शासन सद्धा नहीं हो सकता था तथा वह संविधान निर्माण में बाधा भी बन सकता था अतः राष्ट्रसभा ने लिखा कि 'इसके पूर्व एक अन्तरिम सरकार (Interim) बननी चाहिये जो यथासम्भव स्वतन्त्र भारत

की सरकार के समान कार्य करे तथा परिवर्तन काल के लिये सारे प्रबन्ध करे।"
सम्मेलन में प्रांतीय वर्गों के लिये व्यवस्थापक मंडल और कार्यपालिका बनाने
के विषय में भी बात हुई थी उसका विरोध करते हुये प्रधान ने लिखा "इस
का अर्थ होगा उपसंघों का निर्माण, यदि अधिक नहीं, और हमने आपको
पहले ही बता दिया है कि हम इसको स्वीकार नहीं कर सकते। इसका परिस्थाम यह होगा कि व्यवस्थापिका तथा कार्यपालिका प्रबन्ध के तीन स्तर बन
जायेंगे जो अप्रगतिशील तथा असंयुक्त होंगे जिससे निरन्तर संघर्ष होगा।
किसी अन्य देश में ऐसा प्रबन्ध नहीं सुना।"

देश के बटवारे के विषय में लीग के प्रस्ताव पर राष्ट्रसभा के प्रधान ने लिखा था कि 'सम्मेलन को भारत विभाजन के किसी प्रस्ताव पर विचार करने का अधिकार नहीं है। यदि विभाजन होना है तो विद्यमान शासकों के बिना ही संविधान सभा यह निर्णय करेगी।"

लीग श्रीर राष्ट्रसभा के या हिन्दू श्रीर मुसलमानों के समान संख्या में सदस्य लेने के 'समता' प्रस्ताव को लीग ने सरकार एवं व्यवस्थापक मण्डल दोनों में लागू करना चाहा था । यह सर्वथा श्रन्यायपूर्ण था कि ११४ जनसंख्या वाली जाति ११४ की बराबरी करे । इसका विरोध करते हुये राष्ट्रसभा ने लिखा था ''हम यह श्रनुभव करते हैं कि प्रत्येक वर्ग श्रीर जाति के मिन्तिष्क से संदेह श्रीर श्राशंका निकालने के लिये सब कुछ सम्भव प्रयत्न करने चाहिये पर इस के लिये किसी श्रवास्तविक मार्ग को नहीं श्रपनाना चाहिये जो कि जनतन्त्रवाद के मूल सिद्धान्त के विरुद्ध जाये, क्यों कि हम जनतन्त्रवाद पर ही श्रपना संविधान बनाने की श्राशा करते हैं।"

८. मंत्री प्रतिनिधि मंडल की नवमसूत्री योजना

प्रमाई को प्रतिनिधि मण्डल ने दोनों दलों को प्रसन्न करने के लिये एक नवम सूत्री योजना बनाई जो इस प्रकार थी:

९. एक अखिल भारतीय संघीय सरकार व्यवस्थापक--मण्डल सिंहत होगी जो वैदेशिक नीति, सुरत्ता, संचार एवं मृल अधिकारों को संभा-लेगी और उसे इन विषयों के लिये धन संग्रह करने का आवश्यक शक्ति होगी।

- २ शेष सारी शक्ति प्रान्तों में निहित होंगी।
- प्रान्तों के वर्ग बन सकते हैं तथा वे वर्ग यह निर्णय करेंगे कि
 कौन से प्रान्तीय विषय सामान्य रूप से वर्गों में निहित हों।
 - ४. वर्ग ग्रपनी कार्यपालिका तथा व्यवस्थापक मण्डल बना सकते हैं।
- १० संघ के व्यवस्थापक मंडल में सुिस्लम बहुमत प्रान्तों श्रीर हिन्दू प्रान्तों के बराबर प्रातिनिधि होंगे चाहे वर्ग बने हों यह नहीं। देशी राज्यों के भी प्रतिनिधि साथ होंगे।
- ६. संघ की सरकार भी व्यवस्थापक मण्डल के समान संतुलन वाली ही होगी।
- ७. दस दस वर्ष बाद कोई भी प्रान्त संविधान में संशोधन की मांग कर सकता है। इस के लिये पहली संविधान सभा के समान आधार पर ही दूसरी संविधान सभा बनेगी।
- प्त. उपर्युक्त स्त्राधार पर संविधान निर्माण करने वाली सभा निम्न प्रकार बनेगीः
- क. प्रत्येक प्रान्तीय धारा सभा से प्रतिनिधि चुने जायेंगे जो कि प्रत्येक दल की शक्ति के अनुसार उसकी संख्या का १० वाँ भाग होंगे।
- ख. ब्रिटिश भारत के प्रतिनिधियों के ब्रनुपात से राज्यों के प्रति-निधि भी जनसंख्या के ब्राधार पर बुलाये जायोंगे।
- ग. इस प्रकार बनी हुई संविधान सभा यथा सम्भव शीघ्र ही नई देहली बैठेगी।
- घ, प्रारम्भिक बैठक में कार्यक्रम बनाने के बाद यह तीन भागों में विभाजित हो जायेगी, एक हिन्दू बहुमत प्रान्तों के लिये दृसरे मुस्लिम बहुमत प्रान्तों के लिये और तीसरे देशी राज्यों के लिये।
- ङ. प्रथम दो भाग फिर पृथकतः समवेत होकर प्रान्तीय संविधानों का या उनकी इच्छा हो तो वर्गीय संविधान का निर्णय करेंगे।
- च. जब यह हो चुकेगा तब किसी प्रान्त को यह छूट होगी कि वह अपने पुराने वर्गमें से हट कर नये में चला जाये या अलग रहे।
- छ. तत्परचात तीनों भाग एक साथ मिलकर उपयुक्त १ से ७ कन्डिकाओं के मान्य श्राधार पर संघ का संविधान बनायेंगे।

ज. साम्प्रदायिक प्रश्न पर प्रभाव डालने वाला कोई बड़ा प्रश्न संघीय संविधान सभा में तब तक स्वीकृत न माना जायेगा जब तक कि दोनों मुख्य जातियों के बहुमत उसे स्वीकार न करें।

६. वायसराय शीघ्र ही उपर्युक्त संविधान-सभा का निर्माण कोगा।

ए-भारत की प्रतिक्रिया

उपयुक्त योजना में लीग को वर्गींकरण के बहाने पाकिस्तान मिल जाता और निर्वल केन्द्र में भी वे पूर्णतः शिवतशाली होते क्यों कि उन की इच्छा के बिना कुछ नहीं हो सकता था [देखिये म (ज)] तथा उन्हें बाकी जातियों के बराबर स्थान मिल जाते जो कि १६३४ के संवि-धान के पासंग (वजन) से भी अधिक अन्यायपूर्ण था। इसके अति-रिक्त ऊपर लिखित नियम बनाने का अर्थ भारत की संविधान सभा को स्वतन्त्रतापूर्वक कार्य करने से रोकना था। इतने पर भी लीग वाले प्रसन्न नहीं थे वे चाहते थे कि प्रान्तों को वर्गों से निकलने की स्वतन्त्रता न हो और केन्द्र जितना निर्वल किया जा सके उतना बने जिस से कि अन्त में वह समाप्त ही हो जाये। राष्ट्रसभा के प्रधान मौलाना आजाद ने ह मई को निम्न लिखित पत्र लिखा:

"हम यह मानते हैं कि आप के रखे हुये प्रस्ताव संविधान सभा की स्वतन्त्र इच्छा को सीमित करने के अभिप्राय से बनाये गये हैं। हम नहीं समभते कि ऐसा कैसे हो सकता है।.....कोई निर्णय जो अभी इस मामले पर किया जाये वह हो सकता है कि उन निर्णयों के विपरीत हो जो कि हम या संविधान सभा अन्य मामलों पर करना चाहें। केवल एक ही उचित मार्ग हमें दिखता है कि एक संविधान सभा बने जिसे अस्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा के लिये कुछ प्रतिबन्धों के अतिरिक्त

श्रपना संविधान बनाने की सर्वांश में स्वतन्त्रता हो। श्रतएव हम इस बात से सहमत हो सकते हैं कि कोई बड़ा साम्प्रदायिक प्रश्न सम्बन्धित दलों की सहमति से या जहां इस प्रकार का समभौता न हो सके वहां पंच निर्णय द्वारा निबटे।

"श्राप के भेजे हुए प्रस्तावों से यह भी प्रतीत होता है कि भिन्न भिन्न वर्गों के लिये दो या तीन भिन्न भिन्न संविधान वनें श्रीर वे संविधान उन श्रसंयुक्त वर्गों पर श्राश्रित एक कृत्रिम सामान्य ढांचे द्वारा मिलाये जायें।

"ग्रारम्भ में प्रत्येक प्रान्त को एक विशेष वर्ग में मिलने के लिय ग्रानिवार्यता है चाहे वह मिलना चाहे या नहीं। सोमाप्रान्त को जो कि स्पष्टतः राष्ट्र सभाई प्रान्त है कांग्रेस के विरोधी किसी वर्ग में मिलने को क्यों वाध्य किया जाये।"

श्रागे राष्ट्र सभा के प्रधान ने लिखा था :

"श्रव मैं श्रापके स्मरण पत्र के कुछ विषयों पर विचार करूंगा तथा उनके विषय में कुछ श्रपने सुभाव रखूंगा":

संख्या १ : हम ने यह देखा है कि आप ने संघ को अपने विषयों के लिये धन प्राप्त करने की आवश्यक शक्ति दी है। हम समभते हैं कि यह स्पष्ट हो जाना चाहिये कि संघ को अपने अधिकार से कर उगाहने की शक्ति होगी। इस के अतिरिक्त मुद्रा और आयात निर्यात भी संघीय विषयों में सम्मिलित होने ही चाहियें, तथा अन्य विषय भी जो कि ध्यान से सोचने पर इन से धनिष्ट रूप से सम्बधित पाये जायें। एक अन्य आवश्यक तथा अनिवार्य संघीय विषय भी है वह है 'योजना निर्माण'। योजना का कार्य ठीक तरह केन्द्र में ही हो सकता है, यद्यपि प्रान्त एवं इकाइयां अपने अपने अदेशों में इसको कार्यान्वित करेंगे।

संघ को यह भी शक्ति होनी चाहिये कि संविधान के असफल होने पर या गम्भीर सार्वजनिक संकट की स्थिति में वह आवश्यक कार्य-वाही कर सके।

संख्या ४ व ६ : हम कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में श्रसम वर्गों के बीच प्रस्तावित समता के सर्वथा विरुद्ध हैं। यह श्रन्यायपूर्ण

है तथा संघर्ष उत्पन्न करेगी। ऐसे उपबन्ध में संघर्ष का बीज है श्रोर स्वतन्त्र विकास के लिये नाशकारी है। यदि इस विषय पर या अन्य ऐसे किसी विषय पर सममौता नहीं हो तो हम इसे पंच निर्णय पर छोड़ने के लिए उद्यत हैं।

संख्या ७: हम यह सुक्ताव मानने के लिये तैयार हैं कि संविधान पर दस वर्ष बाद पुनिर्विचार का उपवन्ध हो ।.....पर यह भी कहा गया है कि पुनिर्विचार करने के लिये इसी संविधान सभा के समान त्राधार बाली ही संस्या हो । त्रव तो विशेष परिस्थिति के कारण ऐसा हो रहा है। हमें श्राशा है कि भारत का संविधान वयस्क मताधिकार पर श्राधारित होगा। दस वर्ष पश्चात का भारत किसी गम्भीर प्रश्न पर वयस्क मताधिकार से कम किसी प्रकार से विचार कर के संनुष्ट न होगा।

संख्या द—क: हम यह सुभाव रखना चाहते हैं कि न्यायपूर्ण श्रोर उचित निर्वाचन का तरीका जो सब दलों के लिये न्यायपूर्ण है वह श्रानुपातिक प्रतिनिधित्व का है जिस से प्रयेक को एक मत देने का श्रधिकार हो। यह याद रखना चाहिये कि प्रान्तीय धारा सभाश्रों में इस समय के निर्वाचन के श्राधार के कारण श्रद्धपर ख्यकों का पलड़ा बहुत सुका हुश्रा है।

्वे का अनुपात भी बहुत कम है। इस से संविधान सभा में कदा-चित २०० से अधिक सदस्य नहीं होंगे। हम चाहते हैं कि प्रान्तीय धारा सभाओं के ऐ सदस्य संविधानसभा में आयें।

संख्या ८—ख: यह अस्पष्ट है पर इस समय हम इसको नहीं लेते।

संख्या द्र—घ, ङ, च, छ : मैंने इन के विषय में पहले ही लिख दिया है। हमारे विचार में इन वर्गों का निर्माण तथा प्रस्तावित कार्य प्रणाली दोनों ही असंगत एव अवांक्रनीय हैं। यदि प्रान्त चाहें तो हम वर्गीकरण को अनुचित नहीं बताते। पर यह विषय संविधान समा द्वारा निर्णय करने के लिये छोड़ देना चाहिये। संविधान का निर्णय और निर्माण संघ से आरम्भ होना चाहिये। इस में प्रान्तों और अन्य इकाइयों के लिये छुछु सामान्य उपबन्ध होने चाहिये। प्रान्त इनको बढ़ा सकते हैं।

संख्या ८ (ज): आज की परिस्थित में हम इस प्रकार की चीज मानने के लिये उद्यत हैं। समभौता न होने पर पंच-निर्णय होना चाहिये।

१ मई को सम्मेलन की बैठक में राष्ट्रसभा की श्रोर से पंडित नेहरू ने प्रस्ताव रखा कि दोनो दलों के भगड़े निपटाने के लिये एक पंच चुनना चाहिये। लीग ने उस समय तो इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया परन्तु दूसरे ही दिन उससे इन्कार कर दिया।

१०. लीग श्रीर राष्ट्रसभा के सुकाव

१२ मई को फिर लीग ने अपने नवीन सुम्माव भेजे। राष्ट्रसभा उनका उत्तर दिया तथा अपने सुम्माव भी रखे। हम पाठकों की सुविधा के लिये लीग के सुम्माव और राष्ट्रसभा का उत्तर नीचे साथ साथ देते हैं। इन के पश्चात १४ मई को मन्त्री प्रतिनिधिमग्डल ने अपने अंतिम सुम्माव रखे थे।

मुस्लिम लीग के सुभाव

1. है मुस्लिम प्रांत (पंजाब, सीमा प्रांत, बल्चिस्तान, सिंध, बंगाल तथा त्रासाम) एक वर्ग में एकत्रित कर दिये जायें जो विदेशी नीति, सुरचा तथा संघ के लिये आवश्यक संचार के अतिरिक्त सब विषयों को संमालेंगे। इन तीन विषयों पर हिन्दू प्रांतों श्रीर सुस्लिम प्रांतों की संविधान समाएं साथ बैठकर विचार करेंगी।

राष्ट्रसभा का उत्तर

9. उचित प्रणाली यह है कि एक ही संविधान सभा सारे भारत के लिए बने श्रोर बाद में यदि सम्बन्धित प्रान्त चाहे तो वर्ग बना सकते हैं। पर यह प्रान्तों पर छोड़ देना चाहिये कि यदि वे वर्ग में कार्य करना चाहें तो उन्हें ऐसा करने की तथा इसके लिए श्रपना संविधान बनाने की स्व-तन्त्रता है।

किसी श्रवस्था में भी कथित वर्ग में श्रासाम को कोई स्थान नहीं है तथा, निर्वाचनों से जैसे प्रकट है, सीमाप्रांत भी इस प्रस्ताव के विरुद्ध है।

- २. उपयुक्त ६ मुस्लिम प्रांतों के लिये प्रथक संविधान सभा होगी जो कि वर्ग और प्रांतों के संविधान बनायेगी और यह निर्णाय करेगी कि कौन से विषय प्रांतीय हों तथा कौन से केन्द्रीय (पाकिस्तान संघ के) होंगे। शेष सार्वभौमिक सत्ता प्रान्तों में निहित होगी।
- ३. संविधान सभा के लिये प्रतिनिधियों के निर्वाचन की प्रणाली ऐसी होगी कि पाकिस्तान वर्ग के प्रत्येक प्रान्त की भिन्न-भिन्न जातियों को अपनी जनसंख्या के अनुपात से उचित प्रतिनिधित्व मिले।

- ४. ब्रान्तों श्रीर पाकिस्तान संघीय सरकार का संविधान बनाने के परचात कोई भी प्रान्त बाहर निकल सकता है किन्तु उस प्रान्त की जनता की सम्मति लेनी होगी कि वे बाहर निकलना चाहते हैं या नहीं।
- ४. संयुक्त संविधान सभा में स्थापक मण्डल होना चाहिये या

- २. हम केन्द्रीय विषयों के अति-रिक्त ग्रन्य शेष सत्ता प्रान्तों में रखने को तैयार हैं। वे उसका श्रपनी इच्छा-नुसार प्रयोग कर सकते हैं तथा वर्ग भी बना सकते हैं। ऐसे वर्ग की श्रन्तिम रूपरेखा क्या होगी यह श्रभी निश्चित नहीं हो सकता। यह बात सम्बन्धित प्रान्तों के प्रतिनिधियों पर छोड देनी चाहिये।
- ३. हम ने यह सुकाया है कि निर्वाचन की सर्वोत्तम प्रणाली 'प्रत्येक के लिये एक मत' के आधार पर होनी चाहिये। इससे प्रत्येक जाति को व्यवस्थापिका सभाश्रों में इस समय के प्रतिनिधित्व के अनुपात से स्थान मिल सकेंगे। हमें जनसंख्या के श्राधार पर चुनाव में भी कोई विशेष श्रापत्ति नहीं है पर प्रान्तों में वजन होने से इसमें कठिनाई होगी। जो सिद्धान्त मान्य होगा वह सब प्रान्तों में लागू होगा।
- ४. किसी प्रांत के लिये बाहर निकलने की आवश्यकता ही नहीं है। क्योंकि वर्ग में सम्मिलित होने से पहले उसकी सहमति श्रावश्यक है।
- ५. हम इसे आवश्यक समभते यह निर्णाय होगा कि संघ का न्यव- हैं कि संघ के लिये व्यवस्थापक मंडल हो तथा उसे कर द्वारा अपना धन

नहीं। संघ को धन देने की प्रणाली भी तभी निश्चित होनी चाहिये, पर उसे कर लगाने की तो अनुमित होनी ही नहीं चाहिये। संग्रह करने की शक्ति हो।

- ६. संघीय कार्यपालिका में तथा यिद व्यवस्थापक मण्डल बने तो उस में भी दोनों प्रांतीय वर्गों को प्रतिनि-धित्व में समता होनी चाहिये।
- ७. ऐसी कोई मुख्य बात जो साम्प्रदायिक प्रश्न पर प्रभाव डाजती हो, वह संयुक्त संविधान सभा में स्वीकृत न सममी जायेगी जब तक कि दोनों वर्गों के प्रतिनिधि पृथक-पृथक इसे न मानें।
- म. किसी भी विवादयुक्त प्रश्न पर चाहे वह कार्यपालिका सम्बन्धी, प्रशासन सम्बन्धी, या व्यवस्थापिका सम्बन्धी हो केवल तीन चौथाई के बहुमत से ही निर्णय हो सकेगा।
- म. यह इतना व्यापक सुमाव है कि कोई भी सरकार या व्यवस्थापक मंडल कार्य ही नहीं कर सकता। एक बार साम्प्रदायिक प्रश्नों का संरच्चण करने के परचात श्रन्य विवादास्पद प्रश्नों के लिये संरच्चण की कोई श्रावश्यकता नहीं है। इस से तो प्रत्येक निहित स्वार्थ की रचा होगी तथा प्रगति श्रसंभव हो जायेगी। हम इसे नहीं मानते।
- वर्गीय तथा प्रान्तीय संवि-धानों में मुल अधिकारों तथा भिन्न भिन्न सम्प्रदायों के धार्मिक. सांस्क्र-
- हमारा सुकाव है कि इन
 अधिकारों का उचित स्थान अखिल
 भारतीय संघ के संविधान में है।

तिक तथा ग्रन्य मामलों के लिये उपबंध होंगे। सारे भारत में मूल ऋधिकारों के विषय में समता होनी चाहिये।

१०. संघ के संविधान में ऐसा उपबंध होना चाहिये कि कोई प्रान्त १० वर्ष बाद अपनी व्यवस्थापिका सभा के बहुमत से संविधान को दोहराने की मांग कर सकता है तथा संघ से पृथक हो सकता है।

१० संघ के संविधान में दोहराने का तो उपबंध होगा ही, श्रिपतु इस पर पूर्णतः पुनर्विचार करने का भी उप-बंध हो सकता है। यद्यपि पृथक होने का श्रिधकार निहित है पर हम इस का उल्लेख नहीं करेंगे क्यों कि हम इस भावना को प्रोत्साहन नहीं देना चाहते।

इसके साथ साथ राष्ट्रसभा ने अपनी श्रोर से ठोस सुमाव भी रखे किन्तु वे भी समभौते का श्राधार न बन सके।

११, मंत्री प्रतिनिधिमंडल की अन्तिम वर्गीकरण योजना

१२ मई को शिमला में लीग तथा राष्ट्रसभा के बीच सुक्तावों का विनिमय होने के बाद तंग होकर प्रतिनिधिमंडल ने यह घोषणा कर दी कि दोनों दलों में समभौता न होने के कारण शिमला सम्प्रेलन भंग कर दिया गया है तथा प्रतिनिधिमंडल तत्काल देहली लौटेगा जहां वह अपना अन्तिम निर्णय करके उस की घोषणा करेगा। यह प्रतिनिधिमंडल योजना १६ मई १६४६ को प्रकाशित की गई जिस में दोनों दलों को प्रसन्न करने के लिये मध्यवर्ती मार्ग जुना गया था। राष्ट्रसभा तथा लीग दोनों ने इसे मान लिया था किन्तु अन्त में लीग ने संविधान सभा बनने पर उस से असहयोग कर दिया। अब हम प्रतिनिधि मंडल योजना के कुछ अंशों को नीचे देते हैं।

ब्रिटिश मन्त्री प्रतिनिधिमण्डल एवं वायसराय महोदय का १६ मई १६४६ का वक्तव्य।

"१. गत १४ मार्च को, भारत को प्रतिनिधि मण्डल भेजने से कुछ ही पहले, श्रीयुत एटली, ब्रिटिश प्रधान मन्त्री, ने यह शब्द प्रयोग किये थे:

'मेरे सहयोगी भारत को यथासम्भव शीघातिशीघ तथा पूर्णतः स्वतन्त्रता प्राप्त करने में सहायता देने के निमित्त अपना अधिकाधिक प्रयत्न करने की इच्छा से भारत जा रहे हैं। वर्तमान शासन के स्थान पर किस प्रकार की सरकार बने यह तो भारत को ही निर्णय करना है, किन्तु उसे वह निर्णय करने के लिये व्यवस्था स्थापित करने में सहायता देना ही हमारी आकांत्ता है।.....

में त्राशा करता हूँ कि भारतीय ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल में ही रहने का निर्णय करेंगे। मुक्ते विश्वास है कि उन्हें इस में बहुत लाभ दिखेगा।...

किन्तु यदि भारत इस प्रकार निर्णय करे तो श्रपनी स्वतन्त्र इच्छानुसार ही करेगा। ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल श्रीर साम्राज्य वाह्य द्याव की श्रांखलाश्रों से जुड़ा हुआ नहीं है। यह स्वतन्त्र राष्ट्रों का स्वतन्त्र संगठन है। यदि इसके विपरीत भारत ने स्वतन्त्र रहने का निश्चय किया तो हमारे विचार में उसे ऐसा करने का अधिकार है। हमारा यह कार्य होगा कि उस परिवर्तन को यथासम्भव सरल तथा संघर्ष रहित बनाने में सहायता दें।'

२ इन ऐतिहासिक शब्दों का भार लेकर हमने, मन्त्री प्रतिनिधिमण्डल श्रीर वायसराय ने, भारत के विभाजन या एकता के श्राधारमूल प्रश्न पर दोनों मुख्य राजनैतिक दलों को समभौते पर पहुँचाने के लिये श्रधिकतम प्रयत्न किया है । नई दिल्ली में लम्बे विचार विनिमय के उपरान्त हम शिमला में राष्ट्रसभा तथा मुस्लिम लीग को एक सम्मेलन में साथ लाने में सफल हुये। वहां पर भावों का पूर्ण विनिमय हुश्रा तथा दोनों दल समभौते पर पहुंचने के लिये बहुत रियायतें करने के लिये तत्पर थे, किन्तु श्रन्त में दोनों दलों के बीच शेष खाई को पाटना श्रसंभव सिद्ध हुश्रा तथा कोई समभौता नहीं हो सका। क्योंकि कोई समभौता नहीं हो सकता है, श्रतः हम श्रपना कर्त्तव्य समभते हैं कि नये संविधान के शीध निर्माण की बात पक्की करने के लिये हम जो उत्तमोत्तम व्यवस्था समभते हैं उसे प्रस्तुत करें। यह वक्तव्य ब्रिटिश सरकार की पूर्ण म्वीकृति से दिया जाता है।

३. हम ने एतदानुसार यह निश्चय किया है कि श्रविलम्ब ऐसी

ब्यवस्था करनी चाहिये कि जिस से स्वयं भारतीय ही भारत का भावी संविधान निरिचत कर सकें श्रीर जब तक नवीन संविधान निर्मित न हो सके तब तक ब्रिटिश भारत की शासन ब्यवस्था चलाने के निमित्त तत्काल एक श्रन्तरिम सरकार बना दी जाये। हमने जनता के बड़े दलों के समान ही छोटे दलों के साथ न्याय करने का प्रयत्न किया है तथा ऐसी व्यवस्था की सिफा-रिश करने का प्रयत्न किया है कि जो भारत के भावी शासन की व्यवहारिक प्रणाली सुक्तायेगी एवं सामाजिक, राजनैतिक तथा श्रार्थिक चेत्र में प्रगति करने का श्रच्छा श्रवसर श्रीर सुरन्ता के लिये हड़ श्राधार प्रदान करेगी।

- ४, प्रतिनिधि मगडल के समज्ञ जो विस्तृत वक्तव्य दिये गये हैं उन का इस वक्तव्य में सिंहावलोकन करने की कोई इच्छा नहीं है, किन्तु यह उचित है कि हम यह कहें कि इन में भारत की एकता के लिये, मुस्लिम लीग के समर्थकों के श्रतिरिक्त, लगभग सब श्रोर से सर्वतोमुखी इच्छा प्रगट की गई है।
- ४. किन्तु यह विचार हमें भारत विभाजन की सम्भावना को निष्पच होकर एवं भली प्रकार से जाँचने से नहीं रोक सका है क्योंकि हम मुसलमानों की सच्ची तथा भीषण चिन्तावृति से बहुत प्रभावित हुए हैं कि कहीं वे सदा के लिये हिन्दू बहुमत शासन के अधीन न हो जायें। यह भावना मुस्लिमों में इतनी दृढ़ तथा विस्तृत हो गई है कि वह केवल संरच्यों से नहीं मिट सकती। यदि भारत में आन्तरिक शान्ति रहनी है तो वह ऐसे उपायों से ही हो सकती है जिन से मुसलमानों को अपनी संस्कृति, धर्म और आर्थिक तथा अन्य हितों के लिये आवश्यक मामलों में नियन्त्रण का विश्वास हो सके।

बड़ा पाकिस्तान श्रसम्भव

६ हम ने इस कारण पहले मुस्लिम लीग द्वारा मांगे हुए पृथक तथा सम्पूर्ण-प्रमुख-संपन्न पाकिस्तान राज्य के प्रश्न पर विचार किया। ऐसे पाकिस्तान में दो प्रदेश सम्मिलित होते, एक उत्तर पश्चिम में अर्थात पंजाब, सिंध, सीमाप्रान्त तथा बिटिश बल्चिस्तान और दूसरा उत्तर पूर्व में अर्थात बंगाल तथा आसाम। लीग बाद में सीमाओं को ठीक करने के विषय में सोचने के लिये तैयार थी पर उसने इस पर हठ किया कि पाकिस्तान

के सिद्धांत को पहले मानना चाहिये। पाकिस्तान के प्रथक राज्य के लिये युक्ति का यह आधार था कि प्रथम तो मुस्लिम बहुमत को अपनी इच्छानु-सार अपने शासन की प्रणाली निश्चित करने का अधिकार है, और दूसरे पाकिस्तान को प्रशासन सम्बन्धी तथा आर्थिक दृष्टि से कार्य योग्य बनाने के लिये ऐसे बहुत से प्रदेश भी उसमें मिलाने चाहियें कि जिन में मुस्लिम अल्पसंख्या में हैं।

उल्लिखित हैं प्रान्तों से बने पाकिस्तान में श्रमुस्लिम श्रल्प-संख्यक श्रत्यधिक होंगे जैसे कि निम्न श्रांकड़ों से प्रकट होता है (यह श्रांकड़े १६४१ की जनसंख्या के श्राधार पर हैं):

उत्तर पश्चिमी प्रदेश	मुस्लिम	श्रमुस्लिम
पंजाब	१,६२,१७,२४२	૧, २२,०१, ४७ ७
सीमाप्रान्त	२७,८८,७६७	२,४१,२७०
सिंघ	३२,०८,३२४	१३,२६,६=३
बलूचिस्तान	४,३८,६३०	६२,७०१
	२२६,५३,२६४	135,80,739
	(६२.०७ प्रतिशत)	(३७.६३ प्रतिशत)
उत्तर पूर्वी प्रदेश		
वंगाल	३,३०,०४,४३४	२,७३,०१,०११
श्रासाम	३४,४२,४७६	६७,६२,२४४
	३,६४,४७,६१३	३,४०,६३,३४४
	(४१.६६ प्रतिशत)	(४म.३१ प्रतिशत)

शेष ब्रिटिश भारत में मुस्लिम श्रत्पसंख्यक २ करोड़ के लगभग हैं जो कि १८ करोड़ ८० लाख जन संख्या में बिखरे हुए हैं।

इन श्रंकों से यह प्रकट है कि मुस्लिम लीग द्वारा मांगा हुश्रा पृथक सम्पूर्ण प्रभुत्व संपन्न पाकिस्तान राज्य बनने से साम्प्रदायिक श्रल्पसंख्यकों की समस्या हल नहीं होती, श्रौर न ही ऐसे पाकिस्तान में श्रासाम तथा पंजाब तथा बंगाल के वे जिले जिनमें जनता मुख्यतः श्रमस्लिम

सन १६३४ का संविधान

है सिम्मिलित करना न्याययुक्त है। प्रत्येक युक्ति जो कि पाकिस्तान के पत्त में दी जा सकती है वही श्रमुस्लिम प्रदेशों को पाकिस्तान से पृथक रखने के लिये दी जा सकती है। यह विषय सिखों की श्रवस्था पर विशेष प्रभाव डालता है।

- ७. छोटा पाकिस्तान भी नहीं : श्रतः हमने यह विचार किया कि क्या एक छोटा पाकिस्तान जो मुस्लिम बहुमत के प्रदेशों तक सीमित हो समभौते का सम्भवतः श्राधार बन सकता है। मुस्लिम लीग ऐसे पाकिस्तान को सर्वथा श्रव्यवहारिक समभती है क्योंकि इस से निम्न प्रदेश पाकिस्तान से निकल जाते हैं:
 - श्र. पंजाब में सारा श्रम्बाला तथा जलंधर का डिवीजन
 - ब. सिलहट जिले के अतिरिक्त सारा आसाम
 - ज. पश्चिमी बंगाल का भाग जिस में कलकत्ता सम्मिलित है।

(कलकत्ते में मुस्लिम जनसंख्या केवल २३.६ प्रतिशत है।)

हमारा भी यह विश्वास है कि कोई भी ऐसा मार्ग, जिससे पंजाब श्रीर बंगाल का पूर्णतः विभाजन हो, जैसा कि इसमें होता, इन प्रान्तों के निवासियों के बहुत बड़े भाग की इच्छा तथा हितों के विपरीत होगा। बंगाल श्रीर पंजाब की श्रपनी श्रपनी भाषा, इतिहास तथा परम्परायें हैं। इसके श्रतिरिक्त पंजाब के बटवारे से सिखों का श्रवश्य विभाजन हो जाता तथा वे सीमा के दोनों श्रोर पर्याप्त संख्या में रह जाते। श्रतण्व हम विवश्य हो कर इस परिणाम पर पहुंचे हैं कि न छंटे न बड़े सम्मूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न पाकिस्तान से साम्प्रदायिक गुत्थी सुलक्ष सकती है।

म. पाकिस्तान से अन्य हानियां : उपरोक्त युक्तियों के महान बल के अतिरिक्त महत्वपूर्ण प्रशासन सम्बन्धी, आर्थिक तथा सैनिक विचार भी हैं। भारत के यातायात, डाक तथा तार की सारी व्यवस्था संयुक्त भारत के आधार पर बनी है। उन्हें खंडित करने से भारत के दोनों भागों को गंभीर हानि होगी। संयुक्त सुरक्ता व्यवस्था के लिये तो युक्ति और भी प्रबल है, भारतीय सेना सारे भारत की रक्ता के लिये ही बनाई गई है और

उस के दो खंड करने हो भारतीय सेना की उच्च कार्यकुशलता तथा परम्परा को घातक धक्का लगेगा एवं भयानक परिणाम होंगे। भारतीय जल और वायु सेनाओं की शक्ति बहुत कम हो जायेगी। प्रस्तावित पाकिस्तान के दो भागों में बहुत ही सुभेद्य सीमायें हैं और गहराई के युद्ध (Defence in Depth) में रचार्थ पाकिस्तान का चेत्रफल काफी नहीं होगा।

- एक महत्वपूर्ण विचार यह भी है कि खंडित भारत के साथ मिलने में देशी राज्यों को भी श्रिधिक कठिनाई होगी।
- १०. श्रन्त में एक भौगोलिक तथ्य भी है कि प्रस्तावित पाकिस्तान राज्य के दो भाग लगभग ७०० मील दूर हैं श्रौर युद्ध एवं शांति दोनों में उनके बीच संचार (Communications) हिन्दुस्तान की सद्भावना पर निर्भर होगा।
- ११. अतएव हम ब्रिटिश सरकार को यह सिफारिश नहीं कर सकते कि जो अधिकार इस समय ब्रिटिश हाथों में हैं वह दो सर्वथा पृथक सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न राज्यों को सौप दिए जायें।

**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**

१४. देशी राज्य स्वतन्त्र होंगे: अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करने से पहले हम देशी राज्यों के ब्रिटिश भारत के सम्बन्ध को लेते हैं। यह बिल्कुल स्पष्ट है कि भारत के स्वतन्त्र होने के पश्चात, चाहे ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल के अन्तर्गत चाहे बाहर, जो सम्बन्ध अब तक देशी नरेशों तथा ब्रिटिश सम्राट में थे वे न रह सकेंगे। प्रभुसत्ता न ही ब्रिटिश सम्राट रखेगा और न नये शासन को ही हस्तांतरित की जाएगी। यह तथ्य उन्होंने पूर्णतः मान लिया है जो कि राज्यों की श्रोर से हम से मिले थे। उन्होंने इसके साथ ही हमें आश्वासन भी दिया है कि राज्य भारत के नए विकास में सहयोग देने को तथ्य तथा उसके इच्छुक हैं। यह सहयोग किस रूप में होगा यह नवीन सांविधानिक रूपरेखा बनाते समय विचार विनिमय का विषय है तथा यह किसी प्रकार आवश्यक नहीं है कि यह सहयोग सारे राज्यों के लिए एक रूप में हो। श्रत: हमने निम्न कंडिकाओं में जितना विस्तृत विवरण ब्रिटिश भारत के प्रांतों का लिखा है उतना राज्यों का नहीं।

१४. नई योजना का आधार: श्रम हम वह हल बताते हैं जो कि हमारे विचार में सारे दलों के दावों के प्रति न्यायपूर्ण होगा श्रोर साथ साथ सारे भारत का एक स्थायी तथा व्यवहारिक संविधान बनाने के लिए संभवतः समुचित होगा।

हम सिफारिश करते हैं कि संविधान निम्नलिखित श्राधार पर बने :

- (१) एक भारतीय संघ होना चाहिए जिसमें ब्रिटिश भारत और राज्य हों तथा वह निम्न विषयों को संभाले, सुरत्ता, विदेशी नीति तथा संचार, और उसे इन विषयों के लिए श्रावश्यक धन प्राप्त करने की शक्ति होनी चाहिए।
- (२) संघ के लिए एक कार्यपालिका तथा एक व्यवस्थापक मण्डल होना चाहिए जो ब्रिटिश भारत तथा देशी राज्यों के प्रतिनिधियों से बनेंगे। कोई प्रश्न जो महान साम्प्रदायिक महत्व का हो उस को निश्चित करने के लिए व्यवस्थापक-मंडल में दोनों बड़े सम्प्रदायों में से प्रत्येक के उपस्थित तथा मत देने वाले कुल सदस्यों के बहुमत की श्रीर उपस्थित तथा मत देने वाले कुल सदस्यों के बहुमत की श्रावश्यकता होनी चाहिए।
- (३) संघीय विषयों के अतिरिक्त सारे विषय और शेष अधिकार प्रांतों में निहित होने चाहिए ।
- (४) उन श्रधिकारों श्रौर विषयों के श्रतिरिक्त जो कि वे संघ को श्रपित करेंगे शेष सब विषय तथा श्रधिकार राज्यों के पास रहेंगे।
- (१) प्रान्तों की स्वतन्त्रता : प्रान्त वर्ग बनाने के लिए स्वतन्त्र होने चाहियें जिनमें कार्यपालिका तथा व्यवस्थापक मण्डल हों तथा प्रत्येक वर्ग सामान्य रूप से रखने के विषयों का निर्णय कर सके [१६ (४) श्रीर (१) कंडिका से तुलना करिये।]
- (६) संघ तथा वर्गों के संविधान में एक उपबन्ध होना चाहिए जिस से दस दस वर्ष के बाद कोई प्रांत, अपनी व्यवस्थापिका सभा के बहुमत से संविधान में परिवर्तन की मांग कर सके।
 - १६. हमारा यह उद्देश्य नहीं है कि उपर्युक्त कार्यक्रम के अनुसार

संविधान का विस्तृत विवरण रखें, श्रिपितु हमारा उद्देश्य ऐसी रूपरेखा बनाने का है जिससे कि भारतीय भारत के लिए संविधान बना सके ।

यह सिफारिशें करना भी हमारे लिए इस कारण त्रावश्यक हो गमा है कि बिना इस के दो बड़ी जातियों को संविधान निर्मात्री सभा में लाने की त्राशा नहीं रही थी।

१७ अब हम संविधान निर्माण के लिए ज्यवस्था की चर्चा करते हैं, जिसे अब स्थापित करना चाहिए, जिससे कि नया संविधान बनना सम्भव हो सके।

१८ संविधान सभा में प्रतिनिधित्व: एक नयी वैधानिक व्यवस्था निश्चित करने के लिए एक सभा बनाने में यह समस्या है कि सारी जनता का सम्भवतः विस्तृत तथा ठीक प्रतिनिधित्व किस प्रकार प्राप्त किया जाये। सब से सन्तोषजनक उपाय तो स्पष्टतया वयस्क मताधिकार पर चुनाव होता किन्तु ऐसी चेष्टा करने से नये संविधान के निर्माण में सर्वथा श्रस्वीकार्य विलम्ब होगा। व्यवहारिक तरीका यही है कि स्रभी चुनी हुई प्रान्तीय व्यवस्थापिका सभाक्षों से निर्वाचन संस्थात्रों का काम लिया जाये। किन्तु उनकी बनावट में दो बातें हैं जो इसमें कठिनाई उत्पन्न करती हैं। एक तो प्रांतीय सभात्रों की सदस्य संख्या प्रत्येक प्रांत की जनसंख्या से श्रनुपात नही खाती। उदाहरणार्थं १ करोड़ की जन संख्या वाले त्रासाम में १०८ सदस्यों की धारा सभा है पर ६ गुनो जनसंख्या वाले बंगाल में केवल २४० सदस्यों की सभा है। दूसरे साम्प्रदायिक पंचाट द्वारा अल्पसंख्यकों को दिए हुए वजन के कारण प्रत्येक प्रांतीय ब्यवस्थापिका सभा में सम्प्रदायों की संख्या उनकी प्रांत में जनसंख्या के अनुपात के अनुसार नहीं है यथा मुसलमानों के लिये बंगाल धारा सभा में ४८ प्रतिशत स्थान हैं यद्यपि वे प्रांत की जनसंख्या के ४४ प्रतिशत हैं। इन बातों के ठीक करने के भिन्न भिन्न उपायों पर **ब**हुत ध्यान से विचार करने पर हम इस परिणाम पर पहुँचे हैं कि श्रिधिकतम न्यायपुर्ण श्रीर न्यवहारिक योजना यह है कि :

(श्र) प्रत्येक प्रांत को उसकी जनसंख्या के श्रनुपात से स्थान दिए जायें, लगभग १० लाख के पीछे एक, यह वयस्क मताधिकार के निकटतम योजना है।

- (ब) प्रांत को मिले स्थान प्रत्येक बड़ी जाति में उसकी संख्या के श्रानुपात से बांटे जायेंगे।
- (ज) यह उपबन्ध हो कि प्रांत में प्रत्येक जाति के लिए नियत प्रतिनिधि उसकी ब्यवस्थापिका सभा के उसी जाति के सदस्यों द्वारा निर्वाचित हों।

हमारे विचार में इस प्रस्ताव के लिए यह पर्याप्त है कि केवल हिन्दू, मुस्लिम तथा सिख तीन ही बड़ी जातियां मानी जायें और 'व्यापक' जाति में मुस्लिम तथा सिखों के अतिरिक्त सब आ जायें। क्यों कि अन्य जातियों को प्रांतीय व्यवस्थापक मण्डलों में प्राप्त विशेष स्थानाधिकार (वजन) न रहेगा अतः हमने २०वीं कंडिका में उनके हितों के विषय में पूर्ण प्रतिनिधित्व देने का प्रबन्ध किया है।

१६. (१) त्रतएव हमारा यह प्रस्ताव है कि प्रत्येक प्रान्तीय व्यवस्था-पिका सभा द्वारा निम्नलिखित संख्या में प्रतिनिधि निर्वाचित होंगे, सभा का प्रत्येक भाग व्यापक, मुस्लिम या सिक्ख अपने अपने प्रतिनिधि श्रनुपात से 'एकल संक्षाम्य मताधिकार' की प्रणाली से चुनेगा:

प्रतिनिधित्व का क्रम

'ऋ' शाखा

प्रान्त	व्यापक	मुस्लिम	योग
मद्रास	४४	8	38
ब∓बई	38	२	23
.युक्तप्रान्त	४७	ភ	१ १
बिहार	₹3	Ł	३६
मध्यप्रान्त	१६	1	30
ंडंडीसा	3	٥	3
		-	-
कुल योग	π ૧૬૭	२०	320

'ब' शाखा

प्रान्त	व्यापक	मुस्लिम	सिक्ख	जोड़
पंजाब -	~	3 &	8	२८
सीमाप्रान्त	•	₹:	•	Ą
सिंध	3	ર	0	8
कुल ['] जोड़	8	2 2 2	8	34

'ज? शाखा

प्रान्त	व्यापक	मुस्तिम	जोड़
बंगाल	२७	33	६०
त्रासाम	ø	æ	90
कुल जोब	इ ३४	३६	७०

ब्रिटिश भारत का जोड २ ६ २

. देशी राज्यों का जोड़.....१३ (त्रधिकतम)

महायोग '''३८४

नीट:— चीफ किमश्नरों के प्रांतों के लिए इस प्रकार प्रतिनिधित्व होगा कि केन्द्रीय व्यवस्थापक मंडल में दिल्ली तथा श्रजमेर मेरवाड़ा के प्रतिनिधि 'श्र' शाखा में मिल जायेंगे श्रीर उसी शाखा में कुर्ग व्यवस्थापिका परिषद् का एक प्रतिनिधि श्रा जायेगा। 'ब' शाखा में एक ब्रिटिश बलूचिस्तान का प्रतिनिधि जोड़ दिया जायेगा।

(२) राज्यों को प्रतिनिधित्व : हमारी यह इच्छा है कि अन्तिम रूप संविधान सभा में राज्यों को उचित प्रतिनिधित्व दिया जाये जो कि ब्रिटिश भारत के लिये स्वीकृत जनसंख्या के हिसाब से १३ स्थान से अधिक नहीं होगा। उन्हें भेजने की प्रणाली विचार विमर्श से तय की जानी होगी। प्रारम्भिक अवस्था में राज्यों का प्रतिनिधित्व 'वार्ता समिति' करेगी।

- (३) इस प्रकार से चुने हुए प्रतिनिधि यथासंभव शीघ्र ही नई देहली में अपनी बैठक करेंगे।
- (४) एक प्रारंभिक बैठक होगी जिसमें कार्यक्रम की रूपरेखा निश्चित होगी, एक सभापति ख्रौर श्रन्य पदाधिकारी चुने जायेंगे तथा एक परामर्श दात्री समिति (देखिये नीचे कंडिका २०) बैठाई जायेगी जो कि इन विषयों पर परामर्श देगी:—

नागरिक अधिकार, अल्पसंख्यक, कवायली तथा पृथक किये हुए प्रदेश। तत्पश्चात प्रान्तीय प्रतिनिधि इस कंडिका की उपकंडिका (१) में लिखित 'अ' 'ब' तथा 'ज' शाखाओं में बट जायेंगे [क'डिका १४ (४) से तुलना करें]।

- (१) यह शाखायें अपनी अपनी शाखा के प्रान्तों के लिये प्रांतीय संविधान बनाएंगी तथा यह निश्चित करेंगी कि कोई वर्गीय संविधान बनाया जाये या नहीं छेर यदि बनाया जाये तो वर्ग क्या क्या प्रान्तीय विषय संभालें, निम्नलिखित उपकंडिका (८) के उपबंधों के अनुसार प्रान्तों को वर्गी में से निकलने की स्वतन्त्रता होगी।
- (६) शाखात्रों तथा देशी राज्यों के प्रतिनिधि संघीय संविधान बनाने के लिये फिर समवेत होंगे।
- (७) उपर्युक्त कंडिका ११ के उपबंधों में परिवर्तन सम्बन्धी या कोई बड़े साम्प्रदायिक प्रश्न सम्बन्धी प्रस्ताव संविधान सभा में दोनों जातियों के प्रतिनिधियों के उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों के बहुमतों से ही स्वीकृत होगा। सभापित यह निर्णय करेगा कि कौन सा प्रस्ताव बड़े साम्प्रदायिक प्रश्न से सम्बन्धित है तथा यदि किसी जाति के प्रतिनिधि बहुमत से प्रार्थना करेंगे तो सभापित अपना निर्णय करने से पूर्व संघीय न्यायालय से परामर्श भी करेगा।
- (म) ज्यों ही नवीन संविधान की ब्यवस्था कार्यान्वित होंगी त्यों ही प्रान्तों को अपने वर्ग से निकलने का अधिकार होगा। नये संविधान के अन्तर्गत प्रथम निर्वाचन के परचात प्रान्तीय ब्यवस्थापिका सभा यह निर्णय करेगी।
 - २०. नागरिक श्रधिकार, श्रल्यसंख्यकों श्रीर कवाइली तथा पृथक

कृत प्रदेशों सम्बन्धी परामर्श समिति में प्रभावित हितों का प्रतिनिधित्व होगा श्रीर उनका कार्य यह होगा कि वे संघीय संविधान सभा को मुलाधिकारों की सूची, श्रत्यसं व्यकों के संरच्या के लिये धारायें, तथा कबाइली एवं पृथक कृत प्रदेशों की शासन व्यवस्था के लिये योजना के विषय में परामर्श दें तथा यह भी बतायें कि ये श्रधिकार प्रान्तीय, वर्गीय या संघीय किस संविधान में रखने चाहिये।

२१. वायसराय श्रव प्रांतीय व्यवस्थापक मंडलों से निवेदन करेगा कि श्रपने श्रपने प्रतिनिधि चुनना श्रारम्भ करें तथा राज्यों को कहेगा कि एक वार्ता समिति बनायें।

श्राशा की जाती है कि कार्य की विषमता जितनी जल्दी होने देगी उतनी शीव्रता से ही संविधान बनेगा तथा श्रंतरिम काल यथासंभव छोटा होगा।

- २२. शक्ति हस्तान्तरित करने के कार्य से उत्पन्न प्रश्नों पर त्रावश्यक बातें तय करने के लिये यह त्रावश्यक होगा कि संघीय संविधान सभा श्रीर ब्रिटेन में एक संधि हो।
- २३. अन्तरिम सरकार: जब तक संविधान निर्माण का कार्य चले तब तक भारत का प्रशासन तो चलाना ही होगा। अतः हम मुख्य राजनितक दलों के समर्थन से एक अन्तिरिम सरकार बनाने के प्रश्न को बहुत महत्व देते हैं।.....वायसराय ने पहले ही इसके लिये वार्ता आरम्भ करदी है तथा वह शीघ्र ही ऐसी अन्तिरम सरकार बनाने की आशा करते हैं कि जिस में युद्ध विभाग सहित सारे विभाग जनता के विश्वस्त नेता संभालोंगे। ब्रिटिश सरकार उसे पूर्ण सहयोग देगी।"

१२. योजना की त्रुटियां

उपर्युक्त योजना बहुत सोच समभ कर बनाई गई थी तथा उसमें जनतन्त्रवाद के सिद्धांतों की कुछ भलक श्रवश्य थी पर उसमें कई त्रुटियां भी थीं जिस कारण वह पूर्णतः सफल न हो सकी। हम इस योजना पर कंडिकाश्रों के क्रमानुसार टिप्पणी करेंगे:

श्र. राज्यों की समस्या: १४वीं कंडिका में राज्यों को भारतीय संघ से पृथक रहने की जो स्वतन्त्रता दी गई थी वह कठिनाई उत्पन्न कर सकती थी। राष्ट्रसभा चाहती थी कि राज्यों के प्रतिनिधि भी प्रान्तों के समान जनता द्वारा निर्वाचित हों।

११ व। कंडिका की उपकंडिका (२): चाहे यह शर्त राष्ट्रसभा ने मान ली थी पर यह जनतंत्रवाद के सिद्धांत के सर्वथा विरुद्ध थी तथा एक सम्प्रदाय को प्रगति में वाधा डालने की अनुमति देती थी।

व. यूरोपियन सदस्यों का प्रश्न : १६ वीं कंडिका में प्रतिनिधि मंडल से कुछ बुटियां रह गई थीं। एक तो यह कि आसाम श्रीर बंगाल की धारा सभाओं में ३४ यूरोपियन सदस्य थे जो कि 'व्यापक' सदस्यों के साथ मिल कर ७ प्रतिनिधि संविधान सभा में भेज सकते थे। यद्यपि प्रान्त में उनकी कुल जनसंख्या २१,००० थी। इसका श्र्य यह होता कि १८ वीं कंडिका की भावना के विहद 'व्यापक' सदस्यों में कुछ मुसलमानों का समर्थन करने वाले प्रतिनिधि श्रा जाते। यह याद रखने योग्य है कि 'ज' शाखा में व्यापक श्रीर मुसलमान प्रतिनिधियों की संख्या में केवल दो का अन्तर था, श्रतः वहां सात सदस्यों से ही बहुमत में बहुत श्रन्तर हो जाता। राष्ट्रसभा के श्रापत्ति उठाने पर प्रतिनिधि मंडल ने श्रपनी श्रटि मान ली श्रीर यूरोपियन सदस्यों से यह घोषणा करवादी कि वे मत नहीं देंगे तथा श्रपने प्रतिनिधि संविधान सभा में नहीं भेजेंगे। इस से यह ब्रुटि दूर हुई।

इसी कंडिका में कुर्ग तथा बल्चिस्तान के प्रतिनिधियों के निर्वाचन के बारे में राष्ट्रसभा ने कुछ श्रापत्ति की थी कि निर्वाचन ऐसा हो जिससे जनता के प्रतिनिधि श्रायें।

ज. वर्गीकरण, त्रानिवार्य या नहीं : सबसे अधिक मगड़े का प्रश्न वर्गीकरण का था जो इस योजना से और भी उलमन में पड़ गया। राष्ट्र सभा के प्रधान ने २० मई १६४६ के पत्र में निम्न आलोचना करके इस प्रश्न को स्पष्ट किया था:

"संविधान के आधारों के विषय में आपकी सिफारिशों की कंडिका ११ में लिखा है कि 'प्रान्त वर्ग बनाने के लिये स्वतन्त्र होने चाहियें जिन में कार्य पालिका तथा व्यवस्थापक मंडल हों तथा प्रत्येक वर्ग सामान्य रूप से रखने के

सांविधानिक वार्ता

विषयों का निर्णय कर सकें [कंडिका १४ की उपकंडिका (१)]।' इससे जरा पहले आप लिखन हैं कि, 'संघीय विषयों के अतिरिक्त सारे विषय तथा शेष अधिकार प्रान्तों में निहित होने चाहियें [कंडिका १४ (३)]।' किन्तु बाद में श्राप लिखते हैं [देखये कंडिका १६ की उपकंडिका (४) तथा (४)] कि 'संविधान सभा में प्रान्तों के प्रतिनिधि तीन शाखाओं में बट जायेंगे तथा वे शाखायें अपनी अपनी शाखा के प्रान्तों के लिये प्रान्तीय संविधान बनायेंगी तथा यह निश्चित करेंगी कि कोई वर्गीय संविधान बनाया जाये या नहीं।' इन दो पृथक पृथक उपबंधों में एक महान अन्तर दिखता है। आधारभूत उपबंधों में तो प्रान्तों को पूर्ण स्वतन्त्रता दो गई है कि वे जो चाहें करें, पर बाद में इस मामले में कुछ अनिवार्यता प्रतीत होती है जो कि उस स्वतन्त्रता का हनन करती है। यह ठीक है कि बाद में एक प्रान्त वर्ग में से निकल सकता है किन्त यह स्पष्ट नहीं है कि एक प्रान्त के उसके प्रतिनिधियों को अपनी इच्छा के विरुद्ध कुछ भी करने के लिये कैसे दुबाया जा सकता है। कोई प्रान्तीय व्यव-स्थापिका सभा अपने प्रतिनिधियों को कदाचित यह आदेश दे सकती है कि वे किसी वर्ग में या किसी विशेष वर्ग या शाखा में प्रवेश न करें। 'ब' तथा 'ज' शाखायें बनने से यह स्पष्ट है कि एक ही प्रांत शाखा में प्रमुख रहेगा, शाखा 'ब' में पंजाब श्रौर शाखा 'ज' में ब गाल। यह सम्भव है कि ये प्रमुख प्रान्त सिंध, सीमात्रान्त या त्रासाम की इच्छात्रों के सर्वथा विपरीत संविधान बना दें। ये कदाचित निर्वाचन के ऐसे नियम बनादें कि प्रान्तों के बाहर निकलने के उपबंध को भी व्यर्थ कर दें। ऐसी तो श्रापकी इच्छा नहीं हो सकती क्यों कि यह बात योजना के मूल सिड़ांतों तथा नीति के विरुद्ध होगी।"

गांधी जी ने इस योजना का यह ग्रर्थ निकाला कि वर्गीकरण श्रनिवार्य नहीं है। इस के उत्तर में प्रतिनिधि मंडल ने एक श्रोर वक्तव्य निकाल कर २४ मई को स्पष्ट किया कि उनकी इच्छा श्रनिवार्य वर्गीकरण की ही थी। इस पर महात्मा गांधी ने कहा कि "प्रतिनिधिमंडल विधिनिर्माता तथा न्यायालय दोनों नहीं बन सकता। योजना का श्रर्थ निकालने का श्रधिकार उन्हें नहीं है, यह कार्य कोई न्यायालय ही कर सकता है।" राष्ट्रसभा ने इसका यही श्रर्थ माना कि प्रान्तों को वर्ग में जाने या न जाने की स्वतन्त्रता है तथा इसी श्रर्थ को मान कर वे संविधान सभा में जाकर कार्य करने के लिये तैयार हो गये।

साविधानिक वाना

सभा के (वही समता के आधार पर), एक ईसाई तथा एक सिख होंगे। इसे लोभ में लीग ने १६ मई की योजना को यह कह कर स्वीकार कर लिया कि "हम पाकिस्तान बनाने की सम्भावना पर इसे मानते हैं तथा संविधान सभा में सिम्मिलित होकर यह ध्यान रखेंगे कि प्रांतों तथा वर्गों को संघ से निकलने का अधिकार तथा अवसर है।" उन्होंने यह भी कहा कि वे जब आवश्यक समर्भेंगे संविधान सभा से निकल सकते हैं। उधर सिखों में इस योजना से असन्तोष हुआ क्यों कि उनके लिये मुसलमानों के समान संरच्छा नहीं रखे गये थे और उनको सबल पाकिस्तानी वर्ग में डाल दिया गया था। पर उनकी आपत्तियों की अवहेलना कर दी गई।

१५. अन्तरिम सरकार के निर्माण विषयक वार्ता

श्रव श्रन्तिस्म सरकार के लिये वार्ता श्रारम्म हुई। वायसराय ने १६४४ के शिमला सम्मेलन के श्राधार पर यह योजना रखी कि श्रन्तिस्म सरकार में ४ राष्ट्रसमा के हिन्दू तथा ४ मुस्लिम लीग के मुसलमान, एक सिख तथा एक ईसाई लिया जाये श्रीर इसके श्रितिरेक्त यह भी नियम हो कि किसी बड़े साम्प्रदायिक निर्णय के लिये दोनों जातियों का बहुमत श्रावश्यक हो।

बदली हुई परिस्थितियों में यह प्रस्ताव अस्वीकार्य था। इसमें हरिजनों को एक स्थान पृथक न देकर हिंदुओं को और भी हानि पहुँचाई गई थी। समता का सिद्धांत तो बुरा था ही, समता के साथ साथ दोनों जातियों के बहुमत से प्रस्ताव स्वीकृत होने का नियम बुरा था। "दोनों मिल कर अन्तरिम सरकार का कार्य सर्वथा असम्भव कर देते तथा गतिरोध अवश्य होता" (राष्ट्र सभा का १३ जून का पत्र)। राष्ट्र सभा ने १२ के स्थान पर १४ सदस्यों का एक मन्त्रिमण्डल बनाने का सुक्ताव रखा क्यों कि इस से कम में सुचारु रूप से काम चलना असंभव था। राष्ट्रसभा अपना एक मुसलमान अवश्य रखना चाहती थी।

इस के अतिरिक्त विभागों के वितरण पर भी सममौता नहीं होता था। फिर लीग ने जो नाम दिवे उनमें एक ऐसा व्यक्ति था जो कि राष्ट्रसभा के प्रांत, सीमाप्रान्त का निवासी था तथा निर्वाचन में पराजित हो गया था। राष्ट्रसभा ने उस पर आपत्ति की तो वायसराय ने उत्तर में कहा "किसी दल को दूसरे दल के नामों पर आपत्ति करने का अधिकार नहीं है।" फिर वायसराय ने द राष्ट्रसभा तथा ४ लीग के तथा २ अन्य सदस्य लेकर मन्त्रिमण्डल बनाना

चाहा। इस में भी उसका उद्देश्य समता का था क्यों कि राष्ट्रसभा को १ हिंदू श्रोर १ हिरान रखने की श्रनुमित दी गई थी। वे मुसलमान नहीं रख सकते थे। यदि समता मान ली जाती तो लीग स्वतन्त्र भारत के प्रत्येक मंत्रिमण्डल में भी समता का दावा करती श्रोर जनतन्त्रवाद नष्ट हो जाता। सिद्धांतानुसार तो केवल राष्ट्रसभा को ही मिन्त्रमण्डल बनाने का श्राधकार था क्यों कि व्यवस्थापिका सभा में उसका बहुमत था। यदि विरोधी दल को लिया भी जाये तो समता केसी। इसके श्रतिरिक्त राष्ट्रसभा चाहुती थी कि पारसियों श्रीर श्रन्य छोटी जातियों को भी स्थान मिले तथा हरिजनों को कम से कम दो स्थान मिलें। लीग के प्रस्तावानुसार बहुसंख्यक हिंदू जाति को श्रल्पसंख्यक बनाने का प्रयत्न किया गया था जो घोर श्रन्थं था। यदि वायसराय के श्रनुस्तार किसी दल को दूसरे दलों के नामों पर श्रापत्ति करने का श्रधिकार नहीं था तो लीग को राष्ट्रसभा के मुसलमान पर भी श्रापत्ति नहीं हो सकती थी। इन कारणों से बहुत समय तक पत्र व्यवहार होता रहा परन्तु मिन्त्रमण्डल नहीं बन सका।

१६. राष्ट्रीय सरकार की स्थापना

राष्ट्रसभा ने २४ जून १६४६ के पत्र में १६ मई की योजना को अपने अर्थ के अनुसार मान लिया पर बिना राष्ट्रीय मुसलमान के अथवा समता के आधार पर अन्तरिम सरकार नहीं बनाई। अन्त में लीग से तंग आकर वाय-सराय ने राष्ट्र सभा के नये प्रधान पं० नेहरू को अन्तरिम सरकार बनाने का कार्य सौंप दिया। पं० नेहरू ने लीग को अपनी और से अन्तरिम सरकार में आमंत्रित किया पर उन्होंने उस निमंत्रण को ठुकरा दिया तो पं० नेहरू ने नवम्बर १६४६ में एक सरकार बनाली जिस में उन्होंने राष्ट्रसभा के हिंदू, हरिजन तथा मुसलमान के अतिरिक्त दो बाहर के मुसलमानों को भी ले लिया तथा दो तीन मुसलमानों के स्थान रिक्त भी छोड़ दिये। इन के साथ साथ एक पारसी, एक ईसाई और एक सिख भी लिया गया।

१७. लीग वालों के उपद्रव

इसपर लीग ने प्रवल विरोध आरंभ कर दिया तथा पूर्वी बंगाल के नवालाली जिले में अमुस्लिमों की हत्या, उनका माल जलाना, उनकी स्त्रियों पर अमानुषिक अत्याचार आदि आरम्भ कर दिये। उधर संविधान सभा के निर्वाचन हो चुके

सांविधानिक वार्ता

थे त्रोर उसकी प्रथम बैठक नई दिल्ली में १ दिसम्बरं ११४६ को होनी निश्चित हुई थी पर लीग ने उसमें भाग न लेने की घोषणा कर दी। दिसम्बर के त्रारम्भ में ब्रिटिश सरकार ने राष्ट्रसभा तथा लीग के नेतात्रों को एक बार ब्रिटेन बुलाकर समसौता करने की अन्तिम चेष्टा की पर यह भी असफल रही। लीग असहयोग पर अड़ी रही तथा देश भर में उपद्रव करने की तैयारी करती रही।

१८. संविधान सभा का उद्घाटन

१ दिसम्बर १९४६ को संविधान सभा का बड़ी धूम धाम से उद्घाटन हुआ। लीगी सदस्य अनुपस्थित थे। सदस्यों ने देशभिक्त की शपथ ली तथा डा० राजेन्द्र प्रसाद को अपना अध्यत्त चुना। पहले राष्ट्रसभा ने इस आशा में कि शायद लीग सहयोग करना आरम्भ करदे, धीरे धीरे कार्य आरम्भ कर दिया।२१ दिसम्बर १९४६ को देशी राज्य वार्ता समिति से बात चीत करने के लिये ६ सदस्यों की एक वार्ता समिति बनाई गई क्यों कि राज्यों के लिये रिक्त छोड़े हुये १३ स्थान भरना आवश्यक था। उसको बात करने के लिये निम्न विषय सौंपे गये:

- (अ) १६ मई १६४६ की प्रतिनिधिमंडल योजनानुसार राज्यों के लिये निश्चित अधिकतम ६३ स्थानों का राज्यों में बटवारा, तथा
- (ब) संविधान सभा में राज्यों के प्रतिनिधि भेजने की प्रणाली निश्चित करना।

जब लीग के श्राने की श्राशा ही नहीं रही तब संविधान सभा ने जन-वरी ११४७ के श्रन्त में श्रन्य कई समितियां नियुक्त की जिनके नाम तथा कार्यचेत्र निम्न लिखित थे:

१. २४ जनवरी १६४७ को नियुक्त अल्पसंख्यकों तथा मूलाधिकारियों पर परामर्श देने वाली समिति जिसके लिये प्रतिनिधि मण्डल की योजना की २० वीं कंडिका में उपबंध था। इस समिति के नेता सरदार बल्लभ भाई पटेल थे तथा इसमें ४४ सदस्य थे।

इस समिति ने निम्नलिखित उप-समितियाँ नियुक्त कीं :---

- (१) अल्पसंख्यक उपसमिति (२६ सदस्य)।
- (२) मूलाधिकार उप-समिति (१२ सदस्य)।
- (३) तीन उप-समितियाँ जो भारत के विभिन्न भागों में श्रादिम-जातीय लोगों के विषय में पड़ताल करने के लिये नियुक्त हुई थीं।
- २. २४ जनवरी १६४७ को नियुक्त संवीय अधिकार समिति जिसका कार्य यह निश्चित करना था कि संघ को दिये हुये तीन विषयों में तथा धन प्राप्त करने के अधिकारों में क्या क्या निहित है।
- ३. एक समिति २४ जनवरी १६४७ को नियुक्त हुई थी जो सभा का कार्यक्रम निश्चित करने के लिये थी।

पांचवां ऋध्याय भारत विभाजन और स्वराज्य

१. अवधि नियत

मुस्लिम लीग श्रीर राष्ट्रसभा के श्रसहयोग से ब्रिटिश सरकार चिंतित हो गई श्रीर श्रन्त में भारत को स्वतन्त्रता देने के लिए ३० जून १६४८ श्रन्तिम तिथि निश्चित करदी गई।

- २० जनवरी १६४७ को लोकसभा में बोलते हुए ब्रिटिश प्रधान मन्त्री श्री क्लोमेंट एटली ने कहा:
- "१, बहुत समय से ब्रिटिश सरकार की यह नीति रही है कि भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना करदी जाय। इसी नीति के अनुसार भारतीयों को अधिकाधिक दायित्व सोंपा जाता रहा है और आज नागरिक शासन तथा सेनाओं की बागडोर बहुत हद तक भारतीय असैनिक व सैनिक अफसरों के ही हाथ में है। वैधानिक चेत्र में भी, १६१६ तथा १६३४ में ब्रिटिश संसद द्वारा पास किए गए संविधानों द्वारा काफी राजनैतिक अधिकार भारतीयों को दिये गये थे। १६४० में संयुक्त सरकार ने इस सिद्धांत को मान लिया कि पूर्ण स्वतन्त्रता द्वारा भारतीयों को अपना संविधान स्वयं बनाना चाहिए और १६४२ के प्रस्ताव में तो उन्होंने उन्हें युद्ध के परचात इस कार्य के लिए एक संविधान सभा की स्थापना करने के लिए आमन्त्रित भी कर दिया।

- २. सम्राट की सरकार की धारणा है कि यह नीति सर्वोचित ग्रीर प्रजा-तन्त्रवादी सिद्धांतों के श्रनुकृत है। जब से उन्होंने शासन भार सम्हाला है इसकी पूर्त्ति के लिए भरसक प्रयत्न किया है। प्रधान मन्त्री के पिछले १४ मार्च के वक्तव्य द्वारा, जिसे संसद तथा देश में श्रनुमोदन प्राप्त हुश्रा था, यह स्पष्ट कर दिया गया था कि भारत की भावी कि़्शति तथा संविधान के सम्बन्ध में निश्चय करना भारतीयों का ही कार्य है श्रीर सम्राट की सरकार के मता-नुसार श्रव वह समय श्रा गया है जब भारत सरकार का दायित्व भारतीयों ही के हाथों में सौंप दिया जाय।
- ३ भारत भेजे जाने वाले मन्त्री प्रतिनिधि मण्डल ने पिछले वर्ष भारतीय नेताओं से विचार विनिमय करने में तीन मास से अधिक समय ज्यतीत किया जिससे कि भावी संविधान की रूपरेखा आपस में तय की जा सके और शक्ति सोंपने का कार्य सुगमता तथा शीव्रतापूर्वक सम्पन्न हो सके। जब मन्त्री प्रतिनिधि मण्डल को यह विश्वास हो गया कि उनके पहल किए बिना कोई समभौता हो ही नहीं सकता, तभी उन्होंने अपने प्रस्ताव पेश किये।
- ४. यह प्रस्ताव पिछली मई में जनता के सम्युख प्रस्तुत किए गए थे। इनके अनुसार यह निश्चय किया गया था कि भारत का भावी संविधान विश्वित ढंगों से स्थापित संविधान सभा द्वारा बनाया जाय और इस सभा में सब भारतीयों एवं वृटिश भारत तथा देशी राज्यों के प्रतिनिधि सम्मिलित हों।
- ४. प्रतिनिधि मण्डल के लौट आने के बाद से केन्द्र में बहुसंख्यक जातियों के राजनैतिक नेताओं की एक अन्तःकालीन सरकार स्थापित करदी गई है जिसे वर्तमान संविधान के अन्तर्गत विशाल अधिकार प्राप्त हैं। सब प्रान्तों में व्यवस्थापिका सभाओं के प्रति उत्तरदायी भारतीय सरकारें ही शासन कर रही हैं।
- ६. सम्राट की सरकार के लिए यह खेद का विषय है, कि अभी तक भारतीय दलों में मतभेद है जिनके कारण संविधान सभा के सुचार कार्य में बाधाएं उपस्थित हो रही हैं—जिसके लिए सभा की स्थापना हुई थी। इस योजना का सार यह है कि यह सभा पूर्णरूप से प्रतिनिधित्व करने वाली होनी चाहिए।

भारत विभाजन श्रीर स्वराज्य

जून १६४८ तक शक्ति सौंप दी जायगी

७. सम्राट को सरकार की यह इच्छा है कि मंत्रीप्रतिनिधि मण्डल की योजना के अनुसार, भारत के विभिन्न दलों की स्वीकृति से बनाए गए संविधान द्वारा निश्चित अधिकारियों के अपना दायित्व सोंप दिया जाय। किंतु दुर्भाग्यवश ऐसे संविधान तथा अधिकारियों का अस्तित्व में आजाना इस समय सम्भव नहीं मालूम होता। वर्तमान अनिश्चित स्थिति विपद की आशंकों से परे नहीं है और ऐसी स्थित अनिश्चित समय तक रहने भी नहीं दी जा सकती। सम्राट की सरकार स्पष्टरूप से अपने इस निश्चय को सूचित कर देना चाहती है कि वह जून १६४८ तक उत्तरदायी भारतीयों के हाथ में शिक्त सींप देने के कार्य को सम्पन्न कर देगी।

विभाजन की सम्भावना

- म्, महीनों के किन परिश्रम के बाद मन्त्री प्रतिनिधि मण्डल संविधान निर्माण की बहुत हद तक स्वीकृत परिपाटि द्वंढ लेने में सफल हुआ था। यह उनके पिछली मई के कथनों में स्पष्ट कर दिया गया था। सम्राट की सरकार ने तब यह स्वीकार कर लिया था कि वे पूर्ण प्रतिनिधित्व प्राप्त संविधान सभा द्वारा इन प्रस्तावों के अनुसार बनाये गए संविधानों की संसद में सिफारिश करेगी। किन्तु यदि उपरोक्त ७वें पैरे में निश्चित की गयी तिथि तक सब प्रकार से प्रतिनिधित्व पूर्ण सभा द्वारा ऐसा संविधान न बनाया जा सका, तो सम्राट की सरकार को यह विचार करना पड़ेगा कि बिटिश भारत की केन्द्रीय सरकार को, या विभक्त करके वर्तमान प्रांतीय सरकारों को अथवा किसी ऐसे ढंग से जो सर्वोचित तथा भारतीयों के लिए सर्वाधिक लाभपूर्ण हो, सत्ता सौंपी जाय।
- ६ यद्यपि जून १६४८ तक पूर्ण दायित्व सोंपा जाना शायद सम्भव न हो सके तब भी उसके लिए आवश्यक तैयारियां तो पहले से ही होनी चाहियें। यह आवश्यक है कि नागरिक अधिकारियों की कार्यचमता का मापद्गड उतना ही ऊंचा रखा जाय जितना अब तक रहा है तथा भारत की रचा का कार्य सुचारु रूप से हो। किन्तु यह निश्चित है कि ज्यों-ज्यों दायित्व सौंपने का कार्य आगे बढ़ता जायगा १६३४ के भारत शासन अधि-नियम की शतोंं को निभाना अधिकाधिक कठिन होता जायगा। निश्चित समय पर पूर्ण रूप से दायित्व सौंपने का उपबन्ध लागू हो जायगा।

देशी रियासतें श्रीर सम्राट

- १० जैसा कि मंत्री श्रतितिधिमण्डल द्वारा साफ साफ बताया गया था, सम्राट की सरकार श्रपनी श्रभुशिकत के श्रंतर्गत भारतीय रियासतों को ब्रिटिश भारत की किसी भी सरकार के सुपुर्द नहीं करना चाहती। श्रन्तिम रूप से दायित्व सौंपने से पहले सम्राट की श्रभुशिकत का श्रन्त कर देने की कोई इच्छा नहीं है किन्तु यह विचार किया जा रहा है कि इस श्रन्तिरम काल में व्यक्तिगत रूप से सम्राट हर देशी रियासत से पारस्परिक परामर्श द्वारा श्रपने सम्बन्ध स्थिर कर लें।"
- 19. दायित्व तथा तत्सम्बन्धी समभौतों के लिए सम्राट की सरकार उन दलों के प्रतिनिधियों से बातचीत करेगी जिनको वह दायित्व सौंपने का निश्चय करेगी।"

२. लीग भी मन्त्रिमएडल में

इस घोषणा से अं प्रेजों की सच्चाई प्रकट होने के अतिरिक्त भारतीय दलों में शीव्रता की भावना उत्पन्न हो गई जिस का बड़ा भारी प्रभाव हुआ। प्रथम तो लीग प्रयत्न कर करा कर केन्द्रीय मिन्त्रमण्डल में आ गयी जिस से कि तत्कालीन सरकार को ३० जून १६४८ को शक्ति मिल गई तो लीग उससे बंचित न रहे। किन्तु मिन्त्रमण्डल में उन्होंने रोड़े अटकाने आरम्भ कर दिए जिससे राष्ट्र सभा दुखी हो गई तथा शासन-व्यवस्था बिगड़ गयी।

दूसरे लीग ने संविधान सभा से बाहर रहने में ही लाभ समका क्यों कि उसे श्राशा थी कि संविधान सभा पूर्णरूपेण प्रतिनिधि नहीं होगी तो उसका बनाया हुश्रा संविधान मुस्लिम प्रदेशों पर लागू न होगा तथा इसी प्रकार उसे पाकिस्तान मिल जायेगा। किन्तु यह छोटा या लँगड़ा पाकिस्तान ही हो सकता था जिस में श्रासाम, पूर्वी पंजाब तथा पश्चिमी बंगाल नहीं श्रा सकते थे। श्रव हठधर्म के कारण लीग इस के लिए भी तैय्यार थी।

३. पुन: लीगी उपद्रव तथा प्रान्तीय विभाजनों की मांग

तीसरे लीग ने पश्चिमी पंजाब में भी हिन्दू विरोधी उपद्रवों का श्री-गगोश कर दिया जिससे हजारों हिन्दू मारे गए तथा शेष "मुस्लिम प्रदेश" को

भारत विभाजन श्रौर स्वराज्य

खाली करके भागने लगे। इन उपद्रवों में पंजाब की मुसलमान सरकार सहायता करती थी श्रोर ऐसी ही परिस्थिति पूर्वी बंगाल में थी। श्राखिर पंजाब के हिन्दुश्रों तथा सिखों ने पंजाब विभाजन की मांग श्रारम्भ कर दी जिससे कि श्राधे प्रान्त में तो उनकी सरकार बन कर उनका संरच्या कर सके। हिन्दू महासभा के नेता श्री श्यामश्रमाद मुखर्जी श्रादि ने बंगाल विभाजन की भी मांग श्रारम्भ कर दी।

४. राष्ट्रसभा द्वारा पाकिस्तान स्वीकार

राष्ट्रसभा ने बदली हुई परिस्थितियों में यह अच्छी प्रकार से अनुभव कर लिया कि मुस्लिम लीग के साथ अब या स्वतन्त्र भारत में निर्वाह हो ही नहीं सकता तथा ३० जून १६४८ तक तो लीग देश भर की शांति ज्यवस्था को नष्ट-अष्ट कर देगी। प्रतिनिधि मण्डल की वर्गींकरण योजना से अब देश भर को भय होने लगा क्यों कि यह प्रकट हो गया कि मुस्लिम वर्गों में अमुस्तिमों के लिए कोई स्थान नहीं है। अतः राष्ट्रसभा ने मुस्लिम प्रदेशों को भारत से पृथक करने की स्वीकृति देवी तथा मुस्लिम लीग ने भी छोटा पाकिस्तान मान लिया।

५. ब्रिटिश सरकार की भारत विभाजन घोषणा

ब्रिटिश सरकार ने भी यह सोच कर कि भारत में होने वाले रक्तपात का उत्तरदायित्व अपने ऊपर लेना उचित न होगा, ३ जून को घोषणा कर दी कि भारत का विभाजन होगा तथा ३० जून १६४८ के स्थान पर कुछ मास में ही भारत में दो अधिराज्य बना दिये जायेंगे। भारत विभाजन के साथ साथ पंजाब तथा बंगाल का भी विभाजन करने का निश्चय किया गया। दोनों दलों ने निपटारे के लिये यह योजना मान ली क्योंकि लीग तो पाकिस्तान पाकर प्रसन्न थी चाहे वह छोटा ही था तथा राष्ट्रयभा इसलिए प्रसन्न थी कि उसके पास ८० प्रतिशत भारत रह जाता था। ३ जून १६४७ की घोषणा को इतनी शीव्रता से कार्यान्वित किया गया कि १४ अगस्त १६४७ तक भारत में दो स्वतन्त्र अधिराज्य बन गये। ३ जून की घोषणा के अंश नीचे दिये जाते हैं।

"१. २० जनवरी १६४७ को बादशाह की सरकार ने ऋपनी यह इच्छा घोषित की थी कि वह ब्रिटिश भारत में ऋपने ऋधिकारों को जून १६४८ तक

भारतीयों को हस्तान्ति रित कर देगी। उन्हें आशा थी प्रमुख दलों के लिये यह सम्भव हो सकेगा कि वे प्रतिनिधि मण्डल की १६ मई १६४६ की योजना को कार्यान्वित करने में पारस्परिक सहयोग करें तथा भारत के लिये एक संविधान बनायें। यह आशा पूर्ण नहीं हुई है।

- २. मद्रास, बम्बई, युक्त प्रांत, बिहार, मध्य प्रांत, आसाम, उड़ीसा, मीमा प्रांत के बहु संख्यक प्रतिनिधि तथा दिल्ली, अजमेर मेरवाड़ तथा कुर्ग के प्रतिनिधि एक नया संविधान बनाने के कार्य में प्रगति कर चुके हैं। दूसरी छोर मुस्लिम लीग दल ने जिसमें बिटिश बिल्चिस्तान का प्रतिनिधि तथा बंगाल, पंजाब श्रीर सिंध के बहुसंख्यक प्रतिनिधि सम्मिलित हैं संविधान सभा में भाग न लेने का निर्ण्य किया है।
- ३......भारतीय राजनैतिक दलों में समभौता न होने के कारण बादशाह की सरकार ने भारत के राजनैतिक नेतात्रों से खूब विचार विनिमय कर के इसके लिये निम्न योजना बनाई है.....।
- थ. बादशाह की सरकार की यह इच्छा है कि वर्तमान संविधान सभा के कार्य को बीच में न रोका जाये। अब क्यों कि निम्न विश्ति प्रांतों के लिये उपबंध कर दिये जाते हैं, अतः ब्रिटिश सरकार को विश्वास है कि इस घटना के परिणाम स्वरूप संविधान सभा में संलग्न प्रांतों के मुस्लिम लीगी प्रतिनिधि भी अब इसमें अपना उपयुक्त भाग ले सकेंगे। साथ ही यह भी स्पष्ट है कि इस संविधान सभा द्वारा निर्मित संविधान देश के उन भागों पर लागू नहीं हो सकता जो कि इसे स्वीकार करने के इच्छुक नहीं हैं। बादशाह की सरकार को संतोप हो गया कि निम्नांकित प्रणाली उन प्रदेशों की इच्छा जानने की उत्त-मोत्तम क्रियात्मक परिपाटी है कि वे अपना संविधान—
 - (श्र) वर्तमान संविधान सभा से बनवायेंगे, या
 - (ब) किसी नवीन तथा पृथक संविधान सभा से बनवायेंगे जिस में कि वर्तमान सभा में भाग न लेने के इच्छुक प्रदेशों के प्रतिनिधि होंगे।

जब यह हो चुकेगा, तब यह निश्चय करना संभव होगा कि किस प्राधिकारी या प्राधिकारियों को सत्ता हस्तान्तरित की जानी चाहिये।

भारत विभाजन और स्वराज्य

१. बंगाल और पंजाब की न्यवस्थापिका सभाओं को पृथक पृथक कहा जायेगा कि वे यूरोपियन सदस्यों रहित दो भागों में एकत्रित हों। एक भाग सुस्लिम बहुल जिलों का तथा दृसरा शेष प्रांत का प्रतिनिधि होगा। जनसंख्या के विषय में १६४१ के दुंसंख्या के खंक माने जावेंगे। सुस्लिम बहुल जिले इस घोषणा की अनुसूची में दिये हैं।

अनुसूची में वर्णित जिले

 पंजाब में :---लाहीर श्रेणी के : गुजरावाला, गुरुदासपुर, लाहीर, शेखुपुरा, स्यालकोट।

रावलपिंडी श्रेगी के : त्राटक, गुजरात, भेलम, मियांवाली, रावलपिंडी शाहपुर ।

मुलतान श्रेणी के : डेरा गाजी खां, भांग, लायलपुर, मिंटगुमरी, मुल-तान, मुजफ्फर गढ़।

(२) बंगाल में:--

चटगांव श्रेशी के : चटगांव, नवाखाली, तिप्परा ।

ढाका श्रेणी के : बकरगंज, ढाका, फरीदपुर, मैननसिंह।

प्रादेशिक श्रेणी के : जैसोर, मुर्शीदावाद, नादिया।

राजशाही श्रेणी के : बोगरा, दिनजपुर, मालदा, पबना, रंगपुर, राजशाही।

६. प्रत्येक व्यवस्थापिका सभा के दो भागों के सदस्य यह मत देने के अधिकारी होंगे कि प्रांत विभाजित हो या न हो। यदि किसी भाग ने केवल बहुमत से विभाजन का निर्णय किया तो विभाजन हो जायेगा तथा तदनुसार व्यवस्था की जायेगी।

용 용 왕 왕

- द्र. विभाजन का निर्णय होने पर व्यवस्थापिका का प्रत्येक भाग श्रपने प्रदेशों की श्रोर से यह निर्णय करेगा कि उपयुक्त कंडिका ४ में उल्लिखित किस मार्ग पर चलें।
- ६. सीमा आयोग:यह अल्पकाल के लिये केवल एक प्रारम्भिक कार्य है क्यों कि यह स्पष्ट है कि इन प्रांतों के अंतिम विभाजन के लिये सीमा विषक प्रश्नों के विस्तृत अनुसंधान की आवश्यकता होगी, तथा ज्यों ही किसी प्रांत के लिये विभाजन का निर्णय हो जावेगा त्यों ही एक सीमा आयोग

गवर्नर जनरल द्वारा नियुक्त किया जायेगा जिस के सदस्यों तथा कार्यचेत्र के विषय में सम्बन्धित व्यक्तियों से परामर्श कर लिया जायेगा। इसको निदेश दिया जायेगा कि पंजाब के दो भागों में मुस्लिम तथा अमुस्लिम बहुल प्रदेशों की सीमा निर्धारित करे। इसको अन्य परिस्थितियों को भी ध्यान में रखने का निदेश होगा। बंगाल सीमा आयोग को भी ऐसे ही निदेश होंगे। जब तक सीमा आयोग का निर्ध्य कार्यान्वित न हो तब तक अनुसूची में निर्दृष्ट प्रांतीय सीमार्थे प्रयुक्त होंगी।

- १०. सिंध : सिंध की न्यवस्थापिका सभा भी यूरोपियन सदस्यों रहित एक विशेष बैठक में कंडिका चार के विषय में अपना निर्णय करेगी।
- ११. सीमाप्रांत की स्थिति विशेष है। इस प्रांत के तीन में से दो प्रति-निधि वर्तमान संविधान सभा में इस समय भाग ले रहे हैं। किन्तु भौगोलिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए तथा अन्य कारणों से यह स्पष्ट है कि यदि सारा पंजाब या उसका एक भाग वर्तमान संविधान सभा में न मिलने का निर्ण्य करे तो सीमा प्रान्त को अपनी स्थिति पर पुनर्विचार करने का अवसर देना आव-रयक होगा। तद्नुसार वहां की धारा सभा के निर्वाचकों का मत लिया जायेगा कि वे कंडिका ४ में निर्दृष्ट किस मार्ग पर चलना चाहते हैं।
- १२. ब्रिटिश बल्चिस्तान में भी उस प्रांत का मत जानने के लिये गवर्नर जनरल कोई मार्ग निकालेगा।
- १३. श्रासाम: यद्यपि श्रासाम हिन्दू बहुल प्रांत हैं तथापि सिलहट का जिला, जो बंगाल से स्पर्श करता है, मुख्यतः मुस्लिम है।.......यि बंगाल विभाजन का निर्णय हो जाता है तो सिलहट में मत लिए जायेंगे कि वह श्रासाम में रहे या पूर्वी बंगाल में मिल जाए। यि बंगाल में मिल का निरचय हुश्रा तो उसके लिए भी बंगाल तथा पंजाब के समान एक सीमा श्रायोग बनेगा जो सिलहट तथा स्पर्श करने वाले श्रन्य जिलों के मुस्लिम भागों को पृथक करेगा तथा वे पूर्वी बंगाल में मिला दिए जायेंगे। शेष श्रास्म वर्तमान संविधान सभा में भाग लेता रहेगा।

दोनों संविधान सभात्रों में प्रतिनिधित्व

१४. यदि यह निर्णय हो जाए कि बंगाल और पंजाब विभाजित होंगे तो प्रतिनिधि मण्डल योजना के अनुसार उनके प्रतिनिधियों को १० लाख के

भारत विभाजन और स्वराज्य

पीछे १ के क्रम से पुनः चुनना श्रावश्यक होगा। यदि सिलहट पूर्वी बंगाल में मिलने का निर्णय करते तो उसके विषय में भी इसी प्रकार निर्वाचन होंगे। प्रत्येक प्रदेश को निम्न संख्या में प्रतिनिधि चुनने का श्रधिकार होगा:

श्रान्त	व्यापक	मुस्लि म	सिख	योग
सिलहट जिला	3	२	:	३
पश्चिमी बंगाल	14	8	:	38
पूर्वी बंगाल	9 9	35	:	83
पश्चिमी पंजाब	ર	98	2	30
पूर्वी पंजाब	ξ	8	2	9 2
終	<i>&</i> ,	ę <u>ę</u> ,	₩	

शासन व्यवस्था

- १६. विभाजन का निर्णय होने पर यथासम्भव शीघातिशीघ्र विभाजन के प्रशासन विषयक परिणामों के विषय में
 - (अ) केन्द्रीय सरकार द्वारा संभाले हुए विषयों पर, जिन में सुरत्ता, धन, यातायात भी हैं, दोनों उत्तराधिकारी सरकारों के बीच,
 - (ब) सत्ता हस्तान्तरित करने से सम्बद्ध विषयों पर उत्तराधिकारी सर-कारों तथा बादशाह की सरकार के बीच,
 - (ज) विभाजित होने वाले प्रान्तों के विषय में प्रान्तीय विषयों की व्य-वस्था के लिये यथा सम्पत्ति और ऋण, पुलिस तथा श्रन्य सेवाओं, उच्च न्यायालय, प्रान्तीय संस्थाओं श्रादि के विभाजन के लिये, वार्ता प्रारम्भ करनी होगी।

& & & & &

देशी राज्य

१८. बादशाह की सरकार यह स्पष्ट कर देना चाहती है कि उपरोक्त विनिश्चय केवल ब्रिटिश भारत के विषय में हैं तथा उन से देशी राज्यों के विषय में प्रतिनिधि मंडल द्वारा घोषित नीति में कोई अन्तर न श्रायेगा।

왕 왕 왕 왕

तत्काल सत्ता हस्तान्तरित होगी

२०. मुख्य राजनेतिक दलों ने वार बार यह इच्छा प्रकट की है कि सत्ता हस्तांतिरत करने का कार्य शीवाितशीव होना चाहिये। बादशाह की सरकार को इस इच्छा से पूर्ण सहानुभूति है तथा वे ३० जून १६४८ से पहले भी शीव ही स्वतन्त्र भारत की सरकार या सरकारें बनाने के लिये तैयार हैं। इस इच्छा को पूरी करने की अध्यन्त सुविधाजनक तथा एकमात्र व्यवहारिक प्रणाली के अनुसार ब्रिटिश सरकार का विचार है कि वह इस घोषणा के अनुसार विभाजन का निर्णय होने पर वर्तमान अधिवेशन में ही विधेयक रखेगी जिससे कि इसी वर्ष एक या दो सरकारों को, जैसे भी निर्णय हो, इस वर्ष के अंत तक अधिराज्य पद के आधार पर सत्ता हस्तांतरित कर दी जाये। इस से संविधान सभाओं का यह अधिकार नहीं छिनेगा कि वह उचित समय पर यह निश्चित करे कि जिस प्रदेश पर उसका अधिकार है वह ब्रिटिश राष्ट्र मंडल में रहेगा या नहीं।"

६. पाकिस्तान सम्बन्धी आंकड़े

उपर्यु क्त घोषणा के पश्चात सिलहट, पश्चिमी पंजाब, पृवीं बंगाल, सिंध तथा ब्रिटिश बल्चिस्तान ने घोषणा के अनुसार अपना निर्णय किया तथा वे सब पाकिस्तान में मिलने के पन्न में थे।

सीमाप्रान्त राष्ट्रसभा का प्रान्त था किन्तु अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण उनके लिए भारत में मिलना असम्भव था। अतः उन्हों ने मांग की कि उनसे जनमत-गणना में यह पूछा जाए कि ने पाकिस्तान में मिलना चाहते हैं अथवा स्वतन्त्र होना चाहते हैं। पर ब्रिटिश सरकार ने केवल उनसे यही पूछा कि 'आप पाकिस्तान में मिलना चाहते हैं या भारत में।' इसके विरोध स्वरूप राष्ट्रसभा के समर्थकों ने जनमत-गणना में भाग नहीं लिया। अतः सीमाप्रांत का निर्णय भी पाकिस्तान के पत्त में ही माना गया, यद्यपि वहां अधिकांश मत दाताओं ने जनमत-गणना में भाग नहीं लिया था।

श्चन्त में गवर्नर जनरल ने पाकिस्तानी प्रदेश के लिए एक पृथक संविधान सभा बनवादी तथा विभाजन कार्य श्चारम्भ हो गया। जो भाग पाकिस्तान में चले गए उनका चेत्रफल तथा जन संख्या निम्न प्रकार हैं:—

भारत विभाजन और स्वराज्य

	चेत्र फ त	कुत्तं जनसंख्या	मुस्लिम	त्रमुस्तिम
पूर्वी पाकिस्तान (पूर्वी बंगाल तथा सिलहट)	¥€,008	४,४१ लाख	३,०६ लाख	१४४ लाख
(पूर्वी बंगाल तथा	वर्गमोल			
सिलहट)	J			
पश्चिमी पाकिस्ता	न १,⊏०,६२० वर्गमील —————	२,४० ल(ख	१,८० लाख	७० लाख
योग	२,३६,६२६ वर्गमील	७,०१ लाख	४,८६ लाख	२,१४ लाख

सीमा आयोगों ने इस में साधारण से परिवर्तन किए थे।

विभाजन का निर्णय होते ही एक विभाजन कार्यालय खोला गया तथा प्रत्येक विभाग के लिए विभाजन विशेषज्ञ सिमितियां नियुवत हुई और उनके ऊपर एक मन्त्रिमण्डल की 'विशेष सिमिति' भी बनाई गई। इन सिम-तियों ने अत्यधिक द्रतगित से भारत विभाजन कर डाला।

७. भारतीय स्वतन्त्रता अधिनियम

१८ जुलाई १९४७ को बादशाह ने संसद द्वारा स्वीकृत श्रधिनियम पर हस्ताचर कर दिए जिसका उद्देश्य "भारत में दो स्वतन्त्र श्रधिराज्यों को स्थापित करना" था। इस में लिखा थाः

- धारा १ नये ऋधिराज्य : (१) १४ श्रगस्त १६४७ से भारत में दो स्वतन्त्र ऋधिराज्य स्थापित होंगे जो भारत तथा पाकिस्तान कहलायेंगे।
- (२) कथित अधिराज्य इस अधिनियम में 'नवीन अधिराज्य' के नाम से पुकारे जार्थेंगे तथा कथित १४ अगस्त को 'नियुक्त दिवप' के नाम से पुकारा जाएगा।
- धारा २. नवीन ऋधिर। ज्यों के प्रदेश: (१) इस धारा की उप-धाराओं (३) तथा (४) के अन्तर्गत भारत के राज्यचेत्र में वे प्रदेश सम्मिलित होंगे जो कि नियुक्त दिवस के ८ हले ब्रिटिश भारत में सम्मिलित थे किन्तु वे

प्रदेश नहीं होंगे जो कि इस धार∵की उपधारा (२) के श्रनुसार पाकिस्ताम के प्रदेश होंगे।

- (२) इस धारा की उपधारा (३) तथा (४) के अन्तर्गत पाकिस्तान के निम्न लिखित प्रदेश होंगे।
 - (ग्र) वे प्रदेश जो श्रागामी दो धाराश्रों के श्रनुसार नियुक्त दिवस को पूर्वी बंगाल श्रीर पश्चिमी पंजाब में सम्मिलित किए जायेंगे।
 - (ब) वे प्रदेश जो इस अधिनियम की स्वीकृति के समय सिंध प्रांत तथा ब्रिटिश बल्चिस्तान के चीफ किमश्नरी प्रान्तों में निहित हैं, तथा
 - (ज) यदि नियुक्त दिवस के पहले गवर्नर जनरल यह घोषणा कर दे कि सीमाप्रान्त में हुए जनमत संग्रह में बहुमत पाकिस्तान संवि-धान सभा में भाग लेने के पत्त में है तो वे प्रदेश जो उस प्रांत में निहित्त हैं।
- (३) इस धारा का अर्थ यह नहीं होगा कि किसी प्रदेश को किसी नवीन अधिराज्य में मिलना या उससे पृथक होना वर्जित है, किन्त
 - (अ) कोई प्रदेश जो उपधारा (१) या (२) में वर्णित प्रदेशों में सम्मिलित नहीं है वह उस सम्बन्धित अधिराज्य की इच्छा के विना उस में सम्मिलित नहीं हो सकता।
 - (ब) कोई प्रदेश जो उपधारा (१) के प्रदेश या उपधारा (२) के प्रदेश मेंसम्मिलित हैं या जो 'नियुक्त दिवस' के पश्चात उसमें सम्मि-लित कर लिया गया है वह उस ग्राधिराज्य की इच्छा के बिना उससे प्रथक नहीं किया जा सकता।
- (४) उपधारा (३) के उपबन्धों की न्यापकता के विपरीत न होते हुए इस धारा का यह भी ऋर्थ नहीं लगाया जाएगा कि देशी राज्यों का किसी नवीन ऋधिराज्य में मिलना वर्जित है।

धारा ३ बंगाल तथा त्रासाम:

- (१) नियुक्त दिवस से :
 - (म्र) ११३४ के भारतीय संविधान के अन्तर्गत जो बंगाल प्रांत है उसका म्रस्तित्व नहीं रहेगा, तथा

भारत विभाजन और स्वराज्य

- (ब) इस के स्थान पर दो नए प्रांत बन जायेंगे जो कि पूर्वी ब गाल तथा पश्चिमी ब गाल कहलायेंगे।
- (२) यदि 'नियुक्त दिवस' से पहले गवर्नर जनरल यह घोषणा करदे की सिलहट जिले में हुये जनमत संग्रह में बहुमत सिलहट को पूर्वी बंगाल का भाग बनाने के पत्ते में है तो उस दिन से आसाम प्रान्त का एक भाग इस धारा की उपधारा (३) के अनुसार पूर्वी बंगाल के नवीन प्रान्त का भाग बन जायेगा।
- (३) उहिलाखित नवीन प्रान्तों की सीमायें, तथा उपधारा (२) में उहिल-खित अवस्था होने पर आसाम की सीमायें वे होंगी जो कि गवर्नर जनरल द्वारा नियुक्त सीमा निर्णायक आयोग के निर्णय से निश्चित हों, किन्तु तब तक:
 - (ग्र) इस अधिनियम के प्रथम अनुसूची में लिखित बंगाल के जिले, तथा उपधारा (२) वाली अवस्था होने पर आसाम का सिलहट जिला पूर्वी बंगाल के नये प्रान्त में समका जायेगा।
 - (ब) बंगाल प्रान्त के शेष प्रदेश नवीन पश्चिमी बंगाल में समाविष्ट समक्षे जायेंगे।
 - (ज) उपधारा (२) की श्रवस्था होने पर सिलहट श्रासाम् प्रान्त में से निकल जायेगा।
 - (४) इस धारा में निर्णय का अर्थ है सीमा आयोग के अध्यक्त का निर्णय जो कि वह अन्त में अपनी रिपोर्ट में गधर्नर जरनल को प्रस्तुत करे।

सूचनाः प्रथम श्रनुसूची में उल्लिखित जिले ये थे ः चटगांव, नवाखाली, तिप्परा, बकरगंज, ढाका, फरीदपुर, सेमनसिंह, जैसोर, मुरशीदाबाद, नादिया, बोगरा, दिनाजपुर, मालदा, पबना, राजशाही, रंगपुर।

धारा ४. पंजाब :

- १ नियुक्त दिवस से :
- (श्र) ११३४ के भारतीय शासन श्रधिनियम के कथित पंजाब प्रान्त का श्रस्तित्व नहीं रहेगा।

- (ब) दो नये प्रान्त बना दिये जायेंगे जो पूर्वी पंजाब तथा पश्चिमी पंजाब कहलायेंगे।
- (२) कथित नये प्रान्तों की सीमायें वे होंगी जो कि गवर्नर जनरल द्वारा नियुक्त सीमा श्रायोग के निर्णय से निश्चित हों, किन्तु इस निर्णय तक
 - (अ) इस अधिनियम के द्वितीय अनुसूची में उल्लिखित जिले नवीन पश्चिमी पंजाब के प्रदेश समक्षे जायेंगे।
 - (ब) पंजाब प्रान्त के शेष िलं नवीन पूर्वी पंजाब प्रान्त के प्रदेश समभे जायेंगे।
- (३) इस धारा में निर्णय का त्रार्थ है सीमा समिति के अध्यत्त का निर्णय जो कि वह कार्य के अन्त में अपनी रिपोर्ट में गवर्नर जनरल की प्रस्तुत करें।

द्वितीय अनुसूची में निम्न जिले वर्णित थे : गुजरांवाला, गुरदासपुर, लाहौर, शेखुपुरा, सयालकोट, अटक, गुजरात, भेलम, मियांवाली, शाहपुर, डेरा गांजीखां, भंग, लायलपुर, मिंटगुमरी, मुलतान तथा मुज्जकरगढ़।

धारा ४: नवीन ऋधिराज्य का गवर्नर जरनल: प्रत्येक नवीन अधिराज्य के लिये एक गवर्नर जरनल होगा जो कि बादशाह द्वारा नियुक्त होगा तथा उस ऋधिराज्य के शासन के हेतु बादशाह का प्रतिनिधि होगा।

किन्तु जब तक किसी श्रधिराज्य का व्यवस्थापक मण्डल इसके विप-रीत उपबंध न करे तब तक एक ही व्यक्ति दोनों श्रधिराज्यों का गवर्नर जनरल रह सकता है।

- धारा ६: नये उपनिवेशों के व्यवस्थायक मंडल (१) दोनों नवीन अधिराज्यों के व्यवस्थायक मंडलों को अपने अधिराज्य के लिये अधि-नियम बनाने की पूर्ण शक्ति होगी तथा वे प्रदेश के बाहर प्रभाव रखने वाले अधिनियम भी बना सकते हैं।
- (२) किसी नवीन श्रधिराज्य के व्यवस्थापक मंडलों द्वारा निर्मित किसी श्रिधिनियम का कोई उपबंध इस कारण श्रनियमित या प्रभावहीन

भारत विभाजन और स्वराज्य

नहीं होगा कि वह ब्रिटेन के किसी अधिनियम के विरुद्ध है या इस अधिनियम या िस्सी ब्रिटिश संसद के किसी अन्य वर्तमान या भावी अविनियम के विरुद्ध है या ऐसे किसी अधिनियमके अन्तर्गत बने हुए किसी नियम, उपनियम या आज्ञा के विरुद्ध है और अत्येक अधिराज्य के व्यवस्थापक मण्डल में भी शक्ति होगी कि वह ऐसे किसी अधिनियम, नियम, उपनियम, या आज्ञा को रद्द कर सकता है जहां तक कि वह उस अधिराज्य पर लागू हो।

- (३) प्रत्येक नवीन अधिराज्य के गवर्नर जनरल को पूर्ण अधिकार होगा कि वह बादशाह के नाम से उस अधिराज्य के व्यवस्थापक मण्डल के किसी अधिनियम की स्वीकृति दे सकता है तथा किसी अधिनियम का वह भाग, जो कि अधिनियमों को बादशाह द्वारा अस्वीकृत करने या उन्हें बादशाह की स्वीकृति के लिये रखने या वादशाह की स्वीकृति मिलने तक उनको रोकने के सम्बन्ध में हो, किसी नवीन अधिराज्य के व्यवस्थापक मण्डल के अधिनियमों पर लागू नहीं होगा।
- (४) ब्रिटिश संसद का कोई अधिनियम जो 'नियुक्त दिवस' को या तत्परचात स्वीकृत हो, किसी नवीन अधिराज्य पर लागू नहीं होगा और न लागू सममा हो जायेगा जब तक कि उस अधिराज्य के किसी अधिनियम द्वारा वह उस पर लागू न किया जाये।
- (१) कोई ऐसी राज-आज्ञा जो नियुक्त दिवस के परचात या उसी दिन दी गई हो तथा ऐसे अधिनियम के अन्तर्गत हो जो कि नियुक्त दिवस से पहले स्वीकृत हुआ हो तथा कोई भी आज्ञा, नियम या अन्य पत्र जो ऐसे अधिनियम के अन्तर्गत किसी ब्रिटिश मन्त्री द्वारा या उसकी आज्ञा द्वारा बनाया गया हो नवीन अधिराज्यों पर उनके अधिनियम के रूप में लागू नहीं होंगे और नहीं लागू सममें जायेंगे।
- (६) इस धारा की उपधारा (६) में उल्लिखित शक्ति में उपनिवेशों के भावी ब्यवस्थापक मण्डलों की भावी शक्ति को सीमित करने के लिए अधिनियम बनाने की शक्ति सम्मिलित है।

धारा ७. नवीन ऋधिराज्यों के बनने के परिणाम: (१) नियुक्त दिवस से :

- (त्र) बिटेन में बादशाह की सरकार का उन प्रदेशों के वियव में कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा जो कि नियुक्त दिवस से पहले बिटिश भारत में थे।
- (ब) देशी राज्यों पर बादशाह का प्रभुत्व समाप्त हो जायेगा तथा इसके साथ सारी संधियां श्रीर समभौते जो इस समय बादशाह श्रीर भारतीय नरेशों के बीच उनके राज्यों के विषय में हैं, बादशाह के सारे कर्तव्य जो कि देशी राज्यों या उनके नरेशों के प्रति हैं, तथा वादशाह की सारी शक्ति, श्रिधकार या कार्यचेत्र जो किसी संधि, परम्परा, सनद द्वारा या श्रन्यथा देशी राज्यों के विषय में बादशाह को मिले हुए हैं वे भी समाप्त हो जायेंगे तथा
- (ज) सारी संघियां तथा समभौते जो इस समय वादशाह तथा कवाइली प्रदेशों में अधिकार वाले किसी व्यक्ति के बीच हैं वे भी समाप्त हो जावेंगे तथा बादशाह के कवाइली प्रदेशों से सम्बन्ध में तथा ऐसे व्यक्ति के प्रति सारे कर्तव्य, एवं वादशाह की सारी शक्ति, अधिकार या कार्यचेत्र जो किसी संधि, परम्परा, सनद हारा या अन्यथा कवाइली प्रदेशों के सम्बन्ध में सम्राट को प्राप्त हैं, वे भी समाप्त हो जावेंगे।

किन्तु इस उपधारा की कंडिका (व) तथा (ज) के आदेशों के उपरांत भी संचार, यातायात, आयात-निर्यात, डाक व तार तथा इसी प्रकार के अन्य विषयों पर जो भी समफौते हैं उन के उपबन्धों पर तब तक यथासम्भव कार्य होता रहेगा जब तक कि उन आदेशों को एक ओर से देशी नेश या कबाइली प्रदेशों के अधिकारी अथवा दूसरी ओर से अधिराज्य या प्रांत या उसका कोई भाग रह करने की घोषणा न करदे या वाद के समफौतों से वे रह न हो जायें।

(२) ब्रिटिश संसद की त्रोर से सहमित दी जाती है कि बादशाह की उपाधियों त्रीर नाम में से 'भारतीय सम्राट' शब्द निकाल दिए जायें तथा बादशाह इस विषय में घोषणा कर सकता है।

भारत विभाजन श्रीर स्वराज्य

धारा म. नवीन अधिराज्यों के शासन के लिए अल्पकालीन उपबंध: (१) प्रत्येक नवीन अधिराज्य के लिए ज्यवस्थापक मण्डल की शक्ति का प्रयोग प्रथम तो उस अधिराज्य की संविधान सभा करेगी तथा इस अधिनियम में अधिराज्य के ज्यवस्थापक मण्डल का अर्थ भी यही लगाया जायेगा।

(२) इस घारा की उपघारा (१) के अनुसार अधिराज्य की संविधान सभा जो उपबन्ध बनाए उसकी अनुपिस्थिति में प्रत्येक अधिराज्य का शासन यथासंभव १६२१ के भारतीय शासन अधिनियम के अनुसार होगा, तथा उस अधिनियम के उपबन्ध इस अधिनियम के उपबन्धों के अन्तर्गत एवं उन परिवर्तनों, संशोधनों एवं प्रकों के अन्तर्गत जो कि आगामी धारा के अनुसार गवर्नर जनरल की आज्ञाओं से हों, लागृ होंगे।

किन्तु:

- (अ) कथित उपबन्ध दोनों अधिराज्यों पर पृथक पृथक लागू होंगे तथा इस उपधारा का यह अर्थ न होगा कि नियुक्त दिवस के पश्चात या उस दिन कोई भी केन्द्रीय शासन या व्यवस्थापक मगडल दोनों के लिए सामान्य रहे।
- (ब) इस उपधारा का यह अर्थ नहीं होगा कि नियुक्त दिवस को या तदन्तर बिटिश बादशाह की सरकार का नवीन अधिराज्यों या किसी प्रांत या उनके किसी भाग पर कोई नियन्त्रण रहे।
- (ज) नियुक्त दिवस से वे उपबन्ध जिन के अनुसार गवर्नर जनरल या किसी गवर्नर को अपनी इच्छानुसार कार्य करने या निर्णय करने की अनुमति थी समाप्त हो जायेंगे।
- (द) नियुक्त दिवस से कोई भी प्रांतीय विधेयक १६३१ के भारतीय शासन श्रधिनियम के श्रन्तर्गत बादशाह की सहमति के लिए नहीं रोका जायेगा तथा बादशाह द्वारा उसके श्रन्तर्गत कोई भी प्रांतीय विधेयक श्रस्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- (इ) इस धारा की उपधारा (१) में वर्णित शक्तियों के ग्रतिरिक्त संविधान के ग्रन्तर्गत भारतीय या संघीय व्यवस्थापक मण्डल की सारी शक्ति भी संविधान सभा में निहित होगी।

३ भारतीय शासन अधिनियम १६३४ का कोई उपबन्ध जो कि इस ारा की उपधारा (२) के अनुसार किसी अधिराज्य पर लागू होता है या उसमें वर्णित कोई आज्ञायों जो कि उस अधिराज्य के व्यवस्थापक मण्डल की शक्ति को सीमित करते हों उस अधिराज्य के व्यवस्थापक मण्डल के अधिनियम के समान प्रभावशील होंगे जब तक कि इस धारा की उपधारा (२) के अनुसार उस उपनिवेश की संविधान सभा कोई उपबन्ध न बनाए।

धारा ६ इस अधिनियम को लागू करने के लिए आजाथें:

- (१) गवर्नर जनरल स्राज्ञा देकर निम्न उद्देश्यों से ऐसा उपबंध बना सकता है जो कि उसे स्रावश्यक या सुविधाजनक दिखता हो :
 - (य) इस अधिनियम के उपवन्धों को फार्यान्वित करने के लिए:
 - (ब) नये अधिराज्यों में सपरिषद् गवर्नर जनरल की तथा उन प्रान्तों की जो समाप्त होंगे शक्तियों, अधिकारों, सम्पत्ति, कर्तब्य, ऋगों, आदि को विभाजित करने के लिए;
 - (ज) नये अधिराज्यों में लागृ होने के लिये १६३४ के भारतीय शासन अधिनियम तथा उसके अन्तर्गत राज-आज्ञाओं, नियमों तथा अन्य पत्रों को संशोधित करने, घटाने, बढ़ाने या अनुकृल बनाने के लिये:
 - (द) इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार परिवर्तन के सम्बन्ध में कठिनाइयों को दूर करने के लिये;
 - (इ) ११३४ के भारत शासन श्रधिनियम की नवम श्रनुसूची के श्रित-रिक्त किसी श्रम्य प्रकार से इस श्रिधिनियम की स्वीकृति के पश्चात् तथा नियुक्त दिवस से पहले सपरिषद गवर्नर जनरल का का कार्य चलाने के लिये;
 - (फ) नियुक्ति दिवस से पहले दोनों श्रिधराज्यों की श्रोर से संधियां तथा श्रन्य कार्य करवाने के लिये;

भारत विभाजन और स्वराज्य

- (ग) नये दो या अधिक प्रान्तों के वे कार्य नये अधिराज्यों की आरे से करवाने के लिये जो कि पहले पुराने प्रांतों या ब्रिटिश भारत की श्रोर से किये जाते थे;
- (ह) रिजर्व बेंक सम्बन्धी किसी मामले को या मुद्रा व्यवस्था को नियमित करने के लिये; तथा।
- (ई) उपर्युक्त विषयों पर जिस हद तक यह आवश्यक या सुविधाज-नक दिखाई दे, उस हद तक नये अधिराज्यों में किसी व्यवस्थापक मंडल, न्यायालय या अधिकारी की शक्तियों, कार्यचेत्रों या व्यवस्था में परिवर्तन करने के लिये।
- (२) समाप्त होने वाले प्रांतों के गवर्नर इस धारा के अधिकारों का अपने अपने प्रान्त में प्रयोग कर सकेंगे।
- (३) यह धारा ३ जून १६४७ से कार्यान्वित हुई समभी जायेगी। इसके अतिरिक्त उस अधिनियम में सेवाचों, सेना, अदन तथा भारत से ब्रिटिश सेना के निषक्रमण के विषय में उपबंध थे।

द. स्वतन्त्रता अधिनियम के परिगाम

- १. इस अधिनियम को बनाकर संसद ने अपनी ३ जून की घोषणा को पूरा किया था। इस में भारत का विभाजन सर्वथा रुाध्यदायिक आधार पर हुआ और आसाम, पूर्वी पंजाब तथा पश्चिमी बंगाल भारत को प्राप्त हो गये।
- २. दोनों राज्यों को अधिराज्य पद मिल गया अर्थात् ब्रिटेन की संसद को भारत तथा पाकिस्तान के लिये कोई अधिनियम बनाने का अधिकार नहीं रहा। हमें यह भी अधिकार हो गया कि हम जब चाहें पूर्ण स्वतन्त्र हो जायें।
- ३. केन्द्र सें दोनों सदन विघटित होगये तथा संविधान सभा ही व्यवस्थापक मंडल बन गई।
 - गवर्नरों और गवर्नर जनरल के विशेषाधिकार समाप्त हो गये ।

- श. भारत सम्राट अन्य अधिराज्यों के समान भारत का भी बादशाह ही रह गया।
 - ६. देशी राज्य स्वतन्त्र हो गये तथा कवाइली भी संधिमुक्त हो गये।
- ७. १४ श्रगस्त तक श्रावश्यकतानुसार शासन कार्य चलाने के लिये गवर्नर जनरल को पूर्ण श्रधिकार मिल गये तथा उसने जुलाई में ही दोनों देशों की भिन्न भिन्न सरकारें बना दीं जिससे कि वे विभाजन समभौते के लिये वार्ता कर सकें।
- म. भारत से अंग्रेजी अफसर आदि त्यागपत्र देकर ब्रिटेन या पाकि-स्तान जाने लगे।
- राष्ट्रसभा के मंत्रिमण्डल ने कुछ श्रिधकारियों के श्रितिरिक्त शेष सारे बड़े पदाधिकारी भारतीय ही नियुक्त कर दिये।

११४७ के भारतीय स्वतन्त्रता अधिनियम के अन्तर्गत गवर्गर जनरल ने कई आज़ायें निकालीं और इस प्रकार अनुकूल बनाया हुआ तथा संशोधित १६३४ का भारत शासन अधिनियम लगभग २ वर्ष तक भारत के संविधान का काम देता रहा। इन दो वर्षों के काल में भारत अधिराज्य ही रहा, किन्तु अन्त में भारत हारा यह इच्छा प्रकट करने पर कि भारत बादशाह को नहीं मानना चाहता, ब्रिटिश राष्ट्र मंडल ने एक नई व्यवस्था बनाई, जिससे कि भारत को जनतन्त्रात्मक गण्राज्य घोषित होने के पश्चात भी राष्ट्रमंडल का सदस्य रहने दिया गया।

कामनवैत्थ के देशों के प्रधान मन्त्रियों ने, जिनमें कि भारत के प्रधान मन्त्री माननीय श्री जवाहरलाल नेहरू भी थे, लंदन में समवेत होकर २७ ऋप्रेल १६४६ को जो घोषणा की थी, वह इस प्रकार है:—

"यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, श्रास्ट्रेलिया, न्यूजीलेंड, दिन्या श्रक्रीका, भारत, पाकिस्तान श्रीर लंका की सरकारों ने, जिनके देश ब्रिटिश कामनवैल्थ श्राफ नेशन्स के सदस्य होने के नाते श्रापस में संयुक्त हैं श्रीर ताज के प्रति, जो उनकी स्वतन्त्रतामय संयुक्ति का प्रतीक भी है, समान रूप से निष्ठा रखते हैं, भारत में शीघ होने वाले संवैधानिक परिवर्तनों पर विचार किया है।

भारत विभाजन श्रीर स्वंराज्यं

हैं। भारत सरकार ने कामनबैह्य की दूसरी सरकारों को भारतीय जनता कें इस अभिशाय की सूचना दे दी है कि नये संविधान के आधीन, जो स्वीकृत होने वाला है, भारत सम्दूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न स्वतन्त्र गणराज्य हो जायेगा। किन्तु भारत सरकार ने यह घोषित किया है और इस बात की पुष्टि की है कि भारत चाहता है कि वह कामनबैह्य का सदस्य बना रहे और यह कि उसे यह स्वीकार है कि ब्रिटिश बादशाह कामनबैह्य के स्वतन्त्र सदस्य राष्ट्रों के पारस्परिक स्वतन्त्र सम्बन्ध के प्रतीक हैं और इस नाते वह कामनबैह्य के प्रधान हैं।

"कामनवैत्थ के अन्य देशों की सरकारें, जिन की सदस्यता का आधार इस के द्वारा परिवर्तित नहीं होगा, यह स्वीकार करती हैं और इस निश्चय को मान्यता प्रदान करती हैं कि प्रस्तुत घोषणा के शब्दानुसार भारत की कामन-बैल्थ की सदस्यता बनी रहेगी।

तदनुसार यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, ग्रास्ट्रेलिया, न्यूजीलेंड, दिला श्रक्रीका, भारत, पाकिस्तान श्रोर लंका एतद्द्वारा घोषणा करते हैं कि कामनवैत्थ श्राफ नेशन्स के स्वतन्त्र तथा समान सदस्य होने के नाते वे परस्पर संयुक्त रहेंगे श्रोर शांति, स्वतन्त्रता तथा समुन्नति के हेतु श्रापस में श्रवाध रूपसे सहयोग करते रहेंगे।"

इस घोषणा का श्रनुमोदन संविधान सभा ने प्रस्ताव द्वारा किया किन्तु इसे संविधान का भाग नहीं बनाया गया।

६. संविधान-निर्माण

जैसा कि पहले वर्णन किया जा चुका है १ दिसम्बर १६४६ को भारतीय संविधान सभा का जन्म हुआ था। उस समय यह सभा मन्त्री प्रतिनिधि-मण्डल योजना के अनुसार बनी थी, अतः वह सम्पूर्ण-प्रमुख-सम्पन्न नहीं थी। उसे कथित योजना की कार्यप्रणाली के अनुसार कार्य करना था। पर मुस्लिम लीग ने इस सभा में सहयोग देने से इंकार कर दिया तथा भारत और पाकिस्तान के लिये पृथक पृथक संविधान सभाओं की मांग की। अंत में भारत विभाजन की वोषणा होने पर, भारतीय स्वतन्त्रता अधिनियम के अनुसार भारतीय संविधान सभा एक सम्पूर्ण प्रमुख सम्पन्न

निकाय बन गई और १४ ग्रगस्त १६४७ को रात्रि के १२ बजे संविधान सभा ने भारत का शासन ग्रपने हाथ में प्रहण कर लिया।

सम्पूर्ण प्रभुत्व-सम्पन्न संविधान सभा के अधिवेशन में एक लच्य-मूलक प्रस्ताव पारित हुआ, जिसमें बताया गया कि सभा ऐसा संविधान बनायेगी:

"जिसमें सम्पूर्ण प्रभुत्वसम्पन्न स्वतन्त्र भारत की त्रौर इसके त्रंगभृत भागों की तथा इंसके शासन के श्रंगों की शक्ति श्रोर श्रधिकार जनता से प्राप्त होंगे; श्रोर

जिसमें भारत के सब लोंगों के लिये सामाजिक, श्राधिक श्रोर राज-नैतिक न्याय की; प्रतिष्ठा तथा श्रवसर की श्रोर कान्न की दृष्टि में समा-नता की; विचार, श्रभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना, श्राजीविका श्रोर कारोवार की स्वतन्त्रता की; कान्न तथा सदाचार के श्राधीन रहते हुए प्रस्थाभूति दी जायेगी श्रोर निश्चय से प्राप्ति करायी जायेगी; श्रोर

जिसमें ग्रस्पसंख्यकों, ग्रानुन्नत ग्रादिमजातियों के चेत्रों, ग्रीर दिलत तथा ग्रन्य ग्रानुन्नत वर्गों के लिये पर्याप्त संरच्चर की व्यवस्था की जायेगी; ग्रीर

जिसमें लोकतंत्र के राज्यचेत्र की एकता की, श्रीर जल, थल तथा नम में इसके प्रभुता के श्रधिकारों की, न्यायानुसार श्रीर सम्य राष्ट्रों के कानृन के श्रनुसार रज्ञा की जायेगी; श्रीर यह प्राचीन देश संसार में श्रपना श्रधिकारपूर्ण तथा सम्मानित स्थान प्राप्त करता हुश्रा, विश्व में शांति, विकास तथा मानव कल्याण की उन्नति में स्वेच्छा से श्रपना भाग प्रदान करेगा।"

इस प्रस्ताव के न्य्राधार पर स्वतन्त्र भारत का संविधान बनाया गया। पहले संविधान की रूपरेखा निश्चित करने के लिये निम्न समितियाँ नियुक्त की गईं (जिनमें से कुछ का उल्लेख पहले किया जा चुका है):

- (१) संघ संविधान समिति
- (२) प्रांतीय संविधान समिति

भारत विभाजन और खराज्यं

- (३) अल्पसंख्यक तथा मूलाधिकार संबंधी परामर्शदात्री समिति
- (४) मुख्य ब्रायुक्तों ब्रौर संघ तथा राज्यों में वित्तीय संबन्धों की समितियाँ
- (१) ग्रादिमजातीय चेत्र परामर्शदात्री समिति

इन समितियों ने उपसमितियाँ भी नियुक्त कीं ग्रीर ग्रांत में ग्रपने प्रतिवेदन पेश किये जिन पर सभा ने विचार किया।

ईस प्रकार संविधान के सिद्धान्त निश्चित कर दिये गये और उन्हें कान्न का रूप देने के लिये एक 'मस्विदा समिति' नियुक्त हुई जिसने 'संवि-धान का मस्विदा' तैयार किया।

तत्पश्चात संविधान सभा ने 'संविधान के मस्विदे' पर खंडशः विचार किया तथा कई परिवर्तन किये। ग्रंत में २६ नवम्बर १६४६ को संविधान ग्रंतिम रूप से स्वीकृत हो गया ग्रोर २६ जनवरी १६४० से लागू हो गया।

याद रहे २६ जनवरी १६३० के दिन भारत ने 'स्वतन्त्रता प्राप्ति' तथा 'ऋ' ग्रेजों से सम्बन्ध-विच्छेद' करने की प्रतिज्ञा की थी जो प्रतिवर्ष २६ जनवरी को दौहराई जाती थी। इस कारण १६४० में २६ जनवरी को ही भारत को 'गणराज्य' घोषित किया गया।

बठा अध्याय

देशी राज्यों की समस्या का समाधान

१ संघ में प्रवेश

स्वतन्त्रता का आश्वासन मिलने पर तथा अंग्रेजों का संरच्ण हटते ही देशी नरेशों का रुख भी बदल गया। अब वे समभने लगे कि उन्हें भारत से मैत्री आवश्यक है तथा इसके बिना उनकी रज्ञा नहीं हो सकती, अतः वे भारत में मिलने के लिये उत्सुक हो उठे।

भारत में २० के लगभग बड़े देशी राज्य थे जिन की जनसंख्या ६करोड़ से ऊपर थी अर्थात वे इस योग्य थे कि उन्हें संविधान सभा में पृथक रूप से प्रतिनिधित्व मिल सके । शेष ४३४ छोटे छोटे देशी राज्य थे जिन की जनसंख्या और आय इतनी कम थी कि वे प्रगति नहीं कर सकते थे तथा जनता के लिए कुशल शासन प्रबन्ध की व्यवस्था नहीं कर सकते थे। उन सब को पहले तो भारतीय संघ में सिम्मिलित करने का प्रश्न था, तत्पश्चात भारत सरकार चाहती थी कि छोटे छोटे राज्यों को या तो भारत के किसी प्रान्त में विलीन करके उनके नरेशों को पैन्शन दे दी जाये या छोटे छोटे निकटवर्ती राज्यों को मिलाकर बड़े बड़े राज्य संघ बना दिये जायें, जिससे कि प्रशासन

देशी राज्यों की समस्या का समाधान

सुचारू रूप से चल सके। इसके अतिरिक्त राज्यों में जनतंत्र प्रगाली भी लागू करना आवश्यक था जिससे कि वहां निरंकुशता के नीचे पिसी हुई जनता भी स्वतंत्रता का उपभोग कर सके।

भारत सरकार के राज्य विभाग के मन्त्री सरदार पटेल ने साम, दाम, दंड, भेद की नीति से पहले तो सारे नरेशों को भारतीय संघ में सम्मलित किया। १४ श्रगस्त १६४७ तक केवल काश्मीर, हैदराबाद श्रौर जूनागढ़ के श्रितिरक्त लगभग सभी राज्य संघ में प्रवेश कर चुके थे। नीचे उस प्रवेश पत्र का श्रमुवाद दिया गया है जो भारत में मिलने के लिये भिन्न भिन्न देशी नरेशों ने लिखा था।

प्रवेश पत्र

क्योंकि १६४७ के भारतीय स्वतन्त्रता श्रिधिनियम में यह उपवन्ध है कि १४ श्रगस्त से भारत नामक एक स्वतन्त्र श्रिधिराज्य स्थापित होगा तथा उस पर गवर्नर जनरल द्वारा किये गये संशोधनों तथा परिवर्तनों श्रादि सहित १९३४ का भारतीय शासन श्रिधिनयम लागू होगा;

ऋौर क्यों कि गवर्नर जनरल द्वारा इस प्रकार संशोधित १६३४ के भारतीय शासन ऋधिनियम में यह उपबन्ध है कि कोई भारतीय राज्य उस के नरेश द्वारा प्रवेश पत्र लिखने पर भारत ऋधिराज्य में प्रवेश कर सकता है:

ऋतएव ऋवः 'राज्य का नरेश मैं ''' ऋपने कथित राज्य में तथा उस पर ऋपनी प्रभुता के ऋधिकार से यह ऋपना प्रवेश पत्र लिखता हूँ तथा

1. में एतद्द्वारा यह घोषित करता हूँ कि में भारत श्रधिराज्य में इस इच्छा से प्रवेश करता हूँ कि भारत का गवर्नर जनरल, श्रधिराज्य का ज्यवस्थापक मण्डल, संघीय न्यायालय, तथा श्रधिराज्य की श्रोर से कोई श्रम्य श्रधिराज्य प्राधिकारी इस गेरे प्रवेश-पत्र की शक्ति से, किन्तु इसकी शर्तों के श्रनुसार, केवल श्रधिराज्य की श्रोर से ""राज्य (जिसे श्रागे से 'यह राज्य' कहा जायेगा) के सम्बन्ध में उन कृत्यों का प्रयोग कर सकते हैं जो कि १४ श्रगस्त १६४७ को भारत में लागू १६३४ के भारतीय शासन श्रधिनियम द्वारा उन में निहित हों; तथा में यह भी घोषण करता हूँ कि भारत सरकार, किसी प्रतिनिधि या प्रतिनिधियों द्वारा

या वह जिस प्रकार उचित समके उस प्रकार, इस राज्य के दंड विधान या सम्पत्ति विधान सम्बन्धी शक्तियों, अधिकारों और कार्यचेत्र का प्रयोग कर सकती है जो कि किसी समय राज्यों के सम्बन्ध में बादशाह के प्रति-निधि द्वारा बादशाह की श्रोर से प्रयुक्त होते थे।

- २. में इस पत्र द्वारा श्रपने उपर यह दायित्व लेता हूं कि इस राज्य में इस प्रवेश पत्र द्वारा १६३१ के शासन श्रधिनियम के उपबन्ध जिस हद तक लागू होते हैं, उस हद तक उन्हें में इस राज्य में कार्यान्वित कराऊंगा।
- ३. कंडिका १ के उपबन्धों पर विपरीत प्रभाव न पड़ते हुए मैं रवीकार करता हूं कि इस के साथ नत्थी अनुसूची में विश्वित विषयों पर अधिराज्य का व्यवस्थापक-मंडल इस राज्य के लिये विधि बना सकता है।
- ४. में यह घोषण करता हूँ कि में भारत अधिराज्य में इस आश्वासन पर सम्मिलित होता हूं कि यदि इस राज्य के नरेश तथा गवर्नर जनरल में ऐसी कोई संधि होती है जिससे कि इस राज्य के सम्बन्ध में भारत के ज्यवस्थापक-मंडल के किसी अधिनियम की पूर्ती इस राज्य का नरेश करेगा तो वह संधि इस पत्र का भाग समभी जायगी और उसका तदनुसार अर्थ लगाया जायेगा तथा प्रभाव होगा।
- ५. मेरे इस प्रवेश पत्र की शर्ते अधिनियम या भारतीय स्वतन्त्रा अधिनियम के किसी संशोधन से परिवर्तित नहीं होगी, जब तक मैं इस पत्र के पूरक दूसरे पत्र द्वारा उस संशोधन को न मान लूं।
- द इस प्रवेश पत्र से किसी प्रकार भारत के ज्यवस्थापक-मण्डल को यह अधिकार प्राप्त नहीं होगा कि वह इस राज्य के लिये किसी कार्य के निमित्त भूमि पर बलात-अधिकार करने का कोई अधिनियम बना सके, किन्तु में यह दायित्व अपने ऊपर लेता हूं कि यदि अधिराज्य के किसी अधिनियम के निमत्त जो कि इस राज्य पर लागू होता हो, किसी भूमि पर अधिकार करना आवश्यक हो तो मैं उनकी प्रार्थना पर उनके धन से वह भूमि प्राप्त कर दूंगा या यदि वह भूमि मेरी होगी तो वह उन्हें ऐसी शतों पर हस्तां-तिरत कर दूंगा जो कि निश्चत हो जायें या निश्चित की जायें।

देशी राज्यों की समस्या का सामाधान

- ७. इस पत्र का यह भी अर्थ नहीं होगा कि मैं भारत के भावी संविधान को किसी प्रकार स्वीकार करता हूं तथा ऐसे किसी संविधान के अन्तर्गत भारत सरकार से नये प्रबन्ध करने के सम्बन्ध में जेरे अधिकार को यह पत्र कम नहीं करेगा।
- इ.स. पत्र के उपबंधों के अतिरिक्त भेरे नरेश होने के कारण जो अधिकार, शक्तियां तथा स्वःव सुके प्राप्त हैं उस पर, तथा इस राज्य पर भेरी प्रभुता, या इस राज्य में इस समय लागृ किसी अधिनियम पर, इस पत्र का कोई प्रभाव नहीं होगा।
- १. मैं यह भी घोषणा करता हूं कि मैं यह पत्र इस राज्य की स्रोर से लिखता हूं तथा इस पत्र में जो ब्यवस्था गेरे या राज्य के नरेश के लिये हैं उसके अन्तर्गत गेरे उत्तराधिकार? भी समके जायेंगे।

...... अगस्त ११४७ को मैं अपने हस्ताचर कर के यह पत्र देना हूं। राज्य का नरेश

में इस प्रवेश पत्र को स्वीकार करता हूं।

श्राज ता०.....श्रगस्त १६४७

भारत का गवर्नर जनरल

तीसरी कंडिका में उल्लिखित अनुसूची

- क. रचा (जल, थल, नम सेनाएं, शस्त्र आदि)।
- ख. विदेशी विभाग।
- ग. संचार (डाक, तार, रेल, रेडियो ग्रादि)।
- घ. (१) अधिराज्य के न्यवस्थापक मंडल के चुनाव :
 - (२) उपर्युक्त किसी विश्य के सम्बन्ध में श्रिधिनियमों के विरुद्ध श्रपराध
 - (३) उपर्युक्त विषयों के लिये छानबीन तथा ग्रंकसंग्रह
 - (४) उपयुक्त विषयों के सम्बन्ध में सारे न्यायालयों के कार्य-चेत्र और अधिकार, किन्तु सम्मिलित राज्य के नरेश की

सहमित के बिना राज्य में चेत्राधिकार सम्पन्न न्यायालय के अतिरिक्त किसी अन्य न्यायालय को वहां चेत्राधिकार नहीं दिया जा सकता।

२. काश्मीर

पहले तो काश्मीर ने स्वतन्त्र रहने का प्रयत्न किया किन्तु जब पाकिस्तान के समर्थन से सीमाप्रान्त के कबाइली लोगों ने काश्मीर पर श्राक्रमण कर दिया तब काश्मीर के नरेश तथा जनता के प्रतिनिधियों ने भारत से प्रार्थना की कि काश्मीर राज्य को भारत में सम्मिलित कर लिया जाये तथा उसकी रचा के लिये सेना भेजी जाये। भारत ने यह प्रार्थना इस शर्त पर मान ली कि शांति होने पर वहां की जनता का मत लिया जायेगा कि वह भारत में रहना चाहती है या नहीं। तत्पश्चात काश्मीर नरेश ने ऊपर दिये गये प्रवेश पत्र पर हस्ताचर कर दिये।

३. हैदराबाद

यह भारत का सबसे बड़ा राज्य था जिस की जनसंख्या १,४० लाख थी। उसके साथ एक यथा-्वं सममौता हुआ जिसके अनुसार १ वर्ष के लिये हैदराबाद ने रचा, विदेशी नाति तथा संचार के संबंध में भारत का नियन्त्रण स्वीकार कर लिया। पर इस सममौते को हैदराबाद न निभा सका। कासिम रजवी नामक एक गुंडे ने वहां के प्रशासन पर नियन्त्रण कर लिया और नरेश (निजाम) को अपने हाथ की कठपुतली बना लिया। रजवी ने राज्य में जनता को खुलेआम लूटना आरम्भ किया, कत्या, बलात्कार इत्यादि की घटनाएं रोज होने लगी। कुछ सुसलमानों को सशस्त्र बनाकर भारत के विरुद्ध पाकिस्तान से घड़यन्त्र किया गया तथा सममौते के विरुद्ध पाकिस्तान को धन दिया गया। विदेशों से हथियार मंगाये गये। भारत के प्रदेश में भी रजाकार धुस आते और लूटमार करते। इस पर भारत सरकार ने सितम्बर १६४६ में पुलिस कार्यवाही द्वारा हैदराबाद की जनता का उड़ार किया। तत्पश्चात निज़ाम ने प्रवेश-पत्र पर हस्ताचर कर दिये।

४. जुनागढ़

जूनागढ़ वर्तमान सौराष्ट्र में पहले एक छोटा सा राज्य था। यह राज्य सौराष्ट्र में खूब धुलामिला हुत्रा था तथा इसका पाकिस्तान से कोई भौगोलिक

देशी राज्यों की समस्या का सामाधान

सम्बन्ध न था और यहां की जनता भारत में मिलने की इच्छुक थी, पर मुसलम्मान नरेश ने अपने राज्य को पाकिस्तान के समर्पित कर दिया। इसके परिणाम स्वरूप वहां की जनता ने विद्रोह कर दिया तथा नवाब और उसके परामर्शदाता पाकिस्तान भाग गये और भारत सरकार को शासन प्रबन्ध संभालने का निमन्त्रण दे दिया। राज्य का शासनभार अपने हाथों में ले लेने के बाद भारत सरकार ने वहां जनमत संग्रह किया तो पाकिस्तान के विरुद्ध १६ प्रतिशन से अधिक मत आये तथा वह राज्य सीराष्ट्र में मिला दिया गया।

५. राज्यों का अन्त

सब राज्यों के भारत में सिम्मिलित हो जाने के पश्चात भारत सरकार ने श्रविलंब ही छोटे राज्यों का एकीकरण करने श्रर्थात् उनके बड़े संघ बनाने का कार्य हाथ में लिया । पिछले इतिहास के देखते हुये यह कार्य श्रसम्भव सा दीख पड़ता था किन्तु ११४७ के समाप्त होते ही उड़ीसा तथा मध्यप्रान्त के छोटे-छोटे २४ राज्य उनके नरेशों की इच्छा से उन प्रान्तों में विलीन कर दिये गये। उन राज्यों के नरेशों ने जिस विलीनकरण संधि पर हस्ताचर किये थे वह नीचे दी जाती है:

"१४ दिसम्बर १६४७ को भारत के गवर्नर जनरल तथा......राज्य के राजा के बीच संघि।

क्यों कि राज्य तथा उसकी जनता के तान्कालिक हितों के हेतु,..... राज्य का राजा इसके लिये इच्छुक है कि राज्य का शासन प्रबन्ध शोबातिशोध, तथा भारत सरकार जैसे उचित समभे उस प्रकार, उड़ोसा/मध्यप्रान्त के शासन प्रबन्ध के साथ मिल कर एक हो जाना चाहिये:

श्रतएव निम्न संधि की जाती है:-

प्रथम अनुच्छेद...राज्य का राजा इस संधि द्वारा राज्य के शासन के हेतु और सम्बन्ध में अधिराज्य सरकार को पूर्ण तथा एकाकी अधिकार, कार्य्य- शांकत और सत्ता समर्पित करता है तथा १ जनवरी १६४८ को (जिसे आगे से कथित-दिवस पुकारा जायेगा) राज्य का शासन प्रबन्ध अधिराज्य सरकार को हस्तांतरित करने के लिये सहमत है।

कथित दिवस से अधिराज्य सरकार को यह चमता होगी कि वह कथित शक्ति अधिकार तथा कार्यचेत्र का ैसे उचित समभे तथा जिसके द्वारा उचित समभे वैसे ही प्रयोग करे।

द्वितीय अनुच्छेद्—राजा कथित दिवस सं राज्य की आय में से, करों से स्वतन्त्र, वार्षिक रुपये अपने निजी व्यय के लिये लेने का अधिकारी होगा। अभिन्नाय यह है कि इस धन राशि में राजा के तथा उसके कुटुम्ब के सारे व्यय, जिसमें निजी नौकरों, निवास, विवाह तथा अन्य रीतियों आदि के व्यय भी हैं सम्मिलित होंगे तथा यह धन राशि किसी भी कारण से घटाई या बढ़ाई नहीं जावेगी। कथित धनराशि को नरेश राज्य कोष या ऐसे दूसरे कोष से जो कि अधिराज्य सरकार नियत करे चार समान अशिकाओं में प्रत्येक विमास के आरम्भ में अधिम ले सकता है।

तृतीय ऋनुच्छेद—इस संधि की तिथि पर राजा की जो निजी सम्पत्ति हो (जो राज्य सम्पत्ति न हो), राजा उसका पूर्ण स्वामी होगा तथा उसे भोगने तथा प्रयोग करने का ऋषिकारी होगा।

१ जनवरी ११४८ से पहले राजा अधिराज्य सरकार की अपनी निजी सम्पत्ति की रोकड़, सिक्योरिटियों तथा अचल सम्पत्ति की एक सूची देगा।

यदि कोई विवाद हो जाये कि सम्पत्ति की कोई वस्तु राजा की निजी सम्पत्ति है या राज्य की सम्पति है, तो वह प्रश्न न्याय के अनुभवी ऐसे अधि-कारी के पास जायेगा जिसे अधिराज्य सरकार नियुक्त करे तथा उस अधिकारी का निर्णय अन्तिम होगा और दोनों पत्तकों पर ताग होगा।

चतुर्थ ऋतु च हेर —ाजा, रानी, राजमाता, युवराज तथा युवरानी को सारे व्यक्तिगत विशेषाधिकारों का, जिनका वे १४ ऋगर १९४७ के तत्काल पहले राज्य के प्रदेश में या बाहर उपभोग करते थे, हक्क होगा।

पंचम ऋनुच्छेद्— ऋधिराज्य सरकार यह बचन देती है कि राज्य की गही का उत्तराधिकार तथा राजा के व्यक्तिगत ऋधिकारों, विशेषाधिकारों, सम्मानों एवं उपाधियों का उत्तराधिकार नियम तथा परिपाठि के अनुसार होगा।

देशी राज्यों की समस्या का सामाधान

"इस संधि की पुष्टि में श्री वपुल पंगुनी मैनन, भारत सरकार के राज्य विभाग सिचव ने, भारत के गवना जनरज को खोर से तथा श्राधिकार से हस्ताचर किये हैं तथा.....राज्य के राजा......ने अपने तथा श्रपने उत्तराधिकारियों की खोर से हस्ताचर किये हैं।"

६. प्रान्तों में विलीनकरण

इसी प्रकार स्वतन्त्रता के प्रथम दो वर्षों में ही २१६ देशी राज्यों को प्रान्तों में विलीन कर दिया गया। इस का संचिप्त विवरण नीचे दिया जाता है।

- १. उड़ीसाः यह बहुत छोटा प्रांत था। इस में पहली जनवरी १६४८ को ही २३ देशी राज्य विलीन कर दिये गये जिनका कुल चेत्रफल २३,६३७ वर्ग मील, जनसंख्या ४० लाख ४६ हजार तथा राजस्व ६८ लाख ७८ हजार स्पये था। तत्पश्चात १० लाखकी जनसंख्या वाले मयूरभंज राज्य को भी इसी में विलीन कर दिया गया। इससे उड़ीसा का चेत्रफल लगभग दुगुना हो गया तथा जनसंख्या लगभग डेढ़ गुनी हो गई।
- २. मध्य प्रदेश : इस प्रांत में भी १ जनवरी १६४८ को ही १४ राज्य विलय हो गये जिनका चेत्रफल ३१,७४६, जनसंख्या २८ लाख ३४ हजार तथा राजस्व ८८ लाख ३१ हजार रुपये था। इन में कावर्धा, सरगूजा, खैरगढ़, तथा बस्तर की रियासतें उल्लेखनीय हैं।
- ३. बिहार : इस प्रांत में भी दो रियासतें विलय हो गईं। जिन का चेत्रफल ६२३ वर्ग मील, जनसंख्या २ लाख ४ हजार, तथा राजस्व ६ लाख ४४ हजार रुपये था।
- ४. मद्रास : इस प्रान्त में पुड्कोटई, सुन्दूर तथा वंगलपल्ले के राज्य विलीन किये गये थे, जिनका कुल चेत्रफल १६०२ वर्ग मील तथा जन-संस्या ४ लाख ११ हजार थी।

भारत--नर्य संविधान तक

- ४. युक्त प्रान्त (उत्तर प्रदेश) : इस में बनारस, रामपुर और टिहरी गढवाल तीन राज्य विलीन कर दिये गये जिनका चेत्रफल ६२७६ वर्ग मील तथा जनसंख्या १३ लाख २४ हजार थी।
- ६. पूर्वी पंजाब : इस प्रान्त में भी छोटी छोटी तीन रियासतें, लोहारु, दुजाना श्रीर पटोदी, विलीन कर दी गई जिनका चेत्रफल २७० वर्गमील, जनसंख्या = १ हजार तथा राजस्व १० लाख रुपये वार्षिक है।
- ७. बम्बई : स्वतन्त्रता कं प्रथम वर्ष में इस प्रान्त में छोटे-छोटे १६१ राज्य विलय हुए जिनका चेत्रफल २४ हजार ३३१ वर्गमील, जनसंख्या ४३ लाख १७ हजार तथा राजस्व ३ करोड ७ लाख १४ हजार रुपयेथा। तत्परचात बड़ोदा (२६ लाख) तथा कोल्हापुर (११ लाख) भी इस में ही विजीन कर दिये गये। इसके श्रतिरिक्त दांता राज्य तथा सिरोही का कुछ भाग भी बम्बई में मिला दिया गया।

पश्चमी बंगाल : इसमें कोच-बिहार विलीन किया गया।

७. राज्य-संघों का निर्माण

इसके श्रतिरिक्त कई राज्यों को मिलाकर निम्न लिखित पांच-संघ भी बना दिये गये।

१. संयुक्त राजस्थान : यह चेत्रफल के विचार से भारतीय संघ का सब से बड़ा श्रंग है। इसमें १८ राज्य सम्मिलित हैं। इसका चेत्रफल लगभग सवा लाख वर्गमील तथा जनसंख्या सवा करोड से श्रधिक है। इसके महाराजप्रमुख महाराणा उदयपुर हैं; किन्तु शासनकार्य वास्तव में जयपुर नरेश ही चलाते हैं जो कि राजस्थान के राजप्रमुख हैं। इसके उपराजप्रमुख कोटा नरेश हैं।

संयुक्त राज्य राजस्थान का निर्माण क्रमशः हुन्रा। सर्व प्रथम कोटा नरेश के राजप्रमुख्य में राजस्थान के नौ राज्य इसमें सम्मिलित हुए जिन की कुल जनसंख्या २३ लाख थी। इन राज्यों के नाम हैं, कोटा, वृंदी, किशनगढ, क्रालावाड़, डूंगरुटुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ, टौंक, किशनगढ त्रौर शाहपुरा।

देशी राज्यों की समस्या का सामाधान

तत्परचात महाराणा उदयपुर भी इस में सम्मिलित हो गये तथा उन्हें राज प्रमुख का पद प्राप्त हुआ और कोटा नरेश उपराजप्रमुख बनाए गए। इससे राजस्थान का चेत्रफल २६ हजार ६७७ वर्गमील, जनसंख्या ४२ लाख ६१ हजार तथा राजस्व ३ करोड़ १७ लाख रुपये हो गया।

त्रप्रेल १६४६ में राजपुताना के चार महान राज्य, जयपुर, जोधपुर, जयसलगेर तथा बीकानेर भी इसमें सम्मिलित हो गये तथा बृहद् राजस्थान की रचना हुई। तत्परचात मत्स्य राज्य संघ भी इसी में विलीन कर दिया गया। मत्स्य का निर्माण मार्च १६४८ में हुत्रा था श्रौर इसमें श्रलवर, भरतपुर, धौलपुर, तथा करौली राज्य सम्मिलित थे। मत्स्य का चेत्रफल ७,४३६ वर्गमील जनसंख्यों १८ लाख ३८ हजार तथा राजस्व १ करोड ८३ लाख ६ हजार रुपये था।

इस प्रकार महाराजस्थान में १८ राज्य विलय हो गये जिनका कुल क्षेत्रफल १,२८,४२४ वर्गमील तथा जनसंख्या १,३०,८४,००० है।

२. मध्य भारत (म!लवा) : जिसमें ४० लाख जनसंख्या वाला ग्वालियर तथा १४ लाख जनसंख्या वाला इन्दोर राज्य तथा २० छोटे राज्य भी सम्मिलित हो गये। उन दोनों राज्यों के नरेश क्रमशः इस संघ के राज-प्रमुख तथा उपराजप्रमुख वने और ग्वालियर तथा इन्दौर इस संघ की भीष्म तथा शीत ऋतु की राजधानियां बनीं। इस संघ में ४ सलामी वाले तथा २० छोटे-छोटे राज्य सम्मिलित हुए थे, जिससे इसका कुल चेत्रफल लगभग ४७ हजार वर्गमील, जनसंख्या लगभग ७२ लाख तथा आय म करोड़ रुपये हो गई।

मध्य भारत संघ का निर्माण अप्रैल ११४८ में हुआ।

३. सौराष्ट्र : यह काठियावाड़ के २२२ छोटे बड़े राज्यों का एक संघ बना जिस के राजप्रमुख नवानगर नरेश (जाम साहिब) बनाये गये। ज्नागढ भी इसी में सम्मिलित किया गया था। सौराष्ट्र का क्षेत्रफल २१,०६२ वर्गमील, जनसंख्या ३४ लाख ४६ हजार ख्रोर राजस्व करोड़ रुपये है।

देशी राज्यों की समस्या का समाधान

निम्नांकित तालिकात्रों में संचेप से राज्यों के विलय के आंकड़े दिये गये हैं:—

प्रान्धें में विलीन राज्य

	., ,,			
प्रांत का नाम	राज्यों की संख्या	राज्यों का चेत्रफल (वर्गमीलों में)	राज्यों की जन- संख्या (हजारों में)	
बम्बई	१६५	₹8,9२७	८ ४,३४	
उड़ीसा	२४	२७,६७१	५०,३६	
मध्य प्रदेश	9.4	३१,७४६	२८,३४	
उत्तर प्रदेश	R	६,२७६	१३,२४	
पश्चिमी बंगाल	3	१,३२१	६,४३	
मद्रास	ર	१,६०२	33,8	
बिहार	२	६२३	२,०४	
पंजाब	3	३७०	<u></u> 53	
योग—	२१६	१,०५,७,३६	1,81,85	
	राज्य-संघों मे	विलीन रा डा		
राजस्थान	গুদ	१,२८,४२४	१,३०,८४	
त्रावनकोर-कोचीन	2	६,१४४	७४,६३	
मध्यभारत	२४	४६,७१०	७१,४१	
सौराष्ट्र पटियाला श्रीर	२२२	२१,०६२	३४,५६	
पू॰ पं॰ रा॰ संघ	5	90,088	३४ २४	
योग—	२७४	२,१४,४४०	३,४६,६६	
	वेन्द्र-प्रशा	सित राज्य		
विन्ध्य प्रदेश े	३४	२४,६००	३४,६६	
हिमाञ्चल प्रदेश	२१	90,800	8,34	
भोपाल	9	६,६२१	७,८४	
त्रिपुरा	9	8,088	४,१३	
मनीपुर	3	म,६२०	४,१२	
कच्छ	9	≂, ४६३	4,09	
विवासपुर	9	४४३	9,90	
योग —	६१	६३,७०४	६६,२४	
		The same of the sa		

भारत--नथे संविधान तक

सारांश

योग	<i>१</i> १२	३,८७,८१३	६,०७,¤२
केन्द्र शासित राज्य	६१	६३,७०४	६६,२४
राज़्यसंघों में विलीन राज्य	२७४	२,१४,४४०	३,४६,६६
प्रान्तों में विलीन राज्य	२१६	१,०८,७३६	9,89,45

नया संविधान और देशी राज्य

उपयुक्त तालिकान्नों से पता लग गया होगा कि हैदराबाद, मैसूर तथा जम्मू त्रौर काश्मीर, इन तीन राज्यों के त्रतिरिक्त समस्त देशी राज्यों का किसी न किसी प्रकार विलय हो गया।

राज्यों का इस प्रकार एकीकरण तथा संगठन होने के पश्चात २६ नवम्बर १६४८ को भारत का संविधान पूर्ण हुया। उसमें यह उपबन्ध रखे गये कि राज्य संघों का शासन-प्रबन्ध प्रांन्तों के समान प्रजातन्त्रीय ढंग पर होगा तथा राजप्रमुखों की गवर्नरों के समान स्थिति होगी। समस्त राजप्रमुखों ने इस संविधान को स्वीकार कर लिया जिससे २६ जनवरी १६४० से नए संविधान के लागू होने पर सारी स्थिति ही बदल गई श्रौर पुराने संधिपत्रों का, जिनका वर्णन हम ऊपर कर चुके हैं, लगभग ऐतिहासिक महत्व ही रह गया। साथ ही काश्मीर, हैदराबाद तथा मैसूर के नरेशों ने भी संविधान को स्वीकार करके राजप्रमुख का पद धारण कर लिया।

१० नरेशों की निजी थैलियां (Priny--Purse)

राज्यों के विलय के फलस्वरूप जीवननिर्वाह के हेतु नरेशों की निम्न ऋनुपात से निजी थैलियां दी गई हैं:—

राज्य की प्रथम १ लाख रु० वार्षिक ग्राय पर १५% श्रगली ४ लाख ,, ,, ,, ,, %

१ लाख से श्रधिक राशियों पर ७॥ प्रतिशत, किन्तु १० लाख से श्रधिक नहीं।

देशी राज्यों की समस्या का समाधान

निम्न बड़े राज्यों के विश्वय में अपवाद है और उन्हें दस लाख रुपये प्रतिवर्ष से अधिक निजी थैली के रूप में दिये जायेंगे, पर उनके वंशजों को दस लाख रुपये प्रतिवर्ष ही मिलेंगे।

सं०	राज्य	निजी थेली			
9	हैदराबाद	४०	लाख	रुपये	
२	मैस्र	२६	,,	,,	
३	बड़ौदा	२६॥	,,	5.7	
8	पटियाला	90	,,	"	
¥	त्रावणकोर	35	,,	٠,	
ξ	ग्वालियर	२४	,,	٠,	
9	इन्दौर	94	,,	,,	
5	जयपुर	35	,,	,,	
3	बीकानेर	90	,,	,,	
30	जोधपुर	3011	,,	"	
33	भोपाल	33	,,	,,	

इस प्रकार सब नरेशों को मिला कर प्रतिवर्ष ४ करोड़ ८० लाख रुपये निजी थैलियों के रूप में देने निश्चित हुए जो संघ की संचित निधि पर भार होंगे।

🕾 प्रथम भाग समाप्त 😣

द्वितीय भाग

स्वतन्त्र भारत का संविधान

المعادمة ومع ومع ومع ومع ومع ومع

हम, भारत के लोग, भारत को एक सम्पूर्ण प्रश्रुत्व-सम्पन्न लोकतन्त्रात्मक गणराज्य बनाने के लिये, तथा उसके समस्त नागरिकों को :

सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतन्त्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिये, तथा उन सब में

व्यक्ति की गरिमा श्रौर राष्ट्र की एकता सुनिश्चित करने वाली बन्धुता बढ़ाने के लिये

दृद्संकल्प हो कर अपनी इस संविधान सभा में आज ता० २६ नवम्बर १६४६ ई० (मिति, मागशीर्ष शुक्ला सप्तमी, संवत् दो हजार छै विक्रमी) को एद्द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।

प्रथम अध्याय संविधान के सिद्धान्त

१. मुख्य रचना

प्रस्तावना—स्वतन्त्र भारत का संविधान २६ नवम्बर १६४६ को स्वीकार किया गया तथा २६ जनवरी १६४० को लागृ हुआ। उसकी प्रम्तावना सामने के पृष्ठ पर देखिये।

'भारत के लोग' इस पद से यह स्पष्ट होता है कि प्रभुता का स्रोत जनता है। पिछले संविधानों में सत्ता-स्रोत सम्राट तथा ब्रिटिश संसद् होती थी।

'गणराज्य' शब्द का भी यही श्राशय है कि यहां कोई सम्राट या राजा नहीं होगा, वरन् निर्वाचित प्रतिनिधि ही शासन करेंगे।

प्रस्तावना के पश्चात् इस संविधान में २२ भाग (जिनमें कि ३६८ श्रमुच्छेद हैं) श्रौर म श्रमुस्चियां हैं। प्रथम भाग श्रौर प्रथम श्रमुस्ची में भारत के राज्य चेत्रों का वर्णन है, द्वितीय भाग में नागरिकता का विषय है, तृतीय भाग में मूलाधिकारों तथा चतुर्थ भाग में राज्य की नीति के निदेशक सिद्धान्तों का वर्णन है। तत्पश्चात शासन प्रणाली का विवरण पंद्रहवें भाग तक चलता है

भारत-नये संविधान तक

भाग १६ में ग्रह्पसंख्यकों के विषय में विशेष उपबंध उहिलाखित है। भाग १७ राजभाषा के विषय में है। भाग १८ में संकटकालीन स्थिति के उपबंध है। भाग १६ में प्रकीर्ण विषय हैं तथा भाग २० में संविधान के संशोधन की प्रणाली का वर्णन है। भाग २९ में ग्रह्थायी उपवंध हैं जो प्रथम निर्वाचन तक रहेंगे। श्रम्तिम भाग २२ में संविधान की श्रारंभितिथि तथा नाम श्रादि श्रांकित हैं।

यह संविधान मूलतः संघीय है, क्योंकि भारत २७ राज्यों का संघ होगा। राज्यों तथा 'संघ' की सरकारों के चेत्राधिकार भिन्न भिन्न हैं जिनमें उनका अपना अपना प्राधिकार होगा। चेत्राधिकार के विवाद की स्थिति में उच्चतम न्यायालय निर्णय करेगा। राज्यों का चेत्राधिकार संघीय सरकार द्वारा प्रदत्त नहीं होगा, प्रत्युत संविधान द्वारा प्रदत्त है। परन्तु भारत की नागरिकता एकात्मक ही होगी, सभी लोग भारत के नागरिक होंगे, भिन्न भिन्न राज्यों के नहीं। न्यायपालिका भी एक ही होगी, राज्यों की भिन्न भिन्न नहीं। किसी राज्य को संघ से पृथक होने का अधिकार नहीं होगा। आकस्मिकता अथवा संकटकाल में संविधान का ढांचा एकात्मक भी बन सकता है, यद्यपि सामान्यतः वह मंघीय रहेगा। इस प्रकार भारत एक लचकदार संघ है।

राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की मंत्रणा पर चलेगा त्रतः संविधान का ढांचा संसदीय प्रणाली का है।

इस संविधान में सांप्रदायिक निर्वाचनों का अन्त कर दिया गया है तथा निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे, जिसका अर्थ है कि प्रत्येक नागरिक जिसकी आयु २१ वर्ष से कम न हो, मतदाता होगा। केवल हरिजनों तथा आदिवासियों के लिये उनकी जनसंख्या के अनुपात से स्थान सुर जित रखे गये हैं पर यह स्थान-रक्तण भी केवल दस वर्ष के लिये है।

२. भारत का राज्य-चेत्र

भारत, त्रर्थात इण्डिया, राज्यों का संघ होगा। भारत के राज्य-चेत्र में २७ राज्य होंगे जो तीन भागों में बांटे गये हैं:—

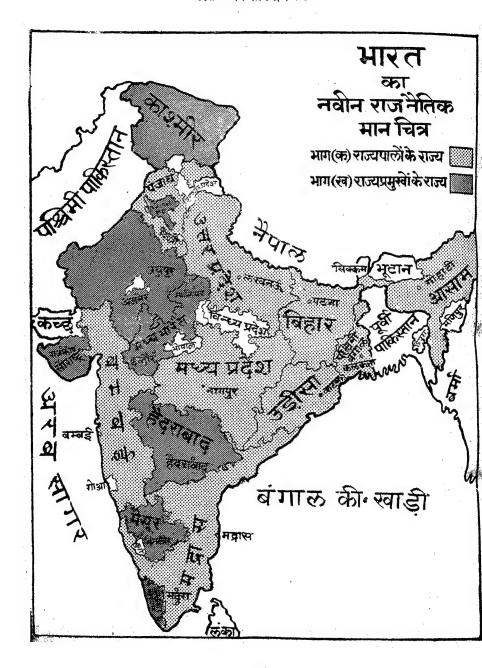
संविधान के सिद्धान्त

भाग (क) राज्यपालों के राज्य (जो पहले प्रान्त थे)

•	
राज्य का नाम	जनसंख्या (हजारों में)
१. उत्तर प्रदेश	६,१६,२०
२. मद्रास	<i>५,</i> ४२,६०
३. बिहार	३ ,६४,२०
४. बम्बई	३,२६,८०
४ पश्चिमी बँगाल	२,४३,२०
६. मध्य प्रदेश	2,08,70
७, उड़ीसा	1,88,90
ध्र पंजाव	१,२६,१०
६ _{.∼} त्र्यासाम	८ ४,३०
	२६,८७,८०

भाग (ख) राजप्रमुखों के राज्य

4101 (37)	
राज्य का नाम	जनसंख्या (हजारों में)
१. हैदराबाद	9,08,80
२. राजस्थान	1,88,80
३. त्रांवकोर-कोचीन	८ ५,८०
४. मैस्र	٣0, ६ 0
४. मध्य भार त	উ ল, ও ০
६ जम्मू तथा काश्मीर	82,00
७. सौराष्ट्र	3,80
= प०पू०प०रा० संघ	33,70
•	€,⊏₹,%०



संविधान के सिद्धान्त

भाग (ग) केन्द्र-प्रशासित राज्य

राज्य का नाम	जनसंख्या (हजारों में)
१. विन्ध्य प्रदेश	३ ८,८०
२ दिल्ली	14,90
३. हिमाचल प्रदेश	१०,८०
४ भोपाल	5, 40
४. ग्रजमेर	७,३०
६. त्रिपुरा	<i>২</i> , ५ ०
७ कच्छ	4,40
म् मनीपुर	4,80
६. कुर्ग	9,00
१०, बिलासपुर	१,३०
	9,00,20

सूचना १.—राज्यों की जनसंख्या संविधान में नहीं दी गई है पर हमने पाठकों की सुविधा के लिये दे दी है। ये ब्रांकड़े १६४० के अनुमानित ब्रांकड़े है जिनके ब्राधार पर स्वतंत्र भारत का प्रथम निर्वाचन होगा।

सूचना २. सामने के मानचित्र में

भाग (क) के राज्यों को बिन्दुओं में दिखाया गया है,

भाग (ख) के राज्यों को रेखाओं में दिखाया गया है, तथा

भाग (ग) के राज्यों को खाली दिखाया गया है।

यह मानचित्र भी १६५० का है।

भारत - नये संविधान तक

इन के श्रतिरिक्त भारत के राज्यत्तेत्र में श्रन्दमान श्रीर निकोबार तथा ऐसे श्रन्य राज्यत्तेत्र, जो श्रर्जित किये जायें, समाविष्ट होंगे [श्रनुच्छेद १ तथा प्रथम श्रनुसूची]।

उपयुक्त विवरण से पता लगेगा कि नये संविधान में प्रान्तों, देशी राज्यों तथा चीफ कमिश्नरी चेत्रों को एक ही नाम 'राज्य' दे दिया गया है।

संसद, विधि द्वारा, संघ में नये राज्यों का प्रवेश या स्थापना भी कर सकेगी (श्रनुच्छेद २) श्रीर

- (क) किसी राज्य से उसका प्रदेश खलग करके ख्रथवा दो या खिक राज्यों या राज्यों के भागों को मिलाकर ख्रथवा किसी प्रदेश को किसी राज्य से भाग के साथ मिलाकर नया राज्य बना सकेगी।
- (ख) किसी राज्य का चेत्र बढा सकेगी,
- (ग) किसी राज्य का चेत्र घटा सकेगी,
- (घ) किसी राज्य की सीमात्रों को बदल सकेगी,
- (ङ) किसी राज्य के नाम को बदल संकेगी,

परन्तु भाग (क) अथवा (ख) के राज्यों में ये परिवर्तन तभी किये जा सकते हैं जब कि सम्बद्ध राज्यों की अनुमति प्राप्त हो जाये (अनु० ३)।

३. नागरिकता

इस संविधान के प्रारम्भ पर प्रत्येक व्यक्ति जिसका भारत राज्यत्तेत्र में श्रिधिवास है, तथा

- (क) जो भारत राज्यत्तेत्र में जन्मा था, ऋथवा
- (ख) जिसके जनकों में से कोई भारत राज्यत्तेत्र में जन्मा था, ऋथवा
- (ग) जो ऐसे प्रारम्भ से ठीक पहले कम से कम पांच वर्ष तक भारत राज्यचेत्र में सामान्यतया निवासी रहा है, भारत का नागरिक होगा (श्रजु० १)।

शरणार्थियों को नागरिता के श्रधिकार: कोई व्यक्ति जो इस समय पाकिस्तान के अन्तर्गत राज्यकेत्र से भारत राज्यकेत्र को प्रवजन कर श्राया है,

संविधान के सिद्धान्त

इस संविधान के आरम्भ पर भारत का नागरिक समका जायेगा (अनु०६)।

जो व्यक्ति १६४७ के मार्च के पहिले दिन के पश्चात भारत राज्यचेत्र से इस समय पाकिस्तान के अन्तर्गत राज्यचेत्र को प्रवजन कर गया है, वह भारत का नागरिक नहीं समका जायगा (अनु०७)।

श्रनु क स्र मितार भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों को भी नागरिकता के श्रिधकार दिये गये हैं यदि वे उसके लिये श्रावेदन-पत्र दें श्रीर पंजीबद्ध कर लिये जायें।

विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से श्रार्जित करने वाले व्यक्ति भारत के नागरिक न होंगे (श्रनु० १)।

इसके अतिरिक्त संसद भी विधि द्वारा नागरिकता के अधिकार का विनियमन कर सकेगी (अनु० ११)।

४. मूलाधिकार

संविधान में यह भाग अत्यंत महत्वपु ण है। इसमें जनता के लिये कुछ मूलाधिकार प्रदान किये गये हैं और प्रत्येक नागरिक राज्य या किसी अन्य नागरिक के विरुद्ध, जो उनमें हस्तचेष करे, न्यायालय में जाकर अपने मूलाधिकारों की रचा कर सकता है ['राज्य' शब्द में भारत सरकार और राज्यों की सरकारें आदि सभी निहित हैं (अनुच्छेद १२)।]

कोई कान्न, जो इन मूलाधिकारों का उल्लंघन करने वाला हो उस मात्रा तक शून्य होगा जिस तक कि वह मूलाधिकारों के उपबंधों से असंगत है, और राज्य आगे भी कोई ऐसा कान्न न बना सकेगा जो मूलाधिकारों को छीनता या कम करता हो अन्यथा वह कान्न भी उल्लंघन की मात्रा तक शून्य होगा (अनु० १३)

मूल अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिय उच्चतम न्यायालय को समुचित कार्यवाहियों द्वारा प्रचालित करने का अधिकार प्रत्याभूत किया गया है। किन्तु आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में हो तब इस अधिकार को छीना जा सकता है।

मूल अधिकारों में से किसी को प्रवर्तित कराने के लिये उच्चतम न्यायालय ऐसे निदेश या आदेश अथवा लेख, जिनके अन्तर्गत बन्दीप्रत्यचीकरण, परमादेश,

भारत - नये संविध नि तक

प्रतिषेध, अधिकार-पृच्छा श्रीर उत्प्रेषण के प्रकार के लेख भी हैं, जो भी समुचित हो, निकालने की शक्ति होगी। किन्तु संसद श्रन्य न्यायालयों को भी इस विषय में शक्ति दे सकेगी (श्रमुच्छेद ३२)।

मुख्य मूलाधिकार निम्न लिखित हैं:--

विधि के समन्न समताः भारत राज्यन्तेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समन्न समता से श्रथवा विधि के समान संरच्या से वंचित नहीं किया जायगा (श्रमुच्छेद १४)।

राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान ऋथवा इन में से किसी के ऋाधार पर कोई विभेद नहीं करेगा।

केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान अथवा इनमें से किसी के आधार पर कोई नागरिक—

- (क) दुकानों, सार्व जनिक भोजनालयों, होटलों तथा सार्व जनिक मनोर जन के स्थानों में प्रवेश के; श्रथवा
- (ख) पूर्ण या श्रांशिक रूप में राज्य-निधि से पोषित श्रथवा साधारण जनता के उपयोग के लिये समर्पित कुश्रों, तालाबों, स्नानघाटों, सङ्कों तथा सार्व जनिक समागम स्थानों के उपयोग के

बारे में किसी भी निर्योग्यता, दायित्व, निर्वेन्धन श्रथवा शर्त के श्रधीन न होगा।

इस अनुच्छेद की किसी बात से राज्य की स्त्रियों श्रीर बालकों के लिये कोई विशेष उपबन्ध बनाने में बाधा न होगी (अनु० १४)।

राज्याधीन नौकरियों का पदों पर नियुक्ति के सम्बन्ध में सब नागरिकों के लिये अवसर की समता होगी।

केवत धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, उर्भव, जन्म-स्थान, निवास अथवा इनमें से किसी के आधार पर किसी नागरिक के लिये राज्याधीन किसी नौकरी अथवा पद के विषयों में न अगात्रता होगी और न विभेद किया जायेगा (अनु० १६)।

किन्तु राज्य को पिछड़े हुए किसी नागरिक वर्ग के पत्त में, जिनका प्रति-निधित्व राज्य की राय में राज्याधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, नियुक्तियों या पदों के रचण के उपबन्ध करने में कोई बाधा न होगी।

संविधान के सिद्धान्त

उपर्युक्त उपबन्धों का उद्देश्य भारत को धर्म निरपेत्त राज्य बनाना है जिसमें किसी विशेष मत के साथ पत्तपात न होगा।

श्रस्पृश्यता का श्रन्तः 'श्रस्प्रश्यता" का श्रन्त किया जाता है श्रीर उसका किसी भी रूप में श्राचरण निषद्ध किया जाता है। ''श्रस्प्रश्यता" से उपजी किसी निर्योग्यता को लागृ करना विधि के श्रनुसार दण्डनीय श्रपराध होगा (श्रनु० १७)।

खिताबों का इ.न्तः सेना या विद्या सम्बन्धी विशिष्टता के सिवाय श्रीर कोई खिताब राज्य प्रदान नहीं करेगा; श्रीर भारत का कोई नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई खिताब स्वीकार नहीं करेगा।

वाक् स्वातन्त्रय द्यादिः सब नागरिकों को वाक्-स्वातन्त्र्य श्रौर श्रिम-व्यक्ति स्वातन्त्र्य का श्रधिकार होगा किन्तु श्रपमान-लेख, श्रपमान-वचन, मानहानि, न्यायालय-श्रवमान को श्रथवा शिष्टाचार या सदाचार पर श्राघात को श्रथवा राज्य की सुरत्ता को दुर्बल करने श्रथवा राज्य को उलटने की प्रवृत्ति को राज्य रोक सकेगा।

सब नागरिकों को शांतिपूर्वक निरायुध सम्प्रेलन का, संस्था या संघ बनाने का, भारत राज्य चेत्र में सर्वत्र अवाध संचरण का, भारत राज्य चेत्र में सर्वत्र अवाध संचरण का, भारत राज्य चेत्र के किसी भाग में निवास करने और बस जाने का, सम्पत्ति के अर्जन, धारण और व्ययन का, तथा कोई वृत्ति, उपजीविका, व्यापार या कारबार करने का भी अधिकार होगा। इन अधिकारों के प्रयोग पर सार्वजनिक व्यवस्था, सदाचार या साधारण जनता के हितों के लिये युक्तियुक्ति निर्बन्धन लगाये जा सकते हैं (अ.न.० १६)

अपराधों के संरत्न्त एः कोई व्यक्ति किसी अपराध के लिए सिट दोष नहीं उहरायां जायगा, जब तक कि उसने अपराधारोपित क्रिया करने के समय किसी प्रवृत्त विधि का अतिक्रमण न किया हो और न वह उससे अधिक दंड का पात्र होगा जो उस अपराध के करने के समय प्रवृत्त विधि के अधीन दिया जा सकता था।

कोई व्यक्ति उसी श्रपराध के लिए एक बार से श्रधिक श्रभियोजित श्रौर दंडित न किया जायगा।

किसी श्रपराध में श्रमियुक्त कोई व्यक्ति स्वयं श्रपने तिरुद्ध साची होने के लिए वाध्य न किया जायगा (श्रनु० २०)।

भारत-नये संविधान तक

किसी व्यक्ति के प्राण अथवा दैहिक स्वतन्त्रता का हरण विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को छोड़कर अन्य प्रकार से न किया जायेगा।

कोई व्यक्ति जो बन्दी किया गया है, ऐसे बन्दीकरण के कारणों से यथाशक्य शीध अवगत कराये गये बिना हवालात में निरुद्ध नहीं किया जायगा और न अपने पसन्द के विधि-व्यवसायी से परामर्श करने तथा प्रतिरचा कराने के अधिकार से वंचित रखा जायेगा।

प्रत्येक व्यक्ति जो बन्दी किया गया है श्रीर हवालात में निरुद्ध किया गया है, बन्दीकरण के स्थान से दंडाधिकारी के न्यायालय तक यात्रा के लिये श्रावश्यक समय को छोड़कर, ऐसे बन्दीकरण से २४ घएटे की कालाविध में निकटतम दंडाधिक री के समन्त्र पेश किया जायगा।

किन्तु जो व्यक्ति तत्समय शत्रु परदेशीय है, ग्रथवा जो व्यक्ति निवारक निरोध उपबन्धित करने वाली किसी विधि के ग्रधीन बन्दी या निरुद्ध किया गया है उसके सम्बन्ध में उपयुक्त नियम लागृ न होंगे (ग्रनु०२२)।

वेगार निषेध—मानव का पर्य और बेगार तथा इसी प्रकार का अन्य जबर्द्स्ती लिया हुआ अम प्रतिषिद्ध किया जाता है और इस उपवन्ध का कोई भी उल्लंबन विधि के अनुसार दंडनीय अपराध होगा।

इस अनुच्छेद की किसी बात से, राज्य को सार्वजनिक प्रयोजन के लिये वाध्य सेवा लागू करने में रकावट न होगी। ऐसी सेवा लागू करने में केवल धर्म, मूलवंश, जाति या वर्ग या इनमें से किसी के आधार पर राज्य कोई विभेद गहीं करेगा (अनु० २३)।

बच्चों को नौकर रखने का निषेध—चौदह वर्ष से कम श्रायु वाले किसी बालक को किसी कारखाने श्रथवा खान में नौकर न रखा जायेगा श्रीर न किसी दसरी संकटमय नौकरी में लगाया जायेगा (श्रनु० २४)।

धर्म की स्वतन्त्रता—सार्वजनिक व्यवस्था, सदाचार श्रौर स्वास्थ्य तथा इस भाग के दूसरे उपबन्धों के श्रधीन रहते हुए, सब व्यक्तियों को श्रन्तः करण की स्वतन्त्रता का तथा धर्म के श्रवाध रूप से मानने, श्राचरण करने श्रौर प्रचार करने का समान हुनक होगा।

संविधान के सिद्धानत

इस अनुच्छेद की कोई बात किसी ऐसी वर्तमान विधि के प्रवर्तन पर प्रभाव अथवा राज्य के लिये किसी ऐसी विधि के बनाने में रुकावट न डालेगी, जो धार्मिक आचरण से सम्बद्ध किसी आर्थिक, वित्तिक, राजनैतिक अथवा श्रम्य किसी प्रकार की लौकिक कियाओं का विनियमयन अथवा निर्बन्धन करती हो; सामाजिक कल्याण और सुधार उपबंधित करती हो, अथवा हिंदुओं की सार्वजनिक प्रकार की धर्म संस्थाओं को हिन्दुओं (जिन में सिख, जैन, बौद्ध भी समाविष्ट हैं) के सब वर्गों और विभागों के लिये खोलती हो।

कृपाण धारण करना तथा लेकर चलना सिक्ख धर्माका द्रांग समका जायेगा (ग्र.नु॰ २१)।

धार्मिक कार्यों के प्रबन्ध की स्वतन्त्रता—सार्वजनिक व्यवस्था, सदा-चार और स्वास्थ्य के अधीन रहते हुए प्रत्येक धार्मिक सम्प्रदाय अथवा उसके किसी विभाग को धार्मिक और पूर्व प्रयोजनों के लिये संस्थाओं की स्थापना और पोषण का, अपने धार्मिक कार्यों सम्बन्धी विषयों के प्रबन्ध करने का, जंगम और स्थावर सम्पत्ति के अर्जन और स्वामित्व का तथा ऐसी सम्पत्ति के विधि अनुसार प्रशासन करने का अधिकार होगा (अनु० २६)।

कोई भी व्यक्ति ऐसे करों को देने के लिये वाध्य नहीं किया जायेगा जिनके त्रागम किसी विशेष धर्म त्रथवा धार्मिक सम्प्रदाय की उन्नति या पोषण में व्यय करने के लिये विशेष रूप से विनियुक्त कर दिये गये हों (इ.सु०२७)।

राज्य-निधि से पूरी तरह से पोषित किसी शिचा संस्था में कोई धार्मिक शिचा न दी जायेगी।

राज्य से अभिज्ञात अथवा राज्य निधि से सहायता पाने वाली, शिचा संस्था में उपस्थित होने वाले किसी ब्यक्ति को ऐसी संस्था में दी जाने वाली धार्मिक शिचा में भाग लेने के लिये अथवा ऐसी संस्था में या उससे संलग्न स्थान में की जाने वाली धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के लिये वाध्य न किया जायेगा जब तक कि उस ब्यक्ति ने, या यदि वह अवयस्क हो तो उसके संरचक ने, इसके लिये अपनी सम्मति न दे दी हो (अनु० २ म्)।

भारत-नये संविधान तक

अलपसंख्यकों के हितों का संरच्या—भारत के राज्यचेत्र अथवा उसके किसी भाग के निवासी नागरिकों के किसी विभाग को, जिसकी अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति है, उसे बनाये रखने का अधिकार होगा।

राज्य द्वारा पोषित अथवा राज्य-निधि से सहायता पाने वाली किसी शिचा संस्था में प्रवेश से किसी भी नागरिक को केवल धर्म, मूलवंश, जाति, भाषा अथवा इनमें से किसी के आधार पर वंचित न रखा जायेगा (अनु०२६)।

धर्म या भाषा पर श्राधारित सब ग्रल्पसंख्यक वर्गों को ग्रपनी रुचि की शिच्चा-संस्थाओं की स्थापना ग्रोर प्रशासन का ग्रधिकार होगा।

शिचा-संस्थाओं को सहायता देने में राज्य किसी विद्यालय के विरुद्ध इसी श्राधार पर विभेद न करेगा कि वह धर्म या भाषा पर श्राधारित किसी श्रह्मसंख्यक वर्ग के प्रवन्ध में है (श्रनु० ३०)।

सम्पत्ति का श्रिधिकारः —कोई व्यक्ति विधि के प्राधिकार के बिना श्रपनी सम्पत्ति से बंचित नहीं किया जायेगा।

किसी अंगम या स्थावर सम्पत्ति पर विना प्रतिकर के राज्य कब्जा न करेगा। प्रतिकर विधि द्वारा निश्चित होगा।

मतदान का अधिकार—प्रत्येक व्यक्ति, जो भारत का नागरिक हो, इक्कीस वर्ष की अवस्था से कम न हो, तथा किसी विधि के अधीन अनिवास, चित्त-विकृति, अपराध अथवा अष्ट या अवैध आचार के आधार पर अन्हें नहीं कर दिया गया हो, मतदाता के रूप में पंजीबद्ध होने का हक्कदार होगा (अनु० ३२)।

धर्म, मूलवंश, जाति या लिंग के आधार पर कोई किसी व्यक्ति निर्वाचक नामाविल में सम्मिलित किये जाने के लिये अपात्र न होगा तथा किसो विशेष निर्वाचक नामाविल में सम्मिलित किये जाने का दावा न करेगा (अनु० ३२४)।

इस उपबन्ध द्वारा साम्प्रदायिक निर्वाचनों का श्रन्त हो जाता है। श्रव संयुक्त निर्वाचन होंगे।

संविधान के सिद्धानत

भारत में यह पहला ही समय है कि मताधिकार को इतना विस्तृत किया गया है। पहले के संविधानों में मतदाता बनने के लिये धन-संबंधी अर्हताएं थीं, पर अब वयस्क मताधिकार रखा गया है। इस समय भारत के ३४ करोड़ लोगों में से लगभग आधे अर्थात १८ करोड़ मतदाता होगे। संसार के किसी देश में इतने मतदाता नहीं हैं।

१६१६ के संविधान में जनता के केवल ३ प्रतिशत लोगों को मतदान का अधिकार था और १६३४ के संविधान में लगभग १० प्रतिशत लोग मतदाता थे। अब भारत में ४० प्रतिशत मतदाता हैं।

५. राज्य की नीति के सिद्धान्त

मूलाधिकारों के प्रतिरिक्त संविधान के चतुर्थ भाग में 'राज्य की नीति के निदेशक तत्वों' का उल्लेख हैं। मूलाधिकारों के समान उन्हें न्यायालयों में जाकर क्रियान्वित नहीं कराया जा सकेगा, तो भी इनमें दिये हुए तत्व देश के शासन में मूलभूत हैं और विधि बनाने में इन तत्वों का प्रयोग करना राज्य का कर्तव्य होगा (श्रुनु० ३७)।

इनमें मुख्य तःव निम्नलिखित हैं :--

- (१) लोककल्याण की उन्नित के हेतु राज्य सामाजिक व्यवस्था बनायेगा (श्रनु० ३८)।
- (२) राज्य श्रपनी नीति का विशेषतया ऐसा संचालन करेगा कि सुनिश्चित रूप से-
 - (क) समान रूप से नर श्रीर नारी सभी नागरिकों की जीविका के पर्यान्त साधन प्राप्त करने का श्रधिकार हो,
 - (ख) समुदाय की भौतिक सम्पति का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार बंटा हो कि जिससे सामृहिक हित का सर्वोत्तम रूप से साधन हो,
 - (ग) ब्राधिक ब्यवस्था इस प्रकार चले कि जिससे धन और उत्पादन साधनों का सर्व साधारण के लिए ब्रह्तिकारी केन्द्रण न हो,

भारत-नये संविधान तक

- (व) पुरुषों श्रीर स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिये समान वेतन हो,
- (ङ) मिक पुरुषों और स्त्रियों का स्वास्थ्य श्रीर शक्ति तथा बालकों की सुकुमार श्रवस्था का दुरुपयोग न हो श्रीर श्राथिक श्रावश्य-कताश्रों से विवश होकर नागरिकों को ऐसे रोजगारों में न जाना पड़े जो उनकी श्रायु या शक्ति के श्रनुकूल न हों,
- (च) शैशव और किशोर अवस्था की शोषण से तथा नैतिक और आर्थिक परित्याग से रचा हो (अनु०३६)।
- (३) श्राम पंचायतों का संघटन—राज्य श्राम-पंचायतों का संघटन करने की चेष्टा करेगा, तथा उनको ऐसी शक्तियां श्रीर प्राधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिये श्रावश्यक हों (श्रनु० ४०)।
- (४) सहायता—राज्य श्रपनी श्रार्थिक सामर्थ्य श्रीर विकास की सीमाश्रों के भीतर काम पाने के, शिचा पाने के तथा बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी, श्रीर श्रंगहानि तथा श्रन्य श्रनर्ह श्रभाव की दशाश्रों में सार्वजनिक सहायता पाने के, श्रिधिकार को प्राप्त कराने का कार्यसाधक उपबन्ध करेगा (श्रनु० ४१)।
- (१) राज्य काम की यथोचित श्रोर मानवोचित दशाश्रों को सुनिश्चित करने के लिए तथा प्रसृति-सहायता के लिए उपबन्ध करेगा (श्रनु० ४२)।
- (६) श्रमिकों के लिये निर्वाह मजूरी द्यादि—उपयुक्त विधान या आर्थिक संघटन द्वारा, अथवा और किसी दूसरे प्रकार से राज्य कृषि के, उद्योग के या अन्य प्रकार के सब श्रमिकों को काम, निर्वाह-मजूरी, शिष्ट-जीवन-स्तर, तथा अवकाश का सम्पूर्ण उपभोग सुनिश्चित करनेवाली काम की दशायें तथा सामाजिक और सांस्कृतिक अवसर प्राप्त कराने का प्रयास करेगा, तथा विशेष रूप से ग्रामों में कुटीर उद्योगों को वैयक्तिक अथवा सहकारी आधार पर बढ़ाने का प्रयास करेगा (अनु० ४३)।
- (७) भारत के समस्त राज्यत्तेत्र में नागरिकों के लिये राज्य एक समान ध्यवहार-संहिता प्राप्त कराने का प्रयास करेगा (श्रञ्ज ७४)।

संविधान के सिद्धान्त

- (प्र) नि:शुलक ऋतिवार्य शिक्षा—राज्य, इस संविधान के प्रारम्भ से १० वर्ष की अवधि के भीतर सब बालकों को १४ वर्ष की अवस्था-समाप्ति तक नि:शुलक और अनिवार्य शिक्षा देने के लिये प्रबन्ध करने का प्रयास करेगा (अन् ० ४४)।
- (६) दुर्बल भागों के हितों की उन्निति—राज्य जनता के दुर्बलतर-वर्गों के, विशेषतया हरिजनों तथा त्रादिम जातियों के शिचा तथा त्रार्थ सम्बन्धी हितों की विशेष सावधानी से उन्नित करेगा और सामाजिक अन्याय तथा सब प्रकारों के शोषण से उन का संरच्छण करेगा (अनु० ४६)।
- (१०) आहार तथा साईजिनिक स्यास्थ्य—राज्य अपने लोगों के आहारपुष्टि-तल और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा सार्वजिनक स्वास्थ्य के सुधार को अपने प्राथमिक कर्तव्यों में से मारेगा तथा विशेषतया, स्वास्थ्य के लिये हानिकर मादक पेयों और औषधियों के औषधीय प्रयोजनों के अतिरिक्त उपभोग का प्रतिवेध करने का प्रयास करेगा (अनु० ४७)।
- (११) कृषि और पशु पालन—राज्य कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों से संघटित करने का प्रयास करेगा तथा विशेषतः गायों और बछुड़ों तथा अन्य दुधारू और वाहक ढोरों की नस्ल के सुधारने के लिये तथा उनके वध का प्रतिषेध करने के लिये अग्रसर होगा (अनु०४८)।
- (१२) राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों की रत्ता—संसद् से विधि द्वारा राष्ट्रीय महत्व वाले घोषित कलात्मक या ऐतिहासिक श्रमिरुचिवाले प्रत्येक स्मारक, स्थान या वस्तु की यथास्थिति लुंडन, विरूपन, विनाश, श्रपनयन, ज्ययन श्रथवा निर्यात के रत्ता करना राज्य का श्राभार होगा (श्रनु० ४६)।
- (१२) राज्य की लोक-सेवायों में, न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने के लिये राज्य चेष्टा करेगा (त्रजु० ४०)।
- (१४) राज्य ग्रन्तराष्ट्रीय शान्ति श्रौर सुरत्ता की उन्नति का प्रयास करेगा (श्रनु० ४१)।

द्वितीय ऋध्याय

संघीय शासन व्यवस्था

१. राष्ट्रपति

भारत का एक राष्ट्रपति होगा (श्रनु० ४२) जो साधारणतः श्रपने पद ग्रहण की तारीख से पांच वर्ष की श्रवधि तक पद धारण करेगा (श्रनु० ४६)।

संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और वह इसका प्रयोग इस संविधान के अनुसार या तो स्वयं या अपने अधीनस्थ पदाधिका-रियों के द्वारा करेगा।

संघ के रचावलों का उच्चतम समादेश राष्ट्रपति में निहित होगा श्रौर उसका प्रयोग विधि से विनियमित होगा। किन्तु इससे सज्यों की सरकारों के श्रधिकारों पर प्रभाव नहीं पड़िगा, श्रौर श्रम्य प्राधिकारियों को कृत्य देने में संसद को वाधा न होगी (श्रमु० ४३)।

राष्ट्रपति का निर्वाचन—राष्ट्रपति का निर्वाचन एक ऐसे निर्वाच चकगण के सदस्य करेंगे जिसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, तथा राज्यों की विधान-सभाग्रों के निर्वाचित सदस्य होंगे।

संघीय शासन व्यवस्था

राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुपाती प्रतिनिधित्व पद्धित के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होगा और उसमें मतदान गृढ शलाका द्वारा होगा।

जहां तक व्यवहार्य हो, राष्ट्रपति के निर्वाचन में भिन्न भिन्न राज्यों के प्रतिनिधित्व के मापमान में एकरूपता होगी।

राज्यों में त्रापस में ऐसी एकरूपता तथा समस्त राज्यों त्रीर संव में समतुल्यता प्राप्त करवाने के लिए संसद तथा प्रत्येक राज्य की विधान-सभा का प्रत्येक निर्वाचित सदस्य इस निर्वाचन में जितने मत देने का हकद्वार है उसकी संख्या नीचे लिखे प्रकार से निर्धारित की जायेगी:—

- (क) किसी राज्य की विधान-सभा के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य के उत्तने मत होंगे, जितने कि एक हजार के गुणित, उस भागफल में हों जो राज्य की जनसंख्या को उस सभा के निर्वाचित सदस्यों की सम्पूर्ण संख्या से, भाग देने से श्रायें;
- (क) एक हजार के उक्त गुणितों को लेने के बाद यदि शेष पांच सौ से कम न हो तो उपखंड (क) में उल्लिखित प्रत्येक सदस्य के मतों की संख्या में एक श्रीर जोड़ दिया जायेगा।
- (ग) संसद के प्रत्येक सदन के त्येक निर्वाचित सदस्य के मतों की संख्या वही होगी जो उपखंड (क) तथा (ख) के अधीन राज्यों की विधान-सभाओं के सदस्यों के लिये नियत सम्पूर्ण मत-संख्या को, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों की सम्पूर्ण संख्या से भाग देने से आये, जिसमें आधे से अधिक भिंन्न को एक गिना जायेगा और अन्य भिन्नों की उपेना की जायेगी।

उपर्युक्त खंड (क) श्रौर (ख) का हिसाब निम्न लिखित उदाहरण से स्पष्ट हो जायेगा:

उत्तर प्रदेश की जनसंख्या ६,१६,२०,००० है । उसकी विधान-सभा में ४३० सदस्य होंगे। यह मालूम करने के लिए कि प्रत्येक निर्वाचित सदस्य

भारत--नये संविधान तक

राष्ट्रपति के निर्वाचन में कितने मत दे सकेगा, हमें सर्वप्रथम ६,१६,२०,००० (जनसंख्या) को ४३० (कुल निर्वाचित सदस्यों की संख्या) से विभाजित करना होगा, और फिर भागफल में १००० का भाग दिया जायेगा। इसमें भागफल ६१ १६९५००० = १४३३००० त्राया। अतः प्रत्येक सदस्य जितने मत देने का हक्कदार होगा उनकी र । है १४३३०२/१००० अर्थात १४३ (शेष ३०२ को नहीं गिना गया क्योंकि वह ४०० से कम है)।

खंड (ग) का उदाहरण

मान लीजिये कि उपयु क हिसाब से राज्यों की विधान-सभाश्रों के सदस्यों के लिए नियत मतों की संख्या ७४,६४० है और संसद के दोनों सदनों के सदस्यों की कुल संख्या ७४० है, तो संसद के प्रत्येक सदस्य के मतों की स'ख्या मालूम करने के लिये हम ७४,६४० को ७४० से विभाजित करेंगे। संसद का प्रत्येक सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में इतने मत देगा:—

 ${}^{\circ}$ ${}^{\circ}_{\sigma}{}^{\circ}_{\tau}{}^{\circ}{}^{\circ}_{\sigma}{}^{\circ}=$ १० ${}^{\circ}_{\sigma}{}^{\circ}_{\tau}{}^{\circ}_{\tau}$ स्र्थांत १०६ (क्योंकि ${}^{\circ}_{\sigma}{}^{\circ}_{\tau}{}^{\circ}_{\tau}$ को ग्राधे से प्रधिक भिन्न होने के कारण, एक गिना जायेगा।

राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए ऋहैताएं — कोई ज्यक्ति राष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र न होगा जब तक कि वह:

- (क) भारत का नागरिक न हो,
- (ख) ३४ वर्ष की त्रायु पूरी न कर चुका हो, तथा
- (ग) लोक-सभा के लिए सदस्य निर्वाचित होने की श्रहंता न रखता हो।

इसके त्रांतिरिक्त कोई व्यक्ति जो भारत सरकार के अथवा किसी राज्य की सरकार के अधीन किसी लाभ का पद धारण किये हुए है, राष्ट्रपति निर्वाचित होंने का पात्र न होगा (अनु० १८)।

राष्ट्रपति न तो संसद के किसी सदन का ग्रौर न किसी राज्य के विधान-मंडल के सदन का सदस्य होगा।

संघीय शासन व्यवस्था

र।ष्ट्रपति द्वारा शपथ — प्रत्येक राष्ट्रपति खौर प्रत्येक व्यक्ति जो राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहा है ख्रपना पद प्रहण करने से पूर्व भारत के मुख्य न्यायाधिपति के समज्ञ निम्न रूप में शपथ या प्रतिज्ञान करेगा खौर उस पर अपने हस्ताच्चर करेगा :

"मैं, श्रमुक, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं श्रद्धा पूर्वक भारत के सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं राष्ट्रपति-पद का कार्यपालन (श्रथवा राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करूंगा तथा श्रपनी परी योग्यता से संविधान धौर विधि का परिचण, संरच्चण और प्रतिरचण करूंगा और मैं भारत की जनता की सेवा और कल्याण में निरत रहुंगा।"

इसी प्रकार की शपथ या प्रतिज्ञान, प्रकार न्तर से, राज्यपाल, सदनों के सदस्य, मन्त्री त्रादि भी करेंगे।

२. राष्ट्रपति पर महाभियोग

संविधान के श्रतिक्रमण करने पर राष्ट्रपित को महाभियोग द्वारा हटाया जा सकेगा (श्रनु० १६)। जब राष्ट्रपित पर महाभियोग चलाना हो, तब संसद का कोई सदन दोषारोप करेगा। इसके लिये उस सदन के समस्त सदस्यों के कम से कम दो तिहाई बहुमत से एक संकल्प पारित होना श्रपेत्तित है। जब दोषारोप संसद के किसी सदन द्वारा इस प्रकार किया जा चुके, तब दूसरा सदन उस दोषारोप का श्रनुसंधान करेगा या करायेगा श्रोर इस श्रनुसंधान में उपस्थित होने का तथा श्रपना प्रतिनिधित्व कराने का राष्ट्रपित को श्रधिकार होगा।

यदि अनुसंधान के फलस्वरूप उस सदन के समस्त सदस्यों के कम से कम दो तिक्वाई बहुमत से उस दोषारोप की सिद्धि को घोषित करने वाला संकल्प पारित हो जाता है तो उस संकल्प का प्रभाव उसकी पारण तिथि से राष्ट्रपति का अपने पद से हटाया जाना होगा (अनु० ६१)।

महाभियोग सम्बन्धी उपर्युक्त उपबन्ध अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं। वास्तव में राष्ट्रपति को संविधान द्वारा प्रदत्त समस्त शक्ति पर इस अनु-च्छेद से संविधानिक रोक लगा दी गई है। कार्यपालिका का स्वामी राष्ट्रपति

भारत - नये संविधान तक

यदि मंत्रि-परिषद की मन्त्रणा के विक् चलने का साहस करे तो वह इस उपबन्ध की अनुपिस्थिति में निरंकुश तानाशाह बन सकता है। अत: यह उपबन्ध रखा गया है। संसद में सदा मंत्रि-परिषद का बहुमत होने से मंत्रि-परिषद महाभियोग का ही भय दिखा कर राष्ट्रपित को अपनी मंत्रणा पर चलने के लिये वाध्य कर सकती है।

३.चमा आदि की राष्ट्रपति की शक्ति

किसी अपराध के लिए सिद्ध दोष किसी व्यक्ति के दंड को ज्ञमा प्रविलम्बन, प्रस्थान या परिहार करने की अथवा दंडादेश का परिहार या लघूकरण की राष्ट्रपति को शक्ति होगी, यदि वह दंड अथवा दंडादेश सेना न्यायालय ने दिया हो, अथवा संधीय विषय सम्बन्धी किसी विधि के विरुद्ध अपराध के लिये दिया गया हो अथवा वह दंडादेश मन्यु का हो (अनु० ७२)।

४. राष्ट्रपति का संरच्या

राष्ट्रपति श्रपने पद की शक्तियों के प्रयोग श्रौर कर्तव्यों के पालन में श्रपने द्वारा किये गये श्रथवा कर्तुमिभियेत किसी कार्य के लिये किसी न्याया-लय को उत्तरदाथी न होगा।

परन्तु महाभियोग के संबन्ध में संसद के किसी सदन द्वारा नियुक्त न्यायालय राष्ट्रपति के श्राचरण का पुनर्विलोकन कर सकेगा श्रीर किसी व्यक्ति का भारत सरकार के विरुद्ध कार्यवाही चलाने का श्रधिकार निर्वन्धित न होगा।

राष्ट्रपति के विरुद्ध उसकी पदाविध में किसी प्रकार की दंड कार्यवाही किसी नय यालय में न चलेगी श्रीर कोई न्यायालय उसे बहुदी या कारावासी करने के लिये कोई श्रादेशिका नहीं निकाल सकेगा।

राष्ट्रपति के विरुड कोई व्यवहार कार्यवाही भी तब तक नहीं चलेगी जब तक कि उसे दो मास पूर्व लिखित सूचना न दे दी जाये (अनुच्छेद १६१)।

यही संरत्तरण सम्बन्धी उपबन्ध राज्यपालों तथा राजप्रमुखों के विषय में भी लागू होंगे।

संघीय शासन व्यवस्था

५. राष्ट्रपति की विधायिनी शक्तियां

उस समय को छोड़ कर जब कि संसद के दोनों सदन सत्र में हैं, राष्ट्रपति तुरन्त कार्यवाही की आवश्यकता होने पर अध्यादेश जारी कर सकेगा, जो संसद के अधिनिमय के समान प्रभावी होगा किन्तु ऐसा अध्या-देश संसद के समच रखा जायेगा, तथा संसद के पुन: समवेत होने के बाद द सप्ताह की समाप्ति पर प्रवर्तन में न रह सकेगा (अनु० १२३)।

६. भारत का उपराष्ट्र पति

भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा जो राष्ट्रपति की मत्यु, पदत्याग अथवा पद से हटाये जाने अथवा अन्य कारण से पद रिक्ता की अवस्था में राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा जब तक नया राष्ट्रपति निर्वाचित न हो जाय। अनुपिस्थिति, बीमारी अथवा अन्य किसी कारण से जब राष्ट्रपति अपने कृत्यों को करने में असमर्थ हो, तब भी उपराष्ट्रपति ही उसके कृत्यों का निर्वहन करेगा (अनु० ६३ और ६४)।

उपराष्ट्रपति पदेन राज्य परिषद का सभापति होगा और अन्य कोई लाभ का पद धारण न करेगा (अनु० ६४)।

उपराष्ट्रपति का निर्वाचन—संयुक्त अधिवेशन में एकत्रित, संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा अनुपाती प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकत संक्रमणीय मत द्वारा उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होगा तथा ऐसे निर्वाचन में मतदान गृह शलाका द्वारा होगा।

उपराष्ट्रपति न तो संसद के किसी सदन का और न किसी राज्य के विधान-मंडल के सदन का सदस्य होगा।

कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र न होगा जब तक कि वह भारत का नागरिक न हो, ३४ वर्ष की आयु पूरी न कर चुका हो और राज्य-परिषद् के लिए सदस्य निर्वाचित होने की अर्हता न रखता हो।

कोई व्यक्ति जो भारत सरकार के श्रथवा किसी राज्य की सरकार के श्रधीन कोई लाभ का पद धारण किए हुए हो उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र न होगा (श्रजु० ६६)।

भारत-नये संविधान तक

उपराष्ट्रपति की पदावधि—उपराष्ट्रपति अपने पड़ ग्रहण की तारीख से पांच वर्ष की अवधि तक पढ़ धारण करेगा, परन्तु उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति को सम्बोधित अपने हस्ताचर सहित लेख द्वारा अपना पढ़ त्याग सकेगा और उपराष्ट्रपति, राज्य-परिषद के ऐसे संकल्प द्वारा, अपने पढ़ से हटाया जा सकेगा जिसे परिषद् के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत ने पारण किया हो तथा जिसे लोक-सभा ने स्वीकृत किया हो (अनु०६७)।

उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ – प्रत्येक उपराष्ट्रपति श्रपने ५ द प्रहण करने से पूर्व राष्ट्रपति श्रथवा उसके द्वारा उस क्षिये नियुक्त किसी व्यक्ति के समज्ञ निम्न रूप में शपथ या प्रतिज्ञान करेगा श्रीर उस पर श्रपना हस्ता-त्तर करेगा, श्रथीतः

में, अमुक..... ईंश्वर की शपथ लेता हूं कि में भारत

के संविधान के प्रति श्रद्धा ग्रौर निष्ठा रखूंगा तथा जिस पद को मैं प्रहण करने वाला हूं उसके कर्तस्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा।

राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से उत्पन्न या सम्बन्धित सब शंकाओं श्रोर - विवादों यी जाँच श्रोर निर्णय उच्चतम न्यायालय करेगा श्रोर उसका निर्णय श्रन्तिम क्षोगा। इसका यह श्राशय है कि उच्चतम न्यायालय किसी च्यक्ति के राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के रूप में निर्वाचन को शून्य घोषित कर सकता है (श्रनु० ७३)।

७ संघ की कार्यपालिका शक्ति

संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार उन विषयों तक होगा जिनके सम्बन्ध में संसद को विधि बनाने की शक्ति है (अर्थात् संघ-सूचि और समवर्ती सूचि के विषयों तक होगा] इसके अतिरिक्त किसी संधि या करार के आधार पर भारत सरकार द्वारा प्रयोग किये जाने वाले अधिकार, प्राधिकार और सेत्राधिकार का प्रयोग भी संघीय कार्यपालिका द्वारा ही किया जायेगा (अनु० ७३)।

संघीय शासनं व्यवस्था

याद रहे भारत की शासन प्रणाली संघीय है अतः संघ की कार्यपालिका शक्ति तथा संसद की विधि बनाने की शक्ति 'संघ सूची' तथा 'समवर्ती सूची' के विषयों तक ही सीमित है जिनका वर्णन आगे चल कर किया जायेगा (देखिये परिशिष्ट)।

८ मंत्रि-परिषद

राष्ट्रपति को अपने कृत्यों का सम्पादन करने में सहायता और मंत्रणा देने के लिये एक मंत्रि-परिषद होगी, जिसका अगुवा प्रधान मंत्री होगा | क्या मंत्रियों ने राष्ट्रपति कोई मंत्रणा दी और यदि दी तो क्या दी, इस प्रश्न की किसी न्यायालय में जांच न की जायेगी (अनु० ७४)।

प्रधान मंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधान मंत्री की मंत्रणा पर करेगा। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यन्त मन्त्री अपने पद धारण करेंगे। मन्त्रि परिषद् लोक-सभा के प्रति सामूहिक रूप से उतरदायी होगी। किसी मंत्री के अपने पद अहण करने से पहले राष्ट्रपति उससे पद की तथा गोपनीयता की शपथें करायेगा। कोई मंत्री जो निरन्तर छः मास की किसी अवधि तक संसद के किसी सदन का सदस्य न रहे, उस अवधि की समाप्ति पर मंत्री न रहेगा। मंत्रियों के वेतन तथा भन्ते वे होंगे जो समय समय पर संसद विधि द्वारा निश्चय करें (अनु० ७१)।

६ सरकारी कार्य का संचालन

भारत सरकार की समस्त कार्थपालिका कार्यवाही राष्ट्रपति के नाम से की हुई कही जायेगी।

भारत सरकार का कार्य अधिक सुविधा पूर्वक किये जाने के लिये तथा मंत्रियों में उक्त कार्य को बांटने के लिये राष्ट्रपति नियम बतायेगा (अनु० ७७)।

प्रधान मंत्री का कर्तव्य होगा कि वह संघ कार्यों के प्रशासन सम्बन्धी मंत्रि-परिषद के समस्त निर्णय तथा विधान के लिये प्रस्थापनायें, राष्ट्रपति को पहुंचाये;

भारत-नये संविधान तक

संघ कार्यों के प्रशासन सम्बन्धी तथा विधान विषयक प्रस्थापनात्र्यों सम्बन्धी जिस जानकारी को राष्ट्रपति मंगावे, उसको दे तथा;

किसी विषय को जिस पर किसी मंत्री ने निर्णय कर दिया है किन्तु मंत्रि परिषद ने विचार नहीं किया हो, राष्ट्रपति की अपेचा करने पर परिषद् के सम्मुख विचार के लिए रखे (अनु० ७८)।

१० भारत का महान्यायावादी

उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने की योग्यता रखने वाले व्यक्ति को राष्ट्रपति भारत का महान्यायावादी नियुक्त करेगा।

महान्यायावादी का कर्तन्य होगा कि वह भारत सरकार को ऐसे विधि सम्बन्धी विषयों पर मंत्रणा दे और ऐसे विधि रूप दूसरे कर्तन्यों का पालन करे जो राष्ट्रपति उसे समय समय पर भेजे या सौंपे। अपने कर्तन्यं के पालन के लिये महान्यायवादी को भारत राज्य-चेत्र में के सब न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होगा।

महन्यायाबादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्थन्त पद धारण करेगा तथा राष्ट्रपति द्वारा निश्चित पारिश्रमिक पायेगा (श्रनु०७६)।

११ संसद की रचना

संसद् का गठन-संघ के लिये एक संसद होगी जो राष्ट्रपित श्रीर दो सदनों से मिल कर बनेगी जिनके नाम क्रमशः राज्य-परिषद श्रीर लोक सभा होंगे (श्रनु० ७१)।

राज्य-परिषद् की रचना

राज्य-परिषद राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत बारह सदस्यों श्रीर राज्यों के दो सौ श्रव्हतीस से श्रनधिक प्रतिनिधियों से मिलकर बनेगी । राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किये जाने वाले सदस्य ऐसे व्यक्ति होंगे जिन्हें साहित्य विज्ञान, कला श्रीर समाज सेवा के बारे में विशेष ज्ञान या व्यवहारिक श्रनुभव है ।

संघीय शासन व्यवस्था

राज्य-परिषद के लिये राज्यपालों तथा राजप्रमुखों के प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधि उस राज्य की विधान-सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा श्रनुपाती प्रतिनिधित्व पद्धति के श्रनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा निर्वाचित होंगे; श्रीर केन्द्रीय शासन के श्राधीनस्थ राज्यों के प्रतिनिधि ऐसी रीति से चुने जायेंगे जैसी कि संसद विधि द्वारा निश्चित करे (श्रनु० ८०)।

राज्यों के प्रतिनिधि द्वारा भरे जाने वाले स्थानों का बटवारा इस प्रकार होगाः---

भाग (क) राज्यपालों के राज्य-१४४ स्थान

9.	श्रासाम	६	ξ.	मद्रास	२७
₹.	पश्चिमी बंगा	ल १ ४	७.	उड़ीसा	3
₹.	बिहार	२१	ح.	पंजाब	5
8.	बम्बई	30	٤.	उत्तर प्रदे	श ३ १
4.	मध्य प्रदेश	92			

भाग (ख) राजप्रमुखों के राज्य-४६ स्थान

۹.	हैदराबाद	99	*.	प०पू०प०रा० संघ	ર
₹.	जम्मू श्रौर		ξ.	राजस्थान	8
	काश्मीर	8	9 .	सौराष्ट्र	8
₹.	मध्यभारत	६	5.	त्रावनकोर-कोचीन	ξ
8.	मैसूर	६			

भाग (ग) केन्दीय शासन के ऋधीनस्थ राज्य-११ स्थान

3.	ग्रज सेर)	3	६ कृच बिहार	3
₹.	कुर्ग ∫		७. दिल्ली	1
₹.	भोपाल	3	म . कच्छ	3
8.	बिलासपुर ्		१. मनीपुर)	3
ধ.	हिमाचल ∫	3	१०. त्रिपुरा	
			११. विन्ध्य प्रदेश १	8

लीक सभा की रचना—राज्यों में के मत दाताओं द्वारा प्रत्यच रीति से निर्वाचित १०० से अधिक सदस्यों से मिल कर लोक-सभा बनेगी।

भारत - नये संविधान तक

प्रति ७,४०,००० जनसंख्या के लिये एक से कम सहस्य तथा प्रति १००००० जनसंख्या के लिए एक से अधिक सहस्य न होगा।

प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन चेत्र को बांट में दिये गये सद्स्यों की संख्या का निश्चित की गईं जनसंख्या से श्रनुपात समस्त भारत में यथासाध्य एक ही होगा।

लोक-सभा में जनसंख्या के प्रत्येक ७.२ लाख के लिये एक स्थान रखा गया है। स्थान वितरण इस प्रकार है:

भाग (क) राज्यपालों के राज्य भाग (ख) राजप्रमुखों के राज्य

9.	उ रप्रदेश	= =	9	हैदराबाद	२४
٧_	श्रासाम	92	2 5	नम्मू ग्रौर	
₹.	बिहार	44		काश्मीर	ξ
8.	बम्बई	४४	₹ ‡	ग्ध्यभारत	99
ሂ.	मध्यप्रदेश	२१	8 1	रैस् र	99
ξ.	मद्रास	**	१ प	. पु. प. रा.स	नंघ १
o .	उड़ीसा	२०	६	राजस्थान	20
5.	पंजाब	3 =	७ र	गौराष्ट्र	Ę
.3	पश्चिमी बंग	ाल ३४	দ রা	विनकोर-कोर्च	ीन१२
	योग	३७४	No. of Contract of	यो	ग ६६

भाग (ग) केन्द्र-प्रशासित राज्य

4.	विन्ध्यप्रदेश	६	.9	त्रिपुरा	2
₹.	दिक्जी	8	7	मनीपुर	2
₹.	हिमाचल प्रदेश	३	ĕ	कुर्ग .	3
8.	ग्रजमेर	२	90	बिलासपुर	3
¥	भोपाल	7	99	ॐंद्रमान	9
६	कच्छ	२			२६

कुल स्थान-४६६

संघीय शासन च्यवस्था

प्रत्येक जनगणना की समाप्ति पर लोक-सभा में, विभिन्न प्रादेशिक निर्वाचन-चेत्रों के प्रतिनिधित्व का पुनः समायोजन किया जायेगा।

परन्तु ऐसे पुनः समायोजन से उस समय विद्यमान लोक-सभा के प्रतिनिधित्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा (त्रानु० ८१)।

संसद् के सद्नों की अविधि: राज्य-परिषद् का विघटन न होगा, किन्तु उसके सद्स्यों में से यथाशक्य निकटतम एक तिहाई प्रत्येक द्वितीय वर्ष की समाप्ति पर निवृत्त हो जायेंगे। लोक-सभा यदि पहिले ही विघटन न कर दी जाये, तो अपने प्रथम अधिवेशन के लिये नियुक्त तारीख से पांच वर्ष तक चाल् रहेगी और इससे अधिक नहीं तथा पांच वर्ष की समाप्ति का परिणाम लोक-सभा का विघटन होगा।

परन्तु उक्त अवधि को, जब तक आपात स्थिति की उद्घोषणा प्रवर्तन में है, संसद् विधि द्वारा किसी अवधि के लिये बढ़ा सकेगी, जो एक बार एक वर्ष से अधिक न होगी और किसी अवस्था में भी उद्घोषणा के परचात छः मास की अवधि से अधिक विस्तृत न होगी (अनु० = ३).।

१२. सदस्यों की अईता आदि

कोइ व्यक्ति संसद में के किसी स्थान की पूर्ति के लिये चुने जाने के लिये यह न होगा जब तक कि—

- (क) वह भारत का नागरिक न हो,
- (ख) राज्य-परिषद् के स्थान के लिये, कम से कम तीस वर्ष की त्रायु का तथा लोक-सभा के स्थान के लिये कम से कम पच्चीस वर्ष की त्रायु का न हो, तथा
- (ग) ऐसी अन्य अर्हतायें न रखता हो जो कि इस बारे में संसद् निर्मित किसी विधि के द्वारा या अधीन विहित की जायें (अ.नु॰ ८४)।

सदस्यों की अनर्हतायें: कोई व्यक्ति संसद के दोनों सदनों का सदस्य न होगा। कोई व्यक्ति संसद अथवा किसी राज्य के विधान-मंद्रल इन दोनों का सदस्य न होगा।

भारत - नये संविधान तक

यदि कोई सदस्य साठ दिन की कालावधि तक सदन की श्रनुज्ञा के विना उसके सब श्रधिवेशनों से श्रनुपस्थित रहे तो सदन उसके स्थान को रिक्त घोषित कर सकेगा (श्रनु० १०१)।

कोई व्यक्ति संसद का सदस्य बनने के लिये अनई होगा-

- (क) यदि वह भारत सरकार के अथवा किसी राज्य की सरकार के अधीन कोई लाभ का पद धारण किये हुए है,
- (ख) यदि वह विकृतचित्त है
- (ग) यदि वह भारत का नागरिक नहीं है
- (घ) यदि वह अनुनमुक्त दिवालिया है
- (ङ) यदि वह संसद-निर्धित किसी विधि के द्वारा इस प्रकार अनर्ह कर दिया गया है (अनु० १०२)।

यदि संसद के किसी सदन में कोई न्यक्ति सदस्य के रूप में उपर्युक्त अपेचाओं की पूर्ति करने के पूर्व बैठता या मतदान करता है, तो वह प्रत्येक दिन के लिये, जब कि वह इस प्रकार बैठता है पांच सौ रूपये के दंड का भागी होगा (अनु० १०४)।

सदस्यों की शिक्तियां, विशेषाधिकार आदिः इस संविधान के उपवन्धों के तथा संसद की प्रक्रिया के नियमों और स्थायी आदेशों के अधीन रहते हुए संसद में वाक्-स्वातन्त्र्य होगा।

संसद में या उसकी किसी समिति में कही हुई बात किसी के विषय में किसी सदस्य के विरुद्ध किसी न्यायालय में कोई कार्यवाही नहीं चल सकेगी।

श्रन्य बातों में सदस्यों तथा सदन की शक्तियां विशेषाधिकार श्रीर उन्मुक्तियां ऐसी होंगी, जैसी संसद, समय समय पर विधि द्वारा परिभाषित करें, श्रीर जब तक इस प्रकार परिभाषित नहीं की जातीं तब तक इंगलिस्तान की लोकसभा के समान होंगी।

श्रापथ या प्रतिज्ञानः संसद के प्रत्येक सदन का प्रत्येक सदस्य अपना स्थान ग्रहण करने से पूर्व, राष्ट्रपति द्वारा तद्र्थ नियुक्त व्यक्ति के समज्ञ श्रापथ लोगा या प्रतिज्ञान करेगा तथा उस पर हस्ताज्ञर करेगा (अनुच्छेद ११)।

संघीय शासन व्यवस्थी

१३. संसद और कार्यवालिका

राष्ट्रपति समय समय पर सदनों को अथवा किसी सदन को ऐसे समय तथा स्थान पर जैसा कि वह उचित समके, अधिवेशन के लिये बुला सकेगा, सदनों का सत्रावसान कर सकेगा, तथा लोक-सभा का विघटन कर सकेगा। किन्तु संसद के सदनों को प्रतिवर्ष कम से कम दो बार अधिवेशन के लिये बुलाया जायेगा, तथा दो बैठकों के बीच छ मास का अन्तर न होगा (अनु० ८४)।

संसद् के किसी एक सदन को अथवा साथ समवेत दोनों सदनों को राष्ट्रपति सम्बोधित कर सकेगा और इस प्रयोजन के लिये सदस्यों की उपस्थिति की अपेना कर सकेगा।

राष्ट्रपति संसद् में उस समय लिम्बत किसी विधेयक विषयक अथवा अन्य विषयक सन्देश संसद् के किसी सदन को भेज सकेगा और वह सदन, उस सन्देश द्वारा अपेचित विचारणीय विषय पर यथासुविधा शीव्रता से विचार करेगा अनु० = ६)।

प्रत्येक सत्र के श्रारम्भ में, साथ समवेत संसद् के दोनों सदनों को राष्ट्रपति सम्बोधन करेगा श्रीर संसद् को श्राहवान का कारण बतायेगा (श्रनु॰ ८७)।

सदनों विषयक मंत्रियों और महान्यायवादी के अधिकार— भारत के प्रत्येक मंत्री और महान्यायवादी को अधिकार होगा कि वह किसी भी सदन में, सदनों के किसी संयुक्त बैठक में, तथा संसद की किसी समिति में, जिसमें उसका नाम सदस्य के रूप में दिया गया हो, बोले तथा दूसरे प्रकार से कार्यवाहियों में भाग ले, किन्तु इस अनुच्छेद के आधार पर उसको मत देने का हक्क न होगा (अनु० ८८)।

१४. संसद के पदाधिकारी

भारत का उपराष्ट्रपति पदेन राज्य-परिषद् का सभापति होगा। राज्य-परिषद् यथासम्भव शीघ्र अपने किसी सदस्य को अपना उप-सभापति चुनेगी (अनु० ८६)।

भारत-नये संविधान तक

जब कि सभापित का पद रिक्त हो, अथवा किसी कालाविध में जब कि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहा हो, अथवा उसके कृत्यों का निर्वहन कर रहा हो, अथवा सभापित अनुपस्थित हो; तब उपसभापित उस पद के कर्तव्यों का पालन करेगा (अनु० ११)।

लोक-सभा का अध्यक्त और उपाध्यक्त—लोक-सभा यथासम्भव शीव्र अपने दो सदस्यों को क्रमशः अपने अध्यक्त और उपाध्यक्त चुनेगी।

जब कि अध्यक्त का पद रिक्त हो या वह अनुपस्थित हो तब उपाध्यक्त उस पद के कर्तन्त्रों का पालन करेगा (अनु० ६३, ६४)।

राज्य-परिषद् के सभापित और उपसभापित को, तथा लोक-सभा के अध्यत्त और उपाध्यत्त को, व वेतन और भन्ते दिये जायेंगे, जो क्रमशः संसद् विधि द्वारा नियत करें। संसद् के प्रःयेक सदन का अपना पृथक सचिवालय कर्मीवृन्द होगा (अनु० ६ ३, ६ ८)।

१५ संसद में कार्य प्रणाली

बहुमत से निश्चय—-संविधान में अन्यथा उपवन्धित अवस्था को छोड़ कर किसी सदन की किसी बैठक में अथवा सदनों की संयुक्त बैठक में सब प्रश्नों का निश्चय उपस्थित तथा मतदान देने वाले सदस्यों के बहुमत से किया जायेगा। अध्यक्त या सभापित या उसके रूप में कार्य करने वाला व्यक्ति प्रथमतः मत न देगा, पर मतसाम्य की अवस्था में उसका निर्णायक मत होगा और वह उसका प्रयोग करेगा (अनु० १००)।

प्रक्रिया के नियम-प्रत्येक सदन अपनी प्रक्रिया के, तथा अपने कार्य संचालन के, विनियमन के लिये नियम बना सकेगा।

भाषा—संसद में कार्य हिन्दी सें या अंग्रेजी में किया जायेगा, किन्तु १४ वर्ष तक विश्रेयक आदि अंग्रेजी में ही पेश होंगे। १४ वर्ष बाद अंग्रेजी में कार्य नहीं होगा, जब तक कि संसद अन्यथा उपबन्ध न करे। कोई सदस्य दोनों भाषाओं में अपनी पर्याप्त अभिन्यक्ति नहीं कर सके, तो यथास्थिति सभापित या अध्यच उसे अपनी मातृभाषा में बोलने की अनुमित दे सकेगा (अनु० १२०)।

संघीय शासन व्यवस्था

न्यायाधीशों की ऋलोचना—उच्चतमं न्यायालयं या उच्चे न्यायालय के किसी न्यायाधीश के कर्तव्य पालन में किये गये आचरण के विषय में संसद में कोई चर्चा नहीं होगी, जब तक कि उसे हटाने का प्रस्ताव नियमानुसार पेश न हो (अनु० १२२)।

विधेयकों के पारण की प्रणाली—धन-विधेयकों तथा अन्य वित्तीय विधेयकों के अतिरिक्त कोई विधेयक संसद के किसी सदन में आरम्भ हो सकेगा। दोनों सदनों द्वारा स्वीकृत होने पर ही कोई विधेयक पारित समका जायेगा (अनु० १०७)।

यदि किसी विधेयक के विषय में या उसमें किये जाने वाले किसी संशोधन पर दोनों सदन श्रंतिम रूप वे श्रसहमत हो जायें, तो राष्ट्रपति दोनों सदनों को संयुक्त बैठक में श्रिधिवेशित होने के लिये श्रिधसूचना देगा श्रौर यदि संयुक्त बैठक में वह विवेयक बहुमत से पारित हो जाये तो वह दोनों सदनों द्वारा पारित समभा जायेगा (श्रनु० १०८)।

धन-विधेयकों पर लोक-सभा की सम्पूर्ण सत्ता—धन-विधेयक राज्य-परिषद में पुरः स्थापित नहीं किया जायेगा। लोक-सभा में पारित हो जाने के परचात, धन-विधेयक राज्य-परिषद में उसकी सिपारिश के लिये जायेगा, तथा राज्यपरिषद उसे चौदह दिन की कालार्वाध के भीतर अपनी सिपारिशों सहित लोक-सभा को लौटा देगी और लोक-सभा उन सिपारिशों में से सबको या किसी को स्वीकार या अस्वीकार कर सकेगी (अनु० १०१)।

राष्ट्रपति की अनुमित—दोनों सदनों द्वारा पारित होने के पश्चात प्रत्येक विधेयक राष्ट्रपति के समज्ञ उपस्थित किया जायेगा तथा राष्ट्रपति या तो उस पर अनुमित दे देगा या उसे, यदि वह धन-विधेयक नहीं है तो, सदनों को अपने संदेश के साथ पुनर्विचार के लिये लौटा सकेगा। परन्तु यदि वह सदनों द्वारा संशोधन सहित या रहित पुनः पारित हो जाये, तो राष्ट्रपति उस पर अपनी अनुमित न रोकेगा।

१६. श्रोय-व्ययक

राष्ट्रपति प्रतिवर्ष संसद के दोनों सदनों के समत्त उस वित्तीय वर्ष के विये प्राक्कितित प्राप्तियों और न्ययों का विवरण (बजट) रखवायेगा । उस

तृतीय अध्याय

राज्यों की शासन-व्यवस्था

१. सामान्य

राज्यपालों तथा राजप्रमुखों के राज्यों में शासन-व्यवस्था की रूपरेखा मुख्यतः केन्द्रीय ढांचे से मिलती हुई है। उन राज्यों में राज्यपालों अथवा राजप्रमुखों की स्थिति सामान्यतः वही है जो संबीय ढांचे में राष्ट्रपति की है और उनका अपनी अपनी मंत्रि-परिषदों से वही सम्बन्ध है जो केन्द्र में राष्ट्रपति का संबीय मंत्रि-परिषद से है। इसी प्रकार उन राज्यों में विधानसभा की वही स्थिति है जो केन्द्र में लोक-सभा की है तथा जिन राज्यों में द्वितीय सदन विधान-परिषद हो, वहाँ उसकी स्थिति राज्य-परिषद के समान ही प्रायः होगी। दोनों व्यवस्थाओं में यह अन्तर है कि राज्यपाल या राजप्रमुख को महाभियोग द्वारा नहीं हटाया जा सकता। राज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जायेगा तथा राष्ट्रपति के प्रसाद काल तक ही अपने पद पर श्रासीन रहेगा, यद्यपि सामान्यतः उसकी पदावधि पांच वर्ष होगी। राजप्रमुख तब तक अपने पद पर रहेगा जब तक राष्ट्रपति उसे इस रूप में मान्यता दे, अर्थात उसकी पदावधि की सीमा न होगी। हेदराबाद में वही व्यक्ति राजप्रमुख की शक्तियों का प्रयोग करेगा जिसे राष्ट्रपति उस समय विजाम स्वीकार करले। ऐसी ही स्थिति काश्मीर तथा मैसूर में होगी।

भारत--नये संविधान तक

२. राज्यों की तीन श्रे णियां

जैसा कि पहले बताया जा चुका है भारत राज्यों का संघ है। भारत में २७ राज्य हैं, जिन्हें तीन श्रेणियों में विभाजित किया गया है। इनमें से १० राज्यों (ग्रजमेर, कच्छ, कोइग, त्रिपुरा, दिल्ली, बिलासपुर, भोपाल, मनीपुर, विन्ध्यप्रदेश तथा हिमाचल प्रदेश) का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा किया जायेगा तथा वह मुख्य त्रायुक्त या उपराज्यपाल नियुक्त करके या पड़ीसी राज्य की सरकार द्वारा इन राज्यों का प्रशासन चलायेगा।

इन राज्यों के लिये मंसद विधि द्वारा विधान-मंडल या मंत्रि-परिपद स्रादि भी बनवा सकती है (स्रजु० २३६-२४२)।

शेष सत्तरह राज्यों में से १ राज्यों में (जो पहले प्रांत थे), एक एक राज्यपाल होगा जो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होगा तथा राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा, किन्तु साधारणतः उसकी पदावधि पांच वर्ष होगी।

उपर्यु क्त राज्यों के श्रितिरिक्त श्राठ श्रन्य राज्य (१) जम्मू श्रौर काश्मीर (२) त्रावनकोर-कोचीन श्रथवा टेक्कू-केरल (३) पटियाला तथा पूर्वी पंजाब राज्य संघ श्रथवा फुलिकया राज्य (४) मध्यभारत (४) मैसूर (६) राजस्थान (७) सौराष्ट्र श्रौर (८) हैदराबाद हैं। इन में राज्यपालों के स्थान पर राजप्रमुख हैं।

राजप्रमुखों के राज्यों पर राष्ट्रपति का अपेचाकृत अधिक नियंत्रण होगा। यह इस लिये किया गया है कि वहां जनतंत्र पद्धति ने इतनी प्रगति नहीं की है जितनी कि राज्यपालों के राज्यों में की है।

३. राज्यपाल या राजप्रमुख

राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल अथवा राजप्रमुख में निहित होगी, तथा वह उसका प्रयोग इस संविधान के अनुसार करेगा (अनु० १२४)।

राज्यपाल या राजप्रमुख संसद या किसी विधान-मंडल का सदस्य न होगा तथा अन्य कोई लाभ का पद धारण न करेगा। राज्यपाल का वेतन सादे पांच हजार रुपये प्रतिमास होगा तथा उसे भन्ते तथा पदावास भी मिलेगा।

राज्यों की शासन-व्यवस्था

राजिश्मुखों को निजी थैली के रूप में जो राशि मिजती है वही मिजेगी तथा श्रपना महल न होने पर पदावास भी मिल सकेगा।

राज्यपाल या राजप्रमुख राष्ट्रपति के समान श्रपने पद की शपथ लेगा।

राज्य के किसी विषय संबंधी किसी अपराध के संबंध में राज्यपाल या राजप्रमुख को चमा या लघुकरण आदि की शक्ति होगी।

राज्यपाल या राजप्रमुख के कृत्य दो प्रकार के हैं—

- (१)जिनमें वह स्वविवेक से कार्य करेगा,
- (२) जिनमें वह मंत्रि-परिषद की मंत्रणा से कार्य करेगा।

उसे किस विषय में स्वविषेक से कार्य करना है, यह निश्चय वह स्वयं ही करेगा (श्रनु० १६३)।

४. राज्यपाल की विधायिनी शक्तियां

उस समय की हो छोड़ कर जब कि विधान-सभा या दोनों सदन सन्न में हैं, राज्यपाल (या राजप्रमुख) तुरन्त कार्यवाही की त्रावश्यकता होने पर श्रध्यादेश जारी कर सकता है, जो विधान-मंडल के श्रधिनियम के समान प्रभावी होगा, किन्तु ऐसा श्रध्यादेश विधान-मंडल के समस रखा जायेगा, तथा विधान-मंडल के पुनः समन्नेत होने के बाद ह सप्ताह की समाप्ति पर प्रवर्तन में न रहेगा।

५. मंत्रि-परिषद

मंत्रि-परिषद का प्रधान मुख्य-मंत्री होगा। मुख्य-प्रन्त्री की नियुक्ति राज्यपाल या राज्यमुख करेगा तथा अन्य मन्त्रियों की भी नियुक्ति वह मुख्य-मन्त्री की मंत्रणा से करेगा। मंत्री अपने पद राज्यपाल या राज्यमुख के प्रसाद पर्यन्त धारण करेंगे। उड़ीसा, बिहार, मध्यप्रदेश और मध्यभारत राज्यों में आदिम जातियों के कल्याण के लिये एक मन्त्री होगा (अनु० १६३, १६४)।

मन्त्रि-परिषद विधान-सभा के प्रति सामृद्धिक रूप से उत्तरदायी होगी श्रिनु १६४ (२)]।

भारत - नये संविधान तक

६. महाधिवक्ता

प्रत्येक राज्यपाल (या राजप्रमुख) राज्य के लिये एक महाधिवक्ता नियुक्त करेगा जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने की योग्यता रखने वाला व्यक्ति होगा। वह राज्यपाल के प्रसाद पर्यन्त पद धारण करेगा तथा भारत के महान्यायवादी के समान उस राज्य के सम्बन्ध में कार्य करेगा (अनु० १६४)।

७. सरकारी कार्य का संचालन

राज्य की सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्यवाही राज्यपाल (या राजप्रमुख) के नाम से की हुई कही जायेगी (श्रनु० १६६)।

मुख्य मंत्री का कर्तव्य होगा कि प्रशासन सम्बन्धी तथा विधान संबंधी सब सूचनायें राज्यपाल (या राजप्रमुख) को देता रहे (श्रुनु० १६७)।

विधान-मंडल की रचना

प्रत्येक राज्य में एक विधान-मंडल होगा जिसमें राज्यपाल। (या राज-प्रमुख) तथा विधान-सभा नामक सदन होगा। पंजाब, पश्चिमी बंगाल, बिहार, मुंबई, उत्तरप्रदेश तथा मैस्र के विधान-मंडलों में एक एक श्रीर सदन भी होगा जिसका नाम विधान-परिषद होगा। संसद, किसी राज्य की विधान सभा की प्रार्थना पर वहां की विधान-परिषद को हटा सकती है, या, नहीं हो तो, उसका सजन कर सकती है (श्रनु० १६८-१६६)।

विधान-सभा — विधान सभा में ६० से लेकर पांच सौ तक सदस्य होंगे जो प्रत्यत्त निर्वाचत द्वारा चुने जायेंगे। जनसंख्या के प्रत्येक ७४ हजार के लिये एक से श्रनधिक प्रतिनिधि होगा (श्रनु० १७०)।

लोक प्रतिनिधित्व प्रधिनियम १६४० के श्रनुसार राज्यों की विधान-सभाश्रों के कुल स्थानों की रांख्या निम्न लिखित होगी :

राज्यों की शासन व्यवस्था

	भाग (क) राष्यपालों के	राज्य
٩.	उत्तर प्रदेश	४३०
₹.	मंद्रास	३७४
₹.	बिहार	३३०
8.	बंबई	३१४
ধ.	पश्चिमी बंगाल	२३ँद
ξ.	मध्य प्रदेश	२३२
৩.	उड़ीसा	80
5.	पंजाब	१२६
8.	त्रासाम	305
	भाग (ख) राजप्रमुखों के र	ाज्य
۹.	हैदराबाद	१७४
₹.	राजस्थान	१६०
₹.	त्रावनकोर-कोचीन	१०८
8.	मेसूर	33
٧.	मध्यभारत	33
ξ.	सौराष्ट्र	६०
o .	प० पू० पं० रा० संघ.	६०

विधान-सभा की कालावधि पांच वर्ष होगी, किन्तु श्रापात की स्थिति मं संसद उसे बढ़ा सकती है।

विधान परिषदः किसी राज्य की विधान-परिषद के सदस्यों की संख्या उस राज्य की विधान-सभा के सदस्यों की संख्या की एक चौथाई से प्रधिक न होगी, किन्तु चालीस से कम भी न होगी।

जब तक संसद श्रन्यथा उपबन्ध न करे, तब तक विधान-परिषद की रचना इस प्रकार होगी कि:

- (क) यथाशक्य तृतीयांश सदस्य नगर पालिकात्रों, नगरमंडलों स्रादि द्वारा चुने जायेंगे,
- (ख) द्वादशांश उस राज्य के स्नातकों द्वारा चुने जायेंगे,
- (ग) द्वादशांश माध्यमिक पाठशालात्रों के शिचकों द्वारा चुने जायेंगे,

भारत—नये संविधान तक

- (घ) तृतीयांश विधान-सभा के सदस्यों द्वारा चुने जायेंगे,
- (ङ) शेष राज्यपाल द्वारा नियुक्ति होंगे जो साहित्य. विज्ञान, कला, सहकारी अंदोलन श्रीर सामाजिक सेवा में विशेषज्ञ हों (श्रमुच्छेद १७१)।

विधान-परिषदों में स्थानों का वितर्ण

राज्य का नीम	कुल स्थान	उपखंड (क)		उपखंड (ग)	उपखंड (घ)	उपखंड (ह)
 राज्यपालों के राज्य			The state of the s			T THE STREET
१. उत्तरप्रदेश	७२	२४	६	હ્	२४	35
२. मद्रास	७२	२४	Ę	Ę	२४	92
३. बिहार	७२	२४	હ	દ્	२४	9 २
४. बम्बई	७२	२४	હ્	8	२४	9 २
१, पश्चिमी बंगाल	২ ૧	90	8	ષ્ઠ	30	8
६, पंजाब	80	33	3	ર	33	5
राजप्रमुख का राज्य						
१. मैसूर	80	13	3	ર	93	=

विधान-परिषद का विघटन न होगा किन्तु उसके एक तिहाई सदस्य प्रत्येक द्वितीय वर्ष की समाप्ति पर बद्दल जायेंगे।

६. सदस्यों की ऋहता

विधान-सभा की सदस्यता के लिये अभ्यर्थी भारत का निगरिक होते के अतिरिक्त २४ वर्ष से अधिक आयु का होना चाहिये, तथा विधान-परिषद के लिये तीस वर्ष से कम न होना चाहिये।

संसद विवान-मंडल की सदस्यता के लिये अन्य योग्यताएं भी निर्धारित कर सकती है।

राज्यों की शासन व्यवस्था

निम्न प्रकार के व्यक्ति सदस्यता के लिये ग्रयोग्य होंगे:--

- (१) जो कोई लाभ का पद धारण किये हुए हो ।
- (२) जो विकृतचित्त हो।
- (३) जो अनुनमुक्त दिवालिया हो।
- (४) जो भारत का नागरिक न हो
- (१) ज़ो संसद की किसी विधि द्वारा अनह कर दिया गया हो।

जो अनर्ह होते हुए सदन में बैठे या मत दे वह प्रत्येक दिन के लिये ४०० रुपये के दंड का भागी होगा।

विधान-मंडलों के सदस्यों की शक्तियां, विशेषाधिकार श्रौर उन्मुक्तियां ! ायः वैसी ही हैं जैसी कि संसद के सदस्यों के विषय में लिखी गई हैं।

राज्य के विधान-मंडल का कोई सदन श्रपनी प्रक्रिया के तथा श्रपने कार्य-संचालन के विनियमन के लिये नियम बना सकेगा।

भाषाः राज्य के विधान-मंडल में कार्य राज्य की राजभाषा या हिन्दी या अंग्रेजी में किया जायेगा। किन्तु पंद्रह वर्ष बाद अंग्रेजी में कार्य न होगा, जब तक कि विधान-मंडल अन्यथा उपबन्ध न करे।

न्यायाधीशों की आलोचनाः—उच्चतम न्यायालय या किसी उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश के अपने कर्तव्य गालन में किये गये आचरण के विषय में विधान-मंडल में कोई चर्चा न होगी।

१०. विधान-मंडल और कार्यपालिका

सदनों के सत्र बुलाने का कार्य, सत्रावसान तथा विघटन का कार्य राज्यपाल (या राजप्रमुख) करेगा। वह सदनों को सम्बोधित भी कर सकेगा तथा उन्हें संदेश भेज सकेगा। सत्र के आरम्भ में वह सदनों को सम्बोधित करके आह्वान का कारण बतायेगा।

भारत नये संविधान तक

विधान--मंडल को प्रतिवर्ष कम से कम दो बार अधिवेशन के लिये आहूत किया जायेगा तथा दो बैठकों के बीच छै मास का अन्तर न होगा (अनु० १७४, १७४ तथा १७६)।

११. विधान-मंडल के फ्दाधिकारी

विधान-सभा में एक अध्यक्त नथा एक उपाध्यक्त होंगे जिन्हें वह सभा निर्वाचित तथा पदः श्रुत कर सकेगी। इसी प्रकार विधान-परिषद में सभापित तथा उपसभापित होंगे। प्रत्येक सदन का पृथक साचिवक कर्मचारी-वृन्द भी होगा, जिस पर उस सदन का नियंत्रण होगा।

१२. विधान-मंडल में कार्यप्रणाली

बहुमत से निश्चयः सदन की बैठकों में सब प्रश्नों का निर्धारण मत देने वाले उपस्थित सदस्यों के बहुमत से होगा।

विधान प्रिकृयाः धन-विधेयक केवल विधान-सभा में ही आरम्भ होंगे, किन्तु अन्य विधेयक विधान-परिषद में भी, जहां वह हो, आरंभ हो सकते हैं। विधान-परिषद बाले राज्य में विधान-सभा से पारित होने के बाद, धन-विधेयक विधान-परिषद को उसकी सिपारिशों के लिये भेजा जायेगा, तथा विधान-परिषद उसे चौदह दिन के भीतर अपनी सिपारिशों सहित विधान-सभा को लौटा देगी, और विधान-सभा उन सिपारिशों को स्वीकार सा अस्वीकार कर सकेगी।

श्रन्थ विधेयक, विधान-सभा में पारित होने के परचात, यदि विधान-परिषद में श्रस्वोकार कर दिये जायें, या तीन मास तक पारित न हों या ऐसे संशोधनों सहित पारित हों जो सभा को स्वीकार्थ न हों, तो सभा उन्हें दोबारा पारित करके परिषद में भेजेगी श्रीर एक मास तक वे परिषद में पारित न हों तो भी पारित समभे जायेंगे।

त्र्यशंत् राज्यों में विधान-परिषद् को किसी विधेयक के विषये से स्रन्तिम निर्णय करने का अधिकार नहीं है।

१३. राज्यपाल या राजप्रमुख की अनुमति

विधान-सभा द्वारा (या जहां दो सदन हों वहा दोनों के द्वारा) पारित होने के पश्चात प्रत्येक विवेयक राज्यपाल (या राजप्रमुख) के समच उपस्थित

राज्यों की शासन व्यवस्था

किया जायेगा तथा वह उस पर या तो अनुमित दे देगा, या उसे, यदि वह धन-विवेयक नहीं हो तो, सदन या सदनों को अपने संदेश के साथ पुनर्विचार के लिये लौटा सकेगा। परन्तु यदि वह विवेयक सदन या सदनों द्वारा संशोधन सहित या रहित पुनः पारित हो जाये तो वह उस पर अपनी अनुमित न रोकेगा।

इसके अतिरिक्त यदि किसी विधेयक द्वारा उच्चन्यायालय की शक्तियों का अल्पोकरण होता हो तो राज्यपाल (या राज्यप्रमुख) उसे राष्ट्रपति के विचारार्थ रिचत भी रख सकेगा, तथा ऐसे विधेयक पर राष्ट्रपति या तो अपनी सम्प्रति दे देगा या अपने संदेश के साथ, राज्यपाल के द्वारा, सदन या सदनों को वापस भेज देगा। यदि वह विधेयक सदन या सदनों द्वारा संशोधन सहित या रहित पुनः पारित हो जाये तो वह राष्ट्रपति के समज्ञ उसके विचार के लिये पुनः उपस्थित किया जायेगा।

१४. राज्यों का आय-व्ययक

प्रत्येक वित्तीय वर्ष के बारे में राज्य के विधान-मंडल के सदन या सदनों के समत्त राज्यपाल या राजप्रमुख उस वर्ष के लिये प्राक्कित प्राप्तियों भ्रौर व्ययों का विवरण (बजट) रखव येगा । उसमें उस राज्य की 'संचित निधि' पर भारित व्यय तथा अन्य व्ययों की राशियां पृथक पृथक दिखाई जायेंगी। राज्यपाल की उपलब्धियां, सदनों के सभापति, उपसभापति, श्रध्यच, उपाध्यच के वेतनादि, ऋण, निचेप-निधि-भार, मोचन भार, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन, श्रादि न्यय राज्य की संचित निधि पर भारित व्यय होंगे। भारित व्यय पर विधान-सभा में मतदान नहीं होगा, किन्तु चर्चा हो सकती है। अन्य व्यय की प्राक्कलमें अनुदानों के रूप में रखी जायेंगी, तथा विधान-सभा किसी मांग को स्वीकार, अस्वीकार श्रथवा कम कर सकती है। राज्यपाल (या राजप्रमुख) की सिपारिश के बिना किसी भी अनुदान की मांग न की जायेगी। इस प्रकार स्वीकृत धन के श्रितिरिक्त कोई धन राज्य की संचित निधि में से नहीं निकाला जायेगा। वर्ष के मध्य में अनुपूरक, अपर या अतिरिक्त अनुदानों की भी मांग विधान-सभा में पेश की जा सकती है। कोई धन-विधेयक राज्यपाल की सिपारिश के बिना प्रस्तावित न किया जायेगा।

चतुर्थं ऋध्याय

संघ और राज्यों के संबंध

१. विषय-वितरण

क्योंकि भारत एक संघ है श्रतः राज्यों तथा केन्द्र में शक्ति विभाजन संविधान द्वारा किया गया है। १९३४ के श्रिधिनयम के श्रनुसार ही इस संविधान में भी तीन स्चियां हैं संघ-स्ची, राज्य-स्ची तथा समवर्ती स्ची जो पुस्तक के पिरिशिष्ट के रूप में दी गई हैं। संसद को संघ-स्ची तथा समवर्ती स्ची के विषयों पर समस्त राज्यक्तेत्र के लिये विधि बनाने का श्रिधिकार है, तथा राज्य-स्ची के विषयों पर उन क्त्रों के विषय में विधि बनाने की शक्ति है जो केन्द्र द्वारा शासित हैं यथा दिल्जी, श्रजनेर, भोपाल, हिमाचल प्रदेश, कच्छ, श्रन्दमान श्रादि । जो विषय किसी स्ची में नहीं हैं उनके बारे में भी संसद को विधि बनाने की श्रनन्य शक्ति है, तथा ऐसे कर लगाने को भी शक्ति है जो किसी स्ची में वर्णित नहीं हों (श्रन्० २४६, २४७)।

यदि राज्य-परिषद दो तिहाई बहुमत द्वारा घोषित कर दे कि राष्ट्रीय हित में यह त्रावश्यक या इष्टकर है कि संसद राज्य-जूची के किसी विषय

संघ और राज्यों के सम्बन्ध

विशेष पर विधि बनाये तो संसद को ऐसा करने की चमता होगी। किन्तु यह नियम एक वर्ष तक ही प्रवृत रहेगा। राष्ट्रपति द्वारा आपात की उद्घोषणा कर देने पर भी संसद को राज्य-सूची के विपयों पर विधि बनाने की शक्ति मिल जायेगी। इन उपबन्धों की कोई बात राज्यों के विधान-मंडलों की विधा-यिनी शक्ति को निर्विन्धत न करेगी, किन्तु विधान-मंडलों की विधियां उसी मात्रा तक प्रभावी होंगी जहां तक कि वे संसद की विधि के विरुद्ध न हो (अनु० २४६, २४०)

संसद किसी अन्य देश के साथ की हुई संधि, करार या अभिसमय अथवा किसी अन्तर्राष्ट्रीय संस्था के विनिश्चय के पालनार्थ समस्त भारत के लिये विधि बना सकती है।

यदि समवर्ती सूची के विषय पर संसद तथा राज्यों के विधान मंडल दोनों विधियां बना दें, तो राज्यों की विधियां विरोध की मात्रा तक शून्य होंगी चाहे संसद की विधि पहले पारित हुई हो या पीछे (अनु० २४१)।

२. प्रशासन-सम्बन्ध

संविधान में यद्यपि संघ की कार्यपालिका को राज्य की कार्यपालिका से भिन्न माना गया है तथापि वास्तव में संघ के सारे कार्यों के लिये प्रत्येक राज्य में उनके अधिकारियों का रहना आवश्यक नहीं है। अर्थात केन्द्र की विधियों को लागू करने के लिये केन्द्र की पुलिस या काराग्रह आदि होना अपेन्तित नहीं है। इस कारण राज्यों की कार्यपालिकाओं को अनुच्छेद २४६ हारा यह आदेश दिया गया है कि वे अपनी शक्तियों का प्रयोग इस प्रकार करें जिससे की संसद की विधियों का पालन सुनिश्चित रहे, तथा इस विषय में संघ राज्यों को निदेश दे सकता है, राज्य संघ की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में अड्झन या प्रतिकृत प्रभाव न डालेंगे, तथा संघ अपने किसी विषय सम्बन्धी क्ररू थ, राज्य की सरकार की सम्मित से, उस सरकार को या उसके पदाधिकारियों को सौंप सकेगा (अनु०२४६,२४७,२४०)।

इस उपबन्धों का श्राशय यह है कि राज्य संघ-सूची के विषय में संघ के श्रभिकर्ता के समान होंगे, किन्तु उन्हें इसके लिये संघ सरकार से श्रात-रिक्त खर्च वसूल करने का श्रधिकार है।

भारत-नये संविधान तक

राज्यों के बीच विवादों की जांच करने, उन पर मंत्रणा देने तथा सिपारिशों करने लिये अष्ट्रपति एक अन्तर्राज्य-परिषद् की भी स्थापना कर सकेगा। अन्तर्राज्यक नदी या नदी-दूनों के या जलों के प्रयोग, वितरण आदि के बारे में विवाद या फरियाद के न्याय-निर्णयन के लिये भी संसद उपबन्ध कर सकेगी

किन्तु याद रहे, साधारणतः राज्यों के बीच के विवाद तथा संघ श्रौर राज्यों के बीच के विवाद उच्चतम न्यायालय में ही जायेंगे।

३. आपात उपबन्ध

जैसा कि हम पहले लिख चुके हैं, भारत का संविधान मूलतः संघीय है किन्तु युद्ध त्रादि त्रापात के समय वह एकात्मक भी हो सकता हैं।

जब राष्ट्रपित का समाधान हो जाये कि गम्भीर श्रापात विद्यमान है जिससे कि युद्ध या वाह्य श्राक्रमण या श्रान्तरिक श्रशांति से या उसके सिनिकट होने से भारत की या उसके किसी भाग की सुरचा संकट में है तो वह श्रापात की उद्घोषणा कर सकता है, जो संसद के प्रत्येक सदन के समच रखी जायेगी, तथा दोनों सदन उसका श्रमुमोदन न कर दें तो वह उद्घोषणा दो मास के परचात प्रवर्तन में न रहेगी।

जब ऐसी उद्घोषणा हो जाये तो संसद को श्रधिकार होगा कि वह राज्य-सूची के विषयों पर विधि बना सके तथा राज्यों को उनकी कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग के विषय में निदेश दे सके (श्रनुच्छेद ३४२-३)।

1

वाह्य त्राक्रमण त्रौर त्रांतरिक त्रशांति से प्रत्येक राज्य का संरचण करमा संघ का कर्तव्य होगा। संघ यह भी सुनिश्चित करेगा कि राज्यों की सरकारें इस संविधान के उपबन्धों के त्रानुसार चलाई जायें (त्रृतु० ३४४)।

४. राज्यों में साविधानिक विफलता

यदि किसी राज्य के राज्यपाल या राजप्रमुख से प्रतिवेदन (रिपोर्ट) मिस्ते पर या श्रन्थथा राष्ट्रपति का समाधान हो जाये कि ऐसी स्थिति

संघ श्रीर राज्यों के सम्बन्ध

पैदा हो गई है जिसमें कि उस राज्य का शासन इस संविधान के उपबन्धों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता, तो राष्ट्रपति उद्घोषणा द्वारा वहां की सरकार के कृष्य राज्यपाल या राज्यमुख को दे सकेगा, विधान-मंडल की शिक्तवयां संसद को दे सकेगा, अन्य किसी प्राधिकारी की शिक्तवयां स्वयं ले सकेगा, तथा संविधान के किसी उपबन्ध को निलम्बित कर सकेगा, किन्तु वह उच्च न्यायालय की शिक्तवयों को कम न कर सकेगा (अनु० ३४६)।

यह उद्घोषणा संसद के दोनों सदनों के समच रखी जायेगी तथा संसद द्वारा अनुमोदित न हो तो दो मास पश्चात समाप्त हो जायेगी।



पांचवां ऋध्याय

न्यायपालिका

१ सामान्य

जैसा कि पहले बताया जा चुका है समस्त भारत की एक ही न्याय-पालिका होगी। उसका निर्माण इस प्रकार होगा:—

> उच्चतम न्यायालय | उच्च न्यायालय | जिला न्यायालय | अन्य छोटे न्यायालय

श्रपीलें श्रादि नीचे से उच्चतम न्यायालय तक विधि श्रनुसार जा सकेंगी। संघ तथा राज्यों के कान्नों के लिये भिन्न भिन्न न्यायालय नहीं होंगे। प्रत्येक न्यायालय का कर्तच्य होगा कि वह विधि श्रनुसार निर्णय करे, चाहे वह विधि राज्य के विधान-मंडल की हो चाहे संसद की।

=यायपालिका

२. संघ की न्यायपालिका

भारत का एक उच्चतम न्यायालय होगा, जिसमें भारत का एक मुख्य न्यायाधिपति तथा अन्य सात से अनिधिक न्यायाधीश होंगे, जिन्हें राष्ट्रपति नियुक्त करेगा। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में वही ज्यक्ति नियुक्त किया जायेगा जो भारत का नागरिक हो, तथा कम से कम लगातार १ वर्ष तक किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रह चुका हो अथवा कम से कम दस वर्ष तक किसी उच्च न्यायालय का अधिवक्ता रह चुका हो अथवा राष्ट्र-पति की राय में पारंगत विधिवेता हो।

उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश पेंसठ वर्ष की आयु तक पद धारण करेगा, तथा अपने पद से तब तक न हटाया जा सकेगा, जब तक कि सिद्ध कदाचार अथवा असमर्थता के कारण संसद का प्रत्येक सदन समस्त सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा, तथा उपस्थित और मतदान करने वाले समस्यों में से दो तिहाई बहुमत द्वारा उसे हटाने का प्रस्ताव पारित न हो जाये। उस अवस्था में उसे राष्ट्रपति पदच्युत करेगा (अनु० १२४)।

जो न्यक्ति एक बार उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश रह चुका हो वह भारत में वकालत नहीं कर सकता।

उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति को वेतन पांच हजार रुपये प्रतिमास तथा अन्य न्यायाधीशों का वेतन ४०००) रुपये प्रतिमास होगा। उन्हें भत्ते आदि तथा सरकारी पदावास भी मिलेगा। उनकी स्वतंत्रता को बनाये रखने के लिये ही उनके वेतनादि संविधान में उल्लिखित हैं और संसद को उन्हें कम करने का अधिकार नहीं है।

उच्च न्यायालय के तीन कार्य होंगे : प्रारंभिक चेत्राधिकार, त्रपीलीय चेत्राधिकार, तथा राष्ट्रपति को परामर्श देने का कार्य।

र. प्रारंभिक च्रेत्राधिकार—उच्चतम न्यायालय का प्रारंभिक च्रेत्रा-धिकार उन विवादों के विषय में होगा जो दो या अधिक राज्यों के बीच या भारत सरकार तथा एक या अनेक राज्यों के बीच हो तथा उसमें कोई ऐसा प्रश्न अन्त्रीयस्त हो जिसपर किसी वैध अधिकार का अस्तित्व या विस्तार निर्भर हो। ऐसे विवाद किसी अन्य न्यायालय में नहीं जा सकेंगे (अनु० १३१)।

भारत-नये संविवान तक

२. अपीलीय त्रेत्राधिकार-किसी उच्च न्यायालय में दिये गये निर्णय, आज्ञापित या अन्तिम आदेश की अपील उच्चतम न्यायालय में हो सकेगी:

संविधात-विषयक—(१) यदि वह उच्च न्यायालय प्रमाणित करदे कि उस मामले में संविधान के निर्वचन का कोई सारवान विधि-प्रश्न ग्रम्त्यमन्त है;

(२) यदि उच्चतम न्यायालय का समाधान हो जाये कि उस मामले में ऐसा विधि-प्रश्न ग्रंत्य्रस्त है;

व्यवहार-विषयक (३) यदि व्यवहार विषयक विवाद में उच्च न्यायालय प्रमाणित करदे कि विवाद-विषय कि राशि या मूल्य बीस हजार रुयये से अधिक है;

(४) यदि उच्च न्यायालय यह प्रमाणित करदे कि अपील में कोई सारवान विधि प्रश्न अंत्रेम्हत हैं;

दं छ-विषयक (१) यदि उच्च न्यायालय ने अपील में किसी श्रिभि-युक्त च्यक्ति की विसुक्ति के श्रादेश को उलट कर उसे मृत्युदं डिया हो;

(६) यदि उच्च न्यायालय ने किसी मामले को परीचण के हेतु भ्रपने पास मंगा कर मृत्यु दंडादेश दिया हो;

व्यापक (७) यदि उच्च न्यायालय प्रमाणित करदे कि मामला उच्चतम न्यायालय में अपील के लायक है (अनु० १३२-१३४)।

इसके अतिरिक्त उच्चतम न्यायालय फेडरल न्यायालय के सारे चेत्राधिकारों का प्रयोग करेगा तथा संसद उसे और चेत्राधिकार तथा शक्तियां भी दे सकती है (अनु० १३४)।

उच्चतम न्यायालय को एक सर्वोपिर श्रधिकार भी दिया गया है कि वह भारत चेत्र में के किसी न्यायालय या न्यायाधिकरण के किसी निर्णय, श्राज्ञाप्ति या दंडादेश की श्रपील के लिये विशेष इजाजत दें सकेगा (श्रजु० १३६)।

न्यायपालिका

३. परामर्श-संबन्धी कार्यः —यदि राष्ट्रपति को प्रतीत हो कि विधि या तथ्य संबंधी कोई प्रश्न ऐसे सार्वजनिक महत्व का है कि उस पर उच्चतम न्यायालय की राय लेना इष्टकर है तो वह उसकी राय ले सकेगा (अनु० १४३)।

संसद किसी प्रयोजन के लिये निदेश, ब्रादेश, बन्दीप्रत्यचीकरण लेख, परमादेश लेख, प्रतिवेध लेख, ब्रधिकार पृच्छा लेख और उत्प्रेषण हे.ख तथा अन्य लेखों के निकालने की शक्ति भी उच्चतम न्यायालय को दे सकेगी (अनु० १२८)।

उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि भारत राज्य-चेत्र के भीतर सब न्यायालयों को मान्य होगी तथा भारत राज्यचेत्र के सभी असैनिक और न्यायिक अधिकारी उच्चतम न्यायालय की सहायता करेंगे (ग्रनु० १४०)।

उच्चतम न्यायालय को किसी व्यक्ति को हाजिर कराने या किसी दुरतावेजों को प्रकट या पेश कराने के लिये ब्रादेश देने की समस्त शक्ति होगी (ब्रजु० १४२)।

३. राज्यों के उच्च न्यायालय

प्रत्येक राज्य के लिये एक उच्च न्यायालय होगा। प्रत्येक उच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा तथा उसे अपने अवमान के लिये दंड देने की शक्ति होगी। उसमें एक मुख्य न्यायाधिपति तथा अन्य न्यायाधीश होंगे जिनकी संख्या राष्ट्रपति नियत करेंगे। मुख्य न्यायाधिपति की नियुक्ति राष्ट्रपति उस राज्य के राज्यपाल या राजप्रमुख से परामर्श करके करेगा। अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करेगा तथा मुख्य न्यायाधिपति से उस विषय में प्रामर्श लेगा। प्रत्येक न्यायाधीश साधारणतः ६० वर्ष की आयु तक पद धारण करेगा और संसद के समावेदन पर राष्ट्रपति द्वारा उसी प्रकार हिराया जा सकेगा और संसद के समावेदन पर राष्ट्रपति द्वारा उसी प्रकार हिराया जा सकेगा जैसे कि उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश हटाया जाता है। न्यायाधीश को एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरित किया जा सकता है तथा उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश भी नियुक्त किया जा सकता है। केवल वही व्यक्ति उच्च न्यायाक्ष्य का न्यायाधीश नियुक्त किया जा सकता है। केवल वही व्यक्ति उच्च न्यायाक्ष्य का न्यायाधीश नियुक्त किया जा सकता है। केवल वही व्यक्ति उच्च न्यायाक्षय का न्यायाधीश नियुक्त किया जा सकता है। केवल वही व्यक्ति उच्च न्यायाक्षय का न्यायाधीश नियुक्त किया जा सकता है। केवल वही व्यक्ति उच्च न्यायाक्षय का न्यायाधीश नियुक्त किया जा सकता है। केवल वही व्यक्ति उच्च न्यायाक्षय का न्यायाधीश नियुक्त किया जा सकता है। केवल वही व्यक्ति उच्च न्यायाक्षय का न्यायाधीश नियुक्त किया जा सकता है। केवल वही व्यक्ति उच्च न्यायाक्षय का न्यायाक्षय का न्यायाधीश नियुक्त किया जा सकता है। केवल वही व्यक्ति उच्च न्यायाक्षय का न्यायाक्षय का न्यायाधीश नियुक्त किया जा सकता है। केवल वही व्यक्ति उच्च न्यायाक्षय का न्यायाक्षय का न्यायाधीश नियुक्त किया जा सकता है। केवल वही व्यक्ति उच्च न्यायाक्षय का न्यायाक्षय नियुक्त किया जा सकता है। केवल वही व्यक्ति उच्च न्यायाक्षय का न्यायाक्यय का न्यायाक्षय का न्यायाक्षय

भारत-नये संविधान तक

कम दस वर्ष तक कोई न्यायिक पद धारण कर चुका हो अथवा किसी उच्च न्यायालय का दस वर्ष तक अधिवक्ता रह चुका हो।

उच्च न्यायालय का न्यायाधीश भारत के किसी न्यायालय में श्रथवा हित्री प्राधिकारी के समज्ञ वकालत या कार्य न करेगा।

प्रत्येक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को साढ़े तीन हजार रुपये प्रतिमास तथा मुख्य न्यायाधिपति को चार हजार रुपये प्रतिमास वेतन मिलेगा, तथा भत्ते, पदावास आदि भी मिलेगो, जो उनके सेवाकाल में घटाये न जायेंगे। किन्तु राजप्रमुखों के राज्यों में इतने वेतनादि नहीं मिलेगे। वहां वेतन-भत्ते आदि राजप्रमुख से परामर्श करके राष्ट्रपति निर्धारित करेगा किन्तु वे वेतनादि भी नियुक्ति के पश्चात कम नहीं किये जायेंगे।

उच्च न्यायालयों की शक्तियां:—उच्च न्यायालय को मूलाधिकारों के अंबंध में या अन्यथा ऐसे निदेश या आदेश या लेख निकालने को शक्ति है, जिनमें बन्दी प्रत्यचीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार-पृच्छा और उत्त्रेषण के लेख भी सम्मिलित हैं। इससे उच्चतम न्यायालय को मूलाधिकारों के विषय में दी गई शक्ति का अल्पीकरण न होगा।

प्रत्येक उच्च न्यायालय अपने त्रेत्राधिकार में सब न्यायालयों और न्यायाधिकरण का अधीत्तण करेगा, उनसे विवरणी मंगा सकेगा, तथा उनके विषय में नियम बना सकेगा।

यदि उसके अधीन न्यायालय में कोई ऐसा मामला लिम्बत है जिसमें, संविधान सम्बन्धी कोई सारवान विधि-प्रश्न निहित है तो उच्च न्यायालय उस मामले को अपने पास मंगा सकता है।

मुख्य न्थायाधिपति उच्च न्यायालय के पदाधिकारियों, सेवकों श्रादि के विषय में नियमानियम बना सकता है।

संसद किसी उच्च न्यायालय के चेत्राधिकार का विस्तार या अपवर्जन कर सकेगी।

न्यायपालिका

४. अधीन न्यायालय

प्रत्येक राज्य में उच्च न्यायालय के अधीन जिला-न्यायालय भी होंगे, जिनमें जिला-न्यायाधीश की नियुक्ति उच्च न्यायालय से परामर्श करके राज्य-गाल करेगा। जिला-न्यायाधीश वही व्यक्ति बन सकेगा जो कम से कम ७ वर्षों तक अधिवक्ता या वकील रह जुका हो। जिला-न्यायालय के अतिरिक्त अन्य न्यायालयों तथा न्यायाधीशों पर भी उच्च न्यायालय का नियंत्रण होगा, तथा वह उनके सम्बन्ध में नियामादि बना सकेगा।



ञ्चठा ऋध्याय विशेष प्राधिकारी

१. सामान्य

भारत दें पत्तपात, श्रष्टाचार श्रादि पर रोक लगाने के लिये सर्वोच्च श्रधिकरण तो न्यायपालिका है ही, जिसके न्यायाधीशों हेको कार्यपालिका के दबाव से मुक्ति दिलाने के लिये यह उपबन्ध किया गया है कि उन्हें एक विशेष रीति से ही पदच्युत किया जा सकेगा। इस प्रकार कुछ श्रन्य स्वतन्त्र श्रधिकारियों की भी संविधान में व्यवस्था की गई है, यथा:

- १. महालेखापरी ज्ञक-जो भारत सरकार तथा राज्यों की सरकारों के लेखाओं की परीचा करेगा।
 - २. निर्वाचन आयोग-जो निर्वाचनों की देखभाल करेगा।
- तोक सेवा आयोग—जो लोक सेवाओं में नियुक्तियों के लिये
 परीचाओं का संचालन करेगा ।

विशेष प्राधिकारी

२. भारत का नियंत्रक-महालेखापरीचक

उच्चतम न्यायालय के समान नियंत्रक महालेखारी चक भी एक स्वतन्त्र प्रभुता सम्पन्न अधिकारी होगा। वह राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जायेगा तथा उसी रीति और उन्हीं कारणों से हटाया जायेगा, जिस रीति और जिन कारणों से उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश हटाया जाता है। न्यायाधीश के समान ही उसके वेतनादि में नियुक्ति के पश्चात कोई खलाभ-कारी परिवर्तन नहीं किया जायेगा। अपने पद पर रह जाने के पश्चात वह किसी पद का पात्र न होगा।

नियंत्रक महालेखा-परीचक भारत सरकारके तथा राज्यों के सब लेखाओं पर नियंत्रण रखेगा तथा लेखाओं को रखने की प्रणाली निरिचत करेगा और संघ लेखा सम्बन्धी अपने प्रतिवेदन राष्ट्र पति के समच उपस्थित करेगा। राष्ट्रपति उन्हें संसद के समच रखवायेगा।

उसी प्रकार राज्य के लेखा सम्बन्धी प्रतिवेदनों को राज्यपाल या राज्यप्रमुख के समन्न उपस्थित किया जायेगा जो उनको राज्य के विधान मंडल के समन्न रखवायेगा।

३ निर्वाचन आयोग

निर्वाचनों में निष्पच्चता एवं न्याय हो इस उद्देश्य से संविधान में उप-बन्धित किया गया है कि निर्वाचनों के लिये नामाविल तैयार कराने तथा समस्त निर्वाचनों के संचालन, अधीचण, निदेशन और नियंत्रण, तथा निर्वाचनों से उद्भूत विवादों के निर्णय की व्यवस्था करने का काम एक 'निर्वाचन आयोग' में निहित होगा। आयोग में एक मुख्य निर्वाचन-आयुक्त तथा अन्य निर्वाचन-आयुक्त होंगे जिन्हें राष्ट्रपति नियुक्त करेगा। इसके अतिरिक्त प्रादेशिक आयुक्त भी आयोभै से परामर्श करके नियुक्य किये जायेंगे।

मुख्य निर्वाचन आयुक्त की स्वतन्त्रता बनाये रखने के लिये यह उपवन्ध बनाया गया है कि उसे वेवल उसी रीति से तथा उन्हीं कारणों से पदच्युत किया जा सकेगा, जिससे कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जा सकता है। अन्य किसी निर्वाचन आयुक्त को मुख्य निर्वाचन-आयुक्त की सिपारिश के बिना हटाया न जायेगा।

भारत - नये संविधान तक

४. लोक-सेवा-आयोग

संघ की लोक सेवाओं में नियुक्तयों के लिये परीक्षाओं का संचालन करने के लिये एक संघ लोक सेवा आयोग होगा तथा इसी प्रकार प्रत्येक राज्य के लिये एक लोक सेवा आयोग होगा।

संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्त तथा अन्य सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और राज्य के लोक सेवा आयोग के अध्यक्त तथा सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल या राजप्रमुख करेगा।

संघ-लोकसेवा-ग्रायोग का सदस्य ६ वर्ष की श्रिधिक तक ग्रथवा ६४ वर्ष की ग्रायु तक, जो भी इनमें से पहले हो, पद धारण करेगा । राज्य लोक सेवा ग्रायोग का सदस्य ६ वर्ष की ग्रविध तक या ६० वर्ष की ग्रायु तक, जो भी पहले हो, पद धारण करेगा। कोई सदस्य ग्रपनी पदाविध की समाप्ति पर उस पद पर पुनिनियुक्ति के लिये ग्रपान्न होगा।

लोक-सेवा-ग्रयोग का सदस्य केवल कदाचार के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा पदच्युत किया जा सकता है। राष्ट्रपति उसे हटाने का ग्रादेश देने से पहिले उच्चतम न्यायालय द्वारा जांच करवायेगा। किन्तु सदस्य को उसके पद से राष्ट्रपति उस ग्रवस्था में हटा सकता है जब कि वह दिवालिया हो जाये, या कोई ग्रन्थ वैतनिक नौकरी करले या मानसिक ग्रथवा शारीरिक दौर्बल्य के कारण ग्रयोग्य हो जाये।

लोक सेवा त्रायोग परीक्षात्रों के संचालन के ग्रांतिरिक्त भर्ती की रीतियों, पदोन्नति, बदली, श्रानुशासन ग्रादि विषयों पर सरकार को परामर्श देगा । किन्तु सैनिक सेवाग्रों के विषय में उसका चेत्राधिकार नहीं होगा।

लोक सेवा-श्रायोगों तथा उनके कर्मचारी वृन्द का व्यृत्य श्रादि भारत की या राज्य की संचित निधि पर भारित व्यय होगा।

संघ लोकसेवा आयोग अपने काम के बारे में राष्ट्रपति को, तथा राज्यों के आयोग राज्यपाल या राजश्रमुख को, प्रतिवर्ष प्रतिवेदन देंगे तथा आयोगों का परामर्श स्वीकार न किया जायेगा तो उनके कारण संसद या राज्यों में विधान-मंडलों को बताये जायेंगे।

सातवां ऋध्याय

विशेष चेत्र तथा जातियां

१. ऋंदमान द्वीप समूह

श्रव तक हम भारत के २७ राज्यों का वर्णन कर चुके हैं। किन्तु राज्यों के श्रतिरिक कुछ श्रन्य भूमिभाग भी भारत के राज्यचेत्र में सम्मिलित हैं, यथा श्रंदमान तथा निकोबार। ऐसे राज्यचेत्रों का प्रशासन राष्ट्रपति करेगा, तथा वहां मुख्य श्रायुक्त या श्रन्य प्राधिकारी भी नियुक्त करेगा। राष्ट्रपति वहां शान्ति श्रौर सुशासन के लिये विनियम बना सकेगा तथा संसदीय विधि में भी वहां के लिये संशोधन कर सकेगा (श्रनुच्छेद २४३)। इसी प्रकार श्रजित किये गये राज्य-चेत्रों का प्रशासन भी राष्ट्रपति करेगा।

रे. अनुसचित और आदिम जाति चेत्र

श्रासाम में विशेषता तथा श्रन्य राज्यों में भी कई ऐसे प्रदेश हैं जहाँ श्रादिम जातियाँ निवास करती हैं। वे जातियाँ बहुत पिछुड़ी हुई होने के कारण उन पर सभ्य लोगों के कान्न लागू नहीं किये जा सकते। उनके निवासियों को श्रन्य लोगों के शोषण से भी बचाने की श्रत्यन्त श्रावश्यकता

भारत - नये संविधान तक

है। अतः उनके विषय में संविधान में विशेष उपबंध रखे गये हैं जो पंचम तथा षष्ठ अनुसूची में उल्जिखित हैं।

त्र्यासाम में ६ स्वायत्त शासी जिले होंने जिनमें से प्रत्येक जिले में २४ से अनिधिक सदस्यों की एक जिला-परिषद होगी।

एक जिले में कई प्रादेशिक परिपर्दे भी हो सकती हैं यदि वहाँ भिनन भिनन प्रकार की श्रादिम जातियां हों।

इन जिला परिषद तथा प्रादेशिक परिषदों में प्रशासन के श्रिधकार निहित होंगे, वे किसी हद तक विधि बना सकेंगी, तथा न्याय-प्रशासन के लिये ग्राम-परिषदें या न्यायालय गठित कर सकेंगी। तथा प्राथमिक विद्यालय स्थापित कर सकेंगी। उन्हें जिला तथा प्रादेशिक निधियों जमा करने की, तथा भूराजस्व निर्धारित करने श्रीर संग्रह करने तथा कर-श्रारोपण की भी शक्ति होगी। वे श्रादिम जातियों के श्रतिरिक्त श्रन्य लोगों की साहूकारी श्रीर व्यापार पर भी नियंत्रण रख सकेगी। स्वायत्त शासी जिलों के प्रशासन की जाँच करने के लिये राज्ययाल एक श्रायोग भी नियुक्त कर सकेगा।

राज्यपाल इन सब परिषदों पर अपना नियंत्रण रखेगा।

श्रासाम के श्रतिरिक्त श्रन्य राज्यों में भी राष्ट्रपति श्रनुस्चित चेत्रों की घोषणा कर सकता है। ऐसे चेत्रों में राज्यपाल या राजप्रमुख यह निदेश दे सकेगा कि वहाँ संसद या विधान मंडल का कोई विशेष श्रधिनियम लागू न हो, तथा वहां की शांति श्रोर सुशासन के लिये नियम बना सकेगा। वह वहां श्रादिमवासियों द्वारा भूमि के हस्तांतरण को रोकने के लिये, भूमि के बटवारे के लिये, तथा साहूकारी के व्यापार के लिये नियम बना सकेगा, किन्तु इसके लिये राष्ट्रपति की श्रनुमित श्रावश्यक होगी।

इसके अतिरिक्त प्रत्येक राज्य में जहां अनुसूचित जातियाँ यत्र तत्र बिखरी पड़ी हैं, एक आदिम जाति-मंत्रणा-परिषद स्थापित की जायेगी जिसके बीस से अधिक सदस्य न होंगे, जिनमें कि तीन चौथाई उस राज्य की विधान सभा में आदिमजातियों के प्रतिनिधि होंगे। वह परिषद उस राज्य की आदिम-

विशेष चेत्र तथा जातियां

जातियों के कल्याण और उन्नति के संबद्घ विषयों पर राज्यपाल या राजशमुख को मंत्रणा देगी।

३ अल्पसंख्यकों का संरत्त्रण

जैसा पहले बताया जा चुका है भारत में संयुक्त निर्वाचन होंगे। मुस्लिम, ईसाई श्रादि वर्गों के लिये १६३४ के श्रधिनियम के समान स्थानों को रिचत नहीं रखा गया है। किन्तु फिर भी श्रनुसूचित जातियों (हरिजनों तथा सिखों के पिछड़े हुये वर्गों) के लिये तथा श्रादिमजातियों के लिये उनकी जन-संख्या के श्रनुपात से स्थान रिचत रहेंगे। यह स्थान-रचण लोकसभा तथा राज्यों की विधान-सभा में होगा। यदि राष्ट्रपति यह समभे कि श्रांग्ल-भारतीयों को लोकसभा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिला है तो वह सभा में उनके एक या दो प्रतिनिधि नाम-निर्देशित कर सकेगा। इसी प्रकार राज्यपाल या राजप्रमुख उस समुदाय के कुछ सदस्यों को विधान-सभा में नाम-निर्देशित कर सके गा। यह रचण व्यवस्था केवल दस वर्ष तक चलेगी।

सेवाओं में भी प्रशासन कार्यकुशलता को ध्यान में रखते हुये नियुक्तियों के विषय में श्रनुसूचित जातियों तथा श्रादिमजातियों के दावों का ध्यान रखा जायेगा।

रेल, डाकतार म्रादि संबन्धी सेवाम्रों में श्रांग्ट-भारतीयों को जो रच्चण श्रव प्राप्त है वह दस वर्ष तक बना रहेगा किन्तु प्रति दो वर्ष में दस प्रतिशत कम होता जायेगा।

श्रांग्ल-भारतीयों की शिचा पर जो विशेष व्यय होता है वह भी शनैः शनैः ही कम्नू किया जायेगा तथा दस वर्ष में समाप्त होगा।

राष्ट्रपति एक विशेष पदाधिकारी भी नियुक्त करेगा जो अनुस्चित जातियों के विषय में उसे प्रतिवेदन देगा। इसीप्रकार राष्ट्रपति आदिमजातियों के कल्याण के बारे में प्रतिवेदन देने के लिये १० वर्ष के अन्दर ही एक आयोग नियुक्त करेगा। इसी प्रकार अन्य वर्गों के लिये भी जो कि सामाजिक या शिचा की दृष्टि से पिछड़े हुये हैं एक आयोग नियुक्त किया जायेगा जो

भारत-नये संविधान तक

उनकी कठिनाइयों, उपायों त्रादि के विषय में प्रतिवेदन देगा। उपरोक्त सारे प्रतिवेदन संसद के समत्त रखें जायेंगे।

संघ-सरकार श्रादिमजातियों के कल्याणार्थ राज्यों को निदेश भी दे सकेगी।

राष्ट्रपति राज्यपाल या राजशमुख से परामर्श करके उस राज्य की श्रमुसूचित जातियों तथा श्रमुसूचित श्रादिमजातियों की सूची की घोषणा करेगा। एक बार श्रधिसूचना द्वारा यह सूची प्रकाशित होने पर उसमें परिवर्तन करने का श्रधिकार केवल संसद ही को होगा।



श्राठवां श्रध्याय

राजभाषा

१. संघ की राजभाषा

संविधान के अनुच्छेद ३४२ के अनुसार भारत की राजभाषा हिन्दी, तथा लिपि देवनागरी होगी, और अंक अंग्रेजी के होंगे, किन्तु १४ वर्ष तक समस्त राजकाज अंग्रेजी में होगा। १४ वर्ष की कालाविध में राष्ट्रपति किसी राजीकीय प्रयोग के लिये हिन्दी भाषा का तथा देवनागरी अंकों का प्रयोग प्राधिकृत कर सकेगा।

संविधान के आरम्भ से ४ वर्ष ५२वात तथा १० वर्ष ५२वात राष्ट्र-पति एक आयोग गठित करेगा जिसमें भारत की मुख्य भाषाओं के प्रतिनिधि होंगे और की राजकीय प्रयोजनों में हिन्दी भाषा के उत्तरोत्तर अधिक प्रयोग के बारे में सिपारिश करेगा (श्रनुच्छेद ३४४)।

श्रायोग के प्रतिवेदन पर विचार करने के लिये तीस सदस्यों भी एक समिति गठित की जायेगी जिसमें २० लोक-सभा तथा १० राज्य-परिवद के सदस्य होंगे जो कमशः उन सदनों द्वारा चुने जायेंगे।

भारत--नये संविधान तक

भारत की मुख्य भाषाएं (संविधान की अष्टम अनुसूची)

3	हिन्दी	Ę	कन्नड़	33	पंजाबी
२	संस्कृत	(9	कश्मीरो	32	बंगाली
æ	उ द्र [°]	5	गुजराती	१३	मराठी
8	श्रसमिया	8	तामिल	38	मलयालम
y	उडिया	90	तेलुग		



राजभाषा -

२. प्रादेशिक भाषाएं

राज्यों को अधिकार दिया गया है कि वे अपने राज्य की किसी भाषा अथवा हिन्दी को राजभाषा बना सकते हैं किन्तु जब तक ऐसा निर्णय न हो, तब तक अंग्रेजी का ही प्रयोग होता रहेगा (श्रनु० ३४१)।

याद रहे उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, मध्य भारत तथा बिहार इन पांचों हिन्दी-भाषी राज्यों ने हिन्दी को श्रपनी राजभाषा घोषित कर दिया है।

कोई दो या श्रधिक राज्य श्रपने पारस्परिक संचार के लिये. हिन्दी या तत्समय संघ की राजभाषा का प्रयोग कर सकते हैं किन्तु संघ के साथ राज्यों का संचार संघ की राजभाषा में ही होगा (श्रनु० ३४६)।

उच्चतम तथा उच्च न्यायालयों का कार्य श्रंभेजी में ही होगा जब तक कि संसद श्रन्यथा उपबन्ध न करे। किन्तु राज्यपाल या राजप्रमुख राष्ट्रपति की श्रनुमति से उस राज्य के न्यायालय में श्रन्य भाषा के प्रयोग को प्राधिकृत कर सकता है (श्रनु० २४=)।

स्मरण रहे इसके अधीन मध्य भारत तथा राजस्थान के उच्च न्यायालयों में हिन्दी के प्रयोग को प्राधिकृत किया गया है तथा हैदराबाद और प० प्० पं० रा० सं० के उच्च न्यायालयों में उद्दे के प्रयोग की अनुमति दी गई है। किन्तु वे सब उच्च न्यायालय अपने निर्णय, आज्ञप्ति अथवा आदेश अंग्रेजी में ही देंगे।

संसद तथा राज्यों के विधान-मंडलों में सब श्रिधिनियम श्रंग्रेजी में पारित किये जायेंगे तथा अध्यादेश, श्रादेश, नियम श्रादि अंग्रेजी में ही निकाले जायेंगे, किन्तु यदि कोई विधान-मंडल श्रन्य भाषा में कार्य करे तो उस राज्य का राजप्रमुख या राज्यपाल उन श्रिधिनियमों श्रादि का श्रंग्रेजी श्रनुवाद प्रकाशित करायेगा।

भारत-नथे संविधान तक

कोई व्यक्ति व्यथा के निवारण के लिये संघ या राज्य के किसी पदा-धिकारी को त्रपना श्रमिवेदन उस राज्य की किसी भाषा में दे सकता है।

हिन्दी भाषा का विकास

हिन्दी भाषा का विकास तथा प्रसार-वृद्धि करना संघ का कर्तव्य होगा तथा उसकी श्रात्मीयता में हस्तचे प किये बिना श्रन्य भारतीय भाषाश्रों के के रूप, शैली तथा पदाविल को श्रात्मसात करते हुए उसके शब्द-भंडार के लिये मुख्यत: संस्कृत से श्रीर गौखतः श्रन्य भारतीय भाषाश्रों से शब्द श्रह्ण करते हुए हिंदी की समृद्धि सुनिश्चित करना भी संघ का कर्तव्य होगा (श्रमुंश्चेट्द ३५१)।

नौवां ऋध्याय

संविधान का संशोधन

भारत का संविधान लचकदार है। इसका संशोधन एक विधेयक द्वारा हो सकता है जिसे संसद के दोनों सदन अपनी अपनी समस्त सदस्य संख्या के बहुमतों से तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के दो तिहाई से अन्यून बहुमत से स्वीकार करें तथा तत्परचात राष्ट्रपति की स्वीकृति मिल जाये।

किंतु निम्न उपबन्धों में तभी संशोधन हो सकता है जब कि संसद में उक्त प्रकार पारित होने के बाद उस विधेयक का कम से कम आधे राज्यों के विधान-मंडल समर्थन करें:—

- (क) राष्ट्रपति के निर्वाचन सम्बन्धी उपबन्ध (अनु० ४४ और ४४) स घ और राज्यों की कार्यपालिका शक्तियां (अनु० ७३ और १६२)
- (ख) न्यायपालिका सम्बन्धी उपबन्ध (भाग ४ का अध्याय ४ तथा भाग ६ अध्यायर) संघ और राज्यों के सम्बन्ध (भाग ११ अ० १)
- (ग) विषय-वितरण और
- (घ) संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व।

परिशिष्ट

नये संविधान की सप्तम अनुसूची

सूची १--संघ-सूची

(जिन विषयों पर संसद् को विधि बनाने का श्रिधिकार है।)

- १ भारत की तथा उसके प्रत्येक भाग की प्रतिरचा।
- २ नौ, स्थल श्रौर विमान-बल, संघ के श्रन्य सशस्त्र बल ।
- ३ कटक-चेत्र।
- ४ नौ, स्थल श्रौर विमान बल की कर्मशालायें।
- ४ शस्त्रास्त्र, युद्धीपकण, विस्फीटक, श्रम्यस्त्र ।
- ६ अगुशक्ति।
- ७ प्रतिरत्ता संबन्धी उद्योग ।
- म केन्द्रीय गुप्तवार्ता श्रौर श्रनुसंधान विभाग ।
- ह प्रतिरत्ता, विदेशीय कार्य या सुरत्ता सम्बन्धी निवारक निरोध।
- १० विदेशीय कार्य ।
- ११. राजयनिक, वाणिज्य दृतिक स्रोर व्यापारिक प्रतिनिधित्व।
- १२ संयुक्तराष्ट्र-संवटन।
- १३ अतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में भाग लेना तथा उनके विनिः च्यों की पूर्ति।
- १४ विदेशों से संधि श्रीर करार।
- १४ युद्ध श्रीर शांति।
- १६ विदेशीय सेत्राधिकार।
- १७ नागरिकता, देशीयकरण तथा अन्यदेशीय ।
- १८ प्रत्यर्पेण ।

परिशिष्ट :

- १६ भारत में प्रवेश, उससे निर्वासन, पार-पत्र।
- २० भारत के बाहर की तीर्थयात्राएं।
- २१ महासागर या वायु में किये गये अपराध।
- २२ रेल।
- २३ राष्ट्रीय राज-पथ।
- २४ तर्देशीय जल-पथ तथा राष्ट्रीय जल-पथ ।
- २४ समुद्र-नीवहन।
- २६ प्रकाश-स्त∓भ।
- २७ महा-पत्तन ।
- २८ पत्तन-निरोधा।
- २६ वायु-पथ
- ३० रेल-पथ।
- ६१ डाक श्रीर तार; संचार।
- ३२ संघ-संपत्ति।
- ३३ संघ के प्रयोजनों के लिये संपत्ति का ग्रर्जन।
- ३४ देशी राज्यों के शासकों की सम्पत्ति।
- ३४ संघ का लोक-ऋण।
- ३६ चलार्थ, टंकरण श्रीर विधिमान्य, विदेशीय विनिमय।
- ३७ विदेशीय ऋग्।
- ३८ भारत का रचित बैंक।
- ३६ डाकघर बचत बेंक।
- ४० सरकारी लाटरी।
- ४१ दिदेशी व्यापार, शुल्क-सीमान्त ।
- ४२ श्रंतरीज्यिक व्यापार।
- ४३ व्यापारी निगम, सहकारी संस्थान्त्रों को छोड़कर।
- ४४ श्रंतर्राज्यिक निगम, विस्व विद्यालयों को छोड़कर।
- ४४ महाजनी ।

भारत-नये संविधान तक

- ४६ विनिमय-पत्र, चैक, वचन-पत्र।
- ४७ बीमा।
- ४८ श्रेष्ठि-चत्वर, वादा बाजार ।
- ४६ एकस्व, स्राविष्कार, ब्यापार-चिह्न ।
- ४० बाटों श्रीर मापों का मान स्थापन । ः
- १९ निर्यात की वस्तुओं के गुणों का मान-स्थापन।
- ४२ लोक हित के उद्योग।
- ४३ पैट्रोलियम, ज्वालाग्राही द्वय ।
- १४ लोक-हित सम्बन्धी खानें।
- ४४ श्रम का विनियमन, खानों में सुरचितता।
- ४७ मञ्जली पकड़ना श्रोर मीन-चेत्र I
- १८ लवण का निर्माण।
- ५६ श्रफीम।
- ६० चल-चित्र।
- ६९ संघ-सेवकों संबन्धी श्रौद्योगिक विवाद ।
- ६२ राष्ट्रीय महत्व के पुस्तकालय, संप्रहालय श्रादि ।
- ६३ काशी हिन्दू विश्वविधालय, श्रलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय तथा दिल्ली विश्वविद्यालय श्रादि।
- ६४ राष्ट्रीय महत्व की वैज्ञानिक या शिल्पिक संस्थाएं।
- ६१ कुछ ग्रन्य संघ ग्रमिकरण ग्रीर संस्थाएं।
- ६६ उच्चतर शिचा में एक सूत्रता लाना।
- ६७ राष्ट्रीय महत्व के प्राचीन स्मारक, अभिलेख, श्रवशन ।
- ६८ भूपत्तिमाप, भूतत्त्वीय, प्राणकीय परिमाप त्रादि ।
- ६६ जनगणना ।
- ७० श्रखिल भारतीय सेवाएं।
- ७१ संघ-निवृत्ति-वेतन।

परिशिष्ट

- ७२ निर्घाचन (संसद श्रीर विधान-मंडलों के)।
- ७३ संसद् के सदस्यों त्रादि के वेतन।
- ७४ संसद के सदस्यों के विशेषाधिकार ग्रादि।
- ७४ संब के मंत्रियों, राष्ट्रपति, राज्यपाल ग्रादि के वेतन, भन्ते श्रादि।
- ७६ लेखात्रों की परीचा।
- ७७ उच्चतम न्यायालय का गठन, चेत्राधिकार श्रादि ।
- ७८ उच्च न्यायालयों का गठन त्रादि।
- ७६ उच्च न्यायालय का दूसरे राज्य में चेत्राधिकार।
- म० किसी राज्य के आरची दल का अन्य राज्य में चेत्राधिकार ।
- प्रश्निक्षांच्या प्रवास स्थार निरोधा ।
- ≒२ कृषि श्राय को छोड़ कर श्रन्य श्राय पर कर ।
- **८३ सीमा-शुल्क।**
- प्रभ तमाकू, मद्म, श्रफीम, भांग श्रादि के श्रतिरिक्त समस्त वस्तुओं पर उत्पादन-शुल्क ।
- पर **निगम-कर** ।
- पद कृषि भूमि के अतिरिक्त मूल-धन पर कर ।
- ५७ कृषि भूमि को छोड़ कर अन्य सम्पत्ति-शुल्क।
- मन कृषि भूमि को छोड़ कर श्रन्य सम्पत्ति-उत्तराधिकार-शुल्क ।
- महं रेल, समुद्र, वायु द्वारा ले गई वस्तुओं या यात्रियों पर कर ।
- ६० श्रेष्ठि चत्वर श्रीर वादा बाजार के सौदों पर कर।
- ६१ विनिमय-पत्र, चैक आदि पर कर।
- ६२ समाच्चार पत्रों पर कर, विज्ञापनों पर कर।
- ६३ इस सूची से संबंधित विषयों के अपराध।
- ६४ इस सूची से संबंधित विषयों पर जांच ऋादि।
- ६४ क्यायाद्धयों पर इस सूची संबंधी विषयों का चेत्राधिकार।
- ६६ इस सूची के विषयों पर फीसें (न्यायालय फीसों को छोड़ कर)।
- ६७ सूची (२) या (३) में अवर्णित अन्य विषय।

भारत-नये संविधान तक

सूची २-राज्य-सूची

(जिन विषयों पर राज्यों को विधि बनाने का अधिकार है)

- १ सार्वजनिक व्यवस्था
- २ ग्रारची
- ३ न्याय-प्रशासन
- ४ कारागार, सुधारालय श्रादि
- १ स्थानीय शासन
- ६ सार्वजनिक स्वास्थ्य ग्रौर स्वच्छता
- ७ भारत के ग्रन्दर की तीर्थयात्राएें
- मादक पान
- ह अंगहीन तथा नौकरी के अयोग्य व्यक्तियों की सहायता
- १० रमशाने तथा कबरस्थान
- ११ शिज्ञा जिसके श्रन्तर्गत विश्वविद्यालय भी हैं i
- १२ पुस्तकालय, संप्रहालय श्रादि
- १३ स्ची १ में श्रनुल्लिखित संचार श्रर्थात सड़कें, नौकाघाट श्रादि
- १४ कृषि
- १४ पशु के नस्ल की उन्नति
- १६ पश्वरोध
- १७ जल, सिंचाई, नहरें, बंध, जलशक्ति श्रादि
- १८ भूमि
- १६ बन
- २० वन्य प्राशियों श्रीर पत्तियों की रत्ता
- २१ मीनचेत्र
- २२ प्रतिपालक श्रिधिकरण, भारप्रस्त श्रीर कुर्क सम्पदार्थे
- २३ खान श्रीर खनिज
- २४ उद्योग

परिशिष्ट

- २४ गैस
- २६ राज्य के श्रन्दर व्यापार वाणिज्य
- २७ वस्तुत्रों का उत्पादन, सम्भरण, वितरण
- २८ बाजार श्रीर मेले
- २६ माप स्थापन को छोड़ कर बाट श्रीर माप
- ३० साहूकारी, कृषि ऋणिता का उद्धार
- ३१ पन्थशाला
- ३२ ब्यापारिक, साहित्यक, वैज्ञानिक, धार्मिक संस्थायें, सहकारी समाजें, निगम
- ३३ नाट्यशाला, चलचित्र, क्रीड़ा, प्रमोद आदि
- ३४ पण लगाना और जूआ
- ३४ राज्य में निहित कर्मशालाएं, भूमि स्रौर भवन
- ३६ राज्य के प्रयोजनार्थं संपत्ति का ऋर्जन
- ३७ संसदीय विधि के श्रधीन विधान-मंडल के निर्वाचन
- ३८ विधान-सभाश्रों के सदस्यों के श्रधिकार श्रादि
- ३६ विधान-सभात्रों के सदस्यों त्रादि के वेतन त्रादि
- ४० राज्य के मंत्रियों के वेतन आदि
- ४१ राज्य लोक सेवाएं
- ४२ राज्य निवृत्ति वेतन
- ४३ राज्य का लोकऋण
- ४४ निखात निधि
- ४४ मू-राज्य
- ४६ कृषि श्राय पर कर
- ४७ कृषि भूमि का उत्तराधिकार शुल्क
- ४८ कृषि भूमि का सम्पत्ति शुल्क
- ४६ भूमि श्रीर भवनों पर कर

परिशिष्ट

- इ.चि भूमि के त्रतिरिक्त अन्य सम्पत्तियों का हस्तान्तरणः, विलखों
 आदि का पंजीयन
- ७ संविदाएं
- ८ श्रभियोज्य दोष
- १ दिवाला
- १० न्यास
- ११ महाप्रशासक श्रीर राज न्यासी
- १२ साच्य श्रीर शपर्थे
- १३ व्यवहार प्रक्रिया
- १४ न्यायालय-श्रवमान
- ११ त्राहिणडन, श्रस्थिरवासी श्रीर श्रादिम जातियां
- १६ उन्माद श्रीर मनोवक्र्य
- १७ पशुत्रों के प्रति निर्दयता निवारण
- १८ खाद्य पदार्थों में मिश्रग
- १६ श्रीषधि श्रीर विष
- २० श्रार्थिक श्रीर सामाजिक योजना
- २१ वाणिज्यिक श्रीर श्रीचोगिक एकाधिपत्य, गुट्ट श्रीर न्यास
- २२ व्यापार संघ, श्रमिक विवाद
- २३ सामाजिक सुरचा, सामाजिक बीमा, वेकारी
- २४ श्रमिकों का कल्याण
- २४ श्रमिकों का परीच्या
- २६ विधि वृत्तियां, वैद्यक वृत्तियां त्रादि
- २७ दौरेगार्थियों की सहायता श्रीर पुनर्वास
- २८ पूर्व श्रीर धार्मिक संस्थाएं
- २६ सांक्रामिक रोगों का निवारण
- ३० जीवन सम्बन्धी सांख्यकी
- ३१ महा-पत्तनों के श्रतिरिक्त श्रन्य पत्तन

भारत-नये संविधान तक

- ३२ नौ-वहन, जल पथ
- ३३ लोकहित के उद्योगों सम्बन्धी व्यापार, वाणिज्य
- ३४ मूल्य नियंत्रण
- ३४ यंत्र चालित यान
- ३६ कारखाने
- ३७ वाष्ययन्त्र
- ३८ विद्युत
- ३६ समाचार-पत्र, पुस्तकें श्रीर सुद्रणालय
- ४० पुरातत्व सम्बन्धी स्थान
- ४१ निष्क्राम्य सम्पत्ति
- ४२ अर्जित सम्पत्ति पर प्रतिकर
- ४३ किसी राज्य में, राज्य के बाहर पैदा हुए दावों विषयक वसूलियां
- ४४ मुद्रांक-शुल्क
- ४४ संघ-सूची श्रीर समवती-सूची सम्बन्धी विषयों के लिये जांच
- ४६ समवर्ती सूची संबंधी विषयों पर न्यायालयों के चेत्राधिकार
- ४७ समवर्ती सूची सम्बन्धी विषयों के बारे में फीसें

समाप्त